राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 170

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 28 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

शिखर धवन चोट के कारण बाहर, संजू को मौका

>> 14

सरोकार

शौचालयों, ट्रेनों में हैंडवॉश को सुलभ बनाएगी यह युक्ति

मेरठ : ट्रेन हों या सार्वजनिक शौचालय, अधिकांश जगहों पर हाथ धोने का साबुन

(लिक्विड सोप) सुलभ नहीं होता। कहीं खत्म, तो कहीं होता ही नहीं। एमआईईटी ने समाधान प्रस्तुत कर दिखाया है। ताकि स्वच्छ भारत में स्वच्छता का अधिकार हर किसी को, हर जगह सुलभ हो। (पेज-10)

जागरण विशेष

उत्तराखंड में दयारा बुग्याल को सुरक्षा देंगे जूट के जाल

उत्तरकाशी : हिमालय की गोद में फैले औषधीय पौधों व घास के मैदानों

(बुग्याल) को बचाने की पहल की जा रही है। शुरुआत हो रही है उत्तरकाशी में समुद्रतल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल से। (पेज-10)

महाराष्ट्र में आज से ठाकरे राज

मिली सत्ता ▶ उद्धव आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, उपमुख्यमंत्री राकांपा और स्पीकर कांग्रेस का होगा

शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस के एक-एक या दो-दो प्रमुख नेता भी लेंगे शपथ

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र में आज से ठाकरे राज की शुरुआत होने जा रही है। पिछले एक माह में अनेक उलटफेर के बाद अंततः गुरुवार शाम 6.40 बजे उद्धव ठाकरे दादर स्थित शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का मंच उस स्थल से चंद कदमों की दूरी पर होगा, जहां 2013 में उनके पिता शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे की अंत्येष्टि की गई थी। उद्धव के साथ तीनों पार्टियों के एक-एक या दो-दो प्रमुख नेता भी शपथ ग्रहण करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा में विश्वास मत के बाद होगा। सरकार में उपमुख्यमंत्री का पद राकांपा और विधानसभा स्पीकर का पद कांग्रेस के पास रहने की संभावना है।

ठाकरे परिवार का कोई सदस्य पहली बार किसी संवैधानिक पद की शपथ लेने जा रहा है। वह भी धुर विरोधी कांग्रेस-राकांपा को साथ लेकर बन रही सरकार में। कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना और कुछ छोटे दलों को मिलाकर बनी महाविकास अघाड़ी की शिवसेनानीत सरकार में 56 विधायकों वाली शिवसेना को राकांपा के 54, कांग्रेस के 44 विधायकों के अलावा सपा, प्रहार पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, बहुजन विकास अघाड़ी जैसे कुछ छोटे दलों का भी समर्थन प्राप्त है।

आदित्य ने सोनिया-मनमोहन से मिलकर दिया निमंत्रण : यशवंतराव चह्वाण सेंटर में राकांपा के वरिष्ठ नेता शरद पवार की उपस्थिति में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक के तुरंत बाद उद्धव के पुत्र आदित्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इनके अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और द्रमुक नेता एमके स्टालिन को भी न्योता दिया गया है। साथ ही विभिन्न जिलों के करीब 400 किसानों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है।

फड़नवीस को देना पड़ा था इस्तीफा : चुनाव परिणाम आने के 34 दिन बाद बनने जा रही इस सरकार से पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बीते सप्ताह सीएम पद की शपथ ली थी। उन्हें राकांपा विधायक दल के नेता अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ समर्थन का भरोसा दिलाया था, लेकिन परिवार के दबाव में अजीत को स्वयं उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस कारण फड़नवीस को भी न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि भाजपा को भी किरकिरी का सामना करना पड़ा।

विस में सुप्रिया सुले ने किया विधायकों का स्वागत : बुधवार सुबह महाराष्ट्र विधानमंडल के विशेष सत्र में प्रोटेम स्पीकर बबनराव पाचपुते ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के लिए विधानभवन पहुंचे विधायकों के स्वागत के लिए राकांपा सांसद एवं शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले स्वयं खड़ी थीं। आदित्य ठाकरे और अपने भतीजे रोहित का उन्होंने गले लगाकर स्वागत किया। वहीं, घर वापसी करने वाले बड़े भाई अजीत पवार का उन्होंने गले लगकर और पैर छूकर स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का भी प्रवेश के समय हाथ मिलाकर स्वागत किया।

ठाकरे राज (विशेष) पेज>>4

मुंबई में बुधवार को महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने के बाद बाहर लोगों का अभिवादन करते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। प्रेट्र

अहमद पटेल बोले, सुलझ गए सारे मुद्दे

बुधवार शाम करीब चार घंटे चली महाविकास

अघाड़ी की बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल सिर्फ यह कहकर आगे बढ़ गए कि बैठक में सारे मुद्दे सुलझ गए हैं। बाकी जानकारी गुरुवार को दी जाएगी।

यह विद्रोह नहीं था। मैं राकांपा का नेता था। क्या राकांपा ने मुझे हटाया? क्या आपने कहीं पढ़ा? मैं यही कहता रहा हूं कि मैं राकांपा में था, राकांपा में हूं और राकांपा में ही रहूंगा। **- अजीत पवार, राकांपा नेता**

राकांपा नेता अजीत पवार के भाजपा को समर्थन देने के मसले पर मैं सही समय आने पर बोलूंगा। **देवेंद्र फड़नवीस, कार्यवाहक मुख्यमंत्री**

शिवाजी पार्क में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मुंबई हाई कोर्ट ने इस नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस तरह के भीड़भाड़ वाले समारोह में आमजन की सुरक्षा पर चिंता जरूर जताई है।

मप्र में नसबंदी के बाद 13 महिलाओं को फर्श पर लिटाया, छह को नोटिस

नईदुनिया, विदिशा : मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन के बाद गंभीर लापरवाही सामने आयी है। पलंग उपलब्ध नहीं होने पर 13 महिलाओं को बरामदे में लिटा दिया गया। डीएम कौशलेंद्र सिंह के निर्देश पर प्रभारी सीएमएचओ डॉ. केएस अहिरवार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) सहित छह को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार, सोमवार को ग्यारसपुर में आयोजित नसबंदी शिविर में 41 महिलाओं के ऑपरेशन किए गए थे। स्वास्थ्य केंद्र में पलंग कम होने से 13 महिलाओं को बरामदे में बिस्तर बिछाकर लिटा दिया गया। मंगलवार को इसकी शिकायत मिलने पर प्रभारी सीएमएचओ डॉ. अहिरवार ने मौके पर जाकर जांच की। प्रभारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. बीपी शर्मा और स्टाफ ने बताया कि 41 महिलाओं के ऑपरेशन हुए थे, लेकिन 28 पलंग होने के कारण 13 महिलाओं को जमीन पर गद्दे बिछाकर लिटाया गया। डॉ. अहिरवार ने बताया कि जांच के बाद डीएचओ डॉ. हंसा शाह, प्रभारी बीएमओ बीपी शर्मा, मेडिकल ऑफिसर डॉ. टीएस मीणा और तीन स्टाफ नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का जवाब मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। डॉ. अहिरवार के मुताबिक, शिविर में महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की अव्यवस्था बनी थी। हालांकि, उन्होंने इसे लापरवाही नहीं माना। अधिकारियों के मुताबिक सभी महिलाओं को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सभी स्वस्थ बताई जा रही हैं।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में भारी कमी : राजनाथ

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद राज्य में आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी आई है। बुधवार को लोकसभा में शून्य काल के दौरान विपक्षी दल के सदस्यों की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर रक्षा मंत्री ने स्वयं अपनी तरफ से यह जानकारी दी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

हरियाणा के चर्चित आइएएस खेमका का 53वां तबादला

चंडीगढ़ : हरियाणा के चर्चित आइएएस अधिकारी डॉ. अशोक खेमका पर फिर तबादले की गाज गिरी है। घपले-घोटालों को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध खेमका को मनोहर लाल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की ओर से पहला तबादला आदेश मिला है। ज्ञात हो, इसे मिलाकर 28 साल के कॅरियर में खेमका का यह 53वां तबादला है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

निजीकरण नहीं हुआ तो बंद हो जाएगी एयर इंडिया : पुरी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हुआ तो इसका परिचालन बंद करना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा, सरकार इस विमानन कंपनी में पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। 31 मार्च, 2020 तक इसके विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ढाका कैफे आतंकी हमले में सात को मौत की सजा

ढाका : बांग्लादेश की विशेष अदालत ने राजधानी ढाका के एक कैफे पर 2016 में हुए आतंकवादी हमले के मामले में बुधवार को सात लोगों को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश मुजीबुर रहमान ने कहा, दोषियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए। बांग्लादेश के इस सबसे बड़े आतंकी हमले में भारतीय छात्रा समेत 20 लोगों की मौत हुई थी।

शाह बोले, स्टेटस सिंबल नहीं है एसपीजी की सुरक्षा

- एक्ट में संशोधन पर लगी लोकसभा की मुहर
- गृह मंत्री ने कहा- गांधी परिवार ने बगैर एसपीजी 600 बार यात्राएं कीं
- गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं, अधिक कवर वाली जेड-प्लस दी है

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में एसपीजी विधेयक पर बोलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एसपीजी में संशोधन का बिल लोकसभा में पास हो गया। इनसंशोधनों के पीछे राजनीतिक विद्वेष की भावना के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2015 से अब तक एसपीजी को बताए बिना 600 बार यात्राएं की हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि एसपीजी को स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि गांधी परिवार की सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि बदली गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एसपीजी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि गांधी परिवार की ओर से किस तरह एसपीजी सुरक्षा का दुरुपयोग किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के बाद राहुल गांधी ने एसपीजी को बिना बताए भारत में 1,892 बार और विदेश में 247 यात्राएं की हैं। इसीतरह सोनिया गांधी दिल्ली में 50 बार, देश के विभिन्न भागों में 13 बार और विदेश में 29 बार एसपीजी के बगैर घूमी हैं। प्रियंका गांधी एसपीजी कवर लिए बगैर दिल्ली में 339 दफा, देश के विभिन्न हिस्सों में 64 बार और विदेश में 94 बार घूमी हैं। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि सुरक्षा में रहने वाले एक सदस्य तो रात के दो बजे लुटियन दिल्ली में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हैं और उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मी पीछे छूट जाते थे। उन्होंने कहा कि एसपीजी सुरक्षा को स्टेटस सिंबल के रूप में देखना सही नहीं है। सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंभीरता का हवाला देते शाह ने कहा कि पिछले 20 सालों में उन्होंने एक बार भी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं किया।

खतरे का आकलन दो बार किया : शाह ने बताया कि गांधी परिवार पर खतरे का दो बार आकलन करने के बाद उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का फैसला लिया। गांधी परिवार को अब भी पूरे देश में सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा मिलेगी, जिसमें एंबुलेंस व गंतव्य पर पहले से छानबीन का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद क्यों हल्ला कर रही है। इसके पहले वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, इंद्रकुमार गुजराल से लेकर मनमोहन सिंह की भी एसपीजी सुरक्षा हटाई थी, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा।

पुराने एक्ट के तहत हटाई सुरक्षा पेज>>3

अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार याचिका नौ दिसंबर से पहले

- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है तैयारी
- जफरयाब जिलानी ने पुलिस-प्रशासन पर लगाया पक्षकारों को धमकाने का आरोप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका नौ दिसंबर से पहले दाखिल करेगा। बोर्ड याचिका को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को अयोध्या में विवादित स्थल राम लला को देने का निर्णय किया है। इसके बदले सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में दूसरे स्थान पर पांच एकड़ भूमि देने का निर्णय किया है। इसी निर्णय का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है।

तैयारी अंतिम चरण में : बोर्ड के सचिव व बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने बताया कि पुनर्विचार याचिका की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे पास याचिका दाखिल करने के लिए नौ दिसंबर तक का समय है। इसलिए दिसंबर के पहले हफ्ते में पुनर्विचार याचिका दाखिल हो जाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पुनर्विचार याचिका दाखिल न करने के फैसले पर उन्होंने कहा कि इससे पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

पुनर्विचार याचिका हमारा संवैधानिक अधिकार : उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिलानी ने आरोप लगाया कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाले मुस्लिम पक्षकारों को जिला प्रशासन व पुलिस धमका रही है। उन्हें जेल में बंद करने की धमकी दी जा रही है। इससे कई पक्षकार डरे हुए हैं। पुलिस व जिला प्रशासन के इस रवैये का भी उल्लेख पुनर्विचार याचिका में किया जाएगा। बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाले पक्षकारों के नामों की जानकारी फिलहाल नहीं देगा।

जफरयाब जिलानी फाइल फोटो

जमीयत का अरशद मदनी गुट भी दाखिल करेगा अर्जी

नई दिल्ली : मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्ग से ही हो रहे विरोध के बाद भी जमीयत उलेमा-ए-हिंद का अरशद मदनी गुट पुनर्विचार याचिका के फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। जमीयत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रामंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की तैयारी चल रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह में याचिका दायर की जा सकती है। जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी बताया है कि उनके नेतृत्व में कानून विशेषज्ञों और उलेमाओं के पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था, जिसने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। (पेज-6)

झारखंड में भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र

रांची : भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में पिछड़ों और महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के साथ-साथ हर बालिका को केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा का वादा किया है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में जनजातीय विकास का संकल्प दोहराया है तो किसानों, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में विकास की उम्मीदें जताई हैं। औद्योगिक विकास की भी चिंता की गई है। (पेज-5)

मेरे खिलाफ कोई सुबूत नहीं, जमानत मिलनी चाहिए : चिदंबरम

नई दिल्ली : पिछले 99 दिनों से जेल में बंद पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आइएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। कोर्ट स कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है उन्हें जेल में रखना ठीक नहीं है। बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री की जमानत याचिका पर बहस पूरी कर ली गई। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे। (पेज-5)

1144 करोड़ रुपये के सिटी सेंटर घोटाले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर समेत सभी बरी

- अदालत ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए
- 36 लोगों के खिलाफ 12 साल से चल रहा था मामला

जागरण संवाददाता, लुधियाना

बहुचर्चित 1144 करोड़ रुपये के सिटी सेंटर घोटाले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित सभी 36 आरोपितों को बरी कर दिया गया है। इनमें से पांच लोगों का निधन हो चुका है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह की अदालत ने विजिलेंस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए 12 साल से चल रहे इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट में मौजूद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अदालत ने उन पर लगे कथित आरोपों को आखिरकार खारिज कर दिया।

सेशन जज गुरबीर सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए। मुख्यमंत्री और उनके परिवार द्वारा खरीदी गई जमीन उनके नाम पर है और उसे बेनामी संपत्ति नहीं कहा जा सकता। नगर सुधार ट्रस्ट लुधियाना के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय परमजीत सिंह सीबिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सुबूत नहीं मिला परंतु उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हिदायतों और राय की अनदेखी की। वहीं, नगर सुधार ट्रस्ट के पूर्व कार्यकारी अधिकारी दयाल चंद गर्ग के घर से बरामद 40 लाख रुपये की राशि का इस केस से कोई संबंध सामने नहीं आया।

> हमने 13 साल केस का सामना किया। अदालत ने हमें बेकसूर पाया और सभी को बरी कर दिया है। हमें शुरू से न्याय प्रणाली में पूरा भरोसा था।
> **- कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब।**

> आरोपितों को सजा दिलवाने के लिए सेशन कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
> **- सिमरजीत सिंह बैंस, विधायक और अध्यक्ष लोक इंसाफ पार्टी।**

कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य पर यह लगे थे आरोप

विजिलेंस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके पुत्र रणइंदर सिंह और दामाद रमिंदर सिंह पर आरोप लगाया था कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान निजी बिल्डर को लाभ पहुंचाया गया, जिससे राज्य के खजाने को 1144 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा। कैप्टन ने एलआइटी अधिकारियों व अन्य लोगों के साथ मिलकर मैसर्ज टुडे होम्स का पक्ष लिया और बिड्स (निविदा) में छेड़छाड़ की। कैप्टन ने परियोजना को मंजूरी देने से इन्कार करने पर एलआइटी के चेयरमैन अशोक गरचा को हटा दिया था। विजिलेंस ने एलआइटी के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी दयाल चंद गर्ग से 40 लाख की रिश्वत की वसूली का दावा भी किया था। दिल्ली निवासी चेतन गुप्ता से एक पेन ड्राइव बरामद कर कैप्टन और उनके बेटे रणइंदर सिंह के खातों में मैसर्ज टुडे होम्स द्वारा कथित रूप से करोड़ों रुपये के लेन-देन के विवरण का दावा किया था।

सुधा मूर्ति बोलीं

टेल्को की पहली महिला इंजीनियर सुधा मूर्ति की कहानी, इंजीनियरिंग कालेज में 600 छात्रों में वह अकेली छात्रा थीं, केबीसी-11 में शिरकत करेंगी, फिनाले एपीसोड कल होगा प्रसारित

धारा के विपरीत बढ़ने वाले ही बदलाव लाने में सक्षम

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

बहाव के विपरीत दिशा में बढ़ने वाले ही बदलाव लाते है। इसकी जीती जागती मिसाल हैं इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति। जिस दौर में महिलाओं को पढ़ाना-लिखाना भी जरूरी नहीं समझा जाता था, उस दौर में वह टेल्को की पहली महिला इंजीनियर बनी थीं। उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक बातों का रहस्योद्घाटन 'कौन बनेगा करोड़पति-सीजन-11' के फिनाले एपिसोड करमवीर में किया। यह एपिसोड 29 नवंबर को सोनी टीवी पर प्रसारित होगा।

महिला सशक्तिकरण की मिसाल सुधा मूर्ति के लिए पढ़ाई से लेकर नौकरी तक का सफर बेहद मुश्किलों भरा था। वह बताती हैं, 'वर्ष 1968 में इंजीनियरिंग करने का मन बनाया। पिता सरकारी डॉक्टर थे। मां शादी से पहले स्कूल टीचर थीं। इंजीनियरिंग करने की बात सुनते ही दादी ने कहा, इंजीनियरिंग कर ली, तो शादी के लिए बिरादरी में अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि लड़की का इंजीनियरिंग करना कल्पना से परे है।' इसमें काफी हद तक सच्चाई भी थी क्योंकि जिस कालेज में दाखिले के लिए आवेदन किया था, उसमें 600 विद्यार्थी थे, मैं अकेली लड़की थीं।

बकौल सुधा 'प्रिंसिपल ने मेरे नंबरों के आधार पर मुझे दाखिला तो दिया, लेकिन तीन शर्तें थीं-पूरे इंजीनियरिंग कोर्स के दौरान मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी, मैं कालेज कैंटीन नहीं जा सकती और किसी लड़के से बात नहीं कर सकती। पहली शर्त मुश्किल नहीं थी। दूसरी शर्त आसान थी क्योंकि कैंटीन इतनी खराब थी कि मैं वहां जाना ही नहीं चाहती थी। तीसरी शर्त का पालन एक साल तक किया। मैं रैंक होल्डर बन चुकी थी। अतः लड़कों ने ही मुझसे बात करना शुरू कर दिया था।'

उन्होंने बताया कि वर्ष 1974 में एमटेक करने के बाद अमेरिका जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। इसी दौरान 'टेल्को कंपनी (वर्तमान में टाटा मोटर्स) का एक नोटिस देखा, जिसमें युवा इंजीनियरों की जरूरत थी। वेतन 1500 रुपये महीना थी। नोटिस में लिखा था कि महिला विद्यार्थी आवेदन न करें। इस बात ने मुझे विचलित कर दिया! मैंने पोस्टकार्ड उठाया और गुस्से में लिखने बैठ गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हमारे फाउंडर्स डे पर जेआरडी (जहांगीर रतनजी दादाभाई) टाटा आते थे। मैंने लिखा, 'डियर जेआरडी टाटा, टाटा परिवार औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आपने कई होटलों और टिस्को कंपनी का निर्माण किया है, लेकिन आपकी सोच बहुत पिछड़ी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं? हमारे समाज में 50 फीसद महिलाएं हैं। यदि ऐसी ही सोच जारी रही तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे।' मैंने पत्र पर मिस्टर जेआरडी टाटा, टेल्को, मुंबई लिखकर पोस्ट कर दिया। पता गलत था लेकिन उन्हें मेरा पत्र मिल गया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, मेरा टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाए ताकि उन्हें सही उम्मीदवार मिल सके। मैंने 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। लग रहा था कि वो जानबूझकर मुझे फेल कर देंगे, लेकिन मैं पास हो गई और नौकरी मिल गई। इसके बावजूद मैं अमेरिका जाने वाली थी। इस पर पिताजी ने कहा, यदि मैं सचमुच ये मानती हूं कि इस क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो मुझे नौकरी करके इसे साबित करना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो यह महिलाओं के लिए गलत उदाहरण होगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम न सिर्फ यह नौकरी करो, बल्कि अच्छा प्रदर्शन भी करो। मैंने पिता की बात मानी और टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बन गई।' सुधा मूर्ति की प्रेरणादायक कहानी सुनकर अभिभूत शो के एंकर अमिताभ बच्चन ने उनका ऑटोग्राफ लेने के साथ उनके चरण भी छुए।

इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति के पैर छूते अमिताभ बच्चन। सौजन्य से - सोनी टीवी

अंतरिक्ष में कामयाबी की एक और छलांग

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बुधवार को देश के अर्थ ऑब्जर्वेशन और मैपिंग सेटेलाइट कार्टोसैट-3 तथा 13 अमेरिकी नैनो सेटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया। (पेज-16 भी देखें) प्रेट्र

- इसरो ने बुधवार सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर कार्टोसैट-3 और 13 नैनो अमेरिकी सेटेलाइट को किया लांच
- 44.4 मीटर लंबे पीएसएलवी-सी 47 रॉकेट से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया प्रक्षेपण
- प्रक्षेपण के 17 मिनट 46 सेकेंड बाद कार्टोसैट-3 और 26 मिनट 56 सेकेंड बाद अमेरिकी नैनो सेटेलाइट कक्षा में स्थापित
- 1625 किलोग्राम वजनी कार्टोसैट-3 सर्वाधिक रेज्यूलेशन वाला सेटेलाइट है। यह पांच साल तक करेगा काम

40 हजार लोग पहुंचे प्रगति मैदान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अंतिम दिन। 14 नवंबर को शुरू हुए मेले का बुधवार को समापन हो गया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 28 नवंबर 2019

एफओबी का कराया जाएगा तकनीकी अध्ययन

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) बदहाल हो चुके फुट ओवरब्रिज (एफओबी) और सब-वे की दशा सुधारने के लिए तकनीकी अध्ययन कराएगा। अभियंताओं की एक टीम इस कार्य में लगाई गई है, जो यह जानकारी जुटा रही है कि कौन सा एफओबी कितना पुराना है और उसमें क्या-क्या काम होना है। इस योजना में 2012 से पहले के बने सभी एफओबी और सब-वे शामिल किए गए हैं।

कुछ माह पहले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश पर योजना विभाग ने लोगों के इस्तेमाल करने और नहीं करने के नजरिये से 74 एफओबी और 37 सब-वे का अध्ययन कराया था। एक माह तक कराए गए इस अध्ययन की रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी, जिसमें यह भी बताया गया था कि किस एफओबी का कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 74 एफओबी में से 57 में लिफ्ट नहीं है। नौ एफओबी पर ही लिफ्ट सही से संचालित हो रही हैं, बाकी जगह लिफ्ट टूटी हैं या खराब हैं। केवल 17 एफओबी में एस्केलेटर हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि सभी एफओबी में लिफ्ट और एस्केलेटर होने चाहिए। एफओबी और सब-वे का प्रयोग नहीं करने वाले ज्यादातर लोगों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्ड होने पर वे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये हैं खास एफओबी

2010 में 12 करोड़ 33 लाख की लागत से जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के पास अर्ध चंद्राकार दो फुट ओवरब्रिज बनाए गए थे। इसी तकनीक से राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर दो एफओबी बनाए गए थे। एनएच-9 की योजना के चलते दो एफओबी तोड़ दिए गए हैं। गाजीपुर गांव के पास मुख्य मार्ग पर इसी तकनीक से बनाया गया एफओबी मौजूद है। ब्रिटानिया चौक के पास भी एफओबी बनाए गए हैं।

अध्ययन के दौरान एफओबी का इस्तेमाल करने वालों की संख्या

- 2 लाख 28 हजार 226 लोगों ने पूर्वी जोन में एफओबी का इस्तेमाल किया
- 52 हजार 978 लोगों ने उत्तरी जोन में एफओबी का किया इस्तेमाल
- 1 लाख 79 हजार 870 लोगों ने दक्षिणी जोन में एफओबी का इस्तेमाल किया।

क्या कहती है रिपोर्ट

- कई एफओबी में गंदगी और कहीं जीर्ण स्थिति में
- 64 फीसद एफओबी पर ही छत
- 78 फीसद एफओबी में लाइट मिली
- 32 फीसद एफओबी में फर्श नहीं
- फर्श ठीक नहीं होने के कारण लोगों को चोट लगने की आशंका रहती है
- लोगों को पता नहीं चल पाता है कि एफओबी और सब-वे कहां हैं

अध्ययन के दौरान एफओबी का इस्तेमाल नहीं करने वालों की संख्या

- 99 हजार 625 लोगों ने पूर्वी जोन में एफओबी का नहीं किया इस्तेमाल
- 28 हजार 433 लोगों ने उत्तरी जोन में एफओबी का इस्तेमाल नहीं किया
- 60 हजार 893 लोगों ने दक्षिणी जोन में एफओबी का इस्तेमाल नहीं किया

बारिश से बदला दिल्ली का मिजाज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में बुधवार को हुई बारिश और तेज हवा ने यहां की फिजा को ठंड से भर दिया। शाम के समय तो दिल्लीवासियों को ठीकठाक ठंड का अहसास होने लगा था। चूंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। साथ ही पंजाब एवं राजस्थान में भी बारिश हुई है, इससे आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने के आसार हैं। दिसंबर की शुरुआत भी ठंडक के साथ ही होगी। माह के पहले हफ्ते में ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा।

बुधवार को दिल्ली में सुबह से बादल छाए रहे। तेज पुरवईया हवा भी चल रही थी। हालांकि बारिश दोपहर बाद हुई। अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से पांच डिग्री तक अधिक है। सबसे अधिक बारिश जाफरपुर में हुई, जहां साम मिमी तक बारिश दर्ज की गई। रिज में 0.8 मिमी, पूसा में एक मिमी बारिश हुई। पालम, लोदी रोड और सफदरजंग में बूंदाबांदी हुई। हवा में नमी का स्तर 58 से 89 फीसद तक रहा।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने की भी संभावना है। हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 एवं 15 डिग्री रहने की संभावना है। शुक्रवार के बाद मौसम साफ होने लगेगा। ऐसे में कोहरा बढ़ेगा। शनिवार को मध्यम श्रेणी का कोहरा देखने को मिल सकता है।

राजधानी में बारिश के बाद वातावरण में ठंडक बढ़ गई। अगले महीने के पहले सप्ताह तक न्यूनतम तापमान के 10 डिग्री से नीचे पहुंचने के आसार। जागरण

'अनधिकृत कॉलोनियों पर राजनीति न करे केंद्र'

आमने-सामने ▶ केजरीवाल ने की दिन तीन में सभी को रजिस्ट्री देने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग

सीएम बोले, कई पत्र लिखे, खूब दबाव बनाया, तब इन्हें पक्का करने का बिल लाए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अनधिकृत कॉलोनियों पर राजनीति बंद कर अब रजिस्ट्री की जानी चाहिए। यही नहीं रजिस्ट्री सौ या पांच सौ लोगों की नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली की होनी चाहिए। केंद्र की पिछली सरकारों की तरह इस सरकार में भी यह सिर्फ चुनावी वादा बनकर न रह जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ सौ लोगों को रजिस्ट्री देकर फोटो खिंचाने की तैयारी की है, जो सरासर गलत और जनता के साथ धोखा होगा। सीएम ने कहा विधानसभा चुनाव नजदीक देख भाजपा भी अनधिकृत कॉलोनियों में गई, लेकिन वहां लोगों ने आम आदमी पार्टी (आप) के काम गिनाने शुरू कर दिए। इसके बाद केंद्र सरकार अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का बिल संसद में पेश करने को मजबूर हो गई। लेकिन अब फिर से जनता के साथ धोखा करने की तैयारी है।

सौ लोगों को रजिस्ट्री देकर अन्य लोगों को चुनाव बाद रजिस्ट्री देने की बात हो रही है। यह काम तो कई दशकों से हो रहा है। चुनाव में रजिस्ट्री देने का वादा होता है, फिर अगले चुनाव में आने को कह दिया जाता है। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले यह सब कई वर्षों से देख रहे हैं। उन्हें चुनाव दर चुनाव के छलावे में रखना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को इन कॉलोनियों को वैध घोषित कर तीन दिन में सभी को रजिस्ट्री देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। कहा कि जब 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान वह अनधिकृत कॉलोनियों में जाते थे, तो वहां रह रहे लोगों की परेशानी से रूबरू हुए थे। उसी समय उन्होंने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद इन कॉलोनियों को नारकीय जीवन से बाहर निकाला जाएगा। पिछले पांच साल में इनमें कायापलट हुआ है।

दिल्ली में आप की सरकार बनने के बाद अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने और विकास के लिए काम तेज हुआ। अब एक-दो माह से कॉलोनियों को पक्का कराने की बात की जा रही है, आखिर पांच साल से क्यों नहीं कराया गया।

कई पत्र लिखे, दबाव बनाया तब लाए बिल : केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का दिल्ली में सरकार बनते ही प्रस्ताव भेजा था। चार साल केंद्र सरकार सोती रही। खूब पत्र लिखे, खूब दबाव बनाया, इसके बाद केंद्र सरकार इन कॉलोनियों को पक्का करने का बिल लेकर आई। अब चुनाव से पहले 100 या 500 लोगों को रजिस्ट्री दिलाकर भाजपा कांग्रेस की तरह कार्य न करे। कांग्रेस ने 2008 के चुनाव से ठीक पहले इसी तरह से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे, मगर चुनाव बाद कुछ नहीं हुआ।

दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पांच वर्षों में अनधिकृत कॉलोनियां में कालापलट कर दिया। जागरण

अनधिकृत कॉलोनियों पर भ्रम फैला रही आप : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ मनोज तिवारी बोले, मुख्यमंत्री ने इन कॉलोनियों में कोई काम नहीं किया

भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर दिल्लीवासियों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। संसद में बिल भी पेश कर दिया गया है, लेकिन आप नेता इसे लेकर अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इन कॉलोनियों में कोई काम नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को नरक से भी खराब बताया है। अदालत की इस टिप्पणी के बावजूद यह सरकार नहीं सुधर रही है। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में सबसे बड़ी बाधा दिल्ली सरकार थी। इन कॉलोनियों में न तो सड़कें बनाई गई हैं और न पानी-सीवर की समस्या दूर की गई।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) अनधिकृत कॉलोनी के लोगों के साथ धोखा करती रही हैं। वहीं, भाजपा ने अपना वादा पूरा करते हुए केंद्र में नरेंद्र मोदी की दूसरी बार सरकार बनने के सौ दिनों में यह काम कर दिया। इससे आप नेता परेशान हैं। मुख्यमंत्री अब गलत आंकड़े पेश करके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य कराने के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में कहीं कोई काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भारी-भरकम राशि इन कॉलोनियों में खर्च करने का दावा कर रहे हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए इस राशि से कौन से काम कराए गए हैं। सच्चाई यह है कि लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्हें पानी भी खरीदकर पीना पड़ता है। अब तक इन कॉलोनियों में लोगों को पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इन कॉलोनियों में मकानों पर नंबर लगाने का काम शुरू कर दिया है। 16 दिसंबर से मालिकाना हक देने और नियमितीकरण की प्रक्रिया वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों के विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

अब दुष्कर्म व हिंसा की शिकार महिलाओं को नहीं होगा भटकना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ दिल्ली में पहला सखी-वन स्टॉप सेंटर शुरू

दुष्कर्म व हिंसा पीड़ित महिलाओं को अब एक ही छत के नीचे कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। पीड़िता को कहीं भटकना न पड़े, इसी उद्देश्य के साथ दिलशाद गार्डन स्थित मानव व्यवहार व संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) में सखी-वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई है। इस सेंटर में पीड़िताओं को कानूनी, पुलिस, चिकित्सा, मनोचिकित्सा की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्हें यहां अस्थायी आश्रय भी मिलेगा। बुधवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन किया। दिल्ली में यह पहला सेंटर है, जो 24 घंटे खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार निर्भया फंड के जरिये इस तरह के सेंटर दस अन्य जिलों में भी स्थापित किए जाएंगे।

वन स्टॉप सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस सेंटर की सफलता बहुत जरूरी है। यहां जो भी महिला आए, वह निराश होकर वापस न जाए। यही इसकी सफलता तय करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कागजों पर तो बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन जब तक उसका लाभ किसी को न मिले तो वे बेकार हैं। महिलाओं को हर संभव मदद मिलनी चाहिए, यही लक्ष्य हम सभी का होना चाहिए। इस सेंटर में कई विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इस सेंटर में किसी भी कर्मचारी या विभाग की उदासीनता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बहुत कम समय में इस सेंटर को तैयार करने में शामिल इहबास के निदेशक डॉ. निमेष जी देसाई और शाहदरा के जिलाधिकारी संजीव कुमार की तारीफ की।

समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दुष्कर्म और पीड़ित महिलाएं अपने आपको अकेला न महसूस करें। इसके लिए इस तरह के सेंटर की जरूरत थी, जिसे दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है। इस सेंटर की देखरेख जिलाधिकारी के अधीन ही रहेगी।

डॉ. निमेष जी देसाई ने कहा कि यहां आने वाली महिलाओं को सुरक्षित माहौल का अहसास दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिलाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि अच्छी सोच के शुरू किए गए इस प्रयास को सफल बनाया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने दी जाएगी। कार्यक्रम में मंच संचालन जितेंद्र अरोड़ा ने किया।

अक्षरधाम मंदिर को मिली मंजूरी में नहीं है कोई गलती

जासं, नई दिल्ली : एनजीटी ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि अक्षरधाम मंदिर के विस्तार के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से मिली मंजूरी में कोई गलती नहीं है। एनजीटी ने कहा कि रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि अक्षरधाम मंदिर के विस्तार की योजना यमुना डूब क्षेत्र में नहीं है। एनजीटी ने अक्षरधाम मंदिर प्रबंधन की तरफ से दायर अर्जी पर केंद्र से जवाब मांगा था।

मंदिर प्रबंधन से अर्जी में पूछा था कि यह साफ किया जाए कि मंदिर विस्तार डूब क्षेत्र में है या नहीं? एनजीटी ने 2015 में अक्षरधाम मंदिर के विस्तार को यमुना डूब क्षेत्र में मानते हुए कुल निर्माण की लागत का पांच फीसद जुर्माने के तौर पर अदा करने को कहा था। एनजीटी के पूर्व के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसके बाद जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनी। अब उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने पाया कि अक्षरधाम मंदिर के विस्तार के लिए प्रबंधन को जो मंजूरी मिली थी, उसमें कोई गलती नहीं है।

कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली में लागू होगी न्याय योजना : चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ बोले, गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को सालाना 72 हजार दिए जाएंगे

▶ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी द्वारा घोषित की गई न्याय योजना लागू की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे के हरेक परिवार को सालाना 72 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी द्वारा मित्रों की मदद के लिए लाई गई नोटबंदी योजना ने महिलाओं की कमाई व बचत को भी कालाधन बताकर उनकी न केवल रसोई पर डाका डाला, बल्कि उन्हें पूरी तरह कंगाल कर दिया।

चोपड़ा प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी अभियान के तहत चांदनी चौक जिले में आयोजित सम्मेलन में मौजूद महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी कर रही थीं। सम्मेलन को पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल, मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने भी संबोधित किया। मालूम हो कि महिला कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर पूरी दिल्ली के जिलों में महिला सशक्तीकरण के लिए सम्मेलन की शुरुआत की थी, जो अभी भी चल रहे हैं। इस दौरान चोपड़ा ने समाजसेवी महिलाओं को शील्ड व शॉल देकर सम्मानित भी किया।

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के कारण राजधानी आज रेप कैपिटल बन गई है। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब केजरीवाल मोमबत्ती लेकर धरने पर बैठे थे। दिल्ली में अब महिलाओं के साथ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, उसे देखते हुए तो केजरीवाल को मोमबत्ती नहीं, हैलोजन लाइट लेकर प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन वह चुप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन औसत दुष्कर्म के छह मामले सामने आ रहे हैं।

जेएनयू छात्र संघ ने बनाई मानव शृंखला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई छात्रावास की फीस के खिलाफ छात्र संघ ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर मार्च निकाला और मानव शृंखला बनाई। इसमें छात्र संघ की अध्यक्ष आईशी घोष, उपाध्यक्ष साकेत मून व महासचिव सतीश चंद्र यादव मौजूद थे। शाम चार बजे विश्वविद्यालय के छात्र राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-5 पर जुटने लगे और इसके बाद सेंट्रल पार्क के पास चक्कर काटते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन एवं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी बीच कुछ युवाओं ने छात्र संघ एवं संस्थान के छात्रों के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। अतिसंवेदनशील माने जाने वाले कनॉट प्लेस में गहमागहमी का माहौल नजर आने लगा। पुलिस के सिपाही एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान भी जेएनयू के छात्रों के मार्च के साथ ही चल रहे थे।

युवाओं के समूह ने किया विरोध : शाम 5.30 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से थोड़ी दूर 15 से 20 युवाओं ने जेएनयू के छात्रों के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने मामले को संभालते हुए इन युवाओं को विश्वविद्यालय के छात्रों से दूर रखा और कुछ देर बाद इन्हें कहीं और जाने के लिए कह दिया। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे रजत श्रीवास्तव ने कहा कि हम जेएनयू या इसके छात्रों के विरोध में नहीं है। कुछ छात्र बेमतलब की आजादी की हमेशा बात करते रहते हैं। मेरा सवाल है कि इन्हें किस चीज से आजादी चाहिए। अगर इन्हें इतनी ही आजादी चाहिए तो यह पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं। प्रदर्शन के नाम पर मेट्रो व सड़क जाम करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। साथ ही इन युवाओं ने वंदे मातरम और जय श्रीराम के भी नारे लगाए। इन युवाओं ने खुद को किसी भी संगठन के साथ जुड़े होने से इन्कार किया।

जेएनयू में छात्रावास की फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्र कनॉट प्लेस में मानव शृंखला बनाने के लिए जुटे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जागरण

मुख्यमंत्री बोले, मध्यस्थता केंद्रों को बनाएंगे रोल मॉडल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : जिस तरह से दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक दुनिया के लिए मॉडल बन गए हैं, उसी तरह यहां के मध्यस्थता केंद्रों को भी रोल मॉडल बनाएंगे, जिससे कि लोगों के आपसी विवाद का निपटारा बिना पैसा खर्च व समय बर्बाद हुए हो सके। पूरे देश में मध्यस्थता केंद्र खोले गए, लेकिन हर जगह ये केंद्र एक-दो साल चलकर बंद हो गए, जबकि दिल्ली में मध्यस्थता केंद्रों ने दस साल पूरे कर लिए। लोगों का विश्वास भी इनमें इतना बढ़ा कि आज हम छह नए केंद्रों का उद्घाटन कर रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली डिस्प्यूट रिज्योल्यूशन सोसायटी (डीडीआरएस) के स्थापना के दस साल पूरे होने पर दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में कहीं।

छह नए मध्यस्थता केंद्रों के उद्घाटन के मौके पर केजरीवाल ने कहा कि डीडीआरएस ने दस साल में काफी कुछ किया है। मध्यस्थता केंद्र से मुझे गांधी जी के जीवन की एक घटना याद आती है। वह वकील थे। दक्षिणी अफ्रीका की एक फर्म में वह नौकरी कर रहे थे। उन्हें पहला केस मिला। केस बहुत बड़े आदमी का था। गांधी जी ने केस में दोनों पार्टी को बैठाकर समझौता करा दिया। फर्म नाराज हो गई। उसे केस चलने से बहुत पैसा मिलने वाला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां सालों केस नहीं चलता। खर्च नहीं होता। दिल्ली के मध्यस्थता केंद्रों में 33 हजार केस सुलझे हैं। यह बहुत बड़ी सफलता है। इसे अगले साल और प्रमोट करेंगे। कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मजबूरी में ही कोई कोर्ट जाता है। बहुत पैसा और समय खर्च होने के कारण लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते। इस मौके पर डीडीआरएस के चेयरमैन जस्टिस मदन लाल मेहता, जस्टिस मदन बी लोकुर व मुख्य सचिव विजय कुमार देव मौजूद थे।

एक से सवा माह में सुलझ जाते हैं केस : डीडीआरएस की स्थापना 27 नवंबर 2009 को हुई थी। अभी 10 केंद्र हैं। बुधवार को छह नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया। मध्यस्थता केंद्रों में अब तक 75 हजार केस आए, जिनमें से 33 हजार केस सुलझ लिए गए। सफलता का फीसद 44 है।

घोषणा

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री बोले, वर्ष 2020 में आयोजित होने वाला मेला ईज ऑफ लिविंग की थीम पर आधारित रहेगा

अगले साल पांच गुना बड़े क्षेत्र में होगा भव्य मेला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अगले साल अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन भव्य और बड़ा होगा। ऐसे में मेले में जहां इस साल चार लाख से अधिक लोगों ने आनंद लिया, वहीं अगले वर्ष यह संख्या करीब 15 लाख पहुंचने का अनुमान है। जगह बढ़ने के साथ यहां पर कन्वेंशन सेंटर भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2020 में आयोजित होने वाला मेला ईज ऑफ लिविंग की थीम पर आधारित रहेगा। ये बातें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रगति मैदान में आयोजित 39वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन पर कहीं।

उन्होंने कहा कि नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हमें स्टार्टअप व स्टैंडअप पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए भारत की कल्पना को साकार करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण के साथ रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत निवेश कर हमें पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को भी प्राप्त करने की जरूरत है।

प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार राज्य को बेहतर मंडप व उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्रदान करते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। संजय

उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में विभिन्न स्थानों पर चार मेगा प्रमोशन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिनमें भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (आइटीपीओ) को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर) एलसी गोयल ने कहा कि अगले साल आयोजित होने वाला मेला भव्य व इस बार की तुलना में पांच गुना बड़ा होगा, जो यहां आने वाले पर्यटकों के लिए देखने लायक होगा।

बिहार को स्वर्ण और असम को रजत पदक से सम्मानित किया

समापन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। इनमें बिहार को स्वर्ण पदक मिला तो असम को रजत पदक से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश को कांस्य पदक मिला। इसके साथ ही झारखंड व पश्चिम बंगाल को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

विदेशी मंडपों में बहरीन को मिला स्वर्ण

विदेशी मंडपों में बहरीन को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। टर्की को रजत पदक मिला व चीन को कांस्य पदक दिया गया। इसके अलावा ट्यूनेशिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मारी बाजी

मंत्रालयों के मंडपों में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को स्वर्ण पदक मिला। इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को रजत पदक तो खादी ग्रामोद्योग को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।

तकनीकी बिड में चारों कंपनियां सफल घोषित

जासं, ग्रेटर नोएडा : जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकनीकी बिड में चारों कंपनियां सफल घोषित हुई हैं। प्रदेश की परियोजना निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति (पीएमआइसी) की बुधवार को लखनऊ में हुई बैठक में उन्हें सफल घोषित किया गया है। अब इन चारों कंपनियों की फाइनेंशियल बिड 29 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) के ग्रेटर नोएडा कार्यालय में खोली जाएगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकनीकी बिड छह नवंबर को खोली गई थी।

एयरपोर्ट के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, च्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड व एंकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग लिमिटेड ने बिड डाली है। लखनऊ में बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीएमआइसी की बैठक हुई जिसमें सभी कंपनियों को तय शर्तों पर खरा पाया गया। नियाल के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि फाइनेंशियल बिड ग्रेटर नोएडा स्थित नियाल कार्यालय में 29 नवंबर को दोपहर बाद तीन बजे खोली जाएगी। एयरपोर्ट के लिए कंपनी चयन की प्रमुख शर्त अधिकतम राजस्व देना है।

2017 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसके तहत महिलाओं को 5000 रुपये सहायता का प्रावधान किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती की है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में भारी कमी : राजनाथ

रक्षा मंत्री ने कहा, राज्य में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर बोलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य में आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी आई है। बुधवार को लोकसभा में शून्य काल के दौरान विपक्ष की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर रक्षा मंत्री ने स्वयं अपनी तरफ से यह जानकारी दी।

राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में आतंकवादी घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने भारतीय सेना, अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के जवानों की सराहना भी की जो बेहद सतर्कता से वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साढ़े पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर देश के किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। कांग्रेस सदस्य के. सुरेश ने शून्य काल के दौरान यह मुद्दा उठाया था कि जम्मू व कश्मीर में हालात बेहद असमान्य है जबकि सरकार का दावा है कि वहां हालात सामान्य हो चुके हैं। उन्होंने दो दिन पहले कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आतंकी हमले का जिक्र भी किया। विपक्ष रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सुरेश समेत कई सदस्यों ने सरकार से कहा कि, राज्य में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए।

वालाकोट में फिर आतंकी कैंप सक्रिय कर रहा पाकिस्तान : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि पाकिस्तान बालाकोट में फिर से आतंकी शिविरों को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने इस साल फरवरी में हमला कर यहां के आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

जम्मू-कश्मीर में पांच हजार लोग हिरासत में लिए गए थे : गृह राज्यमंत्री रेड्डी ने उच्च सदन को बताया कि पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में पांच हजार से ज्यादा लोगों को निवारक हिरासत में लिया गया था। इनमें से 609 लोग अभी भी हिरासत में हैं, जिनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री-फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। इनमें लगभग 218 पत्थरबाज भी हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद हटाने के बाद से राज्य में पुलिस की गोली से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने के दौरान लगभग दो सौ लोग जख्मी हुए।

पाबंदियों से आय और नौकरियों में कमी की रिपोर्ट नहीं : रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि पाबंदियों के चलते आय और नौकरियों में कमी को लेकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अब वहां के लोग अर्थव्यवस्था का पूरा फायदा महसूस कर सकेंगे।

जम्मू-कश्मीर पर अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ : संसद के उच्च सदन में रेड्डी ने बताया कि अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर किसी तरह का व्यय नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के मुताबिक ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठन किया गया।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक को सरकार ने वापस लिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने लोकसभा से जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक वापस ले लिया है। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को कोटा मुहैया कराने वाला केंद्रीय कानून लागू है। गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को लोकसभा में जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक पेश किया था। यह विधेयक जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन और एक मार्च को लागू अध्यादेश की जगह लेने के लिए लाया गया था। यह अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को राज्य सरकार के कुछ पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति में आरक्षण मुहैया कराता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के इस कानून में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग शामिल हैं। यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप के इलाके में रहने वालों को भी आरक्षण के दायरे में लाने के लिए लाया गया था। अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाने के बाद से केंद्र के कानून अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में भी लागू होंगे। ज्ञात हो, केंद्र सरकार विकास की विभिन्न योजनाओं के जरिये जम्मू कश्मीर में उन्नति की गंगा बहाने को उत्सुक है।

पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य की याचिका

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

अनुच्छेद-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगाए गए नियंत्रणों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनकर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कांग्रेस नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लगाए गए नियंत्रणों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

जस्टिस एनवी रमना, आर. सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया। बुधवार को गुलाम नबी आजाद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने नियंत्रण का विरोध करते हुए कहा कि वह यह समझते हैं कि वहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, लेकिन 70 लाख लोगों को इस तरह बंद करके नहीं रखा जा सकता। यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। राष्ट्रीय सुरक्षा और जीवन के अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिए। सरकार कह रही है कि जम्मू-कश्मीर में सब सामान्य है, लेकिन अनुच्छेद-370 हटने के बाद से लगी पाबंदियों के इतने दिन बीतने के बाद भी वहां सब कुछ ठीक नहीं है। जम्मू-कश्मीर में कारोबार, स्कूल, किसान और पर्यटन बहुत प्रभावित है। सरकार कह रही है कि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे हालात में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अनुराधा भसीन की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में जारी पाबंदियां असंवैधानिक हैं। ऐसे मामलों में संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को अनुच्छेद-370 हटने के बाद से राज्य में इंटरनेट सेवा पर लगी रोक को जायज ठहराते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होने से अलगाववादी, आतंकी और पाकिस्तानी सेना सोशल मीडिया के जरिये लोगों को जिहाद के नाम पर भड़का सकती है। मेहता ने कहा था कि यहां सिर्फ अंदरूनी शत्रुओं से ही नहीं लड़ना है बल्कि सीमा पार के दुश्मनों से भी लड़ना है। उन्होंने इस संबंध में कई उदाहरण भी दिए।

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर हो रहा काम : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में औद्योगिक विकास के लिए कई बिंदुओं पर काम कर रही है। इसके लिए कई प्रोत्साहन देने पर विचार हो रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जम्मू-कश्मीर के आर्थिक हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई 'कश्मीरोनामिक्स कानक्लेव 2019' को संबोधित करते हुए उक्त बात कही। उन्होंने कहा, सरकार जिन योजनाओं पर काम कर रही है उससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और दुबई की कंपनियां जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में पनबिजली, औषधियों, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों और आगामी बजट में इस क्षेत्र को लेकर आप कई घोषणाएं सुनेंगे।

गोयल ने कहा, सरकार जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के स्थानीय उत्पादों को जीआइ टैग देने पर विचार कर रही है। अंतरराज्यीय कंटेनर डिपो के साथ ही अत्याधुनिक संस्थान और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की योजना है। उन्होंने कहा कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला सेक्टर को रेलवे से जोड़ने के लिए 272 किलोमीटर लंबे रेल लिंक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 161 किलोमीटर तक काम पूरा कर लिया गया है। चेनाब रेल पुल के निर्माण का काम भी दोबारा शुरू हो गया है।

ईरानी ने कहा, हथकरघा का केंद्र बन सकता है क्षेत्र : कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में हथकरघा का केंद्र बनने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि चीन हाथ से निर्मित होने वाले कालीन उद्योग से अलग हो रहा है, ऐसे में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस क्षेत्र पर अधिकार जमाने का अवसर है। उन्होंने इस क्षेत्र में शैक्षणिक और आध्यात्मिक केंद्रों को बढ़ावा देने की योजना के बारे में भी जानकारी दी।

पुराने एक्ट के तहत हटाई सुरक्षा

प्रथम पृष्ठ से आगे

शाह ने कहा कि गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा पुराने एक्ट के तहत ही हटाई गई है। प्रस्तावित संशोधनों के बाद बनने वाले एक्ट से उसका कोई लेना-देना नहीं है। बिना सूचना दिए सुरक्षा में बदलाव के आरोप का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि मनमोहन सिंह को खुद खुफिया ब्यूरो के प्रमुख ने जाकर जानकारी दी थी। पर एसपीजी के निदेशक के आग्रह के बावजूद गांधी परिवार की ओर से उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया।

पीएम व परिजनों को सुरक्षा

संशोधन विधेयक को पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन संशोधनों के बाद एसपीजी अपने मूल रूप में आ जाएगी और उसमें अभी तक हुए सारे संशोधन समाप्त हो जाएंगे। इसके तहत एसपीजी की जिम्मेदारी पीएम और उनके सरकारी आवास में साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की ही होगी। इसके साथ ही एसपीजी पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ सरकारी आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों को पांच साल तक सुरक्षा मुहैया कराती रहेगी।

तीखी नोकझोंक के बीच ई-सिगरेट पर रोक संबंधी विधेयक लोकसभा से पास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सत्तापक्ष के कुछ सांसदों ने भी इस विधेयक पर उठाए सवाल
- असंतुष्ट विपक्ष ने प्रस्तावित किए 60 संशोधन, ध्वनिमत से सभी गिरे

सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक लोकसभा में बुधवार को पारित हो गया। विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के भी कुछ सदस्यों ने प्रस्तावित कानून की जरूरत और क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ई-सिगरेट पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की जरूरत बताई, लेकिन असंतुष्ट सदस्यों ने इसमें 60 संशोधनों का प्रस्ताव दिया। हालांकि, प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया।

हर्षवर्धन ने भी विपक्ष के इस आरोप को स्वीकार किया कि भारत में ई-सिगरेट का उपयोग सिगरेट की तुलना में ना के बराबर है। हालांकि, इस पर प्रतिबंध को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआत में ही इसके उपयोग को रोकना जरूरी है। ई-सिगरेट से होने वाले नुकसान को लेकर भी सरकार और विपक्ष बीच में मतभेद थे। हर्षवर्धन ने विदेश में हुए सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि ई-सिगरेट भी सिगरेट की तुलना में 95 फीसद हानिकारक है। एक अन्य सर्वे के हवाले से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ई-सिगरेट को 90 फीसद सुरक्षित पाया गया है।

विधेयक से पहले सितंबर में अध्यादेश के जरिये ई-सिगरेट को प्रतिबंधित किए जाने की जरूरत को साफ करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-सिगरेट निर्माता कंपनी जुलु इस साल के अंत में भारत आने की तैयारी में थी। वहीं विपक्ष की ओर से भारत की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी के दबाव में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया गया। वैसे हर्षवर्धन ने साफ किया कि ई-सिगरेट और सिगरेट की कंपनियों को अलग-अलग करके देखना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि दुनिया में सिगरेट पीने वालों की घटती संख्या को देखते हुए इसे बनाने वाली बड़ी कंपनियां अब ई-सिगरेट के रूप में नया बाजार विकसित करने की कोशिश कर रही हैं।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सिंगापुर जैसे कानून का कड़ाई से पालन करने वाले देश का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने खुद वहां ई-सिगरेट का खुलेआम इस्तेमाल होते देखा था। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश में इसे प्रतिबंधित करना कैसे संभव होगा। बीजद के भर्तृहरि महताब ने प्रस्तावित कानून के तहत एजेंसियों को कहीं भी छापा मारने के अधिकार दिए जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि छापे के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच सिगरेट के इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठाने को लेकर भी तीखी तकरार हुई। हर्षवर्धन का कहना था कि उन्होंने वर्ष 1997 में पहली बार दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए सिगरेट की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया था। इसके बाद सिगरेट के डिब्बे के 80 फीसद भाग पर चित्र के रूप में चेतावनी का श्रेय भी उन्होंने राजग सरकार को दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 60 सालों के अपने शासन में तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस की ओर से इसके लिए पहले बने कानूनों की फेहरिस्त पेश की गई।

केंद्र सरकार ने पेयजल को वैधानिक बनाने की शुरू की कवायद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- उपभोक्ता मंत्रालय ने जलशक्ति मंत्रालय को भेजा मसौदा
- पानी की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली सरकार पर फिर बरसे पासवान

रामविलास पासवान फाइल फोटो

दिल्ली में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दिल्ली सरकार पेयजल में सुधार के लिए तैयार नहीं है। केंद्र अब पेयजल को वैधानिक बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए जलशक्ति मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिस पर वह राज्यों की सहमति के साथ आगे बढ़ सकता है।

पेयजल को वैधानिक बनाने के लिए पानी को एक उत्पाद के रूप में मान्यता जाती है। दूसरे स्तर पर पानी के स्रोत, आपूर्ति लाइन प्रोसेसिंग और भंडारण की पूरी श्रृंखला के कंट्रोल प्वाइंट की गुणवत्ता का मानक होता है। सभी स्तरों पर पानी की जांच होती है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के महानिदेशक पीके तिवारी ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल आर्डर का मसौदा तैयार कर उपभोक्ता मामले विभाग को सौंप दिया है, जिसे अगली कार्यवाही के लिए जलशक्ति मंत्रालय को भेज दिया गया है।

पासवान ने प्रेसवार्ता में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा 'वह दिल्ली के पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर नहीं हैं।' पासवान ने कहा कि उन्हें पूरे देश में पेयजल की गुणवत्ता की चिंता है। इसी क्रम में नौ दिसंबर को बीआइएस के महानिदेशक ने सभी राज्य सरकारों के जलापूर्ति से जुड़े विभागीय अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है। इसमें सभी राज्यों से पेयजल की गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में चर्चा होगी।

दिल्ली में पेयजल की गुणवत्ता के बारे में पासवान ने कहा कि इसके लिए वह बहुत चिंतित हैं। राजधानी में रहने वाले गरीबों के बच्चे जलजनित बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की संयुक्त टीम से जांच कराई जाए और गड़बड़ी मिलने पर उसमें सुधार लाया जाए। पहले चरण में 20 राज्यों की राजधानी के पानी की जांच की गई। दूसरे चरण में जनवरी के पहले सप्ताह में 100 स्मार्ट सिटी में पेयजल की जांच की जाएगी, जबकि तीसरे चरण में 15 अगस्त 2020 तक देश के सभी जिला मुख्यालयों में पीने के पानी की जांच कराई जाएगी। इसका मकसद उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल के प्रति जागरूक बनाना भी है।

लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी से विवाद

- एसपीजी बिल पर चर्चा के दौरान द्रमुक सांसद ने किया गोडसे के बयान का जिक्र
- विपक्ष के विरोध के बाद स्पीकर ने भाजपा सांसद की टिप्पणी को रिकार्ड से हटाया

बुधवार को लोकसभा में बोलतीं भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा सदस्य प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में चर्चा के दौरान टिप्पणी कर विवाद पैदा कर दिया। द्रमुक सदस्य ए राजा ने नाथूराम गोडसे द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान 'महात्मा गांधी की हत्या क्यों की' का उल्लेख किया था। भाजपा सदस्य ने द्रमुक सदस्य के उल्लेख पर हस्तक्षेप किया जिसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (संशोधन) विधेयक पर चल रही बहस में केवल द्रमुक सदस्य के भाषण को ही रिकार्ड किया जाएगा।

द्रमुक सदस्य ए राजा ने कहा, गोडसे ने खुद स्वीकारा था कि गांधी की हत्या करने से पहले 32 साल तक वह उनसे नफरत करता रहा। गोडसे ने गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह एक खास दर्शन में विश्वास करता था। जब विपक्षी सदस्यों ने किए गए हस्तक्षेप का विरोध शुरू किया तो भाजपा सदस्यों ने ठाकुर से बैठ जाने का अनुरोध किया। बाद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के गौरव गोगोई ने ठाकुर की टिप्पणी पर आपत्ति जताई और मांग की कि सदस्य को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ठाकुर गोडसे का समर्थन नहीं करती हैं। ठाकुर ने कहा है कि वह तो उस क्रांतिकारी उधम सिंह के बारे में बोल रही थीं जिन्होंने जनरल डायर को मारा था।

कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ठाकुर की टिप्पणी की आलोचना की है। पार्टी ने कहा है कि यह सत्ताधारी दल की नफरत की राजनीतिक का प्रतिनिधित्व करने वाली टिप्पणी है। भाकपा महासचिव डी. राजा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे भाजपा सांसद ठाकुर की टिप्पणी का समर्थन करते हैं या नहीं।

साध्वी के बयान से पहले भी हो चुका है विवाद: लोकसभा चुनाव के दौरान भी ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा था जिसके बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था। रोड शो के दौरान अभिनेता कमल हासन की एक टिप्पणी कि स्वतंत्र भारत में पहला आतंकी एक हिंदू था पर पूछे गए सवाल का उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली थी। प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि गांधीजी या नाथूराम गोडसे के बारे में की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है और समाज के लिए गलत है। उन्होंने माफी मांग ली है लेकिन मैं कभी उन्हें पूरी तरह माफ नहीं कर सकूंगा।

देश को अब नए साल में मिलेगी नई शिक्षा नीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीति के अंतिम मसौदे पर लगाई मुहर
- नीति का प्रस्तावित मसौदा 31 मई को मंत्रालय को सौंपा गया था

रमेश पोखरियाल निशंक फाइल फोटो

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति फिलहाल अब नए साल में ही आएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीति को इस साल लाने का इरादा टाल दिया है। हालांकि इससे पहले कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी जरूर है, लेकिन इसके लिए भी अभी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। यह स्थिति तब है जब मंत्रालय ने नई सरकार के गठन के बाद अपने सौ दिनों के काम के एजेंडे में इसे शामिल किया था। इस नीति को इसी साल लाया जाना था। शुरुआत के कुछ महीनों में इसे लेकर तेजी भी दिखाई गई, लेकिन बाद में मंत्रालय ने भी इस पर लंबी चुप्पी ओढ़ ली थी।

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को साफ किया है कि प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। बावजूद इसके इसे अब नए साल में ही लाया जाएगा। खास बात यह है कि मंत्रालय ने यह स्थिति उस समय स्पष्ट की है, जब हाल ही में संसद में नई शिक्षा नीति को लेकर किए गए सवालों पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया था कि नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने का काम अभी चल रहा है।

प्रस्तावित नीति के मसौदे को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अगुआई वाली एक टीम ने तैयार किया था। जिसे नई सरकार के गठन के बाद 31 मई को मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक को सौंपा गया था। बाद में इस पर राज्य सरकारों के साथ ही देश भर के लोगों से सुझाव देने का अनुरोध किया गया था। सरकार के आग्रह के बाद सरकार को दो लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। मंत्रालय ने इन्हें परखने के बाद नीति को अंतिम रूप दिया है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और उसके स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में प्रयत्नशील है। उच्च शिक्षा और चिकित्सा

प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक में बदलाव की सिफारिश

शिक्षा नीति में बड़े बदलावों की सिफारिश की गई है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को शामिल किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को बदलने की भी सिफारिश है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में भारत को नालंदा और तक्षशिला जैसी ऊंचाई पर ले जाने का भी रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत उच्च शिक्षा के ग्रॉस एनरोल्डमेंट रेशियो (जीएआर) को 26 से बढ़ाकर 50 फीसद करने का लक्ष्य तय किया गया है।

सार्थक चर्चा

संसद के निचले सदन में सदस्य प्रश्न पूछने के दौरान आवंटित समय का ध्यान नहीं रख पाते, इसके चलते सरकार कई सवालों का मौखिक जवाब नहीं दे पाती

लोकसभा में प्रश्नकाल में सभी 20 मौखिक सवालों के मिले जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- संसद के निचले सदन में अरसे बाद बना इस प्रकार का रिकॉर्ड
- अमूमन चार-पांच सवालों में बीत जाता है एक घंटे का प्रश्नकाल

संसद भवन। फाइल फोटो

लोकसभा में बुधवार को एक रिकॉर्ड बना। प्रश्नकाल के दौरान सूचीबद्ध सभी 20 मौखिक प्रश्नों के जवाब सांसदों को मिले। आम तौर पर प्रश्नकाल के लिए निर्धारित एक घंटे की अवधि चार से पांच मौखिक प्रश्नों और उनके अनुपूरक प्रश्नों में ही खत्म हो जाती है। स्पीकर ओम बिरला ने यह सुनिश्चित किया कि बगैर किसी भूमिका के प्रश्न किए जाएं और मंत्री उसका सीधा व संक्षिप्त जवाब दें।

जानकारों की मानें तो पूर्व में राज्य सभा में ऐसा देखा गया है कि सभी सूचीबद्ध मौखिक सवालों के जवाब तय अवधि में दिए गए हैं। लेकिन लोकसभा में अंतिम बार ऐसा कब हुआ है, इसका तत्काल पता नहीं लग पाया है। राज्य सभा के पूर्व सभापति व उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत के कार्यकाल में कई बार ऐसा किया गया है। इस रिकॉर्ड के बनने के बाद स्पीकर बिरला ने सभी सदस्यों को बधाई दी और कहा कि आगे भी सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इसके लिए सभी सदस्यों का आभार जताया।

बता दें कि कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय, सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्रालय, खनन मंत्रालय से 20 प्रश्नों को मौखिक तौर पर सवाल-जवाब के लिए चयनित किया गया था।

प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही स्पीकर ने जिस तेजी से पहले पांच प्रश्नों के जवाब मंत्रियों से दिलवाए उसके बाद ही सभी प्रश्नों के जवाब हासिल होने की संभावना बनी। ठीक 12 बजे अंतिम 20वां प्रश्न पूछा गया। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने भी मेजें थपाथपा कर इस रिकॉर्ड का स्वागत किया।

रास में सदस्यों के देरी से आने से सभापति नाखुश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा- यह ठीक नहीं, सदन में आने के बाद बातचीत न करने की भी दी सलाह
- सत्ता पक्ष और विपक्ष की ज्यादातर सीटें खाली देख जताई नाराजगी

संसद के दोनों ही सदनों में सदस्यों की अनुपस्थिति का मुद्दा भले ही लगातार उठ रहा है, लेकिन फिलहाल सांसदों के रवैये में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि बुधवार को फिर राज्यसभा में सभापति वैंकेया नायडू ने सदस्यों के आने के समय और उपस्थिति को लेकर चिंता जताई। साथ ही कहा कि यह ठीक नहीं है। उन्होंने सदस्यों से सदन के अंदर बातचीत न करने की भी सलाह दी। कहा कि यदि किसी को बातचीत करनी है, तो वह सदन के बाहर लॉबी में जाकर बातचीत करें।

खासबात यह है कि सभापति की इस नाखुशी से पहले प्रधानमंत्री भी मंत्रियों सहित सदस्यों के सदन में न बैठने को लेकर चिंता जता चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल भी अपने-अपने सांसदों को सदन में पूरे समय उपस्थित रहने और तैयारी के साथ चर्चा में हिस्सा लेने के निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके सांसदों के रवैये में बदलाव नहीं दिख रहा है।

राज्यसभा में सभापति ने बुधवार को सदस्यों के समय से न आने को लेकर यह सवाल तब खड़ा किया, जब 11 बजे से शुरू हुए सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्षों के गिनती के ही सदस्य मौजूद थे। सदन की ज्यादातर सीटें खाली थीं। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों में पिछले दिनों भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था। दोनों सदनों में सिर्फ गिनती के सदस्य मौजूद थे।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

53 साल बाद बाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना का गठन किया। 1989 में पार्टी ने भाजपा से गठबंधन किया। नौवीं विधानसभा (1995 से 99) में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2014 में भी दोनों दलों ने सरकार बनाई, लेकिन ठाकरे परिवार का कोई सदस्य सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर नहीं बैठा। 53 साल बाद अब बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

उद्धव ठाकरे : कैमरे के प्यार से सियासत की तकरार तक

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

यूं तो पूरा ठाकरे परिवार कला की किसी न किसी विधा में पारंगत है, लेकिन सियासत भी इस परिवार की नस-नस में है। सियासत की यही पारिवारिक परंपरा 59 वर्षीय उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने जा रही है।

प्रखर विचारक एवं समाज सुधारक प्रबोधनकार ठाकरे (केशव सीताराम ठाकरे) के पौत्र और शिवसेना के संस्थापक बालासाहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे कभी राजनीति में भी आएंगे, इसकी कल्पना उन दिनों किसी ने नहीं की होगी, जब ठाकरे परिवार के कई और चेहरे राजनीति में चमकने की तैयारी कर रहे थे। 1995 में जब पहली बार शिवसेना-भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी तब उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे को ही शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। वही हावभाव, वही वक्ता शैली और बिल्कुल वही तेवर। बालासाहब ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के पुत्र राज ठाकरे में लोगों को बाल ठाकरे की ही छवि दिखाई देने लगी थी। सौम्य उद्धव उस तेजतर्रार छवि के आगे कहीं टिकते ही नहीं थे। वह तो अपने लंबे लेंस वाले कैमरे से पंढरपुर यात्रा की हवाई तस्वीरें खींचने के लिए जाने जाते थे। लेकिन शिवसेना-भाजपा सरकार के दौरान ही मुंबई में हुए रमेश किणी हत्याकांड में राज का नाम आना शिवसेना में उनके अवसान का कारण बन गया। लेकिन ठाकरे परिवार में उद्धव की राह में रोड़े और भी थे। उनके सगे बड़े भाई जयदेव ठाकरे की महत्वाकांक्षी पत्नी स्मिता ठाकरे भी राजनीति में भाग्य आजमाने को आतुर थीं। जयदेव की परित्यक्ता होने के कारण उनके साथ स्वयं बालासाहब ठाकरे की सहानुभूति भी थी। लेकिन यह सहानुभूति उद्धव और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे की आंखों में हमेशा खटकती रहती थी।

उद्धव की किस्मत देखिए कि 2005 आते-आते राज ठाकरे ने शिवसेना में अपनी उपेक्षा से तंग आकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर लिया और स्मिता ठाकरे भी राजनीतिक परिदृश्य से बाहर हो गईं। अब निरंतर वृद्ध और अशक्त होते जा रहे बालासाहब ठाकरे के साथ मंच पर सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे नजर आने लगे। शिवसेना के लिए मुंबई महानगरपालिका (मनपा) की सत्ता का बड़ा महत्व रहा है। 2007 में उद्धव ठाकरे की पहली राजनीतिक परीक्षा मुंबई मनपा चुनाव में ही हुई। बालासाहब ठाकरे ने उन्हें इन चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी और उद्धव ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सभी आशंकाओं को परे ढकेलते हुए उद्धव ठाकरे 2007 के मनपा चुनाव में 79 सीटें जितवाने में कामयाब हुए। इस परीक्षा में पास होने के बाद उद्धव पर शिवसैनिकों का भरोसा जमने लगा। अब वह 2008-09 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी सक्रिय हो चुके थे। भाजपा के साथ गठबंधन की बातचीत में वह बालासाहब के साथ बराबर के भागीदार होते थे। शिवसेना की सियासत में भी स्वभाव से सौम्य होना उनका गुण माना जाने लगा था। जबकि उनके चचेरे भाई राज ठाकरे का उग्र स्वभाव उनका अवगुण। हालांकि 2008-09 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने काफी अच्छा प्रदर्शन कर शिवसेना को कई तगड़े झटके दिए। उस समय यह माना जाने लगा था कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव को पछाड़ने जा रहे हैं। लेकिन 2013 आते-आते परिदृश्य फिर बदल गया। शिवाजी पार्क की एक दशहरा रैली में बालासाहब साहब ठाकरे अपनी अस्वस्थता के कारण स्वयं नहीं आ सके। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उन्होंने शिवसैनिकों के विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अपने पुत्र उद्धव और पौत्र आदित्य को अपनाने की भावनात्मक अपील की। शिवसैनिकों ने इस अपील को सिरमाथे लिया और आज तक उद्धव का साथ देते आ रहे हैं। कभी मंच पर शर्मीले से दिखने वाले उद्धव अब शिवाजी पार्क की दशहरा रैली में पूरे आत्मविश्वास से भाषण देते नजर आते हैं, तो मीडिया के हर सवाल का जवाब भी उनके पास तैयार रहता है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पत्नी रश्मि के साथ बुधवार को मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। प्रेट्र

सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा से बढ़ी दूरियां

2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का साथ देने के बाद शिवसेना की भाजपा से इसलिए खटक गई क्योंकि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा अपनी बढ़ी हैसियत के अनुसार बराबर सीटों पर लड़ने का आग्रह कर रही थी, जबकि शिवसेना उसे गठबंधन के पुराने फॉर्मूले के अनुसार 117-118 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती थी। आखिरकार गठबंधन टूटा और इसका नुकसान शिवसेना को ही उठाना पड़ा। वह पूरी 288 सीटों पर लड़कर भी 63 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा अपने छोटे सहयोगी दलों के साथ लड़कर 122 सीटें लाने में सफल रही। हालांकि 2014 में बनी देवेंद्र फड़नवीस सरकार में एक माह बाद शिवसेना शामिल तो हो गई, लेकिन चुनाव के दौरान पैदा हुई खटास पूरे पांच साल बरकरार रही। फड़नवीस सरकार में उसे उपमुख्यमंत्री का पद भी नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि उसी खटास का बदला चुकाने के लिए शिवसेना इस बार गठबंधन होते समय तो शांत रही और भाजपा से कम सीटों पर लड़ने को भी तैयार हो गई। लेकिन चुनाव परिणाम आते ही उसने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उसे अहसास हो गया था कि भाजपा उसके बगैर सरकार नहीं बना सकती और कांग्रेस-राकांपा भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। शायद इसीलिए उद्धव ने ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री पद की बात उछालनी शुरू की। मौका आने पर स्वयं मातोश्री से बाहर निकलकर कांग्रेस-राकांपा नेताओं से संपर्क शुरू किया। किसी और शिवसेना नेता को आगे करने के बजाय स्वयं रणनीति का हिस्सा बने। जिसका परिणाम है कि आज उनके रूप में पांच दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति का अहम हिस्सा रहे ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है।

सिर्फ सत्ता के लिए विरोधी विचारों वाले दल साथ आए हैं : शाह

रखी बात ▶ महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान शिवसेना ने किया है भाजपा ने नहीं

कहा, हार्स ट्रेडिंग का आरोप भाजपा पर लगता है और कांग्रेस-राकांपा पूरा अस्तबल ही चुरा ले गए

नई दिल्ली, प्रेट्र : महाराष्ट्र में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर गृह मंत्री व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि धुर विरोधी विचारधारा वाले इन तीन दलों ने सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए हाथ मिलाए हैं और महाराष्ट्र की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान किया है।

यहां बुधवार को टीवी के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने राज्य में स्थिर सरकार के लिए चुनाव पूर्व बने भाजपा-शिवसेना गठबंधन के पक्ष में जनादेश दिया था, लेकिन भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए नैतिकता और सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया। शाह ने कहा कि जनादेश का अपमान शिवसेना ने किया है, भाजपा ने नहीं। शाह ने पूछा, 'मुख्यमंत्री पद देकर समर्थन लेना, क्या हार्स ट्रेडिंग नहीं है। मैं फिर सोनिया गांधी और शरद पवार से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पद पर दावा कर शिवसेना का समर्थन लेकर दिखाएं।' गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा पर हार्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहां तो राकांपा और कांग्रेस गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद देकर पूरा अस्तबल ही चुरा लिया है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह फाइल

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'मैं एक बार फिर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने कभी शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने का आश्वासन नहीं दिया था। यहां तक कि चुनाव के दौरान जिस मंच पर उद्धव और आदित्य ठाकरे भी थे, वहां से भी हमने यही कहा कि देवेंद्र फड़नवीस मुख्यमंत्री होंगे। तब उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया?' उन्होंने कहा कि शिवसेना के सभी विधायक भाजपा के साथ लड़कर चुनाव जीते। शिवसेना के हर प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के बड़े-बड़े पोस्टर और कटआउट लगाए थे।

अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर में पथराव में कमी आई : जम्मू-कश्मीर पर अमित शाह ने कहा कि राज्य से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद सुरक्षा बलों पर पथराव की घटना में 40-45 फीसद की कमी आई है। उन्होंने कहा कि 370 के प्रावधानों को खत्म करने में 70 साल लग गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे करने का संकल्प लिया था। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए बिना जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को हराना मुश्किल था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र के युवाओं के हाथों में हथियार थमाता है। वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान से तय होती है, अगर वह शांति चाहता है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा।

कश्मीर से अतिरिक्त बल वापस गए : शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों की संख्या आज भी उतनी ही है जितनी यह 1990 से रही है। वहां तैनात अतिरिक्त बलों को हटा लिया गया है।

देश में अवैध प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं : अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) का समर्थन किया। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई और देश अपने यहां अवैध प्रवासियों को बसने नहीं देगा। भारत में भी किसी अवैध प्रवासी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएबी की तरह ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भी बहुत महत्वपूर्ण है।

वोट बैंक के चलते लटका रहा राम मंदिर मुद्दा : भाजपा अध्यक्ष शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की वोट बैंक की राजनीति के चलते अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मामला इतने वर्षों तक लटका रहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था नहीं तथ्यों के आधार पर इस मामले में निष्पक्ष फैसला दिया है। फैसले का मुस्लिमों समेत सभी वर्गों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी और उस पर अमल करने के लिए निर्धारित 90 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं मांगेगी।

भाजपा के सामने फेंका जाल तो नहीं थे अजीत!

▶ जूनियर पवार के साथ आने से हटा था राष्ट्रपति शासन

▶ अजीत को सरकार में लाने में फड़नवीस की भूमिका की चर्चा

मिड डे, मुंबई : राकांपा नेता अजीत पवार ने अचानक भाजपा के साथ सरकार गठन के बाद उसे विगत मंगलवार को एकाएक बीच मझधार में छोड़ दिया। अगले ही दिन बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़ी आसानी से पुरानी स्थिति बहाल करने लगे। यह देखकर राजनीतिक हलकों में यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अजीत पवार असल में शरद पवार खेमे के बुने जाल का हिस्सा थे। इससे अजेय माने जा रहे भगवा दल को मुंह की खानी पड़ी। ध्यान रहे कि जूनियर पवार के भाजपा सरकार में सेंध लगाने से एकाएक महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हट गया, जो छह महीने तक जारी रह सकता था। शरद पवार भाजपा को सबक सिखाने के लिए किसी भी कीमत पर अपने गठबंधन (शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस) की सरकार बनाना चाहते थे।

भाजपा के खेमे में इस बात को लेकर चर्चा है कि राजनीतिक उठापटक के कई दौर के बाद पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री फड़नवीस की छवि को तो ठेस पहुंची ही, चूंकि बताया जा रहा है कि अजीत पवार को अपनी तरफ लाने में उनकी खास भूमिका थी और उन्होंने ही भाजपा के हाईकमान से इसकी मंजूरी ली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अजीत पवार ने फड़नवीस का साथ छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्रास वोटिंग के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। लिहाजा, भाजपा के लोगों को लगने लगा है कि क्या पार्टी पवार के जाल में फंस गई और बेवजह बदनामी मोल ले ली। पार्टी में इस बात की भी चर्चा है कि भाजपा हाईकमान ने गठबंधन करने में अजीत के अजीबोगरीब रवैए पर आंख मूंदकर भरोसा कैसे कर लिया। पहले तो अजीत पवार ने गुपचुप तरीके से भाजपा से नाता जोड़ा, अपनी पार्टी से बगावत करने के बावजूद वह अपने चाचा शरद पवार के सामने 'टूट' गए। और बड़ी आसानी से चौड़ी खाई पाटते हुए परिवार और पार्टी में वैसे ही वापसी कर ली, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि उनका साथ देने वाले भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने राज्य में पांच साल सरकार चलाने के बाद एक ही महीने में दो बार इस्तीफा देने का रिकार्ड बनाया। हालांकि भाजपा के पीड़ित और चिंतित नेता इस सवाल का जवाब देने से बचे कि क्या होता अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके अनुरूप होता और भाजपा-अजीत क्रॉस-वोटिंग से अपनी सरकार का बहुमत साबित कर पाते। वहीं, राकांपा में अजीत पवार की वापसी का स्वागत करते हुए पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार ने साबित कर दिया है कि असली चाणक्य कौन है। अजीत अभी भी पार्टी का हिस्सा हैं और उन्हें पार्टी और सरकार में एक बड़ी भूमिका मिलना तय है।

बुधवार को मुंबई में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण में पहुंचे राकांपा नेता और अपने बड़े भाई अजीत पवार का सुप्रिया सुले ने कुछ इस अंदाज में स्वागत किया। प्रेट्र

50-50 फॉर्मूले ने 20 साल बाद भाजपा को फिर किया सत्ता से दूर

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल बाद इतिहास खुद को दोहराता दिखाई दिया जब 50-50 फॉर्मूले के चक्कर में एक बार फिर सत्ता भाजपा के हाथ से फिसल गई। 1999 में यह कहानी तब सामने आई थी, जब भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़कर हाथ आई सत्ता गंवा बैठे थे।

1995 में शिवसेना-भाजपा गठबंधन पहली बार सत्ता में आया था। तब शिवसेना ने 169 सीटों पर लड़कर 73 सीटें और भाजपा ने 116 सीटों पर लड़कर 65 सीटें हासिल की थीं। चूंकि दोनों दलों के बीच ज्यादा सीटें पाने वाले दल का मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला तय था इसलिए शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे और भाजपा के गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री, लेकिन साथ में सरकार चलाकर गोपीनाथ मुंडे को अहसास हो गया था कि कम सीटों पर लड़कर भाजपा कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकेगी। लिहाजा 1999 के चुनाव में उन्होंने बराबर सीटों पर लड़ने का दबाव बनाया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। शिवसेना फिर भाजपा से करीब 53 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी और 69 सीटें जीती। भाजपा को 56 सीटें हासिल हुईं। दोनों दलों को मिलाकर 125 सीटें हो रही थीं। निर्दलीय विधायकों की संख्या 30 थी। चुनाव शिवसेना के मुख्यमंत्री नारायण राणे के नेतृत्व में हुए थे। राणे सरकार बनाने लायक विधायकों को अपने साथ जोड़कर सरकार बनाने को तैयार बैठे थे, लेकिन गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री पद के ढाई-ढाई साल के बंटवारे पर अड़े हुए थे। जो शिवसेना उन्हें ठीक उसी तरह देने को तैयार नहीं थी, जैसे इस बार भाजपा इस फॉर्मूले पर राजी नहीं हुई।

1999 में भाजपा के गोपीनाथ मुंडे ने भी की थी इसी तरह 50-50 की मांग

दूसरी ओर, चंद माह पहले ही सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठन कर चुके थे। कांग्रेस और राकांपा एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़कर आए थे। इसके बावजूद कांग्रेस को 75 और राकांपा को 58 सीटें हासिल हुई थीं। दिल्ली में उपजी कड़वाहट के कारण महाराष्ट्र में उनका साथ आना आसान नहीं था। लेकिन शिवसेना-भाजपा के आपसी संघर्ष ने इन दोनों दलों के बीच संवाद कायम करने में बड़ी भूमिका अदा की।

शरद पवार की परिपक्वता उस समय भी काम आई। गठबंधन के जिस फॉर्मूले पर 1995 में शिवसेना-भाजपा की सरकार बनी थी, चंद दिनों बाद ही उसी फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में कांग्रेस-राकांपा की सरकार शपथ लेती दिखाई दी। कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने और राकांपा के छगन भुजबल उपमुख्यमंत्री। जबकि एक-दूसरे के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वालीं भाजपा-शिवसेना 50-50 के झगड़े में हाथ आई सत्ता गंवा बैठीं। दोनों के हाथ से उस समय जो सत्ता फिसली तो अगले 15 साल तक इन्हें महाराष्ट्र में सत्ता से दूर ही रहना पड़ा। इस बार फर्क सिर्फ इतना रहा कि इस बार ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर शिवसेना न सिर्फ अड़ी रही, बल्कि वह अपनी गठबंधन सहयोगी भाजपा को छोड़कर उन लोगों के साथ सरकार बनाने जा रही है, जिनके विरुद्ध वह अब तक लड़ती आई है।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण...

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर आदित्य ने पिता और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शिवसेना नेता मिलिंद नरवेकर भी साथ थे। प्रेट्र

भाजपा को अजीत पवार का समर्थन नहीं लेना चाहिए था : एकनाथ खडसे

मुंबई, एजेंसियां : वरिष्ठ भाजपा नेता एकनाथ खडसे ने बुधवार को कहा कि भाजपा को राकांपा नेता अजीत पवार का समर्थन नहीं लेना चाहिए था। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाजपा को अजीत दादा पवार का समर्थन नहीं लेना चाहिए था। वह बहुत बड़े सिंचाई घोटाले में आरोपित हैं। वह कई आरोपों का सामना कर रहे हैं लिहाजा हमें उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए था।' अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के सुबूत होने के भाजपा के पूर्व में किए गए दावे पर खडसे ने कहा, 'ऐसा लगता है कि हमने उन्हें कबाड़ में डाल दिया है।' मालूम हो कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री रहे एकनाथ खडसे को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 2016 में इस्तीफा देना पड़ा था।

उन्होंने आगे कहा कि चंद्रशेखर बवांकुले, विनोद तावड़े और उनके जैसे कुछ अन्य नेताओं को हालिया विधानसभा चुनाव प्रचार से जानबूझकर दूर रखा गया। यह फैसला पार्टी को महंगा पड़ा। अगर हमारा इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया गया होता तो भाजपा 20-25 सीटें और जीत सकती थी। खडसे ने कहा कि यह मामला उन्होंने पहले भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उठाया था।

साथ

पति उद्धव ठाकरे के सीएम बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका, भाजपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी अडिग थीं

शिवसेना की बदली रणनीति में रश्मि ठाकरे भी अहम

संजीव शिवाडेकर (मिड डे), मुंबई

रश्मि ठाकरे अब पार्टी के प्रमुख वास्तुकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपने पति उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवसेना के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर रश्मि ठाकरे अडिग थीं।

विधानसभा चुनाव से पहले एक घटना को याद करते हुए शिवसेना के एक नेता ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना-भाजपा नेताओं की बैठक के बाद रश्मि ठाकरे ने भी शिवसेना प्रमुख के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा की थी। मातोश्री के एक विश्वासपात्र ने मिड डे को बताया कि रश्मि की राय थी कि शिवसेना को बराबर सीट और पावर शेयरिंग से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए।

यह पहली बार नहीं है जब डोंबिवली की लड़की रश्मि राजनीतिक घटनाक्रम में दिलचस्पी ले रही थीं। पहले भी जैसे नारायण राणे के पार्टी छोड़ने या उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे को पार्टी से अलग करने में रश्मि ठाकरे ही थीं जिन्होंने पार्टी की बातचीत में हिस्सा लिया था।

इस दौरान रश्मि ठाकरे ने महिला विंग की ओर से आयोजित कई कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया और मुंबई नगर निगम और अन्य चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया। जब शिवसेना में अशांति थी, उस समय पार्टी को फिर से बनाने में उद्धव ठाकरे की मदद की। उस समय परिवार और नेतृत्व विवाद के कारण शिवसेना से अधिकतर लोग जा रहे थे।

रश्मि ठाकरे प्रेट्र

पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में कई लोग रश्मि को सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की बहू या नवनिर्वाचित विधायक आदित्य की मां के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके पास अच्छा राजनीतिक कौशल है। उन्होंने अपने इस कौशल का इस्तेमाल वर्ष 2005 के बाद के दौर में ज्यादा किया जब वह शिवसेना के फैसले लेने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने लगीं। पार्टी कार्यकर्ता का मानना है कि निश्चित रूप से शिवसेना में रश्मि ठाकरे की अहम हिस्सेदारी है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार और चुनाव परिणामों के दौरान रश्मि ठाकरे की अपने बेटे आदित्य को महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में देखने की आकांक्षा थी। आदित्य के चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में 29 वर्षीय आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट करने वाले वर्ली विधानसभा क्षेत्र एवं शहर के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए गए थे। शिवसेना कैंप के संभावित सीएम उम्मीदवार आदित्य से उद्धव ठाकरे में बदल गए। बता दें कि जब उद्धव ठाकरे के नाम को महा विकास अघाड़ी ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी थी तब रश्मि बुधवार को सुबह अपने पति के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलीं थी।

गठबंधन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : महाराष्ट्र में चुनाव बाद हुए शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव बाद हुआ यह गठबंधन मतदाताओं के साथ धोखा है और संविधान का उल्लंघन है। इसमें इस गठबंधन के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है।

यह याचिका महाराष्ट्र में ठाणे के रहने वाले प्रमोद पंडित जोशी ने दाखिल की है। अधिवक्ता बरुन कुमार सिन्हा के जरिये दाखिल याचिका में जोशी ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा ने राजग के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा था और देवेंद्र फड़नवीस उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। चुनाव बाद शिवसेना का राजग से अलग होना मतदाताओं के साथ धोखा है जिन्होंने उस पर भरोसा करके मत दिए थे और राजग को सरकार बनाने के लिए बहुमत से ज्यादा सीटें दी थीं। अवसरवादिता के तहत तीनों दलों के बीच हुआ गठबंधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ, अलोकतांत्रिक और अनैतिक है।

शिवसेना सरकार में मझधार में फंस सकती है बुलेट ट्रेन

मिड डे, मुंबई : महाराष्ट्र में शिवसेना अपने नए साथियों राकांपा और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बन रही सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन और मुंबई मेट्रो के फेज तीन पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। शिवसेना इन दोनों ही प्रोजेक्ट की विरोधी रही है, हालांकि, पार्टी के एक विधायक का कहना है कि उनका विरोध मेट्रो से नहीं, आरे पार्क में हरे पेड़ों को काटे जाने को लेकर था। शिवसेना सरकार से रियल एस्टेट क्षेत्र को बहुत उम्मीद है। उसके लगता है कि इस सरकार में इस क्षेत्र को लाभ होगा।

सरकार बनाने के लिए बने महाविकास अघाड़ी ने किसानों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। शिवसेना के प्रवक्ता मनीषा कायांदे ने कहा कि पार्टी ने पहले भी कहा था कि अगर बुलेट ट्रेन से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं तो उस पर आगे बढ़ने की जरूरत क्या है। सेना ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को फिजूलखर्ची बताया है।

पूर्व की भाजपा-शिवसेना सरकार में मंत्री रहे दीपक केसरकर ने भी बुलेट ट्रेन की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता किसानों का कल्याण करना है। उन्होंने कहा कि अगर बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए आपको 3,500 रुपये (संभावित) का टिकट लेना पड़ेगा, तो फिर कोई विमान से क्यों नहीं जाएगा। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी मेट्रो का विरोध नहीं किया। उन लोगों ने हरे पेड़ों को बचाने के लिए आरे पार्क में मेट्रो के कार शेड के निर्माण का विरोध किया था। लेकिन अब ज्यादातर पेड़ काट दिए गए हैं और वहां कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता ने कहा कि शिवसेना-राकांपा और कांग्रेस तीनों ही दल आरे पार्क में लोगों के विरोध के समर्थन में थे। अब जब इनकी सरकार बन रही है तो उम्मीद है कि वो आरे पार्क को वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेगी और इसे संजय गांधी नेशनल पार्क के इको-सेंसिटिव क्षेत्र के रूप में घोषित करेगी।

4000 करोड़ रुपये की मांग की गृह मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेट करने के लिए। इसके अलावा अगले साल से शुरू होने वाले जनगणना अभियान के लिए 9000 करोड़ की भी मांग की गई है।

भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, हर बीपीएल परिवार को रोजगार का वादा

झारखंड विधानसभा चुनाव ▶ युवाओं, महिलाओं से लेकर हर वर्ग को लुभाने की कोशिश

पिछड़ों-का बढ़ेगा आरक्षण, लड़कियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा, महिलाओं का भी बढ़ाएंगे आरक्षण प्रतिशत

राज्य ब्यूरो, रांची

रांची में बुधवार को भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। जागरण

भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों के अधिकृत दस्तावेज (घोषणा पत्र) में हर वर्ग, हर तबके को लुभाने की कोशिश की है। इसमें हर बीपीएल परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार-स्वरोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। झारखंड की समृद्धि का संकल्प नाम ने जारी पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों, जनजातीय समाज, युवाओं, महिलाओं व गरीबों को तरजीह दी गई है। वहीं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, औद्योगिक व आधारभूत संरचना के तीव्र विकास का वादा भी किया गया है। संकल्प पत्र में पिछड़ों और महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के साथ-साथ बालिकाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात भाजपा ने की है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर, मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा समेत भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।

शाह के वादे को प्रमुखता : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों लोहरदगा की जनसभा में पिछड़े समाज का आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी। शाह के वादे को पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता दी है। वादा किया है कि गहन सर्वेक्षण करा कर छह माह के भीतर संविधान के दायरे में उन्हें सरकारी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा।

आधी आबादी को साधने की कोशिश : मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे और स्पष्ट करते हुए सरकार गठन के तीन माह के भीतर इसे लागू करने की बात कही। भाजपा ने पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ महिलाओं को भी सरकारी सेवाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात कर आधी आबादी को साधने की कोशिश की है। जनजातीय विकास का संकल्प भी दोहराते हुए 2022 तक 70 नए एकलव्य विद्यालयों का के निर्माण के साथ-साथ सभी जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के निर्माण का वादा किया है।

किसानों की भी बात : किसानों को तीन लाख तक सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने और फसल की पूर्ण सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री पूर्ण कृषि बीमा योजना की शुरुआत करने की बात भी भाजपा ने कही है। झारखंड को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने के वादे के साथ-साथ घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए असम की तर्ज पर राज्य में एनआरसी लागू करने की बात भी भाजपा ने कही है। शक्तिस्वरूपा महिला बटालियन और सभी जिलों में एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट की स्थापना भी की जाएगी।

लोंगोवाल तीसरी बार बने एसजीपीसी अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, अमृतसर

एसजीपीसी के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए गोबिंद सिंह लोंगोवाल विजय चिह्न बनाते हुए। बुधवार को एसजीपीसी की जनरल इजलास में उनको अध्यक्ष चुने जाने का एलान किया गया। राघव शिकारपुरिया

जत्थेदार गोबिंद सिंह लोंगोवाल बुधवार को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष चुन लिए गए। लोंगोवाल को छोड़ कर इस बार कार्यकारिणी में कोई भी पुराना पदाधिकारी नहीं चुना गया। दो महिला सदस्यों को भी लिया गया है। पूर्व एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने अध्यक्ष के लिए लोंगोवाल का नाम प्रस्तावित किया, जिसका अलविंदर पाल सिंह पखोके और अमरजीत सिंह ने समर्थन किया।

चार बार विधायक और मंत्री रह चुके लोगोंवाल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के करीबी व विश्वासपात्र माने जाते हैं। वह वर्ष 2017 व 2018 में भी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे। बुधवार को एसजीपीसी के मुख्यालय तेजा सिंह समुंदरी हॉल में हुए आम इजलास में एसजीपीसी के सदस्य बलविंदर सिंह बैंस और सुखेदव सिंह भौर ने दो-तीन समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए चुनाव का बहिष्कार किया। अध्यक्ष चुनने के सारे अधिकार एसजीपीसी सदस्यों ने मंगलवार को ही शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को सौंप दिए थे।

माना जा रहा था कि सुखबीर उन सभी वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दूर करके उन्हें वापस ले आएंगे, जो पार्टी से दूर चले गए हैं। पंथक वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए ऐसा जरूरी माना जा रहा था, लेकिन लोंगोवाल को प्रधान बनाकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए।

हरियाणा से लेकर माझा को दिया उपाध्यक्ष पद : सुखबीर ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद हरियाणा से लेकर पंजाब के माझा क्षेत्र को दे दिया। हरियाणा के कोटे से लिए जाते रहे रघुजीत सिंह विर्क कई वर्षों से एसजीपीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, लेकिन उनकी जगह माझा के रजिंदर सिंह मेहता को यह पद देकर सुखबीर ने वही तेवर दिखाए हैं, जो उन्होंने मालवा में दिखाए।

हरियाणा से केवल दो सदस्य : लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि कार्यकारिणी में हरियाणा से केवल दो सदस्यों को ही लिया गया और कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति को देखते हुए सुखबीर ने यह कदम उठाया है।

भौर का कद भी घटाया : दोआबा क्षेत्र में भी सुखबीर ने अपने तेवर दिखाए। पार्टी से दूर गए वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह भौर की जगह उनका कद कम करने के लिए हरजिंदर सिंह धामी को उनके गृह जिले में खड़ा कर दिया गया है। भौर लंबे समय से पार्टी से बाहर चल रहे हैं। पेशे से वकील हरजिंदर सिंह धामी को महासचिव बनाने में संत समाज का भी सहयोग दिख रहा है। धामी हरियां बेलां वाले संतों के करीबी माने जाते हैं।

21 प्रस्ताव भी पास : आम इजलास में 21 प्रस्ताव भी पास किए गए। इससे पहले एसजीपीसी के मुख्य सचिव डॉ. रूप सिंह ने एजेंडा पेश किया। इसके बाद शोक प्रस्ताव पढ़े गए।

कार्यकारिणी कमेटी : भूपिंदर सिंह (हरियाणा), जगसीर सिंह डबवाली, गुरपाल सिंह गोरा बटाला, शेर सिहं मंडवाला, परमजीत कौर नेहरा, जसमेर सिंह, अमरजीत सिंह भलाईपुर, सुरजीत सिह कंग (राजस्थान), इंद्रमोहन सिंह लखमीर वाला, मगविंदर सिंह खापड़खेड़ी, कुलदीप कौर टोहरा।

154 सदस्यों ने लिया हिस्सा : चुनाव प्रक्रिया में शिअद समर्थक एसजीपीसी के 154 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कुल 185 सदस्यों में से करीब 12 सदस्यों की मौत हो चुकी है, जबकि दो ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया।

चुने गए अन्य पदाधिकारी

रजिंदर सिंह मेहता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष

गुरबख्श सिंह, जूनियर उपाध्यक्ष

हरजिंदर सिंह धामी, महासचिव

पीएमसी बैंक घोटाले में वधावन के दो विमान व यॉट होंगे नीलाम

▶ कोर्ट ने 4,355 करोड़ के घोटाले में आरोपित पिता-पुत्र की संपत्तियों की नीलामी के दिए निर्देश

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र की एक अदालत ने 4,355 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपित व एचडीआइएल समूह के प्रवर्तकों राकेश वधावन तथा उसके बेटे सारंग को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आरबीआइ की तरफ से नियुक्त पीएमसी बैंक के प्रशासक को वधावन पिता-पुत्र के दो निजी विमान व यॉट (लक्जरी नौका) को नीलाम करने की अनुमति दे दी है।

मुंबई के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरके राजेभोसले ने सोमवार को दो विमानों फैल्कॉन 2000 (वीटी-एचडीएल) और चैलेंजर 300 (वीटी-पीआइएल) तथा एक यॉट (फेरेटी 881 एचटी) की नीलामी की अनुमति दे दी। प्रशासक ने कोर्ट से पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में जांच एजेंसी की तरफ से जब्त की गई संपत्तियों को बेचने के संबंध में अनुमति मांगी थी।

प्रशासक का पक्ष रखते हुए वकील रमेश दूबे पाटिल ने कोर्ट को बताया कि प्रतिबंध के कारण बैंक के ग्राहक शीर्ष बैंक की तरफ से तय राशि से ज्यादा की निकासी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अगर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि आरोपितों के लोन खाते में आ जाती है तो इसके ग्राहकों को मदद मिल सकती है।' प्रशासक के वकील ने यह भी बताया कि आरोपित की गिरवी और रेहन रखी गईं संपत्तियां उसके कर्ज और ब्याज की अदायगी के लिए अपर्याप्त हैं।

कोर्ट ने कहा, 'नीलामी से प्राप्त राशि एचडीआइएल और इसके समूह की कंपनियों के कर्ज खाते में जाएगी।' राजेभोसले ने प्रशासक को संपत्तियों को बेचने के तत्काल बाद कोर्ट के समक्ष नीलामी और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को संपत्तियों का पूरा पंचनामा बनाकर नीलामी के दौरान और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को भी कहा। इन संपत्तियों में 15 लक्जरी कारें, सात सीटों वाली स्पीडबोट, दो विमान व एक यॉट शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि पीएमसी बैंक घोटाले में अब तक नौ लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें बैंक के तीन शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। ईओडब्ल्यू का आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने एचडीआइएल समूह से मिलकर उसके बड़े बैंक कर्ज को छिपाए रखने की कोशिश की।

पूर्व नौ सेना प्रमुख सुशील कुमार का निधन, प्रधानमंत्री ने जताया शोक

जागरण संवाददाता, नोएडा : पूर्व नौ सेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का बुधवार को दिल्ली के आरआर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 79 साल के सुशील कुमार को ढाई माह से गले और फेफड़ों में इंफेक्शन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में 1940 में जन्मे सुशील कुमार नोएडा स्थित सेक्टर-21 जलवायु विहार में पत्नी विनीता कुमार के साथ रहते थे। उनका नोएडा के कैलाश अस्पताल में इलाज चलता रहा और फिर वह दिल्ली कैंट स्थित आरआर अस्पताल में चले गए थे। इलाज के दौरान ही बुधवार सुबह चार बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सुशील कुमार की इकलौती बेटी अनीशा इंग्लैंड में रहती हैं। पिता की मृत्यु की खबर मिलने पर वह भी वहां से चल चुकी हैं। घर के सदस्यों के मुताबिक पूर्व नौ सेना प्रमुख का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके निवास पर लाया जाएगा।

सुशील कुमार। फाइल

सुशील कुमार नौ सेना में एडमिरल रहते हुए ही परिवार के साथ नोएडा आ गए थे। वह 1998 से 2001 तक नौ सेना प्रमुख रहे और इसी पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

चिदंबरम ने कहा-मेरे खिलाफ एक भी सुबूत नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में बुधवार को आइएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को अदालत में पेश किया गया। प्रेट्र

पिछले 99 दिनों से जेल में बंद पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आइएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। कोर्ट से कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके खिलाफ एक भी सुबूत नहीं है। वह कोई रंगा बिल्ला जैसे क्रिमिनल नहीं हैं जिसे जमानत देने से देश में गलत संदेश जाएगा। बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री की जमानत याचिका पर बहस पूरी कर ली गई। गुरुवार को ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे।

पी. चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने चिदंबरम पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बुधवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस बीएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ से चिदंबरम को जमानत देने की गुहार लगाते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह माना है कि चिदंबरम के न तो भागने की आशंका है न ही गवाहों को प्रभावित करने अथवा दस्तावेज से छेड़छाड़ करने की। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अगर उन्हें जमानत दे दी जाएगी तो देश में गलत संदेश जाएगा।

सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट यह कैसे कह सकता है कि जमानत देने से देश में एक गलत संदेश जाएगा। क्या चिदंबरम कोई रंगा बिल्ला जैसे क्रिमिनल हैं? सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम को इस मामले में सरगना बना दिया गया जबकि उनके खिलाफ कोई भी दस्तावेजी सुबूत नहीं है।

चिदंबरम की ही ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह कहते हुए चिदंबरम की जमानत खारिज कर दी है कि उन पर गंभीर आरोप हैं। लेकिन कोई मामला गंभीर है कि नहीं, यह उस अपराध में तय सजा से निर्धारित होता है। सात साल से ज्यादा की सजा वाले अपराधों को गंभीर अपराध कहा जाता है। इस मामले में चिदंबरम को जमानत मिलनी चाहिए।

चिदंबरम ने महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर कसा तंज

जासं, नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया डील मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। अदालत से बाहर आने के बाद चिदंबरम ने महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर तंज कसा। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की, जिसका चिदंबरम के वकीलों ने विरोध नहीं किया। कोर्ट से बाहर आने के बाद चिदंबरम ने कहा, 'संविधान दिवस मनाने का यह क्या तरीका था? यह कैसा सम्मान उन्होंने संविधान को दिया है? आधी रात में जो कुछ (आशय महाराष्ट्र के घटनाक्रम से था) भी हुआ, उसके लिए राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब जिम्मेदार हैं। दुख हुआ कि राष्ट्रपति इसमें शामिल रहे।' इसके बाद सुरक्षाकर्मी उन्हें वापस तिहाड़ जेल ले गए।

नई दिल्ली में बुधवार को तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। प्रेट्र

राहुल और प्रियंका ने की तिहाड़ में मुलाकात

इससे पूर्व बुधवार सुबह करीब नौ बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने तिहाड़ जेल संख्या सात में चिदंबरम से मुलाकात की। सुरक्षाकर्मियों के काफिले से घिरे दोनों काले रंग की एक ही कार में सवार थे। जेल परिसर में दाखिल होने के बाद ये सीधे जेल संख्या सात पहुंचे। वहां जेल अधीक्षक कार्यालय परिसर स्थित एक कक्ष में चिदंबरम से उनकी मुलाकात हुई। करीब 25 मिनट की मुलाकात के बाद दोनों जेल परिसर से रवाना हो गए।

भिवानी के प्रवेश ने किया सीडीएस परीक्षा में टॉप

जागरण संवाददाता, भिवानी

▶ दादा आजाद हिंद फौज में रहे, पिता लड़ चुके हैं कारगिल की लड़ाई

प्रवेश कुमार समोता। सौ : परिजन

हरियाणा के भिवानी जिले के गांव दिनोद निवासी प्रवेश कुमार सामौता ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीडीएस-1 2019 (कंबाइन डिफेंस सर्विस) की परीक्षा में देशभर में टॉप किया है। बीते 25 नवंबर को परिणाम आने के बाद मिल रही बधाइयों से खुश प्रवेश के पिता अमीर सिंह सामौता ने कहा कि बेटे की उपलब्धि पर पूरे गांव ही नहीं, बल्कि प्रदेश को भी गौरव महसूस कर रहा है। सेना में हवलदार पद से सेवानिवृत हुए अमीर सिंह का सपना था कि उनका बेटा आइएएस अधिकारी बने, लेकिन प्रवेश सेना में उच्च पद पर जाना चाहते थे। बारहवीं तक विज्ञान संकाय लिया। स्नातक में दाखिले के समय ही तय कर लिया था कि सीडीएस की परीक्षा निकालनी है। गत फरवरी में प्रवेश ने सीडीएस की परीक्षा दी थी। प्रवेश का बड़ा भाई भी आर्मी में है।

प्रवेश के दादा धनसिंह सामौता आजाद हिंद फौज में थे और चार साल तक बर्मा में जेल में बंद रहे हैं। देश सेवा का जज्बा तभी से चला आ रहा है। अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी सेना में रहकर देश की सेवा कर रही है। अमीर सिंह ने भी कारगिल लड़ाई लड़ी है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात रहते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे करने का कार्य किया हुआ है।

हितेश नौसेना अकादमी में देश में रहे अव्वल

हरियाणा के ही रेवाड़ी के हितेश यादव ने भारतीय नौसेना अकादमी में देशभर में प्रथम व भारतीय सैन्य अकादमी में पांचवां स्थान हासिल किया है। रेवाड़ी के जसवंत नगर निवासी हितेश ने एमएनआइटी जयपुर से बीटेक कंप्यूटर साइंस में की। वह पावर लिफ्टिंग में भी दो बार चैंपियन रह चुके हैं। इसी साल मई में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने एमेजन ज्वाइन किया और हैदराबाद में पदस्थ हैं। पिता श्याम सुख यादव दिल्ली पुलिस में एएसआइ हैं। छोटे भाई जतिन यादव आइआइटी गुवाहाटी में बीटेक द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं।

हितेश यादव। सौ : परिजन

धनखड़ का ममता पर फिर हमला, ट्वीट कर कहा-सीएम के व्यवहार से स्तब्ध हूं

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संविधान दिवस पर विधानसभा में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया-'मुख्यमंत्री के व्यवहार से स्तब्ध हूं। उन्होंने किसी तरह का शिष्टाचार नहीं दिखाया, जबकि विस में उपस्थित विधायकों ने मेरा अभिवादन किया। अमित मित्रा, पार्थ चटर्जी, अब्दुल मन्नान समेत सभी ने मेरे प्रति सम्मान जताया, लेकिन मुख्यमंत्री का व्यवहार सही नहीं था।' गौरतलब है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों में काफी समय से तल्खी देखी जा रही है। यही वजह है कि विस में मंगलवार को भी दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के उस आरोप का भी खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने तनिक भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। धनखड़ ने कहा-'मैंने शिष्टाचार दिखाने में किसी तरह की कंजूसी नहीं की। मुख्यमंत्री के प्रति मेरी गहरी श्रद्धा है, लेकिन उन्होंने आशानुरूप व्यवहार नहीं किया।' ट्वीट के जरिये राज्यपाल ने सरकारी कर्मियों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मी कानून व संविधान के दायरे में आते हैं। उन्हें कानून व संविधान से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि मंगलवार को विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल-मुख्यमंत्री की मुलाकात तो हुई थी, लेकिन दोनों में जरा भी बातचीत नहीं हुई थी।

दूसरी तरफ राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने पलटवार करते हुए बुधवार को विधानसभा के सत्र में कहा कि राज्यपाल एक लोकप्रिय सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं।

शिवाजी पार्क में उद्धव के शपथ ग्रहण की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट चिंतित

▶ कहा, सार्वजनिक मैदानों में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की नहीं बननी चाहिए परिपाटी

▶ 'वीकॉम ट्रस्ट' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी खंडपीठ

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके चलते बुधवार को तैयारियां की गईं। प्रेट्र

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के गुरुवार शाम शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा को लेकर बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को चिंता व्यक्त की। हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक मैदानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की परिपाटी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो हर कोई ऐसे आयोजनों के लिए सार्वजनिक मैदानों के इस्तेमाल की मांग करने लगेगा।

जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस आरआइ चगला की खंडपीठ गैरसरकारी संगठन 'वीकॉम ट्रस्ट' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें पूछा गया है कि शिवाजी पार्क खेल का मैदान है अथवा मनोरंजन का मैदान। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा, 'हम गुरुवार के समारोह के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते... हम सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना न हो।' समारोह की सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने कहा कि गुरुवार शाम 6.40 बजे होने वाले इस समारोह में लाखों लोग एकत्रित होंगे। आपको (अधिकारियों को) सुरक्षा पहलू पर भी विचार करना चाहिए। आप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। अदालत ने टिप्पणी की, 'शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए कुर्सियां और पंडाल लगाने के लिए बांस ट्रकों में भरकर लाए जाएंगे। इसका मतलब है कि मैदान बुधवार और गुरुवार को लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होगा।'

बता दें कि एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 2010 में इस इलाके को 'साइलेंस जोन' घोषित कर दिया था। अदालत का कहना था कि शिवाजी पार्क में सिर्फ छह दिसंबर (बीआर आंबेडकर की पुण्यतिथि), एक मई (महाराष्ट्र स्थापना दिवस) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार और बृहनमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने साल में 45 दिन शिवाजी पार्क में खेलों से इतर गतिविधियों की अनुमति देने का प्रावधान कर दिया था। इस पर बुधवार को हाई कोर्ट ने दोनों से जवाब तलब किया और सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

इलैयाराजा बोले

विख्यात गायक, गीतकार व संगीतकार, ने कहा- संगीत के साथ मेरा जन्मों का नाता, इसमें बहुत ताकत होती है

स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हो संगीत, हिंसा में आएगी कमी

स्मिता श्रीवास्तव, पणजी

संगीत की भाषा यूनिवर्सल होती है। हर स्कूल के पाठ्यक्रम में संगीत होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हिंसा में कमी आएगी। यह कहना है विख्यात संगीतकार, गायक व गीतकार इलैयाराजा का। गोवा में चल रहे 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (इफ्फी) के 7वें दिन उन्होंने फिल्ममेकर आर. बाल्की के साथ संगीत पर परिचर्चा की।

इलैयाराजा के संगीत का ही जादू था कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हॉल में मौजूद लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। संगीत की ताकत के बारे में बताते हुए इलैयाराजा ने कहा, 'संगीत में बहुत ताकत होती है। बिना भाव वाले कलाकार के क्लोजअप को आप दिखाएं, हम उसमें संगीत के जरिये भावों को दिखा देंगे।'

पा, पैडमैन और शमिताभ जैसी फिल्में बना चुके आर. बाल्की ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया कि इलैयाराजा ऐसा संगीत तैयार करते हैं कि आप उसमें हर तरह के गाने को ढाल सकते हैं।

इलैयाराजा। फाइल

हर सिचुएशन मैलोडी कैसे हो सकती है? सवाल के जवाब में इलैयाराजा ने बाल्की की खिंचाई करते हुए पूछा, 'तो मुझे क्या करना चाहिए?' बात को संभालते हुए बाल्की ने कहा कि आप यह चमत्कार कैसे करते हैं? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'संगीत मेरे साथ कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। संगीत आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है। अगर आप उस दुनिया में खो नहीं पाते हैं तो वह संगीत नहीं है।'

बाल्की ने बताया, 'जब हम किसी फिल्म के संगीत के लिए इलैयाराजा के स्टूडियो में जाते हैं तो वह उस फिल्म के प्रमुख हिस्सों को जरूर देखते हैं। उस दौरान उनका हाथ चलता रहता है। वह टिशू पेपर पर कुछ लिखते रहते हैं। वह उसे ऑर्केस्ट्रा टीम को दे देते हैं। शाम को जाने पर वह संगीत को रील के साथ प्ले करते हैं। वह सीन में सटीक बैठता है। यहां तक कि हीरो की गर्दन दाएं होगी तो संगीत का पंच भी उधर ही होगा। वह बैकग्राउंड संगीत के लिए भी उसके भावों को हमसे कहीं ज्यादा महसूस कर लेते हैं। कई बार उसमें वह इमोशन डाल देते हैं, जिसे शायद बतौर फिल्ममेकर मैंने महसूस नहीं किया होता है।' बाल्की ने इस मौके पर फिल्म पा में इस्तेमाल बैकग्राउंड म्यूजिक से संबंधित वाकया भी साझा किया।

दर्शकों की फरमाइश पर इलैयाराजा ने ऐ जिंदगी गले लगा ले, सुरमई अखियों में समेत कई गाने गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। बातचीत के दौरान बाल्की ने उन्हें एक सिचुएशन दी, जिस पर इलैयाराजा ने पांच मिनट से कम समय में उसका संगीत तैयार कर दिया। उस दौरान इलैयाराजा ने दर्शकों से पूछा कि क्या वे उतनी देर चुप बैठ पाएंगे? उसके बाद उनके संगीत तैयार करने तक हॉल में सन्नाटा पसरा रहा। यहां तक कि किसी के मोबाइल की घंटी भी नहीं बजी।

'सत्ते पे सत्ता' रीमेक के निर्देशन से फराह खान का इन्कार

पिछले दिनों खबरें आई थी कि वर्ष 1982 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' के रीमेक का निर्देशन फराह खान करेंगी। इफ्फी में परिचर्चा के दौरान फराह ने कहा कि यह अटकलें मीडिया लगा रहा है। मीडिया ने ही अपनी तरफ से फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री की भी घोषणा कर दी है। हमने बस इतना कहा था कि रोहित शेट्टी के साथ मिलकर फिल्म बनाने वाले हैं। एक अन्य सत्र में सुपरहिट तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी फेम कलाकार विजयदेवरा कोंडा और रकुल प्रीत ने शिरकत की। इस मौके पर विजय ने संकेत दिया कि वह हिंदी सिनेमा में जल्द ही कदम रखेंगे।

5000 से ज्यादा राजपत्रित कर्मचारियों को लगाया गया है जम्मू-कश्मीर में बैक टू विलेज कार्यक्रम में। 25 नवंबर से शुरू यह कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान अधिकारियों को एक रात पंचायत में बितानी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 28 नवंबर 2019

न्यूज गैलरी

जम्मू के प्लांवाला में पाकिस्तान ने की गोलाबारी

जम्मू : पाकिस्तानी सेना ने लगातार सातवें दिन बुधवार को भी जम्मू जिले के अखनूर के प्लांवाला में नत्थू टिब्बा क्षेत्र में भारी गोलाबारी की। इसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है। राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी की तरफ से आए दिन गोलाबारी की जा रही है। बुधवार सुबह तीन बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी गई जो पांच बजे तक जारी रही। भारतीय चौकियों व रिहायशी क्षेत्रों में निशाना बनाया। एक सप्ताह से जारी गोलाबारी के कारण सीमावर्ती इलाकों में दहशत है। (राब्यू)

अयोध्या का पहला वाई-फाई पार्क होगा तुलसी उद्यान

अयोध्या : रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर रामनगरी अयोध्या में स्थापित तुलसी उद्यान के दिन भी बहुरेंगे। उद्यान को सुंदर बनाने के साथ यहां वाई-फाई की सुविधा भी होगी। यह पार्क अयोध्या जिले का पहला वाई-फाई (इंटरनेट सुविधा के लिए) पार्क होगा। सिर्फ यही नहीं पार्क में सुबह और शाम मानस की चौपाइयां भी गूंजेंगी। इसके लिए पार्क में म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा। ताकि स्वास्थ्य लाभ के साथ ही यहां आने वाले लोग रामचरितमानस का श्रवण भी कर सकें। अयोध्या में बनने जा रही साढ़े चार किलोमीटर स्मार्ट रोड के किनारे स्थित तुलसी उद्यान और उसके आसपास के इलाकों के सुंदरीकरण के लिए नगर आयुक्त डॉ. नीरज शुक्ल ने सहमति दे दी है। (जासं)

डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर की पत्नी का लंदन में निधन

ब्यास (अमृतसर) : डेरा ब्यास राधा स्वामी के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की पत्नी शबनम ढिल्लों का बुधवार को लंदन में निधन हो गया। वह पेट की बीमारी का इलाज कराने लंदन के बेडफोर्ड अस्पताल में दाखिल थीं। 24 नवंबर को ऑपरेशन के बाद से ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। डेरा ब्यास के सूत्रों के अनुसार शबनम ढिल्लों का शव भारत लाया जा रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि अंतिम संस्कार कब होगा? पहले गुरुवार को डेरा ब्यास में अंतिम संस्कार की बात कही जा रही थी, लेकिन देर शाम तीन-चार दिन बाद अंतिम संस्कार की बात कही गई है। (जासं)

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वृंदावन में

मथुरा : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को वृंदावन आ रहे हैं। वह यहां करीब चार घंटे रुककर विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली से आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सुबह 9.50 बजे हेलीकॉप्टर से वृंदावन के अक्षयपात्र स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। हेलीपैड पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। (जासं)

राज्यसभा की खाली सीट पर अरुण सिंह भाजपा प्रत्याशी

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीट पर प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी की तजीन फातमा के त्यागपत्र से खाली हुई इस सीट पर अरुण सिंह का निर्विरोध निर्वाचित होना निश्चित है। तजीन फातमा सपा नेता मोहम्मद आजम खां की पत्नी हैं। बीते छह माह के भीतर यह सपा के लिए चौथा बड़ा झटका होगा। राज्यसभा में सपा के 14 सदस्यों की संख्या घटकर अब मात्र दस रह गई है। इनमें बगावती तेवर अपनाए अमर सिंह भी शामिल हैं। (राब्यू)

चिन्मयानंद मामले में एसआइटी आज पेश करेगी जांच रिपोर्ट

शाहजहांपुर : चिन्मयानंद प्रकरण में विशेष जांच दल (एसआइटी) गुरुवार को अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगा। इससे पहले टीम दो बार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ चिन्मयानंद के दुष्कर्म करने व चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के मामलों में छह नवंबर को जांच पूरी कर एसआइटी ने सीजेएम की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले एसआइटी ने 23 सितंबर को अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में दी थी। उसके बाद 22 अक्टूबर को इस मामले में दूसरी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 28 नवंबर को जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। (जासं)

जमीयत का अरशद मदनी गुट दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका

तैयारी ▸ कानून विशेषज्ञों ने तैयार किया ड्राफ्ट

दिसंबर के पहले सप्ताह में दाखिल की जा सकती है याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्ग से ही हो रहे विरोध के बाद भी जमीयत उलेमा-ए-हिंद का अरशद मदनी गुट पुनर्विचार याचिका के फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। जमीयत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राममंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्द पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की तैयारी चल रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह में याचिका दायर की जा सकती है।

जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी बताया है कि उनके नेतृत्व में कानून विशेषज्ञों और उलेमाओं के पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था, जिसने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। पैनल का मानना है कि फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ है और संविधान के तहत उनके पास पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प मौजूद है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका का मकसद देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है। बल्कि यह इसलिए भी है क्योंकि सभी धर्म में काफी लोग ऐसे हैं, जिन्हें यह निर्णय समझ में नहीं आया है।

सुप्रीम कोर्ट का राममंदिर पर 9 नवंबर को फैसला आया था, जिस पर अरशद मदनी गुट ने 17 नवंबर को जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा की थी। हालांकि, इनके इस फैसले से जमीयत का महमूद मदनी गुट, पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा इकबाल अंसारी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। महमूद मदनी ने तो इसमें नुकसान का अंदेशा जताते हुए सचेत किया है। दो दिन पहले 100 से अधिक मशहूर हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पुनर्विचार याचिका के निर्णय का विरोध किया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने ऐसा सोचने वालों को देश के अमन के लिए खतरा बताया है।

> जमीयत जैसे इरादे वाले लोग देश में मोहब्बत और भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है। मुसलमानों में ही भेद पैदा किए। शिक्षा और रोजगार की बात नहीं की, अब जबकि देश का मुसलमान फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ से बड़ा दिल दिखाया गया, एक पत्ता भी नहीं हिला, तो यह चाहते हैं कि नफरत बढ़े।
> **-यासिर जिलानी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच**

> सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। ऐसे में मुख्य पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड और इकबाल अंसारी ने फैसले को स्वीकार करते हुए कहा है कि वह लोग पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे। जमीयत तो इस मामले में पक्षकार नहीं है। ऐसे में उसके जाने का मामला ही नहीं बनता है।
> **आलोक कुमार, कार्याध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद (विहिप)**

सुन्नी बोर्ड मना करेगा तो शिया वक्फ करेगा जमीन पर दावेदारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अयोध्या में जमीन को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड में असमंजस की स्थिति को देखते हुए शिया वक्फ बोर्ड ने दावेदारी की तैयारी करनी शुरू कर दी है। शिया वक्फ बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में तय किया गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड यदि किन्ही कारणों से पांच एकड़ जमीन लेने से मना करता है तो वह इसके लिए दावेदारी करेगा। बोर्ड वहां पर एक अस्पताल बनाने का प्रस्ताव ला सकता है।

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कुल सात सदस्यों में से पांच शामिल हुए। सदस्यों को बताया गया कि 1946 में शिया वक्फ बोर्ड जो मुकदमा हारा था, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में 71 साल बाद की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील देरी से दाखिल करने के कारण खारिज कर दी थी।

बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बताया कि सभी का मानना है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वह अंतिम है। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का अंत राष्ट्रहित में है। इस कारण किसी भी तरह की पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का कोई मतलब नहीं है।

सोमनाथ मंदिर न्यास की तर्ज पर बने श्रीराम मंदिर का ट्रस्ट

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▸ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह भी हो सकते हैं शामिल

▸ जल्द ही हो सकती है उच्चस्तरीय बैठक, निर्माण के कानूनी प्रावधान पर विचार

श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर श्रीकाशी विश्वनाथ की नगरी में बीते दो दिनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके अनुषांगिक संगठनों का मंथन हो रहा है। संघ के सर कार्यवाह सुरेश भय्याजी जोशी और सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में बैठकों का दौर जारी है। इसमें मंदिर निर्माण के लिए गठित होने वाले न्यास का ब्लू प्रिंट बनाने के साथ निर्माण में आमजन की भागीदारी पर विचार हुआ। सूत्रों के अनुसार संघ की मंशा है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर न्यास की तर्ज पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नए ट्रस्ट का गठन हो, भले ही स्थायी सदस्यों की संख्या आठ से अधिक कर दी जाए। यह धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा। इस नए ट्रस्ट में श्रीराम जन्मभूमि न्यास भी समाहित रहेगा। इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह सोमनाथ ट्रस्ट में भी सदस्य हैं। सोमनाथ ट्रस्ट में आठ सदस्य हैं। कानून मंत्रालय अदालत के फैसले का अध्ययन कर रहा है। समझा जा रहा है कि जल्द ही मोदी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हो सकती है।

विश्वनाथ धाम की तरह कौरिडोर : बैठक में सुझाव आया कि सरकार श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा कॉरिडोर अयोध्या में भी बना सकती है। इसके अलावा अयोध्या के पांच किमी क्षेत्र में सैकड़ों मठ-मंदिर हैं। यह भी ट्रस्ट के अधीन आ सकते हैं। इस दायरे में लवकुश मंदिर, राम मंदिर, रंगमहल, राम कचेहरी, इमली बगिया, जगन्नाथ मंदिर, तुलसी मंदिर, सीता रसोई, कनक भवन, राम सिंहासन, हनुमान गढ़ी, मणि पर्वत, मोती महल, दशरथ भवन, नागेश्वरनाथ, विष्णु मंदिर आदि आते हैं। श्रीसोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का उदाहरण देते हुए जानकारी दी गई कि यह ट्रस्ट करीब 10 किमी के दायरे में 42 मंदिरों का प्रबंध कार्य देखता है। ट्रस्ट की सालाना आय 40 करोड़ रुपये है। ट्रस्ट में 600 लोग काम करते हैं। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग-बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। बुधवार को सुबह बैठक से पहले सह सर कार्यवाह डा. कृष्ण गोपाल के साथ संघ के पदाधिकारियों ने श्रीकाशी विश्वनाथ कारिडोर का निरीक्षण किया।

रामनवमी तक निर्माण प्रारंभ की इच्छा : अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से ट्रस्ट गठित करने की प्रक्रिया के बीच आरएसएस और विहिप अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। आरएसएस से जुड़े धर्माचार्यों की इच्छा है कि रामनवमी से मंदिर निर्माण शुरू हो जाए। संघ के सर कार्यवाह भय्याजी जोशी ने लोहता स्थित माधव सेवा प्रकल्प में बुधवार को दिन में काशी और अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। इसमें राम मंदिर निर्माण से आमजन को जोड़ने के लिए अभियान के बारे में पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए। गांव-गांव मंदिर पर चर्चा कर जन सुझाव लेने की बात भी कही गई।

कनकमला आइएस आतंकी मॉड्यूल के मुख्य आरोपित को 14 वर्ष कैद की सजा

कोच्चि, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने बुधवार को वर्ष 2016 में केरल व पड़ोसी प्रदेशों में आतंकी वारदातों की साजिश रचने के मुख्य आरोपित को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने सोमवार को मुख्य आरोपित मनसीद महमूद समेत छह लोगों को आइपीसी की विभिन्न धाराओं व गैरकानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी पाया था। उन पर आतंकी संगठन का सदस्य होने और उसे सहयोग प्रदान करने का आरोप है। हालांकि, एक आरोपित जसीम एनके को बरी कर दिया गया। एनआइए ने सभी आरोपितों के खिलाफ कनकमला आतंकी मॉड्यूल मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। विशेष जज पी. कृष्ण कुमार ने दूसरे आरोपित स्वालीह मुहम्मद को 10 साल व तीसरे आरोपित राशिद अली को सात साल की सजा सुनाई। चौथे आरोपित एनके रमशाद व आठवें मोईनुद्दीन को तीन-तीन साल, जबकि पांचवें सफावन को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

जज ने कहा कि आरोपित आइएस में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वह इस आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'उम्मीद करनी चाहिए कि इन युवाओं के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आए। इन्होंने धर्म के नाम पर अपराध करने की भूल की है।'

उल्लेखनीय है कि एनआइए ने अक्टूबर 2016 में कन्नूर जिले में कनकमला आइएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। तब आरोपित जज, पुलिस अधिकारी व राजनीतिज्ञों समेत प्रमुख हस्तियों पर हमले का षड्यंत्र रच रहे थे। एनआइए थाने में आठ आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

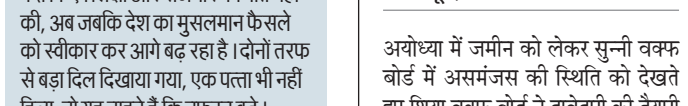

केरल के कोच्चि में बुधवार पुलिस ने कनकमला आइएस आतंकी मॉड्यूल मामले के आरोपितों को अदालत में पेश किया। प्रेट्र

लोकायुक्त अधिनियम को जम्मू-कश्मीर में लागू करने के लिए समिति गठित

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▸ पांच सदस्यीय समिति 13 दिसंबर तक देगी अपनी रिपोर्ट

▸ समिति सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कामकाज का भी जायजा लेगी

जम्मू-कश्मीर में भी अब देश के अन्य राज्यों की तरह प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोकायुक्त होगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को जम्मू-कश्मीर में लागू करने की संभावना तलाशने के लिए उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के निर्देश पर पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। समिति 13 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। समिति सतर्कता आयोग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कामकाज का भी जायजा लेगी।

उपराज्यपाल के निर्देशानुसार, महा प्रशासनिक विभाग ने समिति के गठन की अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक समिति की अध्यक्षता कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के सचिव करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक, महाप्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त सचिव के अलावा कानून, न्याय और संसदीय मामलों विभाग के दो अधिकारी जो समिति अध्यक्ष द्वारा चुने जाएंगे, इसके सदस्य होंगे। समिति भारतीय दंड संहिता के तहत केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में नौकरशाह, जनसेवक, सरकारी अधिकारी की परिभाषा से जुड़े मामलों का अध्ययन करेगी।

एहतिसाब आयोग के पास थे अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2018 को जम्मू कश्मीर समेत 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के लागू होने के पांच साल बीतने पर भी लोकायुक्त की नियुक्ति न करने पर दो सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा था। अलबत्ता, 10 जुलाई 2018 को तत्कालीन राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि जम्मू कश्मीर एहतिसाब आयोग-2002 के प्रावधान और जम्मू कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम-2011, का गठन राज्य कानून के तहत हुआ है। यह अधिनियम के तहत होने वाले कार्यों को पूरा करते हैं और उनके समान ही अधिकार व शक्तियां रखते हैं।

> **केंद्र शासित प्रदेशों में भी होता है लोकायुक्त**
> लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को एक जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। अधिनियम के तहत भारतीय गणराज्य के लिए लोकपाल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है।

छग में दो कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर के छापे, एक करोड़ की नकदी मिली

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के दो बड़े इस्पात कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे में अब तक एक करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हो चुकी है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसमें कई छद्म कंपनियों का भी पर्दाफाश हुआ है। आयकर की एक टीम जांच के लिए कोलकाता भी भेजी गई है। आयकर की टीम ने दोनों कारोबारियों के करीब 40 ठिकानों पर मंगलवार को दबिश दी थी। इसमें 10 मकान और 30 कंपनी, दुकान और ऑफिस शामिल है। बुधवार को दूसरे दिन भी जांच जारी रही। अब तक की जांच में मिले दस्तावेजों में ज्यादातर लेन-देन नगद में होना पाया गया है। आयकर के अफसरों ने बताया कि बुधवार को एक स्थान पर जांच पूरी कर ली है।

सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में अलग-अलग बैंकों में चार लॉकरों की जानकारी मिली है। इन्हें अभी खोला नहीं गया है। आयकर सूत्रों ने बताया कि बड़े पैमाने पर सोना, चांदी और हीरा आदि के गहने मिले हैं। कारोबारी समूह से जुड़े सूत्रों के अनुसार जिस वक्त आयकर की टीम ने दोनों कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी उस वक्त उनमें से एक परिवार के सदस्य अस्पताल में थे। मंगलवार को ही उस परिवार की बहू ने बच्ची को जन्म दिया था। इस वजह से मंगलवार को डायरेक्टरों से पूछताछ नहीं हो सकी।

गुजरात में किशोर को ह्वाइटनर बेचने वाले दुकानदार पर केस

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

▸ एक किशोर के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

गुजरात में एक स्टेशनरी दुकानदार को किशोरों को एक से ज्यादा संख्या में ह्वाइटनर बेचना महंगा पड़ गया। एक किशोर के पिता की शिकायत पर दुकानदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

अहमदाबाद के नवा नरोडा कृष्ण नगर निवासी एक व्यक्ति ने बापूनगर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने बताया कि सोमवार शाम को जब वह घर पहुंचे तो कमरे में घुसते ही उनके बेटे ने अचानक एक कलम जैसी चीज फेंक दी। पूछने पर उसने बताया कि ह्वाइटनर सूंघे बिना उसे बेचैनी महसूस होती है। उसने यह भी बताया कि वह अक्सर बापूनगर इंडिया कॉलोनी के प्रकाश जनरल स्टोर से ह्वाइटनर खरीदता है। इस शिकायत पर पुलिस ने जब प्रकाश जनरल स्टोर में छापा मारा तो वहां बड़ी संख्या में ह्वाइटनर बरामद हुए। स्टोर मालिक शिव प्रकाश जोशी ने बताया कि उन्हें एक से अधिक ह्वाइटनर एक साथ बेचने पर पाबंदी संबंधी जानकारी नहीं थी।

पुलिस ने बताया कि दुकानदार के खिलाफ आइपीसी की धारा 284 (विषैला पदार्थ के प्रति लापरवाही) व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 25 (नाबालिग को मादक पदार्थ देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच के बाद आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी।

ह्वाइटनर एक रासायनिक तरल पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल दस्तावेजों में लिखी गई चीजों को छिपाने या मिटाने के लिए किया जाता है। जहां पर यह तरल पदार्थ लगा दिया जाता है वहां का कागज सफेद हो जाता है और उस पर कलम से लिखाई या टाइपिंग संभव हो जाती है। लेकिन, युवा और किशोर इसका इस्तेमाल मादक पदार्थ के रूप में भी करने लगे हैं।

कई वारदात में शामिल रहे इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

नईदुनिया, दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आगजनी और बम ब्लास्ट समेत कई नक्सली वारदात में शामिल रहे जनमिलिशिया कमांडर ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

किरंदुल थाना क्षेत्र के मलांगिर एरिया कमेटी में सक्रिय हड़मा बुधवार दोपहर एसपी कार्यालय में समर्पण करने पहुंचा। एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव के अनुसार उसने स्वीकार किया है कि उसे नक्सली लीडर देवा ने 2007 में बाल संघम में भर्ती कराया था। नक्सली हेमला विनोद ने उसे जनमिलिशिया सदस्य और बाद में कमांडर बनाया। 13 अप्रैल 2015 को चोलनार सीआरपीएफ कैंप से निकली एंटी लैंड माइन व्हीकल को विस्फोट कर उड़ाने वाली वारदात में वह शामिल था। इस वारदात में पांच जवान शहीद और सात घायल हुए थे। 20 मई 2018 को चोलनार-पेरपा चौक पर पुलिस वाहन को विस्फोट कर उड़ाने में भी वह शामिल था।

रेलवे ने कहा-प्रदर्शनकारी दिव्यांग नौकरी के लिए रख रहे हैं अनुचित मांगें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे ने नियुक्तियों की मांग को लेकर दिल्ली में बार-बार धरना-प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगों से स्पष्ट कहा है कि उनकी मांगें अनुचित हैं। रेलवे ने यह भी साफ किया है कि जो नियुक्तियां की गई हैं वो पूरी तरह नियमों के अनुसार हैं। रेलवे केवल उन्हीं मामलों पर विचार करेगा जिनमें दिव्यांगों ने गलती से खुद को किसी अन्य दिव्यांग श्रेणी में दर्शाया है। ऐसे मामलों पर भी सामाजिक न्याय मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

रेलवे बोर्ड के सदस्य, कार्मिक मनोज पांडेय ने कहा कि दिव्यांग ऐसी मांगें रख रहे हैं जिन्हें मौजूदा नियम-कायदों के तहत पूरा करना संभव नहीं है। मसलन, वे चाहते हैं कि उन्हें न्यूनतम प्राप्तांक से कम अंक मिलने के बावजूद नियुक्ति दे दी जाए, जो कि अनुचित है। कई दिव्यांगों ने न्यूनतम पात्रता अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आरक्षित पदों की संख्या के अनुसार वे सबसे पहले नियुक्ति के पात्र हैं। प्रदर्शनकारियों की 184 शिकायतों में एक भी व्यक्ति नियुक्ति का पात्र नहीं निकला। रेलवे में भर्ती को लेकर दिव्यांगों ने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के मंडी हाउस के निकट दो बार धरना प्रदर्शन किया हैं। दिव्यांगों को मनाने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारी लगातार उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जो दिव्यांग दिल्ली धरना देने आए हैं उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए।

ये लड़ाई पिछले वर्ष लेवल-1 (ग्रुप डी) में भर्ती के लिए निकाले गए 63 हजार पदों में दिव्यांगों के आरक्षित पदों पर नियुक्ति को लेकर है। जिसके तहत कुल 2400 दिव्यांगों की भर्ती होनी थी। जिसमें दृष्टिबाधित 609, बधिर 614, आर्थोपीडिक 612 तथा बहु-दिव्यांगता श्रेणी में 611 रिक्तियां शामिल हैं। इनमें रेलवे अब तक 1021 दिव्यांगों की भर्ती कर चुका है।

> **रेलवे 119 स्थानों पर लगा रहा ऑटोमैटिक कोच वाशिंग प्लांट**
> **जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली** : स्टेशनों को स्वच्छ बनाने की मुहिम में कामयाबी मिलने के बाद रेलवे ने अब अपनी ट्रेनों को भी साफसुथरा रखने की योजना पर काम तेज कर दिया है। इसके लिए स्टेशनों तथा वर्कशॉप पर ऑटोमैटिक कोच वाशिंग के प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। शुरू में 119 स्टेशनों पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे।
> रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि ऑटोमैटिक कोच वाशिंग प्लांट स्थापित करने की योजना के तहत अब तक 16 प्रमुख स्टेशनों व वर्कशॉप पर इस तरह के प्लांट लगाए जा चुके हैं। यहां हर गुजरने वाली ट्रेन को ऑटोमैटिक मशीनों के जरिये बाहर से धोया और चमकाया जाता है।

बिगड़ता मौसम

रामबन में भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, हजारों वाहन फंसे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बढ़ी ठंड

पहाड़ों पर बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश

जेएनएन, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गई है। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में हुए भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है और हजारों वाहन जगह-जगह फंस गए हैं। कश्मीर को पुंछ से जोड़ने वाला मुगल रोड और किश्तवाड़ को अनंतनाग से जोड़ने वाला सिंथनटॉप मार्ग पहले से बंद होने से कश्मीर का देश से सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। श्रीनगर-लेह हाईवे भी बंद है।

मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 27 नवंबर से अधिकांश इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। बुधवार तड़के से ही गुलमर्ग समेत वादी के सभी उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गुलमर्ग में छह इंच, सोनमर्ग में आठ इंच, साधनाटॉप के निकट दो फीट और महागुंसटॉप में डेढ़ फीट ताजा बर्फ पड़ी। वहीं, श्रीनगर, जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर में तड़के शुरू हुई बारिश दिनभर जारी रही। गुलमर्ग, लेह और कारगिल का न्यूनतम तापमान क्रमशः माइनस 3.5, 7.3, और 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, कुपवाड़ा में सर्वाधिक 36.1 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।

हाईवे बंद : जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बुधवार को छोटे वाहनों को दोनों तरफ से आने-जाने की अनुमति थी। दोपहर करीब एक बजे रामबन के मोमपस्सी इलाके में भारी बारिश से सड़क के एक बड़े हिस्से पर पहाड़ से चट्टानें खिसक कर नीचे आ गईं। हाईवे बंद होने पर अधिकारियों ने यातायात रोक दिया, जिससे कई स्थानों पर वाहन फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि मार्ग को यातायात योग्य बनने के बाद पहले फंसे वाहनों को निकाला जाएगा। इधर, श्रीनगर-लेह हाईवे कई दिनों से यातायात के लिए बंद है। बुधवार को जोजिला दर्रे के निकट ताजा बर्फबारी से काम बंद हो गया है। वहीं मुगल रोड भी 7 नवंबर से यातायात के लिए बंद है।

हिमस्खलन का खतरा बरकरार : उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा और अधिक बढ़ गया गया है। मौसम विभाग ने बांडीपोरा, बारामुला, कुपवाड़ा, बड़गाम, अनंतनाग, गांदरबल, शोपियां व कुलगाम जिलों के ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

हिमाचल के किन्नौर में 22 यात्री रेस्क्यू किए : हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम व अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। शिमला के नारकंडा में सीजन का पहला हिमपात हुआ। किन्नौर जिले में पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण कई जगह मार्ग अवरुद्ध हो गया। यहां 22 यात्रियों को बीआरओ, होमगार्ड व पुलिस क्यूआरटी की टीम ने रेस्क्यू किया। कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे, बारालाचा दर्रे, शिंकुला व कुंजम दर्रे में बर्फबारी हुई। मनाली-लेह, मनाली-जांस्कर व मनाली-काजा मार्ग बंद हैं। सोलंग, कोठी, पलचान, कुलंग व रुआड गांव तक बर्फबारी हुई।

वहीं, उत्तराखंड में चारधामों और औली के साथ ही ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होती रही। बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब समेत कुमाऊं के पंचाचोली, मुनस्यारी व पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में तड़के बर्फबारी शुरू हो गई थी। उत्तरकाशी जिले में हर्षिल और सुक्की टॉप पर पूरे दिन रुक-रुककर बर्फबारी का दौर जारी रहा।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के पिओ में भारी बर्फबारी के बीच अपने गंतव्य की ओर जाते लोग। जागरण

पटना एयरपोर्ट पर पौने दो घंटे खड़ा रहा गो-एयर का विमान

जागरण संवाददाता, पटना

पटना से दिल्ली जा रहा गो-एयर का विमान (फ्लाइट संख्या जी 8-2512) बुधवार को एसी में आई खराबी के कारण करीब पौने दो घंटे तक रनवे पर ही खड़ा रहा। इससे कई बुजुर्ग यात्री दम घुटने की शिकायत करने लगे। यात्रियों की शिकायत पर क्रू-मेम्बर ने विमान का दरवाजा खोला और दम घुटने की शिकायत करने वाले करीब दर्जनभर से अधिक यात्रियों को बाहर निकाल रनवे पर बैठाया। एक घंटे में विमान की खराबी को दूर किया गया तब जाकर यात्रियों को पुनः बैठाया जा सका।

इसी फ्लाइट से पत्नी के साथ दिल्ली जा रहे रामसागर सिंह ने बताया कि सारे पैसेंजर विमान में सवार हो गए थे। दरवाजा भी बंद कर दिया गया था। अचानक एस

1476 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है हरियाणा के खनन व भूगर्भ विभाग को परियोजनाओं के निष्पादन में अनियमितता के कारण। यह जानकारी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ओर से विधानसभा में रखी गई रिपोर्ट में दी गई है।

डॉक्टरों को एक साल गांवों में सेवाएं देना होगा अनिवार्य

कैबिनेट का फैसला ▸ बांड की राशि जमा करने पर भी नहीं मिलेगी मुक्ति

मध्य प्रदेश में 89 आदिवासी विकासखंडों में मुख्यमंत्री सुषेण योजना लाग

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीबीएस करने वालों को एक साल ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देना अनिवार्य करेगी। बांड की राशि जमा करने के बाद भी इससे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी बांड की राशि 10 लाख रुपये है और यदि कोई डॉक्टर इस रकम को जमा भी कर दे तो भी उसे इस नियम से छुटकारा नहीं मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग योजना को अंतिम रूप दे रहा है। वहीं, 89 आदिवासी विकासखंडों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री सुषेण योजना के तहत प्रोत्साहन पैकेज देगी। इसमें वेतन के अतिरिक्त राशि, आवास, आने-जाने के लिए वाहन और

कमलनाथ। फाइल

निःशुल्क बिजली की सुविधा दी जाएगी। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर अस्पताल सुविधा को बेहतर बनाने निवेश प्रोत्साहित करने नई नीति को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत निवेशकों को रियायती दर पर जमीन और पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा।

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि 20 जिलों के 89 आदिवासी विकासखंडों में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुषेण योजना लागू की गई है। इसके तहत डॉक्टरों को वेतन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। इसमें अति पिछड़े विकासखंडों में संविदा चिकित्सकों का कुल मानदेय एक लाख से दो लाख रुपये और बाकी पिछड़े विकासखंडों में 90 हजार से एक लाख 85 हजार रुपये तक होगा। नियमित चिकित्सकों का वेतन अति पिछड़े विकासखंडों में 96,100 से बढ़कर 1,42,700 और पिछड़े विकासखंडों 86 ,100 से बढ़कर 1,27,000 रुपये तक दिया जाएगा। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर आवास, आवास से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक आने-जाने वाहन और निःशुल्क बिजली भी मुहैया कराई जाएगी। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में बदलाव किया गया है। अब नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के बाहर 30 बिस्तर तक का अस्पताल बनाने के लिए रियायती दर पर जमीन और पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। यह सुविधा पांच करोड़ का निवेश करने पर मिलेगी। अभी तक कम से कम सौ बिस्तर का अस्पताल बनाने पर निवेश प्रोत्साहन दिया जाता था।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में भारत के रुख को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय कैबिनेट ने अगले हफ्ते पर्यावरण परिवर्तन पर स्पेन में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के 25वीं कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) में भारत के रुख को मंजूरी दे दी है। चिली की अध्यक्षता में यह सम्मेलन दो से 13 दिसंबर तक चलेगा।

भारत पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सकारात्मक और सृजनात्मक रुख रखता है, ताकि इसके साथ ही विकास संबंधी लंबी अवधि के हितों को भी साझा जा सके। सीओपी-25 एक बेहद अहम सम्मेलन है। चूंकि इसके सदस्य देश क्योटो प्रोटोकाल के तहत वर्ष 2020 से पूर्व के समय से पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2020 के बाद के काल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पर्यावरण परिवर्तन के मसले पर भारत का रुख 'युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज' (यूएनएफसीसीसी) के प्राविधानों व सिद्धांतों और पेरिस समझौते से निर्देशित होता है। भारत खास करके हिस्सेदारी और समानता का सिद्धांत मानता है और संबंधित देश की क्षमता के अनुसार उसे जिम्मेदारी दिए जाने की पैरवी करता है। अगले हफ्ते से स्पेन में होने वाले सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुआई पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर करेंगे। वह पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लंबी अवधि के विकास हितों की भी पैरवी करेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण पर रुख और पहल को विश्व भर में सराहा गया है।

हुजूर! नहीं चाहिए इंसाफ, खारिज कर दीजिए मुकदमा

आलोक शर्मा, कानपुर

'हुजूर...अब इंसाफ नहीं चाहिए। ढाई वर्ष से पैरवी कर रहा हूं, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब पैरवी करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अपील पर कोई बल नहीं देना चाहता हूं। मेरी अपील खारिज कर दें...' कानपुर के जनपद न्यायालय में यह अर्जी बिजनौर में शुगर मिल श्रमिकों की लाल झंडा ट्रेड यूनियन के नरेंद्र कुमार व अन्य श्रमिकों ने दी है। इसका एक-एक शब्द पीड़ितों का वह दर्द बयां कर रहा है, जो बार-बार तारीख पर आकर थक चुके हैं और अपील वापस लेने के लिए विवश हैं। कोर्ट ने भी अर्जी स्वीकार कर मामला निस्तारित कर दिया।

बिजनौर की लाल झंडा ट्रेड यूनियन का पंजीकरण 30 जनवरी 2017 को निरस्त किया गया था। इसके पदाधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने श्रमिकों से प्रावधान से अधिक शुल्क वसूला। वहीं, यूनियन के पदाधिकारी दावा करते रहे कि उन्होंने मानक के अनुरूप सदस्यता शुल्क लिया है। किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। सदस्यों से ली अतिरिक्त राशि सदस्यता शुल्क की नहीं बल्कि दूसरे मद की थी। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन ने लाल झंडा ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के तर्कों को नहीं माना और पंजीकरण निरस्त कर दिया। ट्रेड यूनियन

▸ **न्यायालय ने स्वीकार की पीड़ित पक्ष की अर्जी**

> पैरवी करने वाले यूनियन के पक्षकार काफी परेशान हो गए थे। उनके कहने पर ही अपील खारिज करने का प्रार्थना पत्र दिया गया। अपनी तरह का यह पहला मामला है, जिसमें पीड़ितों में स्वयं मुकदमा खत्म करने की अर्जी देने का निर्णय लिया हो।
> **-कौशल किशोर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता**

मामलों की सुनवाई कानपुर जनपद न्यायालय निर्धारित है, इसलिए यूनियन की ओर से नरेंद्र कुमार व अन्य श्रमिकों ने जनपद न्यायाधीश के यहां नौ मई 2017 को अपील की। तब न्यायालय ने रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन से फाइल तलब की। मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि ढाई वर्ष से आदेश हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन की ओर से पत्रावली कोर्ट में ही नहीं पेश की गई। ऐसे में वादी व श्रमिक बार-बार आते और तारीख लेकर लौट जाते। इससे परेशान होकर उन्होंने अपील वापस लेने का निर्णय लिया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है।

तेजस्वी यादव के खिलाफ विशेष कोर्ट में पांचवां गवाह पेश

जासं, मुजफ्फरपुर : बालिका गृह प्रकरण में आपत्तिजनक बयान के मामले में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ बुधवार को विशेष कोर्ट में पाचवां गवाह पेश किया गया। हालांकि पीठासीन पदाधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण काजी मोहम्मदपुर थाना के नया टोला निवासी अशोक कुमार की गवाही एसीजेएम ऋचा भार्गव के विशेष कोर्ट में दर्ज नहीं हो सकी। अगली सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी।

बालिका गृह प्रकरण में आपत्तिजनक बयान को लेकर राज्य के शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने पिछले साल तेजस्वी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इस मामले में मंत्री सुरेश शर्मा की ओर से पिछली तारीख पर चौथे गवाह के रूप में पंखाटोली निवासी लक्ष्मण राम को पेश किया गया था। उनकी गवाही भी दर्ज की गई थी। उन्होंने परिवाद का समर्थन किया। विदित हो कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड को लेकर तेजस्वी ने पिछले साल पटना में मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उनका यह बयान विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इसको लेकर शर्मा ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। मामला एमएलए से संबंधित होने के कारण सुनवाई के लिए सीजेएम ने इसे विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

न्यूज गैलरी

दो दिवसीय यात्रा पर राजस्थान आएंगे राष्ट्रपति

जयपुर : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छह दिसंबर को राजस्थान की दो दिवसीय यात्रा पर आएंगे। राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रपति छह दिसंबर को माउंट आबू में ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगले दिन वे जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एम्स जोधपुर के दीक्षा समारोह में भाग लेंगे। मुख्य सचिव ने बुधवार को सिरोही, उदयपुर और जोधपुर के कलेक्टरों व अन्य अधिकारियों को राष्ट्रपति की यात्रा के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। (प्रेट्र)

'मर्दानी-2' के निर्माताओं और सेंसर बोर्ड को कानूनी नोटिस

जयपुर : अभिनेत्री रानी मुखर्जी की आगामी फिल्म 'मर्दानी-2' का राजस्थान के शहर कोटा में विरोध और तेज हो रहा है। स्थानीय पार्षद गोपाल मेंडा ने फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी के साथ ही सूचना व प्रसारण मंत्रालय को कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें फिल्म से कोटा शहर का नाम हटाने की मांग की गई है। नोटिस देने वाले का आरोप है कि फिल्म में शहर की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। यदि नाम नहीं हटाया गया तो फिल्म का विरोध किया जाएगा और फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। गौरतलब है कि यह विवाद फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से शुरू हुआ है। इसमें फिल्म को सच्ची घटनाओं पर आधारित बताया गया है और दिखाया गया है कि शहर में कोई साइको किलर है, जो लड़कियों का दुष्कर्म कर उनकी हत्या करता है, जबकि कोटा में ऐसा कोई मामला कभी सामने नहीं आया है। यहां के लोगों का कहना है कि कोटा पूरे देश में कोचिंग नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां करीब ढाई लाख विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। ऐसे में गलत तथ्य देकर शहर की छवि खराब की जा रही है। (आइएएनएस)

छग में झारखंड जनमुक्ति परिषद पर लगा रहेगा प्रतिबंध

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) पर लगे प्रतिबंध को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में यह संगठन 2017 से प्रतिबंधित है। गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी करके यह रोक लगाई है। जेजेएमपी पर यह रोक 15 नवंबर 2019 से एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकार का मानना है कि इस संगठन की वजह से लोक व्यवस्था व शांति में बाधा उत्पन्न होगी। इसके साथ ही नागरिकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है। (नईदुनिया)

पांच सैनिक स्कूलों में बेटियों के लिए 10 फीसद सीटें आरक्षित

जागरण संवाददाता, लखनऊ : देश का पहला सैनिक स्कूल अब एक और इतिहास रचने जा रहा है। कैप्टन मनोज पांडेय यूपी सैनिक स्कूल के मॉडल पर देश के पांच सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेटियों के कक्षा छह में एडमिशन के लिए मंजूरी दे दी है। इसके लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। एनडीए (नेशनल डिफेंस एकेडमी) की तैयारी कराने के उद्देश्य से 1960 में देश का पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित किया गया था। पहली बार 2017-18 में लड़कियों का एडमिशन कक्षा नौ में शुरू हुआ। 2017-18 में तत्कालीन रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बाकी सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के एडमिशन के निर्देश दिए थे। इसके लिए यूपी सैनिक स्कूल के मॉडल का अध्ययन किया गया और रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई। अब जाकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बीजापुर और कोड़ागु, महाराष्ट्र के चंद्रपुर, उत्तराखंड के घोड़ाखाल और आंध्र प्रदेश के कालीकिरी सैनिक स्कूल में कक्षा छह में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत सीटें आवंटित करने की मंजूरी दे दी है।

6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन : आदेश के तहत 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक बालिकाओं के एडमिशन के आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे।

पीईबी की परीक्षाओं में बदलाव, हर जवाब के साथ मुश्किल होता जाएगा अगला सवाल

अभिषेक दुबे, भोपाल

मध्य प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी- पूर्व में व्यापम) परीक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रहा है। पीईबी अब आइटम रिस्पांस थ्योरी (आइआरटी) के आधार पर परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। आइआरटी पर परीक्षा होने से सवाल 'कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी)' की तर्ज पर आएंगे। यानी जैसे-जैसे सवाल का जवाब दिया जाएगा, अगला सवाल और भी कठिन होता जाएगा। सवाल क्रमशः कठिन होते जाने से योग्यतम उम्मीदवार का चयन आसान होगा। परीक्षा में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए पीईबी करोड़ों प्रश्नों का बैंक भी तैयार करने जा रहा है। यह व्यवस्था ऑनलाइन परीक्षा में ही संभव होती है।

गौरतलब है कि पिछले एक साल से पीईबी की भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन ही आयोजित की जा रही हैं। पीईबी कृषि, नर्सिंग, आयुर्वेद, होम्योपैथिक आदि कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा व सरकारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले के बाद गिरी साख को बदलने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पहले व्यापम नाम बदलकर पीईबी कर दिया गया फिर ऑफलाइन माध्यम से होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाने लगीं। परीक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव करने के लिए पीईबी प्रश्न बैंक तैयार कराने जा रहा है। हर परीक्षा का उसके पाठ्यक्रम के अनुसार अलग प्रश्न बैंक होगा। प्रश्नों और उसके सही जवाबों की जांच करने के बाद ही प्रश्न बैंक में रखा जाएगा। इससे गलत सवाल या सही सवाल का गलत जवाब की आशंका भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा कभी कोई प्रश्न एक बार परीक्षा में आने के बाद दोबारा नहीं आएगा।

मानकीकरण (नॉर्मलाइजेशन) से मिलेगी मुक्ति : अब तक हर परीक्षा के पहले प्रश्न विशेषज्ञों से लिए जाते हैं। यदि सवाल या सवाल का जवाब गलत होता है तो मानकीकरण प्रणाली से प्रश्न पत्र की कठिनता का स्तर जांच कर एक फॉमूले से औसत अंक दिए जाते हैं। ऐसे में परीक्षार्थी के अंकों में भी अंतर आ जाता है। परीक्षार्थी को ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद जो अंक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, परिणाम जारी होने पर वो बदल जाते हैं। कभी परीक्षार्थी के अंक कम हो जाते हैं तो कभी ज्यादा हो जाते हैं लेकिन प्रश्न बैंक से सवाल आने से इस झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में परीक्षार्थी स्क्रीन पर जो अंक देखेगा परिणाम के समय भी वो ही अंक मिलेंगे।

पीईबी मुख्यालय। फाइल

▸ **कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर सवाल होते जाएंगे कठिन**

> पीईबी की परीक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव होना है। इसका मकसद सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ ही योग्य उम्मीदवार का चयन करना है। आईआरटी आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
> **एकेएस भदौरिया, परीक्षा नियंत्रक, पीईबी**

हाई कोर्ट ने मलविंदर को एक दिन की ईडी रिमांड पर भेजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **हाई कोर्ट ने घर का खाना उपलब्ध कराने की दी अनुमति**

▸ **रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में वित्तीय अनियमितता से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं मालविंदर**

रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) में वित्तीय अनियमितता से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह को हाई कोर्ट ने एक दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर भेज दिया। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने साथ ही सह-आरोपित रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी को भी एक दिन की रिमांड पर भेजा। पीठ ने निचली अदालत द्वारा 23 नवंबर को सिंह और गोधवानी को 7 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को भी रद कर दिया।

पीठ ने बुधवार को जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह मलविंदर और गोधवानी को ईडी की हिरासत में सौंपे। हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें संबंधित निचली अदालत के समक्ष पेश करें। पीठ ने दोनों को अपने परिवार और अधिवक्ता से बुधवार शाम और गुरुवार सुबह मिलने की अनुमति दी। उन्हें घर का खाना खाने की भी अनुमति मिली है। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए ईडी ने दलील दी थी कि कई दस्तावेजों के संबंध में मलविंदर से पूछताछ की जरूरत है। ईडी की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल अमित महाजन

मलविंदर सिंह फाइल

ने कहा कि कंपनी के दो निदेशकों को अगले चार दिन तक पूछताछ के लिए बुलाया गया है ताकि दोनों आरोपितों से उनका सामना कराया जा सके। दोनों आरोपितों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि एजेंसी की जांच पक्षपातपूर्ण है और वह उनके मुवक्किल को प्रताड़ित करना चाहती है। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को रद करने के साथ ही दोनों की हिरासत 28 नवंबर तक बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने 14 नवंबर को तिहाड़ जेल से दोनों को हिरासत में लिया था।

विकल्प होने पर युवाओं को नहीं भा रही अफसरशाही

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार में बुनियादी अफसरशाही लोगों को बहुत अधिक भा नहीं रही। यही वजह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के जरिये ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) बनने के बाद भी कई नए अवसर की तलाश में लग जाते हैं। पीजी के साथ नेट और पीएचडी की उपाधि है तो उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षक बनने की होती है। अगर यह संभव नहीं है तो राज्य सरकार में ही वे किसी अन्य सेवा को तरजीह देते हैं। 2019 में 20 से अधिक ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। इनमें से अधिक लोगों ने शिक्षा को चुना। वे असिस्टेंट प्रोफेसर बने। बाकी अधिकारियों ने बिहार लोक सेवा आयोग की अन्य प्रतियोगिताओं के जरिए अपेक्षाकृत ऊंचे पद पर जाना पसंद किया।

श्रीमती हुस्न आरा, तौकीर हाशमी, रुपेंद्र कुमार झा, पंकज कुमार, रतन कुमार दास जैसे कुछ नाम इन पदाधिकारियों के हैं। ये सब किसी न किसी प्रखंड में पदाधिकारी थे। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल हो गए। इसी तरह अमरेश कुमार, श्रीमती आरुप और मारकंडेय राय जैसे अधिकारी हैं, जो आयोग की परीक्षा में शामिल होकर ऊंची सरकारी सेवा में चले गए। हां, नौकरी छोड़ने के एवज में इन्हें आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी। इन पर राज्य सरकार ने जो कुछ खर्च किया था, उसकी वसूली की गई।

इसलिए छोड़ रहे पद : प्रखंड विकास पदाधिकारी की तुलना में असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह अधिक है। मगर नौकरी बदलने की यह इकलौती वजह नहीं है। अफसरी छोड़ असिस्टेंट प्रोफेसर बने एक सज्जन का कहना था काम का बोझ अधिक है। राज्य और केंद्र सरकार की शायद ही ऐसी कोई योजना है, जो प्रखंड के रास्ते से नहीं गुजरती है। प्रखंडों में काम बढ़ा है लेकिन उस लिहाज से कार्यबल नहीं बढ़ा है। नतीजा यह है कि कम उम्र में ही यह अफसरी उम्र भर चलने वाली बीमारियां दे देती हैं। इसके अलावा जन प्रतिनिधियों की गैर-जरूरी दखलंदाजी भी परेशान करती है।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार स्वीकार करते हैं कि प्रखंड अधिकारियों पर काम का बोझ अधिक है। पदाधिकारियों की रिक्तियां जल्द भर दी जाएंगी। आयोग ने दो किस्तों में 35 ग्रामीण विकास पदाधिकारियों की अनुशंसा की है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन्हें तैनात किया जाएगा।

बिना ट्रेन चलाए, अब नहीं मिलेगा फ्री एक्सीडेंट अवार्ड

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद : ऑफिस में बैठकर काम करने वालों को अब फ्री एक्सीडेंट अवार्ड नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने चालक, गार्ड के अलावा स्टेशन मास्टर, शंट मैन, शंटर, केबिन मैन को यह अवार्ड देने का आदेश दिया है। यह अवार्ड एक लाख रुपये से अधिक का होगा। रेलवे ने ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए चालक, गार्ड को फ्री एक्सीडेंट अवार्ड देने की व्यवस्था कर रखी है। यह अवार्ड ट्रेन नहीं चलाने वाले और ऑफिस में बैठकर काम करने वाले कर्मचारी को मिल रहा था। सुरक्षित ट्रेन संचालन में स्टेशन मास्टर, केबिन मैन, शंटर, शंट मेन की भूमिका होती है। उन्हें यह अवार्ड नहीं मिलता था।

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) के पदाधिकारियों ने 28 मार्च को रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया था। चेयरमैन ने ट्रेन संचालन से जुड़े सभी कर्मियों को अवार्ड देने और अयोग्य को अवार्ड देने पर रोक लगाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अधिशासी निदेशक/सुरक्षा (एम) डिम्पी गर्ग ने 11 नवंबर को पत्र जारी कर फ्री एक्सीडेंट अवार्ड देने के नियम में बदलाव कर दिया। अवार्ड पाने वाले कर्मियों का ट्रेन संचालन रिकार्ड में दर्ज होना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के बाद अवार्ड की राशि वेतन के आधार पर तय होगी, प्रत्येक कर्मचारी को एक लाख से अधिक का अवार्ड मिलेगा।

नई व्यवस्था में ट्रेन संचालन से जुड़े कर्मचारी की मौत हो जाती है तो यह अवार्ड उसकी पत्नी या आश्रित को दिया जाएगा। अपर मंडल रेल प्रबंधक एमएस मीना ने बताया कि फ्री एक्सीडेंट अवार्ड से संबंधित नए आदेश मिल गया है। इसे लागू करने का काम कार्मिक विभाग द्वारा किया जा रहा है।

ऑडियो-वीडियो जांच के लिए हैदराबाद भेजे हैं तो कैसे हो रहे वायरल : हाई कोर्ट

नईदुनिया, इंदौर

मध्य प्रदेश के इंदौर में बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में हाई कोर्ट में चल रही जनहित याचिकाओं में बुधवार को सुनवाई हुई। एक आरोपित की तरफ से याचिकाओं में इंटरविनर आवेदन प्रस्तुत हुआ। इसमें कहा गया कि मामले से जुड़े ऑडियो-वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। इनसे प्रकरण की सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है। इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह बताए कि जब ऑडियो-वीडियो जांच के लिए हैदराबाद भेजे हैं तो ये वायरल कैसे हो रहे हैं।

हनी ट्रैप मामला

हनी ट्रैप मामले में तीन जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट में चल रही हैं। पहली याचिका एडवोकेट निधि वोहरा ने दायर की है, दूसरी एडवोकेट डॉ. मनोहरलाल दलाल व एडवोकेट लोकेंद्र जोशी ने। इसी तरह तीसरी जनहित याचिका में एडवोकेट धर्मेंद्र चेलावत पैरवी कर रहे हैं। तीनों ही याचिकाओं में एसआइटी के गठन और इसके प्रमुख को बार-बार बदलने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।

दो दिसंबर को होगी सुनवाई : मामले की एक आरोपित मोनिका ने एडवोकेट सुदर्शन जोशी के माध्यम से बुधवार को याचिकाओं में इंटरविनर आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें कहा है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि मामले से जुड़े ऑडियो-वीडियो जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद स्थित लैब भेजे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया व अन्य मीडिया माध्यमों पर हनी ट्रैप से जुड़े ऑडियो-वीडियो वायरल हो रहे हैं। जस्टिस एससी शर्मा और शैलेंद्र शुक्ला ने शासन को आदेश दिया कि वह इस मामले में जवाब दे। कोर्ट अब दो दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अन्य मुद्दों के साथ इस मुद्दे पर भी सुनवाई करेगी।

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-नोएडा, सी 03बी, सेक्टर-55, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)]
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
[illegible]
अचल संपत्ति का विवरण
[illegible]
दिनांक: 22.11.2019, स्थान: नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-नोएडा, सी 03बी, सेक्टर-55, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)]
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
[illegible]
अचल संपत्ति का विवरण
[illegible]
दिनांक: 22.11.2019, स्थान: नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

गिरी गाज

अशोक खेमका ने ट्वीट कर अपने तबादले पर उठाए सवाल, लिखा ईमानदारी का इनाम जलालत है

हरियाणा के आइएएस खेमका का 53वां तबादला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के चर्चित आइएएस अधिकारी डॉ. अशोक खेमका पर फिर तबादले की गाज गिरी है। घपले-घोटाले उजागर करने के लिए प्रसिद्ध खेमका को राज्य की गठबंधन सरकार का पहला और 28 साल के कॅरियर में 53वां तबादला मिला है। भाजपा के पांच साल के पहले कार्यकाल में उनका छह बार तबादला हुआ, जबकि दस साल के कांग्रेस शासन में उन्होंने 22 स्थानांतरण झेले।

कोलकाता में जन्मे खेमका ने आइआइटी खड़गपुर से 1988 में बीटेक करने के बाद कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए और वकालत भी कर रखी है। हरियाणा में चौ. बंसीलाल से लेकर मनोहर लाल तक, कोई ऐसी सरकार नहीं बची, जिसमें खेमका का व्यवस्था से सीधे टकराव नहीं हुआ। भजनलाल, ओमप्रकाश चौटाला हों या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हर राज में खेमका सीधे व्यवस्था से टकराते रहे। गुरुग्राम में रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे से जुड़ी जांच के कारण वह सुर्खियों में रहे। 'भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध' के लिए खेमका को वर्ष 2011 में आइएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के साथ एसआर जिंदल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

डॉ. अशोक खेमका। फाइल

> फिर तबादला। लौट कर फिर वहीं। कल संविधान दिवस मनाया गया। आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं नियमों को एक बार और तोड़ा गया। कुछ प्रसन्न होंगे। अंतिम ठिकाने जो लगा। ईमानदारी का इनाम जलालत।
> **-आइएएस अशोक खेमका का ट्वीट**

पिछले साल नवंबर में तत्कालीन राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी से सरकारी वाहन के विवाद के बाद खेमका को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाकर खेल एवं युवा मामले विभाग में नियुक्त किया गया था। तब यह महकमा अनिल विज के पास था। खेल पॉलिसी पर विवाद के बाद खेमका को विगत मार्च में खेल महकमे से हटाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भेजा गया था। इस विभाग के मंत्री भी अनिल विज ही थे। इस बार खेमका को अभिलेख, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभागों का प्रधान सचिव बनाया गया है। यह महकमा जजपा (जननायक जनता पार्टी) कोटे से स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अनूप धानक के पास है।

प्रदीप कासनी ने झेले थे 70 तबादले : वैसे हरियाणा में अभी तक सर्वाधिक तबादले झेलने वाले अधिकारियों की बात करें तो प्रदीप कासनी सबसे ऊपर हैं। फरवरी 2018 में सेवानिवृत्त होने से पहले उनका 70 बार तबादला हुआ था। 1997 बैच के आइएएस प्रदीप कासनी पहले एचसीएस थे। उनकी पत्नी नीलम प्रदीप कासनी भी सीनियर आइएएस रही हैं और राज्यपाल के एडीसी पद से रिटायर हुई हैं। सेवानिवृत्ति के बाद प्रदीप ने अशोक तंवर के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली, लेकिन तंवर के खुद कांग्रेस छोड़ने के बाद वह नेपथ्य में हैं।

दैनिक जागरण
हर समस्या अपने समाधान के साथ ही उत्पन्न होती है

अवसरवादी अघाड़ी

महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भले ही अपने साझा मोर्चे को महा विकास अघाड़ी का नाम देना पसंद किया हो, लेकिन इसमें संदेह है कि यह सरकार विकास के प्रति समर्पित हो सकेगी। शिवसेना नेताओं ने सरकार गठन के पहले ही जिस तरह बुलेट ट्रेन के साथ मेट्रो ट्रेन संबंधी परियोजनाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं उससे यह नहीं लगता कि राज्य का समुचित विकास इस मोर्चे की प्राथमिकता बन पाएगा। वैसे भी महा विकास अघाड़ी के जरिये फिलहाल परिवारवाद की राजनीति का ही विकास होता दिख रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि शिवसेना ने भाजपा से इसीलिए नाता तोड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर आमादा थे। हालांकि उनका यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अनुभवहीन आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में सरकार का गठन करने से इन्कार किया। इसके बावजूद शिवसेना को परिवारवाद की राजनीति को पोषित करने का मौका तो मिल ही रहा है। ऐसा ही मौका शरद पवार को भी मिल रहा है। वह केवल पर्दे के पीछे से सरकार ही नहीं चलाएंगे, बल्कि परिवारवाद को भी पोषित करेंगे। यदि कुछ घंटों के लिए शरद पवार से छिटककर भाजपा से जा मिले अजीत पवार फिर से नेता विधायक दल बनने के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री भी बन जाएं तो हैरत नहीं। जो भी हो, अजीत पवार को माफ कर उनकी घर वापसी का जैसा स्वागत हो रहा है उससे यह साफ है कि भाजपा ने एक तो उन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और दूसरे, इसकी परवाह नहीं की कि अगर वह अपने वादे पर खरे नहीं उतरे तो क्या होगा?

अजीत पवार की ओर से किया गया यह दावा भाजपा के लिए एक छलावा ही साबित हुआ कि वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हैं। कहां तो वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को अपने साथ बता रहे थे और कहां दस विधायक भी उनके साथ खड़े नहीं दिखे। सवाल केवल यह नहीं है कि भाजपा ने उन पर भरोसा क्यों किया, बल्कि यह भी है कि उन पर भरोसा करने की जरूरत ही क्या थी? आखिर भाजपा ने इतनी आसानी से यह कैसे भुला दिया कि अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों का उल्लेख खुद उसके नेताओं की ओर से किया जाता था? इसका कोई मतलब नहीं कि सरकार गंवाने और साथ ही बदनामी मोल लेने के बाद अजीत पवार से समर्थन लेने पर अफसोस जताया जा रहा है। भाजपा को अफसोस करने से ज्यादा अपनी गलतियों पर गंभीरता से गौर करना चाहिए।

गांव का विकास

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के साथ ही उनके कार्यभार संभालने का क्रम शुरू हो गया है। इस कड़ी में ग्राम पंचायतों की पहली बैठक गुरुवार को होने जा रही है। जाहिर है कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर गांवों के विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। वजह यह कि राज्य में गांव ही पिछड़ेपन का सबसे अधिक दंश झेल रहे हैं। असल में विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में गांवों की दशा किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा एवं रोजगार समेत मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण बेहतर भविष्य की तलाश में वहां से पलायन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य गठन से लेकर अब तक 1702 गांव जनशून्य हो चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद में ऐसे गांव भी हैं जहां लोगों को अंगुलियों पर गिना जा सकता है। खुद पलायन आयोग की रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है। आयोग की ओर से सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि अगले पांच साल तक गांवों के विकास पर ही मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए। इस परिदृश्य में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सबसे अधिक बढ़ गई है। अब उन्हें ही तय करना है कि वे गांव का कैसा विकास चाहते हैं। यानी, यह उनकी गांव के चहुंमुखी विकास के प्रति सोच प्रदर्शित करने के साथ ही इसके लिए कदम बढ़ाने के कौशल का परिचायक भी होगा। सभी को साथ लेकर उन्हें गांव के विकास की योजनाओं का खाका खींचकर अंतिम व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचाने के लिए कमर कसनी है। वर्तमान में इसके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। कारण यह कि राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार का फोकस भी गांवों के विकास पर है। केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (जीपीडीपी) इसमें अहम भूमिका निभाएगा, जिसके आधार पर गांव के विकास की योजनाएं तैयार होंगी। ये योजनाएं ग्राम पंचायतों को ही तय करनी हैं और फिर इनके जीपीडीपी पोर्टल में अपलोड होने पर सरकारें बजट का आवंटन करेंगी। लिहाजा, पंचायत प्रतिनिधियों को इस मोर्चे पर अपना कौशल दिखाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं वे अपने-अपने गांवों के लिए जुटा सकें। साथ ही राज्य सरकार के समक्ष गांव के विकास का खाका रखना होगा। तभी अपेक्षित परिणाम हासिल हो पाएंगे।

पलायन का दंश झेल रहे गांवों के विकास के लिए अब नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर दारोमदार है। उन्हें यह दायित्व पूर्ण मनोयोग से निभाना होगा

सत्ता के साथ साख भी गई

प्रदीप सिंह

यह साफ है कि भाजपा ने अजीत पवार की ताकत का तो गलत अंदाजा लगाया ही, शरद पवार को भी बहुत हल्के में ले लिया

आजमाई हुई कहावत है-सहज पके सो मीठा होय। महाराष्ट्र में सत्ता के उतावलेपन में भाजपा ने इस कहावत से जुड़ी सीख को अनदेखा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि साफ-सुथरी और ईमानदार छवि वाले उसके युवा नेता देवेंद्र फड़नवीस बलि का बकरा बन गए। महाराष्ट्र में जो हुआ उसके लिए सिर्फ फड़नवीस ही दोषी नहीं हैं। पिछले डेढ़ साल में भाजपा ने दूसरी बार मुंह की खाई है। भाजपा ने कर्नाटक की गलती से कोई सबक नहीं सीखा और गलत घोड़े पर दांव लगाकर औंधे मुंह गिर गई। वह भूल गई कि उसका मुकाबला राजनीति के धुरंधर शरद पवार से था। शरद पवार ने फड़नवीस को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घेर कर ढेर किया। 80 घंटे, जी हां सिर्फ 80 घंटे में भाजपा ने महाराष्ट्र में चुनाव बाद अर्जित की हुई सारी सद्भावना गंवा दी। महाराष्ट्र में जनादेश भाजपा-शिवसेना गठबंधन को मिला था, लेकिन नतीजे के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा कुलांचे मारने लगी। आखिरकार उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया। बीते शनिवार की सुबह लोग सोकर ही उठे होंगे तो पता चला कि महाराष्ट्र में फड़नवीस मुख्यमंत्री और राकांपा के अजीत पवार उपमुख्यमंत्री बन गए हैं। राजनीतिक हलकों में इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। राज्यपाल और प्रधानमंत्री के इस कदम की आलोचना हुई तो भाजपा की ओर से पूछा गया कि क्या कोई गैर संवैधानिक काम हुआ है? इसके पहले जब फड़नवीस ने राज्यपाल को सूचित किया था कि शिवसेना के अलग हो जाने के बाद वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं तब वह नायक और शिवसेना खलनायक नजर आ रही थी।

राजनीति में महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसमें जमीनी हकीकत के साथ कोई मेल तो होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में लोकलाज भी कोई चीज होती है। कोई पूछ सकता है कि लोकलाज की अपेक्षा हमेशा भाजपा से ही क्यों? वाजिब सवाल है। भाजपा से यह सवाल इसलिए, क्योंकि वह राजनीति में सबसे अलग होने का दावा करती है। जिस दिन भाजपा ऐसा दावा करना छोड़ देगी, लोग भी पूछना छोड़ देंगे। भाजपा ने जो किया उसे गुनाह बेलज्जत कहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की बात और भ्रष्टाचार के आरोप में आकंठ डूबे अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात किसके गले उतरती? इसका यह भी मतलब है कि भाजपा अपने नए मतदाताओं के मिजाज को या तो समझ नहीं रही या उसकी परवाह नहीं करती। जो नए और युवा लोग भाजपा से जुड़े हैं वे एक हद तक नैतिकतावादी हैं। वे टैक्स चोरी करने वाली जमात जैसे नहीं हैं। ईमानदारी से टैक्स देने और देश के बारे में शिद्दत से सोचने वाले लोग हैं। यह विरोधाभास उनके गले नहीं उतरेगा।

अवधेश राजपूत

इससे इन्कार नहीं कि व्यावहारिक राजनीति में समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन आखिर आप कोई लक्ष्मण रेखा खींचेंगे या नहीं? जो दूसरों ने किया या जो कर रहे हैं वही आप भी करेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? सवाल यह भी है कि आपने अपनी पहली गलती (कर्नाटक) से कोई सबक सीखा क्या? जिस काम से आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा जोड़ दी उसमें ऐसा कच्चा खेल खेले ही क्यों? जो नेता अपनी पार्टी के विधायकों के दस्तखत का गलत इस्तेमाल कर रहा हो उस पर भरोसा क्यों कर लिया? कोई प्लान बी क्यों नहीं था? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पार्टी को देर-सबेर देना पड़ेगा।

भाजपा ने इस पूरे प्रकरण में अजीत पवार की ताकत का तो गलत अंदाजा लगाया ही, शरद पवार को भी बहुत हल्के में ले लिया। भाजपा की रणनीतिक गलतियों का सिलसिला विधानसभा चुनाव से ही शुरू हुआ। पहली गलती शिवसेना से चुनावी गठबंधन करना। ऐसी पार्टी से गठबंधन किया जो पांच साल तक प्रदेश नेतृत्व से लेकर प्रधानमंत्री तक को गरियाती रही। दूसरी गलती शरद पवार को ईडी का नोटिस भेजकर एक खुले दरवाजे को बंद कर दिया। वह भूल गई कि 2014 में भाजपा की सरकार को सदन में पवार की राकांपा ने ही बचाया था। तीसरी बड़ी गलती, सत्ता का उतावलापन। उसे चुपचाप किनारे बैठकर तीनों पार्टियों का सत्ता का खेल देखना चाहिए था। तीन पार्टियों की सरकार अपने अंतर्विरोधों के बोझ तले स्वयं ही दब जाती। भाजपा ने उतावलेपन में इन तीनों पार्टियों की केमिस्ट्री और मजबूत कर दी। इस तरह भाजपा ने सत्ता और साख, दोनों गंवाई।

महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए एक महीने चले इस प्रकरण के कई सबक हैं। सबसे बड़ा सबक भाजपा के लिए है। चुनाव में भी जीतेंगे और चुनाव के बाद भी जीतेंगे, यह अपवाद हो सकता है, नियम नहीं। पार्टी के पुराने नेताओं को हाशिये पर धकेलने और दूसरे दलों से लोगों को लाने का अनुपात तय होना चाहिए। प्रदेश में किसी एक नेता का नेतृत्व स्थापित करने के लिए पुराने नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकालना नुकसानदेह हो सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा इसके ताजा उदाहरण हैं। ये बातें उस समय दिखाई नहीं देतीं जब आप लगातार जीत रहे हों। जीत आपको मुगालते में रखती है। उस समय सब अच्छा ही अच्छा दिखता है। पराजय रुककर सोचने, संभलने का मौका देती है। यह सोचने का भी कि कहां क्या गलती हुई और उसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए?

उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा को शरद पवार के पर लगे तो वह मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए। अब आगे का रास्ता उन्हें खुद ही तय करना पड़ेगा। गठबंधन सरकार चलाना और वह भी परस्पर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों की, बहुत कठिन काम है। फिर ठाकरे को कोई प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है। उद्धव की यही कमजोर नस शरद पवार की ताकत बढ़ाएगी। इस पूरे प्रकरण में शरद पवार पहले से अधिक ताकतवर होकर उभरे हैं। सरकार का रिमोट कंट्रोल पवार के हाथ में होगा। यह इस सरकार की ताकत भी है और कमजोरी भी। 80 घंटे की सरकार बनाकर भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में शरद पवार का कद बढ़ा दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में ईडी का नोटिस मिलने के बाद और फिर वैकल्पिक सरकार बनवाकर अपनी ताकत का अहसास करा दिया। पवार के राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की धुरी बनने का रास्ता खुल गया है। पवार और विपक्ष को यह मौका भाजपा की एक गलती ने दिया है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो यह अनुभवी बल्लेबाज को जीवनदान देने जैसा है। अब पवार और बाकी विपक्षी दलों पर निर्भर है कि वे इसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं?

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

सवाल खड़े करती आंकड़ों की पहरेदारी

डॉ. अरविंद चतुर्वेदी

सही सूचनाओं के जनता तक पहुंचाने के मार्ग में अवरोध खड़े करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ के उपभोग आंकड़ों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ सरकार पर इन आंकड़ों को जारी करने का दबाव बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये आंकड़े औसत भारतीय उपभोक्ता द्वारा व्यय में कमी की पुष्टि करते हैं। इसी कारण सरकार इन्हें जारी करने के बजाय उन पर कुंडली मारकर बैठ गई है ताकि उसकी किरकिरी होने से बच जाए। इस बीच कुछ लोग इन आंकड़ों की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। यह सही है कि एनएसएसओ के आंकड़े तैयार करने में कभी-कभार इतना समय लग जाता है कि उनकी सामयिकता एवं उपयोगिता ही संदिग्ध हो जाती है, फिर भी उनसे तमाम रुझानों की दशा-दिशा मिल जाती है। चूंकि आंकड़े सरकार को असहज कर सकते हैं तो इसी कारण वह इन्हें सार्वजनिक करने से कतरा रही है।

देश में प्रमुख आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण एवं प्रकाशन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन संस्थाएं करती हैं। इनमें एनएसएसओ और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रमुख संस्थाएं हैं। हाल में दोनों का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। प्रत्येक पांच वर्ष बाद यह विभाग उपभोक्ता खर्च के आंकड़ों का एक व्यापक सर्वेक्षण करता है। उसमें देश भर के गांव, कस्बों और शहरों से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। फिर इनका राष्ट्रीय स्तर पर आकलन किया जाता है। इससे पता लगता है कि भारतीय लोग किस मद में कितना खर्च कर रहे हैं? इसके साथ ही यह भी मालूम पड़ता है कि पहले की तुलना में खर्च घटा है या बढ़ा है? इससे भारतीयों की आय-व्यय क्षमता में उतार-चढ़ाव का अंदाजा लगता है।

ऐसे आंकड़ों के सहारे ही सरकार राज्यवार गरीबों की संख्या, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, कुल सकल घरेलू आय, उपभोक्ता व्यय में परिवर्तन की दिशा आदि तय करती है। सरकार की योजना निर्माण में इन आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्ष 2004-05 के बाद एक सर्वेक्षण 2009-10 में किया गया था। जब इन आंकड़ों के चलते गरीबी रेखा की सीमा को लेकर विवाद छिड़ा तो उक्त आंकड़े संदिग्ध मानकर वापस ले लिए गए। इसके बाद सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उस समिति ने दोबारा आंकड़े जुटाकर गरीबी रेखा की नई परिभाषा निर्धारित की थी। फिर 2011-12 के बाद उपभोक्ता व्यय का कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं हुआ। इसीलिए 2017-18 के आंकड़ों की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी ताकि पता लग सके कि संप्रग सरकार की तुलना में राजग सरकार के दौरान उपभोक्ता व्यय में क्या बदलाव आया है? वैसे इन आंकड़ों की उपयोगिता यहीं तक सीमित नहीं थी। इनके आधार पर गरीबी रेखा का आकलन, गरीबों की संख्या, गरीबी उन्मूलन योजनाओं की समीक्षा और उनमें भविष्य की राह तैयार करने की रणनीति भी तैयार की जानी थी। हमारे देश में सकल राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका तो माइक्रो लेवल पर आंकड़े इकट्ठे करने से जुड़ा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा इसकी गणना होती है। दूसरा तरीका उपभोक्ता व्यय से जुड़ा है। उपभोक्ता व्यय की तस्वीर से स्पष्ट हो जाता है कि सकल राष्ट्रीय आय का वास्तविक स्तर क्या है। इसमें कोई भी कमी किसी सरकार के प्रदर्शन का एक अहम पैमाना मानी जाती है।

2017-18 के सर्वेक्षण के कुछ आंकड़े बाहर आ गए हैं। इनके मुताबिक 2017-18 में उपभोक्ता व्यय 2011-12 की तुलना में 3.7 प्रतिशत कम हुआ है। इन आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय जो छह वर्ष पहले 1501 रुपये था, 2017-18 में घट कर 1446 रुपये हो गया। इस गिरावट को नोटबंदी से भी जोड़ा जा रहा है। इससे एक निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता है कि नोटबंदी के कारण लोगों की क्रय-व्यय क्षमता में कमी आई। यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। सरकार नहीं चाहेगी कि उपभोक्ता व्यय में आई कमी के तार नोटबंदी के साथ जोड़े जाएं। इससे उसके आलोचकों को बैठे-बिठाए एक मौका मिल जाएगा।

वैसे देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आंकड़े छिपाने या उनमें हेराफेरी के आरोप पिछली सरकारों पर भी लगते रहे हैं। पहले भी राष्ट्रीय सकल आय की गणना के संबंध में विवाद हुए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों ने इस विवाद के कारण इस्तीफे भी दिए थे। खुद मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके अरविंद सुब्रमण्यन ने अपने पद से हटने के बाद आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। श्रम शक्ति और रोजगार संबंधी आंकड़ों पर भी पिछले महीनों में सवाल उठाए गए। उस समय भी सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए थे।

हालांकि पिछले कई वर्षों के दौरान केंद्र सरकार राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के तौर-तरीकों, विश्लेषण और तकनीक में सुधार की बातें करती रही हैं, मगर जमीनी हकीकत इससे उलट है। आंकड़ों की विश्वसनीयता, शुद्धता, गुणवत्ता एवं सामयिकता को लेकर भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का पुनर्गठन करना होगा। उसे न्यायिक अधिकार देकर सशक्त बनाने के प्रयास करने होंगे। साथ ही नई तकनीक का प्रयोग भी इस दिशा में खासा उपयोगी साबित हो सकता है। भले ही 2017-18 के आंकड़ों से सरकार की कुछ मोर्चों पर कमजोरी उजागर होती, लेकिन उनके आधार पर नई नीतियों का खाका तो तैयार होता। इन आंकड़ों को 2009-10 की तरह अमान्य घोषित करके 2011-12 की तरह नए सर्वेक्षणों के परिणाम की प्रतीक्षा की जा सकती थी। अब नया सर्वेक्षण 2020-21 में होगा। तब तक हमारे पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। इससे तमाम योजनाओं के लिए सही सूचनाएं एवं जानकारियां नहीं मिल पाएंगी। इसे किसी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। सही सूचनाओं के जनता तक पहुंचाने के मार्ग में अवरोध खड़े करने से सरकार की साख पर आंच आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति से बचा जाना चाहिए था।

(लेखक इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सांख्यिकी विभाग के डीन रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संवाद की महत्ता

सामाजिक होने के क्रम में मनुष्य द्वारा संवाद स्थापित करने की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संवाद के माध्यम से दो व्यक्तियों में विचारों का आदान-प्रदान होता है। मनुष्य के विचारों में असहमति सामान्य है, किंतु स्वस्थ वैचारिक संप्रेषण में असहमति के प्रति पूरी सहमति होनी चाहिए। इस बात को हम बेहतर समझते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का वैचारिक स्तर और सोचने की दृष्टि भिन्न होती है। इन्हीं आधारों पर वह किसी तथ्य के प्रति समर्थन अथवा विरोध करता है। संभव है कि उसके विचारों से सहमत न हुआ जाए, किंतु उसके विचार प्रकट करने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

सहमति और असहमति स्वस्थ संवाद की अनिवार्य आवश्यकता है। इसमें समस्या तब पैदा होती है जब वैचारिक मतभिन्नता के चलते मतभेद, मनभेद का रूप धारण कर लेते हैं। इस स्थिति में मनुष्य संवाद स्थापित करने से कतराने लगता है वह भी सिर्फ इस आधार पर कि विचार भिन्न हैं। संवादहीनता से दोनों को क्षति होती है। आज के दौर में मनुष्य अपनी प्रशंसा का इतना आदी हो चुका है कि वह अपने विचारों के प्रति असहमति को स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी सोच वाले मनुष्य के सम्मुख अन्य व्यक्ति अपने विचारों का खुलकर प्रदर्शन करने से संकोच करने लगते हैं। यह अवस्था उसे संवाद रिक्तता की स्थिति में ला खड़ा करती है।

घर-परिवार, दोस्तों में हमें अक्सर यह सुनने को मिलता है कि वह मुझसे बात नहीं करता तो मैं उससे बात क्यों करूं! जब यह सोच मनुष्य के मस्तिष्क में अपना घर बना लेती है तो इससे दो लोगों के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में यदि हम स्वयं उस व्यक्ति विशेष के साथ चर्चा की पहल करें तो बात बन सकती है। एक पहल द्वारा दूरियों को निकटता में बदला जा सकता है। संवाद तमाम गलतफहमियां दूर करता है। संवाद की आवश्यकता सिर्फ व्यक्ति या परिवार में ही नहीं, बल्कि संस्था और समुदाय में भी होती है। जरूरी है कि संवाद सदैव द्विपक्षीय हो ताकि विचारों का आदान-प्रदान चलता रहे।

सौरभ जैन

मिलावट की मार से त्रस्त

कपिल अग्रवाल

खराब गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पाद सेहत के लिए खतरे के साथ ही वैश्विक बाजार में भी साख गिराने का काम कर रहे हैं

भारतीय खाद्य संरक्षण व मानक ब्यूरो (एफएसएसएआइ) द्वारा में दूध की शुद्धता व गुणवत्ता को लेकर किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 40 फीसद से ज्यादा नमूने खरे नहीं उतर पाए। इनमें खुले में बिकने वाले दूध के साथ ही कई दिग्गज कंपनियों के पैकेटबंद उत्पाद भी शामिल थे। सभी में कीटनाशकों, प्रिजरवेटिव्स व अफ्लाटोक्सिन-एम जैसे हानिकारक तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों से ज्यादा पाई गई। इससे तमाम नई बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ गई है। केवल दूध ही नहीं, लगभग सभी प्रकार के फास्ट फूड व शीतल पेय समेत अधिकांश खाद्य पदार्थों के मामले में कमोबेश यही कहानी है। टमाटर, सेब, अमरूद, आलू आदि तमाम खानपान की वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान खोती जा रही हैं और रूस, ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे अनेक छोटे-बड़े देश वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराते जा रहे हैं।

भारत सरकार विभिन्न खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांच पर करोड़ों रुपये खर्च करती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जैसी आठ से भी ज्यादा सरकारी एजेंसियां इस काम में लगी हैं। फिर भी इसके संतोषजनक नतीजे नहीं मिल रहे।

वास्तव में यह मुनाफाखोरी की बीमारी है जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। घरों में गाय या भैंस पालने वाले यह बखूबी जानते हैं कि गर्मी में दूध को बिना उबाले अगर दो-तीन घंटे भी बाहर छोड़ दें तो वह खराब हो जाता है। दूसरी ओर थैलियों में बंद रसायनयुक्त दूध कई-कई दिनों तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कई जगहों पर दूध प्रदूषित चारे से पोषित पशुओं को हानिकारक इंजेक्शन लगाकर निकाला जाता है। इससे मानव शरीर में स्नायुतंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मस्तिष्क में थक्का (क्लॉटिंग) बनने की बीमारी हो जाती है। इंजेक्शन लगाने से पशु प्रारंभ में बहुत जल्दी और ज्यादा दूध देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। देश में इनकी रोकथाम व निरीक्षण के लिए कृषि मंत्रालय की देखरेख में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि प्रयोगशालाएं, तमाम संस्थानों के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा रसायन व उर्वरक मंत्रालय के परीक्षण केंद्रों समेत वैज्ञानिकों की लंबी चौड़ी फौज है। इस संबंध में प्रत्येक वर्ष एक बड़ी धनराशि भी खर्च की जाती है, लेकिन शायद उनकी कार्यप्रणाली दुरुस्त न होने के कारण जनता को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता।

देश को इससे तीन तरह का नुकसान हो रहा है। पहला, कीटनाशकों के बेजा इस्तेमाल से पर्यावरण दूषित होता है। दूसरा आम लोगों को विषाक्त खाद्य पदार्थ मिलते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और तीसरा खराब गुणवत्ता के कारण निर्यात के अवसरों से हाथ गंवाना पड़ रहा है। यही कारण है कि भारत के दुग्ध उत्पादों का निर्यात लगभग नगण्य है। इसकी तुलना में ब्राजील, सऊदी अरब, आयरलैंड और बेलारूस जैसे कई छोटे-बड़े देश इस मामले से भारत के मीलों आगे हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अवसरवादी राजनीति का दौर

राजनीतिक नैतिकता का बेसुरा राग शीर्षक लेख के तहत राजीव सचान ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक दलों में नाटकबाजी चली उसे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला बताया। देश में राजनीतिक नैतिकता अब रह कहां गई है। गठबंधन की राजनीति में विभिन्न विचारधाराओं का समावेश होता है। ये आपसी कलह को जन्म देती हैं। इसकी चपेट में राष्ट्रीय स्थिरता कभी भी खतरे में आ सकती है। देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नजर नहीं आती जिसमें अवसरवादी नेता न हों। आज भारत की राजनीति साम, दाम, दंड और भेद की राजनीति की परंपरा का भी रुख कर चुकी है। हां, इनमें से अभी दंड का कोई अनुसरण नहीं करता, लेकिन लोकतंत्र में इस परंपरा का एक भी भाग शामिल नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में लगभग तीन दशक पुराने भाजपा-शिवसेना के गठबंधन का टूटना दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का मतदाता यह जानता है कि यह दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिवसेना ने अपनी विचारधारा के विपरीत कांग्रेस और राकांपा से हाथ मिलाने की कोशिश में भी यह दर्शाने की कोशिश की है कि उसे हर हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम से भाजपा को भी सबक लेना चाहिए और उसे क्षेत्रीय दलों के बहुत ज्यादा भरोसे नहीं बैठना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

प्याज को लेकर कदम उठाए सरकार

प्याज ने आम जनता के आंसू निकाल दिए हैं। कहीं-कहीं प्याज 100 किलो बिक रहा है। भाव में 3 दिनों में 20 से 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और यह भी अनुमान है कि 15 दिसंबर से पहले प्याज की कीमतों में कमी नहीं आ सकती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात में लगातार बारिश के कारण प्याज की फसल खराब हुई है। इससे दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्याज आयात का फैसला तो किया गया है, लेकिन उससे पहले भी कुछ राहत के उपाय करने होंगे।

विजय किशोर तिवारी, शिक्षक, नई दिल्ली

जनादेश का अपमान

आखिरकार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जिद पूरी हो गई। भले ही इसके लिए ऐसी पार्टियों से गठजोड़ करना पड़ा, जिनके खिलाफ वह चुनाव लड़े थे। कायदे से राज्य में भाजपा-शिवसेना सरकार बननी चाहिए थी, क्योंकि जनादेश इन दोनों के गठबंधन को मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में दोनों ही दल अलग दिशा में चल दिए। यह एक तरह से जनादेश का अपमान है।

daleepkpatpatia@gmail.com

पवार का कद बढ़ा

राजनीतिक धोखा कहें या भाजपा का अति-आत्मविश्वास या फिर राजनीति की तिकड़मबाजी, लेकिन इस अनैतिक राजनीतिक रस्साकशी में 105 विधायकों वाली सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की डोर से दूर कर दिया गया। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार का महाराष्ट्र व केंद्रीय राजनीति में कद बढ़ गया है। तीन धुरविरोधी दलों के मिलन से बना महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं आदि को आगे किस दिशा में ले जाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। भाजपा द्वारा सरकार बनाना एक बड़ी व ऐतिहासिक भूल मानी जाएगी, जोकि शायद शरद पवार की राजनीति का शिकार हो गई।

दीपक गौतम, सोनीपत

सिद्धांतविहीन राजनीति

महाराष्ट्र की राजनीति से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि राजनीतिक दलों में विचारधारा का महत्व नगण्य हो चुका है। दूसरी तरफ अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में नेतागण जनमत का अपमान करने से भी नहीं चूकते। हालांकि एक राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता का उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार होता है, किंतु सिद्धांतविहीन राजनीति कतई उचित नहीं है। ऐसे उदाहरण भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता व मजबूती तो प्रदान नहीं करते, अपितु इसके उलट संवैधानिक मूल्यों की नित बलि देते प्रतीत होते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है कि बहुमत न मिलने की स्थिति में जनमत की स्वाभाविक अभिव्यक्ति शासन में किस प्रकार से हो।

अंजन मिश्रा, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

6.1 फीसद होने का अनुमान व्यक्त किया है आइएमएफ ने भारत में आर्थिक वृद्धि दर का। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक ने भी भारत में लगभग इसी के आसपास यानी 6 प्रतिशत वृद्धि दर होने का अनुमान जताया है।

आजकल

सुस्ती का मुकाबला करती अर्थव्यवस्था

डॉ. अश्विनी महाजन
एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं समेत कई अन्य संगठनों एवं संबंधित विशेषज्ञों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती और धीमेपन को लेकर चिंता जताई जा रही है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी के कारण चिंतित होना भी स्वाभाविक ही है। लेकिन क्या यह अर्थव्यवस्था में मंदी की ओर इशारा करती है या फिर यह धीमापन अल्पकालिक है? तथ्यों की पड़ताल बताती है कि यह अल्पकालिक है और जल्द ही इसमें सुधार आने की उम्मीद है

देश में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बीते दिनों दो प्रकार के परस्पर विरोधी बयान आते रहे हैं। एक ओर लोगों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है या आने का आगाज दे रही है। वे इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे आइएमएफ, विश्व बैंक और मूडीज सरीखी रेटिंग एजेंसियों का हवाला देते हैं। उल्लेखनीय है कि आइएमएफ द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्रोथ की संभावनाओं को घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। वहीं विश्व बैंक ने भी इसे 6.0 प्रतिशत पर आंका है। मूडीज ने तो भारत की साख रेटिंग को 'स्थिर' से घटाकर 'नकारात्मक' कर दिया है और उसके बाद एजेंसी ने 2019 के लिए ग्रोथ की संभावनाओं को अपने पूर्व के 5.8 प्रतिशत के लक्ष्य को घटाकर 5.6 प्रतिशत कर दिया है।

दूसरी ओर सरकार समेत कई अन्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ग्रोथ में महज कुछ धीमापन आया है, लेकिन मंदी की कोई आशंका नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने अपने लिखित बयान में कहा कि ग्रोथ में आए धीमेपन के बावजूद आइएमएफ के अक्टूबर 2019 के वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में भारत को जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। इस बीच, मुद्रास्फीति जो लंबे समय से काफी कम चल रही थी, सितंबर माह के 3.99 प्रतिशत से आगे बढ़ती हुए अक्टूबर 2019 में 4.62 प्रतिशत रिकार्ड की गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति के कारण हुई। दरअसल अक्टूबर में खाद्य पदार्थों में खुदरा मुद्रास्फीति 7.89 प्रतिशत रिकार्ड की गई, जो पिछले माह 5.1 प्रतिशत ही थी।

मुद्रास्फीति में आए इस उछाल से प्रभावित होकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया है कि अर्थव्यवस्था 'स्टेगफ्लेशन' यानी 'मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक ठहराव' की स्थिति में प्रवेश कर सकती है। हालांकि आम भाषा में 'मुद्रास्फीति' कीमतों में वृद्धि को कहते हैं, लेकिन आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार कीमतों में हर वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते। किसी एक माह या एक वर्ष या दो-तीन वर्षों तक की कीमत वृद्धि को भी मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता। कीमत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहने के लिए उसे लंबे समय तक भारी वृद्धि होना पड़ेगा। यहां समझना होगा कि मोदी सरकार के आने के बाद कीमतों में वृद्धि, ना केवल घटती गई, एक समय तो यह तीन प्रतिशत से भी कम हो गई।

कम मुद्रास्फीति से परेशान थे पूर्व प्रधानमंत्री? एक बयान के अनुसार कीमतों में लगातार कम वृद्धि के कारण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इस कारण देश में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आ रही है। उनके इस बयान से काफी बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री, बैंकर और अन्य जानकार सहमत थे कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, मुद्रास्फीति में होने वाली लगातार गिरावट को रोकना चाहिए।

कीमतों में वृद्धि अच्छी खबर : आज जब मुद्रास्फीति की मात्रा एक-दो माह में बढ़ी है, इसे 'स्टेगफ्लेशन' कहना राजनीति से प्रेरित माना जाएगा। वह भी तब जब एक माह पहले ही डॉ. मनमोहन सिंह मुद्रास्फीति में लगातार कमी से चिंताग्रस्त थे और मुद्रास्फीति में वृद्धि को आर्थिक गतिविधियों में उठाव के लिए जरूरी मान रहे थे। समझना होगा कि लगातार कम होती कीमतें, रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में अपेक्षित कमी न किया जाना, और उसके कारण बाधित होती आर्थिक गतिविधियां और उसके फलस्वरूप सरकार के द्वारा टैक्स प्राप्तियों के लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं, चिंता का कारण बन रही थीं। कीमतों में थोड़ा-बहुत उछाल आने से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री एलबॉन फिलिप्स ने कीमत वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में इस संबंध को 'फिलिप्स वक्र' की सहायता से बताया था कि नीति निर्माताओं की कीमत वृद्धि और रोजगार में वृद्धि के बीच एक सौदेबाजी होती है। फिलिप्स के विश्लेषण को मानें तो मुद्रास्फीति में हुई यह वृद्धि अच्छी खबर है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, उत्पादन और रोजगार भी बढ़ेगा।

सही राह पर सरकार : इस बात को समझते हुए कि देश में मांग में धीमापन रोकने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए राजकोषीय संतुलन को बनाए रखते हुए, आर्थिक गतिविधियों का इस प्रकार से संचालन करना होगा कि अन्य प्रकार से बिगाड़ न हो जाए। दरअसल वर्ष 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने करों में छूट और सरकारी खर्च में अनाप-शनाप वृद्धि करनी शुरू कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि देश का राजकोषीय संतुलन बिगड़ गया। राजकोषीय घाटा जीडीपी के छह प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ गया। कीमतों में बेहताशा वृद्धि होने लगी। परिणामस्वरूप ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि हुई और इस कारण से जीडीपी ग्रोथ धीमी हो गई। आर्थिक वृद्धि दर लगभग पांच प्रतिशत पर और मुद्रास्फीति दो अंकों को पार करते हुए 12 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसे अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा अवांछनीय स्थिति माना जाता है, जब तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति के स्थान पर जीडीपी में धीमी ग्रोथ हो।

इस बात को समझते हुए वर्तमान सरकार समझदारी के उपाय अपना रही है और उसके कदमों को सराहा भी जा रहा है। हर हालत में राजकोषीय घाटे को एक सीमा से बढ़ने नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण ब्याज दरों को घटाया जा सका है, जिससे उपभोक्ता मांग और निवेश मांग दोनों के बढ़ने की संभावना है। स्थिर पूंजी निर्माण की गति में थोड़ी वृद्धि भी देखी गई है। देश में निवेश के माहौल को भी बेहतर बनाने हेतु कॉरपोरेट करों की दर को घटाकर 22 प्रतिशत और नई कंपनियों के लिए मात्र 15 प्रतिशत किया गया है, जो अन्य कम करों वाले एशियाई देशों के समकक्ष है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा दिए जा रहे तमाम प्रोत्साहन दीर्घकाल में न केवल आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन और रोजगार बढ़ाएंगे, बल्कि इससे सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा।

उधर हालांकि विश्व बैंक और आइएमएफ वर्ष 2019 के लिए जीडीपी ग्रोथ की संभावनाओं को कम आंक रहे हैं, लेकिन साथ ही वर्ष 2020-21 और 2021-22 को लेकर वे आश्वस्त हैं कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। विश्व बैंक का मानना है कि वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ क्रमशः 6.9 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत रहेगी। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर भी है और सरकार के प्रयासों का समर्थन भी।

प्रतीकात्मक

गारंटी सीमा बढ़ने से कायम होगी साख

सतीश सिंह
आर्थिक मामलों के जानकार

पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी बैंक) में हुए घोटाले से उत्पन्न वित्तीय संकट का सामना कर रहे ग्राहकों को राहत देने के लिए अब सरकार बैंक खाताधारकों को उनके जमा राशि पर मिलने वाली गारंटी की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार जल्द ही बैंकों में खाताधारकों के जमा रकम पर गारंटी की सीमा बढ़ा सकती है। गारंटी पर लगने वाले बीमा प्रीमियम में बदलाव का भी प्रस्ताव है। अभी बैंक जमा राशि पर हर ग्राहक को एक लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर देते हैं। यह गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपरेशन के तहत मिलती है। यानी यदि किसी बैंक के अपने खाते में ग्राहक ने 10 लाख रुपये जमा किया है और किसी कारणवश वह बैंक डूब जाता है तो ग्राहक को महज एक लाख रुपये मिलने की गारंटी होती है। सरकार बैंकों में डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को एक लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर सकती है।

सरकार फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल को भी नए रूप में लाने का प्रयास कर सकती है। इसके तहत सरकारी बैंकों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि डूबने या दिवालिया होने पर वे जमाकर्ताओं को गारंटी की रकम देने के बाद शेष राशि का कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालांकि भारत में अभी तक कोई बैंक दिवालिया नहीं हुआ है, लेकिन कई बैंक और वित्तीय संस्थान दिवालिया होने के कगार पर जरूर पहंच चुके हैं और सरकार की मदद से ही वे संकट से उबर सके हैं। मालूम हो कि पीएमसी में घोटाले का पता चलने के बाद रिजर्व बैंक ने छह महीने के लिए इस बैंक का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था।

सहकारी बैंक का गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश देशों में सहकारी बैंक हैं, जो जमा लेने और उधार देने का काम करते हैं। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करना भी है। सामान्यतः इनकी शाखाएं एक राज्य तक सीमित होती हैं। भारत में चार तरह के सहकारी बैंक हैं- प्राथमिक सहकारी साख समितियां, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। सहकारी बैंक सहकारी साख संगठन की सर्वोच्च संस्था है। जिस प्रकार से साख समितियों का नियंत्रण जिले में स्थित केंद्रीय बैंक करता है, उसी प्रकार राज्य भर में फैले हुए केंद्रीय बैंकों को राज्य सहकारी बैंक संगठित करता है। इस तरह, यह बैंक राज्य भर में फैली हुई कृषि सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था है।

सहकारी बैंकों में घोटाले का एक बड़ा कारण रिजर्व बैंक और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की दोहरी नियंत्रण व्यवस्था को माना जा रहा है। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार होती है। इनका नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है। इन बैंकों पर निगरानी रखने का कार्य मुख्य तौर पर राज्य सरकार करती है। वर्ष 1993 से 2004 के बीच रिजर्व बैंक ने बड़ी संख्या में कोऑपरेटिव बैंकों को लाइसेंस दिए जिससे इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। हालांकि बाद में इनका विलय भी हुआ, पर यह संख्या ज्यादा नहीं थी। वर्ष 2004 में 1,926 कोऑपरेटिव बैंक थे जो 2018 में घटकर 1,551 रह गए। वर्ष 2004 में इन बैंकों की पूंजी 1,32,100 करोड़ रुपये थी जो 2018 में 5,63,200 करोड़ रुपये हो गई।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली अभी भी मजबूत और स्थिर है। पीएमसी बैंक में हुए घोटाले के आधार पर पूरी बैंकिंग प्रणाली को त्रुटिपूर्ण मानना गलत है। फिलहाल, देश में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। खाताधारकों की जमा पूंजी बैंकों में सुरक्षित रहे इसके लिए बीमा कवर में इजाफा करने की भी जरूरत है। हालांकि इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक जल्द नए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

खरी-खरी

आम आदमी, बंदर और बंदरबांट

हेमंत कुमार पारीक

इस वक्त एक खबर आई है बंदरों की। पूर्वजों की कोई नहीं सुन रहा है। इधर बंदरबांट में लगे हैं लोग। दो बिल्लियां और एक बंदर! बंदर कौन और बिल्ली कौन? तराजू लिए बंदर खड़ा है। कभी मंदिर के कंगूरे पर जा बैठता है। खिड़की से उसे जज साहब देख लेते हैं। उदास से, अनशन पर बैठे बंदर को देख उनके मन में उथल-पुथल मचती है। क्या, क्यों, कैसे, कहां जैसे सवाल पैदा हो जाते हैं। इस सवालों के कारण ही कोर्ट-कचहरी हैं। प्रबंधन की भाषा में ये मित्र कहे जाते हैं। इसलिए मंदिर के कंगूरे पर बैठे बंदर के विषय में उन्होंने सोचा। शायद उसे सपने में देख लिया होगा, पर बताया नहीं।

कोर्ट-कचहरी में सपने नहीं चलते, पर हमारे देश में सपनों का बड़ा महत्व है। बिना सपना देखे सब वीरान और अधूरा-सा लगता है। इसलिए दीपावली के समय अचानक लोगों को सपने आने लगते हैं। नेता को सपने में लक्ष्मी दिखती है तो आम आदमी को उल्लू। आम आदमी की किस्मत भगवान ने पेन से नहीं, बल्कि चॉक से लिखी है। उल्लू की किस्मत उल्लू के लायक ही होती है। फिर भी वह खुश है। उल्लू बनाने के तरीके तो लक्ष्मी-पुत्रों को आते हैं। आम आदमी इन लक्ष्मी-पुत्रों की हरकतें देखकर ही खुश है। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि उन तीनों में से बंदर कौन है? बंदरबांट का मुजाहिरा चालू आहे!

पर हमने कभी सोचा नहीं था कि बंदर भी संसद में एक विषय होगा। किस्मत खुल गई। अभी तक तो आम आदमी की बातें चला करती थीं। बंदर पहली बार संसद की स्क्रीन पर दिखा। धन्यभाग हमारे! मंकी सफारी की बातें होने लगी हैं। इधर बंदर मथुरा-वृंदावन में उछल-कूद मचा रहे हैं, तो उधर जेएनयू और बीएचयू में भी कुछ ऐसा ही आलम है। हमारे घर के अगल-बगल रहने वाले पुलिस और वकील भी कुछ इस तरह की उछल-कूद कर रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि उनके लिए भी एक-एक सफारी बनाई जाए। बंदर का संसद में आगमन अच्छी खबर है। इधर कुत्ते आतंक मचाए हुए हैं मोहल्ले में। कहीं भैंसों का ठसक है रोड पर तो कहीं गधे दुलत्ती जड़ रहे हैं, सड़क चलते हुए आम आदमी को। आम आदमी ही एक ऐसी शै बची है, जिस पर अब नेताओं के अलावा जानवर भी अपना गुस्सा निकालने लगे हैं। अच्छा हो कि आम आदमी के लिए भी एक सफारी बनाई जाए। कम से कम गधों की लात खाने से तो बचेगा आम आदमी।

ट्वीट-ट्वीट

महाराष्ट्र का मजाक बनाकर रख दिया राजनीति ने!
रूबिका लियाकत@RubikaLiyaquat

वास्तव में इसका उलट भी सही है कि राजनीति का मजाक बनाकर रख दिया महाराष्ट्र ने।
ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

महाराष्ट्र के महानाटक को देखने के बाद अब तो देखना यह है कि शिवसेना किस मुंह से हिंदुत्व की बात करेगी? कांग्रेस किस मुंह से 'सेक्युलरिज्म' की बात करेगी और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेगी?
अशोक श्रीवास्तव@ashokshrivasta6

लोकतंत्र को प्रभावी और परिपक्व बनाने के लिए यह आवश्यक है कि केवल समान विचारों वाले ही नहीं, बल्कि विपरीत विचार धाराओं वाले भी साथ मिलकर परस्पर विश्वास और भरोसे के साथ काम करें। विविधतापूर्ण और बहुदलीय प्रणाली वाले देश में यह बहुत जरूरी है।
सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

हिमाचल प्रदेश डायरी

इतने ही दिलफरेब हैं गम रोजगार के?

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

कई बार ख्याल आता है कि अगर बिहार, राजस्थान, कश्मीर और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश न हों तो हिमाचल प्रदेश का क्या बने? नेपाल न हो तो सेब की आर्थिकी कौन संभाले? भवन निर्माण से लेकर सेब के बाग संभालने तक, रंग रोगन करने से लेकर दर्जी का काम कौन करेगा? पीठ पर गैस का सिलेंडर उठा कर कौन चलेगा? हिमाचल प्रदेश को इनका आभारी होना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के समाज का एक हिस्सा अपने ही होने के प्रति आभारी नहीं है, इनका आभार क्यों व्यक्त करेगा?

यह उस प्रदेश की बात है जहां बेरोजगारों की संख्या साढ़े आठ लाख के करीब है। जहां सरकारी नौकरी को जीने की पहली शर्त माना जाता है। एक व्यक्ति पीएचडी है, एक एमएससी है, एक एमफिल है, एक इंजीनियर है, ये कोई काम नहीं करते सिवाय इसके कि पटवारी की परीक्षा के लिए आवेदन करें। सचिवालय में अगर चतुर्थ श्रेणी का पद विज्ञापित हो तो उसके लिए आवेदन करना भी इनका अधिकार है। लेकिन स्वरोजगार ऐसा शब्द है जिसका नाम लेना गवारा नहीं है। यही त्रासदी है हिमाचल की। यहां इस बात पर समाज का हिस्सा अवश्य शोर मचाएगा कि प्रवक्ताओं की भर्ती में बाहर के लोगों को शामिल क्यों किया गया। आपत्ति इस पर भी हो सकती है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में झारखंड के लोग क्यों आए? लेकिन इस बात का जवाब ऐसी मानसिकता के पास नहीं है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 27 में से चार पद क्यों रिक्त रहे हैं। जाहिर है स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और सामान्य वर्ग से संबद्ध पूर्व सैनिक वाली श्रेणी के लिए 'उपयुक्त अभ्यर्थी' ही नहीं मिले।

मिलने में संकट उत्पन्न होना ही था, क्योंकि जब बिना प्रतियोगिता के प्रवक्ता का पद भाता हो, जब सपना तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद हों, तो हिमाचल प्रशासनिक सेवा बहुत दूर की बात हो गई न। प्रवक्ताओं के लिए नई शर्त के फेर में वे लोग भी पिसेंगे जो हिमाचली हैं,

लेकिन रोजगार या अन्य कारणों से किसी और राज्य के बोर्ड में दसवीं या बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। आदर्श विहीनता को दोष देना बहुत आसान है, पर आदर्श विहीनता है नहीं। अपने आसपास आदर्श हैं, लेकिन श्रम और समय के सम्मान का संकट है। वरना सराज घाटी की छतरी पंचायत का निशांत सरकारी स्कूल में पढ़कर भी इस पद पर पहुंच जाए तो जाहिर है, उसने अभाव का रोना नहीं रोया, बल्कि पिछले वर्ष खंड विकास अधिकारी का पद पाकर भी मेहनत जारी रखी और इस बार एसडीएम बनकर ही सुकून पाया। जिसके पास दृष्टि है, उसके लिए बेरोजगारी का मतलब ही क्या है? और अगर बेरोजगारी है ही तो फिर हिमाचली युवाओं को बाहर का छोड़ें, घर का काम करने में भी परेशानी क्यों है? जब कौशल नहीं होगा तो बेरोजगारी स्वतः होगी। हिमाचल प्रदेश में समाज के अलावा शासकों की भी बड़ी भूमिका रही है। यहां 45 वर्ष तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस मृगतृष्णा में जीवन के हरे वर्ष अतीत हो चुके होते हैं। इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन इन प्रश्नों के उत्तर तलाशेगा और हल भी दे सकता है, लेकिन श्रम के सम्मान को किस पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जाता है।

पर्यटन और बागवानी के अलावा पशुपालन में बेहद संभावनाएं है, लेकिन कोई यह भी तो बताए कि करना चाहता कौन है? यह गरीबी रेखा के लिए कैसा आकर्षण है कि सरकारी कागजों में उसकी छांव सबको भली लगती है। सब उसे ओढ़ना चाहते हैं! अकर्मण्यता की बर्फ क्या इतनी सर्द होती है कि पुरुषार्थ का ताप उस तक पहुंच ही नहीं पाता? यह कौन सी पीएचडी है कि हिंदी में प्रार्थनापत्र ही गलतियों से लैस हो? किस जज्बे की इंजीनियरिंग है कि पटवारी बनना स्वीकार है? कौन सा आत्मसम्मान है कि दिल्ली के ढाबे में काम करना आसान है, गांव में दो गाय नहीं पाली जा सकती? यह कौन सी समझ है कि चोर रास्ते से दुबई या कहीं और जाने के चक्कर में जीवन भर की कमाई लुटाई जा सकती है, लेकिन पर्यटकों के लिए होटल या रेस्तरां नहीं खोला जा सकता? व्यवस्था सहयोग न करे तो शोर मचाया जाए।

इस सबके आलोक में बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपालियों के श्रम के बिना हिमाचल को देखें और कल्पना करें कि क्या हम कुशल हैं? श्रम का सम्मान करते हैं? किसी स्कूल में एनएसएस के स्वयंसेवी परिसर की सफाई करें या बावड़ी का पानी बचाने की कोशिश करें तो तिल का ताड़ बन जाता है। हिमाचल के सब संसाधनों का माकूल दोहन हो जाएगा अगर अभिभावक और अध्यापकों के साथ जनप्रतिनिधि भी इंसानसाजी सीख लें। यह क्या समझ है कि हर जनप्रतिनिधि हैंडपंप या महिला मंडल को चिमटे, ढोलकी और गिलास देने को तत्पर रहता है, लेकिन पूरे स्काउट्स एंड गाइड जैसे संगठन के पास अपना प्रशिक्षण भवन नहीं है। यही प्राथमिकताएं पहचानी जाएं तो सपने पूरे होंगे। अकर्मण्यता में जीने वालों के सपने कहां से सुहाने होंगे? यह समय आबिद अदीब के इस शेर को पढ़ने का है :

जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके,
उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाएगी?

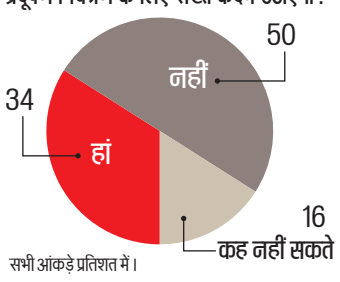

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या चुनाव पूर्व और चुनाव उपरांत राजनीतिक गठबंधन को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

साहब का प्रिय स्वप्न था हो भगवे की धूम,
किंतु सोनिया-शरद के रहे चरण तुम चूम।
रहे चरण तुम चूम शपथ ले नाम खा रहे,
साहब के विपरीत मार्ग पर आप जा रहे!
मानेंगे हर बात शरद की उद्धव जी अब,
तब पीटेंगे शीश स्वर्ग में बैठे साहब!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

पारदर्शी बने राजनीतिक फंडिंग

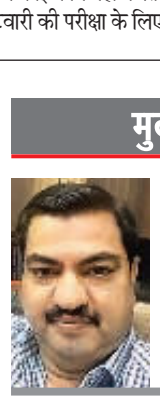

विजय कपूर
वरिष्ठ पत्रकार

भारत में चुनावों में व्यापक पैमाने पर धन खर्च किया जाता है जिसे एकत्र करने के तरीके पूर्णतया पारदर्शी नहीं हैं, लिहाजा इसे पारदर्शी बनाया जाना चाहिए

भारत में राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने की सख्त आवश्यकता है। समय आ गया है कि राजनीतिक फंडिंग का जो इस समय तरीका है यानी बड़ी मात्रा में नकद दान के स्रोत को गुप्त रखना, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। अन्य सुधारों के साथ ही राजनीतिक फंडिंग सुधार को वरीयता दी जानी चाहिए। जिस तरह चुनावी बांड योजना को पहले लाया गया और फिर उसे लागू किया गया, उससे अनेक गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। क्या वह अपने वर्तमान रूप में अधिक पारदर्शी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकती है?

शायद इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही अंदेशा था तभी तो 2017 में तत्कालीन आरबीआइ गवर्नर ने तत्कालीन वित्त मंत्री को लिखा था कि बेयरर बांड्स नगद पैसे की तरह होते हैं, उन्हें केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को जारी करने की अनुमति देना खतरे से भरा है। चुनाव आयोग ने भी सावधान किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को अवैध विदेशी फंड्स मिलने लगेंगे। लेकिन इन आपत्तियों को अनदेखा कर दिया गया और इस योजना को लोकसभा में वित्त विधेयक (बजट) के रूप में पारित कर दिया गया ताकि उसे राज्यसभा से न गुजरना पड़े, जहां उस समय सरकार के पास बहुमत नहीं था।

इस योजना का उद्देश्य यह बताया गया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग 'क्लीन-अप' हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि दानकर्ता का नाम गुप्त रखने से यह भला कैसे संभव है? इससे राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट फंड मिलने लगा जिनमें विदेशी व शैल कंपनियों से हासिल फंड भी शामिल हैं। लेकिन जिस व्यवस्था से राजनीतिक चंदा स्वच्छ होना था उस योजना से तो यह भी पता नहीं चला कि फंड्स आए कहां से? इस योजना के समर्थन में एक तर्क यह दिया गया कि गोपनीयता दानकर्ता को भविष्य की आशंकित परेशानी से सुरक्षित रखती है, लेकिन लोकतंत्र का तो सारा वजूद ही पारदर्शिता पर आधारित है। मतदाताओं को यह मालूम होना उनका हक है कि राजनीतिक दलों को किन किन जगहों से फंड्स मिल रहे हैं। दानकर्ता की पहचान गोपनीय रखने से किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इसके अलावा आरबीआइ की जगह सरकारी एसबीआइ को बांड्स जारी करने का अधिकार देने से यह शंका उत्पन्न होती है कि इस व्यवस्था के कामकाज को सरकार प्रभावित कर सकती है? ध्यान रहे कि बैंक को दानकर्ता की जानकारी रखनी होती है, आग्रह किए जाने पर यह जानकारी इनफोर्समेंट एजेंसीज को देनी होती है, जिससे यह आरोप संभावित हो जाता है कि सरकार इस जानकारी को हासिल करके अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकती है।

जिस अंदाज में इस योजना के नियमों से छेड़छाड़ की गई कि इन बांड्स को खरीदने व जमा करने की समयावधि बदल दी गई, उससे इस विमर्श को ही बल मिलता है कि इस व्यवस्था से सत्तारूढ़ दल को जबरदस्त व अनुचित लाभ मिल जाता है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से मालूम होता है कि पहली खेप में जो 222 करोड़ रुपये मूल्य के बांड्स जारी किए गए थे, उसमें से 95 प्रतिशत भाजपा के खाते में गए। इस योजना का चिंताजनक होना इस बात से भी जाहिर होता है कि जिन पहले 11 चरणों में 5,896 करोड़ रुपये मूल्य के बांड्स बेचे गए उनमें से 91 प्रतिशत से अधिक एक करोड़ रुपये वाले थे।

राजनीतिक फंडिंग के तरीके में सुधार लाने के लिए पारदर्शिता व जवाबदेही पहली शर्त है। इस मामले में इस बुनियादी बात का पालन नहीं किया गया। ध्यान रहे कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के तहत भी नहीं आते हैं, ऐसे में राजनीतिक फंडिंग का पूर्णतया पारदर्शी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में चुनावों में धन की भूमिका बढ़ती जा रही है। कुछ राजनीतिक दल एकाध चुनाव बहुत कम पैसा खर्च करके जीत सकते हैं, लेकिन जीत को अनेक चुनावों तक बरकरार रखने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए प्रत्याशियों और पार्टियों को होर्डिंग व प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया में विज्ञापनों पर खर्चा करना होता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को पैसा देना होता है, रैलियां आयोजित करनी होती हैं। यह बात अब छिपी नहीं है कि देश में गिफ्ट्स, पैसा, शराब आदि भी चुनावी खर्च का हिस्सा है। चूंकि पैसे की जरूरत होती ही है, इसलिए मुख्य मुद्दा यह हो जाता है कि जीतने वाला प्रत्याशी जनता की सेवा करेगा या उसके लिए काम करेगा जिसने उसे व्यापक धन मुहैया कराया है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक फंडिंग के नियम व सुधार में निरंतर विकास किया जा रहा है। इसमें फोकस पब्लिक फंडिंग, खर्च की सीमा, फंडिंग में पारदर्शिता, नियमों का पालन न करने पर सजा आदि पर है। देश में जो चुनावी बांड योजना है उसमें लगभग सारा फंड सत्तारूढ़ दल को मिल जाता है। उसे और एनफोर्समेंट एजेंसीज को ही मालूम होता है कि किसने किसको कितना पैसा दिया है, इसलिए दानकर्ता को अगर किसी उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा तो यह काम सत्तारूढ़ दल एनफोर्समेंट एजेंसीज के जरिये ही करा सकता है।

बहरहाल जनता के पास यह जानकारी नहीं होती है, ऐसी गोपनीयता से भला अच्छा लोकतंत्र कैसे संभव है? लेकिन असल खतरा दीर्घकाल में है। अगर अपारदर्शिता के साथ मोटा पैसा ही चुनावों को संचालित करेगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। गोपनीय फंड्स के नाम पर एनजीओ के तो पंजीकरण रद कर दिए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के नहीं, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग ने इसमें सुधार के सुझाव दिए हैं, पर उन्हें अपनाया नहीं गया है। सभी प्रकार की फंडिंग में पारदर्शिता हो, राजनीतिक दल आरटीआइ के अधीन आएं, चुनाव खर्च व दान पर सीमा निर्धारित हो, नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड हो। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर एक याचिका विचाराधीन है। ऐसे में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

- इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

6 महीने से निष्क्रिय ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने जा रही है कंपनी। यह प्रकिया 11 दिसंबर से शुरू की जाएगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 28 नवंबर 2019

बुग्याल को जूट के जाल से मिलेगी सुरक्षा

- बुग्याल संरक्षण और उपचार को उत्तराखंड में होने जा रहा नया प्रयोग
- पारिस्थितिकी और पर्यटन के लिहाज से हैं अहम, कटाव से पहुंच रही क्षति, रोकने को लगाए जाएंगे जूट निर्मित जाल, पिरुल और बांस के खूंटों से बनेंगे चेक डैम

इस तरह मिट्टी के कटाव से खत्म हो रहे बुग्याल। जागरण

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी

हिमालय की गोद में फैले औषधीय पौधों और मखमली घास से लकदक मैदानों (बुग्याल) को बचाने के लिए नई पहल की जा रही है। इसकी शुरुआत हो रही है उत्तरकाशी जिले में समुद्रतल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल से। दरअसल, भू-क्षरण और कटाव के कारण बुग्यालों को खासा नुकसान पहुंच रहा है। आग से भी बहुत क्षति पहुंचती है। पारिस्थितिकी और पर्यटन के लिहाज से बुग्यालों का खासा महत्व है। इसीलिए इनके संरक्षण को सरकार खासा ध्यान दे रही है। हालांकि यह प्रयोग एकदम नया है। ओडिशा से जूट और नारियल के रेशों से तैयार जाल (केयर नेट) के 90 बंडल उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। जबकि पिरुल (चीड़ की पत्ती) धरासू रेंज के सिलक्यारा से लाई जा रही है। कोटद्वार से बांस के खूंटे पहुंच रहे हैं। केयर चेक डैम और केयर नेट से बुग्याली क्षेत्र में कटाव को रोकने के लिए कमर कस ली गई है।

हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं बुग्याल, जिनका संरक्षण वर्तमान में बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल, बीते कुछ वर्षों में प्राकृतिक कारणों और मानवीय हस्तक्षेप के चलते बुग्यालों में भूस्खलन की रफ्तार बढ़ी है। इससे उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे संकटग्रस्त बुग्यालों में सबसे ऊपर है दयारा बुग्याल। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 50 किमी दूर दयारा बुग्याल 30 वर्ग किमी क्षेत्र फैला हुआ है। उत्तरकाशी वन विभाग के मंडल वन अधिकारी (डीएफओ) संदीप कुमार बताते हैं कि दयारा बुग्याल में मिट्टी के कटाव-क्षरण को लेकर एक सर्वे किया गया। इसमें सौ से अधिक स्थानों पर मिट्टी का कटाव मिला, जो भूस्खलन की ओर बढ़ रहा है। इसलिए बुग्याल के ट्रीटमेंट को विशेषज्ञों की सलाह से केयर नेट और केयर चेक डैम की योजना बनाई गई। केयर नेट जूट और नारियल के रेसों से बनी एक प्रकार की मैट या जाल है। इसके 90 बंडल उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, जिन्हें उन स्थानों पर बिछाया जाना है, जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है और केयर चेक डैम नहीं बन सकते। जबकि केयर चेक डैम (बाड़) पिरुल के बनाए जाएंगे। इनके लिए पत्थरों के स्थान पर बांस के खूंटों को गाड़ा जाएगा।

डीएफओ संदीप कुमार कहते हैं कि बुग्यालों का अति संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र होने के कारण दयारा बुग्याल में अनुरक्षण और संवर्धन का कार्य बुग्याल के पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार किया जा रहा है, ताकि उपचार के दौरान भी बुग्याल को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। दयारा बुग्याल के शुरुआती हिस्से धिनाड़ा के 300 मीटर हिस्से में बड़ा भूस्खलन सक्रिय है। इसकी चपेट में दयारा बुग्याल को जाने वाला रास्ता भी आ रहा है। बुग्याल में कुंती माता के सेरे (खेत) के ऊपरी हिस्से में भारी कटाव हो रहा है। इसके अलावा काणाताल के निकट भी बुग्याल का काफी अधिक कटाव हो रहा है।

पर्यटकों के लिए खास है दयारा : हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र में जहां बुग्यालों की अहम भूमिका है, वहीं पर्यटकों के लिए भी ये बेहद खास हैं। शीतकाल में दिसंबर से लेकर अप्रैल तक बुग्याल की ढलानों पर बर्फ की चादर बिछी रहती है। शीतकालीन खेलों के लिए भी यहां आदर्श स्थितियां हैं। स्कीइंग विशेषज्ञ सतल सिंह पंवार बताते हैं कि दयारा बुग्याल में स्कीइंग के लिए गुलमर्ग से बेहतर स्थितियां हैं। जबकि, मई से लेकर नवंबर तक यहां पर्यटक प्रकृति का आनंद लेते हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

जागरण विशेष

कमजोर भौगोलिक गठन, भूमि संरचना, भूकंपीय सक्रियता, अधिक बरसात और बादलों के फटने जैसी प्राकृतिक घटनाएं बुग्याली क्षेत्र में मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण होती हैं। हालांकि बुग्यालों में अत्याधिक मानवीय हस्तक्षेप भी मिट्टी के कटाव का कारक है। इसके अलावा बुग्यालों में एक ही स्थान पर पशुओं को चराना भी इसकी एक वजह है।

– देवेंद्र पटवाल, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तरकाशी

सार्वजनिक शौचालयों, ट्रेनों में हैंडवॉश को सुलभ बनाएगी यह युक्ति

स्वच्छता का अधिकार ▸ एमआइईटी के प्रोफेसर ने बनाया हैंडवॉश प्रोसेसर-कम-डिस्पेंसर, बार-बार भरने की नहीं पड़ेगी जरूरत

विवेक राव, मेरठ

ट्रेन हों या सार्वजनिक शौचालय, अधिकांश जगह हाथ धोने का साबुन (लिक्विड सोप) मुहैया नहीं होता। कई जगह सोप खत्म हो जाता है, तो कहीं इसका इंतजाम ही नहीं होता है। मेरठ, उप्र स्थित मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एमआइईटी) के प्रोफेसर ने इसका समाधान प्रस्तुत कर दिखाया है। ताकि स्वच्छ भारत में स्वच्छता का अधिकार हर किसी को, हर जगह सुलभ हो।

स्वस्थ समाज

स्वच्छता का सीधा संबंध सेहत से है। और सेहत का जीवन से। जब सेहत ही न सहेजी जा सके, तो जीवन का अधिकार अधूरा। यह अधूरापन आप हर उस स्थान पर महसूस करते हैं, जहां स्वच्छता का अनुपालन न हो सके। घर या दफ्तर में तो समस्या पेश नहीं आती, लेकिन सार्वजनिक शौचालयों या ट्रेन में शौचालय का उपयोग करने के बाद ठीक से हाथ न धो पाने की समस्या अकसर पेश आती है। कई जगहों पर हाथ धोने के लिए हैंडवॉश डिस्पेंसर (लिक्विड सोप की बोतल) तो मुहैया होती है, लेकिन उसमें साबुन अकसर खत्म हो चुका होता है। अधिकांश शौचालयों और ट्रेनों में तो यह सुविधा ही नहीं होती। ऐसे में यदि पेपर सोप भी न हो तो हाथों को गंदा रखने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता।

इस समस्या से निपटने और देशभर में चल रही स्वच्छता की मुहिम को एक कदम आगे बढ़ाते हुए एमआइईटी के प्रोफेसर नितिन शर्मा ने ऐसा हैंडवॉश प्रोसेसर-कम-डिस्पेंसर बनाया है, जिससे खुद ही लिक्विड सोप तैयार होता रहेगा। न तो बार-बार खाली होने की समस्या रहेगी और न भरने की। आम डिस्पेंसर के मुकाबले यह लंबे समय तक काम करता रहेगा। प्रो. नितिन कहते हैं, यही नहीं, ज्यादातर सार्वजनिक शौचालयों में निम्न गुणवत्ता का लिक्विड सोप उपयोग किया जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए हैंडवॉश प्रोसेसर-कम-डिस्पेंसर डिजाइन किया गया है। इसमें बस कुछ मात्रा में केमिकल रखना होता है, जो पानी के साथ अपने आप लिक्विड सोप (साबुन) में बदल जाता है। उच्च गुणवत्ता का एक लीटर सोप 20 रुपये में तैयार हो सकता है, जोकि बाजार में उपलब्ध अन्य हैंडवॉश लिक्विड सोप के मुकाबले काफी कम कीमत है। मेरठ इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इस युक्ति को पेटेंट करा लिया है। मेरठ के सुलभ शौचालयों में इस हैंडवॉश प्रोसेसर-कम-डिस्पेंसर को जल्द ही एमआइईटी की तरफ से नो प्राफिट-नो लॉस आधार पर लगाया जाएगा। संस्थान के चेयरमैन विष्णु शरण अग्रवाल बताते हैं कि नगर निगम और कैंट बोर्ड को इसका प्रयोग करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

- **लिक्विड सोप खुद होता रहेगा तैयार, लंबे समय तक चलेगा काम**

इस युक्ति से मेरठ सहित देश के अन्य सार्वजनिक शौचालयों और ट्रेनों में सस्ता और गुणवत्तायुक्त हैंडवॉश सोप उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा जाएगा।

– डॉ. नितिन शर्मा, एमआइईटी, मेरठ, उप्र

लिक्विड सोप बनाने के लिए प्रो. नितिन शर्मा ने एसिड स्लरी (साबुन बनाने में प्रयुक्त रसायन), पानी और सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया है। इसमें 20 फीसद केमिकल है, शेष 80 फीसद पानी। डिस्पेंसर में पानी और केमिकल डालने के बाद 10 मिनट में सोप तैयार हो जाता है। एक डिस्पेंसर मैन्युअल है, जबकि दूसरा बैट्री चालित। गांवों के शौचालय में मैन्युअल, जबकि शहरों में बैट्री चालित डिस्पेंसर लगा सकते हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित एमआइईटी में डिपार्टमेंट आफ फार्मेसी के प्रो. नितिन शर्मा हैंडवॉश के डिस्पेंसर के साथ। जागरण

अब घर बैठे की जा सकेगी सर्वाइकल कैंसर की पहचान

आविष्कार ▸ आइआइटी मंडी के शोधकर्ताओं ने विकसित की पोर्टेबल डिवाइस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डिवाइस करती है माइक्रोस्कोप की तस्वीरों का विश्लेषण

जागरण संवाददाता, मंडी

महिलाओं में सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में घर बैठे ही पता चल सकेगा। समय रहते इलाज होने से यह बीमारी महिलाओं के लिए जानलेवा नहीं बनेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी के शोधकर्ताओं ने सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए पोर्टेबल डिवाइस ईजाद की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस यह डिवाइस सटीक तरीके से माइक्रोस्कोप की तस्वीरों का विश्लेषण करती है।

यह शोध आइआइटी के स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनिल साव व अर्नव भावसर के नेतृत्व में सृष्टि गौतम व क्रांति गुप्ता ने किया। इसे बेंगलुरु के एंड्रा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया था। टीम ने उद्योग साझेदारों के साथ एआइ आधारित एल्गोरिद्म विकसित की, जो डिवाइस को सर्वाइकल कैंसर की जांच करने में सक्षमता प्रदान करती है।

मैनुअल पैप स्मीयर टेस्ट की रिपोर्ट आने में समय लगता था। खर्च भी अधिक होता था। पोर्टेबल डिवाइस से जल्द रिपोर्ट मिलेगी। टेस्ट का खर्च भी कम आएगा और टेस्ट स्वचालित तरीके से होगा।

– डॉ. अर्नव भावसर, आइआइटी मंडी

10 में से एक महिला पीड़ित

गर्भाशय के मुख्य द्वार सर्विक्स में सेल्स की अनियमित वृद्धि को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। यह सर्विक्स में ह्यूमन पेपीलोमा वायरस (एचपीवी) के कारण होता है। दुनियाभर में 10 में से एक महिला इससे पीड़ित है। जानकारी के अभाव में यह बीमारी जानलेवा बनती जा रही है।

अभी पैप स्मीयर टेस्ट एकमात्र विकल्प : सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए अब तक पैप स्मीयर टेस्ट एकमात्र विकल्प है। इसमें विशेषज्ञ गर्भाशय के मुख्य द्वार की कोशिका निकालकर माइक्रोस्कोप से जांचते हैं। शोध के अनुसार इस टेस्ट की सटीकता 60 से 85 प्रतिशत के बीच है।

पोर्टेबल डिवाइस के लाभ : पोर्टेबल डिवाइस से मरीज की जांच घर में की जा सकेगी। डिवाइस के प्रोटोटाइप का क्लीनिकल परीक्षण किदवई मेमोरियल अस्पताल बेंगलुरु, मणिपाल अस्पताल कर्नाटक व राज राजेश्वरी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बेंगलुरु में किया गया। प्रोटोटाइप की सटीकता 88 प्रतिशत रही है।

प्री प्रोसेसिंग तकनीक का भी विकास : शोधकर्ताओं ने तस्वीरों में कोशिका का पता लगाने के लिए एक प्री प्रोसेसिंग तकनीक का भी विकास किया है। इन सेल्स को कन्वॉल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स में डाला जाता है ताकि कैंसर सेल्स का सटीक वर्गीकरण हो जाए।

पैथोलॉजिस्ट की कमी दूर होगी : डिवाइस पैथोलॉजिस्ट की कमी की समस्या कम करने में भी मदद करेगी। यह पैप स्मीयर टेस्ट की जांच को स्वचालित करेगी। इससे पैथोलॉजिस्ट का काफी समय बचेगा। जांच का खर्च कम होगा और परिणाम अधिक सटीक होंगे।

इटावा सफारी में कुलांचे भरते दिखेंगे आगरा के कृष्ण मृग

सोहम प्रकाश, इटावा

- दुर्लभ वन्यजीवों को रास आएगा यहां का प्राकृतिक माहौल, दिसंबर में 78 कृष्ण मृग शिफ्ट करने की चल रही तैयारी

आगरा के सिकंदरा स्थित अकबर मकबरा के 78 कृष्ण मृग (काले हिरण) इटावा सफारी पार्क में शिफ्ट करने की तैयारी है। वहां कृष्ण मृग के अनुकूल प्राकृतिक वास के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। सिकंदरा में उचित वातावरण न मिलने से वन विभाग चिंतित है। शिफ्टिंग के लिए सीजेडए (सेंट्रल जू अथॉरिटी) की अनुमति मिल गई है। दिसंबर में शिफ्टिंग की संभावना है।

सिकंदरा में वर्ष 2010-11 में कृष्ण मृग की संख्या 144 थी, जो घटकर 78 रह गई है। वर्ष 2011 के बाद से इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहां सियारों का भी आतंक है। सियार कई बार हिरनों को निवाला बना चुके हैं। मृगों की संख्या घटने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग ने कृष्ण मृग के बेहतर प्राकृतिक प्रवास के लिए इटावा सफारी पार्क को अनुकूल माना है। अलबत्ता शिफ्टिंग की फाइल वर्ष 2014 से चल रही है, तब इटावा सफारी पार्क में एंटीलोप सफारी अस्तित्व में नहीं थी इसलिए पहले कानपुर चिड़ियाघर से लेकर अन्य सफारी पार्क में शिफ्टिंग का विचार बना था, लेकिन दूरी अधिक होने से वाहन में लंबा सफर तय न कर पाने को लेकर प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था।

हिरणों की शिफ्टिंग आसान नहीं है। हल्की भी असुविधा पर दिल का दौरा पड़ने का अंदेशा रहता है। इसकी वजह से शिफ्टिंग के लिए बोमा विधि अपनाई जाएगी। इसमें गाड़ी में हिरणों के लिए खाद्य सामग्री रखी जाएगी। वह वहां आकर खाना खाने के बाद निकल जाएंगे। आवागमन बढ़ने पर उन्हें कैद कर लिया जाएगा। पूरी गाड़ी में अंधेरा रहेगा ताकि उनको कुछ दिखाई न दे। शिफ्टिंग में एक माह से अधिक का समय लगेगा।

कृष्ण मृग फाइल

वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए इटावा सफारी पार्क की एंटीलोप सफारी में वर्तमान में 45 काले हिरण हैं। शुरुआत में 50 काले हिरणों की क्षमता वाली इस सफारी की क्षमता अब बढ़कर 200 तक पहुंच गई है। शिफ्टिंग के बाद सफारी में काले हिरनों का कुनबा बढ़कर सवा सौ हो जाएगा। शिफ्टिंग सुप्रीम कोर्ट के करीब चार साल पुराने आदेश के परिपेक्ष्य में की जा रही है।

– वीके सिंह, निदेशक इटावा सफारी पार्क

राजभवन के लिए सिरदर्द बनीं प्रधानमंत्री के नाम लिखीं 17 लाख चिट्ठियां

संजीत कुमार, रायपुर

- छत्तीसगढ़ में चार गाड़ियों में भरकर कांग्रेसियों ने धान के मुद्दे पर सौंपी हैं
- सूझ नहीं रहा करें क्या, पीएमओ से मांग सकते हैं मार्गदर्शन

किसानों और व्यापारियों से पीएम के नाम लिखवाए गए 17 लाख पत्रों को कांग्रेसियों ने मंगलवार को वाहनों में भरकर रायपुर में राजभवन को सौंपा था। नईदुनिया

छत्तीसगढ़ में धान के मुद्दे पर कांग्रेस ने किसानों और व्यापारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर करीब 17 लाख पत्र लिखवाकर राजभवन को सौंप दिए हैं। राजभवन तक पत्र पहुंचाने के बाद अब कांग्रेस जहां इन पत्रों से मुक्त हो गई है, वहीं राजभवन का सिरदर्द बढ़ गया है। राजभवन सचिवालय को समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आए पत्रों का क्या किया जाए। यही वजह है कि अब इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से मार्गदर्शन मांगने पर विचार किया जा रहा है।

दरअसल, लाखों की संख्या में पहुंचे पत्रों को लेकर राजभवन दोहरी चिंता में है। एक तो इतनी बड़ी संख्या में आए पत्रों को रखा कहां जाए और दूसरा इसका किया क्या जाए। पत्रों की वजह से एक पूरा कमरा भर गया है।

लेना ही नहीं चाहिए था : सूत्रों के अनुसार राजभवन सचिवालय का एक बड़ा वर्ग इतने बड़े पैमाने पर पत्र लिए जाने के ही खिलाफ है। उनकी राय में इतनी तदाद में पत्र लेना ही नहीं चाहिए था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने जिस वक्त इन पत्रों को राजभवन को सौंपा, उस वक्त राजभवन में न तो राज्यपाल अनसुइया उइके थीं और न ही सचिव।

...ताकि नजीर न बने : राजभवन इस घटना के बाद ऐसे उपाय पर भी विचार कर रहा है कि जिससे यह नजीर न बने और ऐसा फिर न हो। सूत्रों के अनुसार इसकी वजह यह मानी जा रही है कि यदि यह घटना नजीर बन गई तो कल को कोई भी आ कर ऐसे ही लाखों की संख्या में पत्र सौंप जाएगा। ऐसे में राजभवन पोस्ट ऑफिस बन कर रह जाएगा।

ज्ञापन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता : राजभवन सचिवालय के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के नाम का ज्ञापन लिया जा सकता है, लेकिन ज्ञापन कुछ पन्नों का हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या में नहीं। वैसे भी किसी और का ज्ञापन कोई दूसरा कैसे दे सकता है।

यह कर सकता है राजभवन : सभी 17 लाख चिट्ठियों को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने की बजाय पीएमओ को राजभवन की तरफ से केवल एक पत्र भेजा जाए और 17 लाख पत्रों की विषयवस्तु बता दी जाए। इससे इतनी बड़ी संख्या में पत्र भेजने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और पीएमओ तक बात भी पहुंच जाएगी।

प्रयागराज में संगम किनारे बनेगा तीर्थ पुरोहितों का ट्रस्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- पूजा पाठ व्यवस्थित होगा, श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली भी रुकेगी
- सेना की जमीन पर लगता है कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला

वैष्णो देवी धाम और तिरुपति बालाजी की तर्ज पर अब प्रयागराज में भी संगम किनारे तीर्थ पुरोहितों का ट्रस्ट बनाया जाएगा। इसके लिए सेना योजना बन रही है। ट्रस्ट बनने पर सभी तीर्थ पुरोहितों को निर्धारित जगह दी जाएगी और पूजा कराने वालों के शुल्क की पर्ची कटेगी। इससे पूजा पाठ व्यवस्थित होगा और श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली भी रुकेगी। संगम किनारे की जमीन सेना की है। इसी पर कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता है।

इन आयोजनों के लिए जिला प्रशासन सेना से हर साल लीज पर जमीन लेता है। यहीं पर संगम किनारे सदियों से साल के बारह महीने तीर्थ पुरोहित पूजा कराते आए हैं। चूंकि वह परंपरागत पूजा पाठ कराते आए हैं इसलिए कभी अनुमति लेने की जरूरत नहीं समझी। यहां पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अस्थि विसर्जन, पिंड दान, गोदान, मुंडन आदि कराते हैं।

सेना ने निकाला बीच का रास्ता :पिछले दिनों सेना ने तीर्थ पुरोहितों को बेदखल कर दिया। उसके बाद से तीर्थ पुरोहित आंदोलित हैं और दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी भी हो रही है। ऐसे में सेना ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि यहां भी उसी तरह ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिस तरह वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी में है।

पुरोहितों के लिए निर्धारित होगा स्थान

ट्रस्ट बनने से तीर्थ पुरोहितों के लिए स्थान निर्धारित कर दिया जाएगा। साथ ही यहां पूजा कराने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किया जाएगा। उसकी पर्ची कटेगी। इससे सभी काम व्यवस्थित होंगे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी।

ट्रस्ट में यह होंगे शामिल

ट्रस्ट में सेना, प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों के संगठन प्रयागवाल सभा के पदाधिकारी रहेंगे। शुल्क की धनराशि से वहां की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।

मास्टर प्लान से बसे टिहरी शहर में आबाद किया 'सेहत का गांव'

टिहरी के प्रगतिशील किसान व उद्यमी सुरेंद्र डबराल। जागरण

अनुराग उनियाल, नई टिहरी

- **बदलाव**
- मुनाफा कमाना नहीं, जैविक उत्पादों से लोगों को स्वस्थ रखना है सुरेंद्र डबराल का एकमात्र ध्येय
- नौ साल से किराए पर जमीन लेकर कर रहे जैविक खेती, दूसरे देशों में भी है इनके उत्पादों की डिमांड

उत्तराखंड में मास्टर प्लान से बसे एकमात्र शहर नई टिहरी एक छोटा सा जैविक गांव फल-फूल रहा है। लोगों की सेहत संवारने के लिए इस गांव को बसाया है 'आरके' के नाम मशहूर 65 वर्षीय फोटोग्राफर सुरेंद्र डबराल ने। उन्होंने नौ साल पहले कैमरा छोड़कर जैविक खेती की राह पकड़ी और आज यह उनका जुनून बन चुकी है। उनकी बगिया में तैयार जैविक उत्पादों की सिर्फ टिहरी में ही, दूसरे देशों में भी डिमांड है।

आज के भागादौड़ भरे जीवन में बीमार होना सामान्य बात हो गई है। इसी को देखते हुए सुरेंद्र बीते नौ साल से जैविक खेती के फार्मूले पर काम कर रहे हैं, ताकि लोग बीमारियों से दूर रह सकें। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2010 में नई टिहरी के बौराड़ी में गैस गोदाम के पास किराए पर लगभग पांच नाली (5800 वर्ग फीट) भूमि और एक टिन शेड लिया। यहां उन्होंने रोज मेरी (गुलमेंहदी), गेंठी, सरसों, लेमन ग्रास, चौलाई, गन्ना, फरड़ आदि की खेती करनी शुरू की। इसके अलावा सुरेंद्र ने आसपास के गांवों से कच्चे जैविक उत्पाद लेकर उनसे खाद्य पदार्थ बनाने की भी शुरुआत की। इससे उन्हें अच्छी-खासी आमदनी हो जाती है। साथ ही गांव के कुछ लोगों को भी वह रोजगार दे रहे हैं। इनमें महिलाएं भी हैं।

कभी नहीं रखा लाभ-हानि का हिसाब : सुरेंद्र बताते हैं कि रिसर्च व सामान खरीदने में जो भी लागत आती है वह भी उत्पादों की बिक्री से वसूल हो जाती है। मुनाफा कमाना मेरा ध्येय नहीं है। मेरी कोशिश बस इतनी है कि लोग शुद्ध खानपान से अपने शरीर को स्वस्थ रखें और जैविक खेती के लिए प्रेरित हों। रही बात कमाई की तो स्वास्थ्यवर्द्धक उत्पादों की जरूरत सबको होती है। सो, मेरे उत्पाद हाथोंहाथ बिक जाते हैं। लाभ-हानि का हिसाब मैंने कभी नहीं रखा।

इन चीजों की खास मांग

सुरेंद्र डबराल के उत्पादों की डिमांड दूसरे देशों में भी है। जापान, जर्मनी, थाइलैंड, डेनमार्ग और अमेरिका में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी उनसे स्थानीय उत्पाद मंगाते हैं। इनमें लहसुन, मिर्च, गोभी आदि सब्जियों का अचार, जैविक दालें, एलोवेरा व गिलोय का जूस, सिरका वगैरह प्रमुख हैं। इसके अलावा नवरत्न आटा भी डबराल का प्रमुख उत्पाद है।

नमामि यमुना पुनरुद्धार योजना

मंदाकिनी, बागै, वाल्मीकि नदी संग बड़े नालों पर होगा काम, राजापुर से बरगढ़ तक सर्वे शुरू, सूखा संकट से मिलेगी बड़ी राहत

यमुना को जीवन देने के लिए मुस्कुराएंगी 'सहेलियां'

हेमराज कश्यप, चित्रकूट

प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में दम तोड़ रही कान्हा की यमुना को जीवन देने के लिए उनकी 'सहेलियां' मुस्कुराएंगी। यमुना को निर्मल-अविरल करने के लिए केंद्र सरकार की नमामि यमुना पुनरुद्धार योजना में पहले यमुना की सहायक नदियों को निर्मल और अविरल बनाया जाएगा, तब वह यमुना में मिलेंगी। इस सपने को अमलीजामा पहनाने के लिए पौधारोपण, मंदाकिनी में गिरने वाले 16 नालों की टैपिंग, वेटलैंड, जल संचयन और ईको पार्क की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राजापुर से बरगढ़ तक का सर्वे शुरू हो गया है। जल्द ही डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।

चित्रकूट सीमा पर बहने वाली यमुना प्रदूषण मुक्त हैं लेकिन सहायक नदियां, मंदाकिनी, बागै और वाल्मीकि प्रदूषित हैं। मंदाकिनी नगरीय नाले के जरिये सीवेज और ड्रेनेज से प्रदूषित होती है तो बागे और वाल्मीकि कच्चे नालों की मिट्टी और ग्रामीण क्षेत्रों की गंदगी से। इन नदियों का जल स्तर भी दिनोदिन गिर रहा है। इनमें 50 फीसद जल भी नहीं बचा है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं को भी पानी नहीं मिलता है। ऐसे में यमुना का पुनरुद्धार करने की योजना नदियों को जीवन देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की जीवनरेखा भी बनेगी। योजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी सरकार ने वन विभाग को दी है। वन अनुसंधान केंद्र (एफआरआइ) प्रयागराज ने इसके लिए राजापुर से बरगढ़ तक सर्वे शुरू कर दिया है।

यह होंगे मुख्य कार्य : यमुना पुनरुद्धार के लिए सरकार पांच बिंदुओं पर काम करेगी। यमुना में गिरने वाली नदी-नालों की मिट्टी कटान रोकने, जल संचयन, ईको पार्क, वेटलैंड तकनीक से जल शोधन का काम होगा। वर्षा जल रोकने के लिए नालों पर चेकडैम बनेंगे।

मुख्य काम यमुना और मंदाकिनी नदी में होगा। नाले रोके जाएंगे, साफ किए जाएंगे। बागै व वाल्मीकि नदी की सफाई के लिए वेटलैंड तकनीक अपनाई जाएगी। नदियों को पुनर्जीवन मिलने से सिंचाई व पेयजल की भी समस्या दूर होगी।

–कैलाश प्रकाश, प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

नमामि यमुना पुनरुद्धार योजना के तहत पहले यमुना की सहायक नदियों को निर्मल बनाया जाएगा। फाइल

दैनिक जागरण
सबरंग
साहित्य के...
नई दिल्ली, गुरुवार, 28 नवंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

प्रगति की राह, युवाओं को ले आती है यहां

न्यू सीलमपुर फेज-2 स्थित प्रगति पुस्तकालय में तैयारी करते छात्र

फुर्सत का ज्ञान

सीलमपुर जैसे कस्बाई इलाके में शांत वातावरण की बात हो तो आप इसे केवल कल्पना ही कहेंगे। उससे भी बढ़कर पढ़ाई के लिए उपयुक्त माहौल मिल जाए तो। शोर-शराबे और भीड़भाड़ वाले इस इलाके में यह बिल्कुल संभव है, इस बात का एहसास आपको प्रगति पुस्तकालय में पहुंचते ही हो जाएगा। किताबों से सजी रैक के बीच टेबल-कुर्सी पर पढ़ाई करते छात्रों को देख हर कोई पढ़ने को प्रेरित होता है। 1996 में पूर्व आइपीएस दीप चंद ने पुस्तकालय की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी कि यहां शिक्षा को बढ़ावा मिले। न्यू सीलमपुर फेज- 2 स्थित पुस्तकालय का संचालन प्रगति संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसके चेयरमैन पूर्व आइपीएस दीप चंद और अध्यक्ष पूर्व एसीपी राम चंद हैं।

शिक्षा के प्रति छात्रों को जागरूक करना उद्देश्य : पुस्तकालय की देखरेख करने वाले विष्णु दयाल ने बताया कि जब दीप चंद आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए तब उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में शिक्षा का कोई खास माहौल नहीं है। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, उन्हें पढ़ाई के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्होंने प्रगति पुस्तकालय की शुरुआत की ताकि बच्चे पढ़-लिखकर जीवन में आगे बढ़ सकें।

ये किताबें करती हैं आकर्षित : वैसे तो यहां सीबीएसई की सभी कक्षाओं की हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास समेत प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हजारों पुस्तकें हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं, जो पाठकों को खासा आकर्षित करती हैं। जैसे प्रतियोगी परीक्षा की किताबें पढ़ते-पढ़ते अगर कोई पाठक ऊब जाए तो स्वेट मर्डेन की चिंता छोड़ो सुख से जियो, विकास के पथ, आगे बढ़ो, उन्नति की राहें इत्यादि किताबें उन्हें सुकून देने के साथ प्रेरित भी करती हैं। इसके अलावा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्माल थिंग्स, मुस्लिम फिलॉसफी एंड फिलॉसफर्स, हिंदी व अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध 101 व्यक्तित्व की जीवनी, पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया, झुग्गी अरुण साहिबाबादी का गजल संग्रह आदि किताबें पाठकों को खूब भाती हैं।

प्रतिस्पर्धा से जगती है पढ़ाई की ललक : इस पुस्तकालय की खासियत यह है कि यहां आने वाले ज्यादातर छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले होते हैं, इसलिए एक-दूसरे को देखकर उनमें पढ़ाई की ललक जगती है। पुस्तकालय परिसर में एक पार्क भी है। जिन छात्रों को खुले व हरियाली भरे वातावरण में पढ़ने का मन होता है वे किताबें लेकर पार्क में लगी बेंच पर बैठकर पढ़ाई का आनंद लेते हैं। यहां बह्मपुर, मौजपुर, सीलमपुर, करावल नगर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। वर्तमान में करीब 300 लोगों ने पुस्तकालय की सदस्यता ली हुई है।

उच्च पदों पर नौकरी पा रहे छात्र : यहां ज्यादातर एसएससी, यूपीएससी, नेट, सीए आदि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ने आते हैं। छात्र कहते हैं यहां बैठकर पढ़ने से उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दूर-दूर से बच्चे यही सपना लेकर पढ़ने आते हैं कि वे भी यहां से पढ़कर अधिकारी के पद पर नियुक्त होंगे। संयोजक विष्णु दयाल कहते हैं कि हर वर्ष 4-5 बच्चे या तो अधिकारी बनकर निकलने हैं। इस वर्ष भी तीन बच्चों ने सीए की परीक्षा पास की।

ऐसे लें सदस्यता : शुरुआत में यहां पढ़ाई करने के लिए 10 रुपये सदस्यता शुल्क लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। स्कूली छात्रों के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क 250 रुपये व अन्य के लिए 500 रुपये है। साल के किसी भी दिन सदस्यता ली जा सकती है, लेकिन यह सदस्यता सिर्फ 31 मार्च तक मान्य होती है।

ऐसे पहुंचे : सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से 10-15 मिनट पैदल चलकर या ऑटो रिक्शा से प्रगति पुस्तकालय पहुंचा जा सकता है।

खुलने का समय : सोमवार से शनिवार तक सुबह आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक और रविवार को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक यहां पढ़ाई कर सकते हैं।

-रितु राणा

बातचीत

दिल्ली से भाषाई खाद मिली और लेखन समृद्ध हो गया

डोगरी भाषा की खूबसूरत और चंचल कवयित्री, फैज से लेकर मोमिन तक को गुनगुनाना, हर भाषा के प्रति स्नेह सम्मान, बीमारियों को धता बताकर अस्सी वर्ष की उम्र में जीने की चाहत जिनकी जिंदादिली का प्रमाण है। जिनकी रचनाओं को देखकर रामधारी सिंह दिनकर ने कलम छोड़ने की बात कर दी, ऑल इंडिया रेडियो की एंकर, उद्घोषिका और समाचार वाचक, गीतकार, पद्मश्री व साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजी गईं पद्मा सचदेव आज भी उसी चुलबुलेपन से मिलती हैं। जम्मू से दिल्ली और डोगरी से हिंदी भाषा तक के सफर के उतार चढ़ाव, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति चिंता, साहित्यकारों की बैठकों जैसी तमाम बातें और उनसे जुड़ी यादों के बारे में **प्रियंका दुबे मेहता** ने **पद्मा सचदेव** से विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश :

● आपने डोगरी में कविताएं लिखीं और फिर हिंदी लेखन में आईं, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई?

मैं राजपुरोहित की बेटी हूं। पिता जी बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी वजह से मुझे संस्कृत के श्लोक कंठस्थ हो गए थे। आर एक बार संस्कृत आ जाए तो कोई भाषा कठिन नहीं लगती। मुझे कविता लिखना अपने आप ही आ गया। लोकगीत गाना बहुत अच्छा लगता था। जहां भी लोकगीत चल रहे होते थे वहां मैं अपने छंद जोड़ देती थी और धीरे धीरे कविता लिखना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि किसी भी रचना शैली को लिखना सीखा नहीं जाता, वह अपने अंदर से अपने आप आती है। मैंने डोगरी में कविता लिखीं और आलेख व साक्षात्कार हिंदी में लिखें।

● जम्मू से दिल्ली कैसे कब आना हुआ?

मैं जम्मू में ऑल इंडिया रेडियो से आठवीं के बाद ही जुड़ गई थी। एक कविता पढ़ने के बीस रुपये मिलते थे। उसी दौरान सरदार जी से मुलाकात हुई और वे दिल्ली के थे। उन्होंने दिल्ली आने की बात रखी, मुझे लगा मेरा इकलौता मित्र, जो मुझसे दास्तानें सुनता था वह दूर हो जाएगा। फिर उद्घोषक के लिए साक्षात्कारों की घोषणा हुई तो मैंने उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया और मुझे दिल्ली बुला लिया गया।

● फिर एक नए शहर को जम्मू जैसी जगह से आने के बाद कैसे देखा? कैसी लगी दिल्ली?

जम्मू में लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं। पहली बार दिल्ली आकर थोड़ा अंतर महसूस हुआ लेकिन धीरे-धीरे यहां की आबोहवा में घुल मिल गई। इंडिया गेट के पास कामकाजी महिला होस्टल में रहती थीं। तब दिल्ली बेहद शांत और खुली थी। कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाजार और चांदनी चौक का हिस्सा उस दौर में भी चकाचौंध से भरा था। हम अक्सर इंडिया गेट घूमने जाया करते थे। पालिक बाजार व अन्य जगहों पर विंडो शॉपिंग करना मुझे बेहद पसंद था।

● और लेखन पर इस शहर का क्या प्रभाव पड़ा?

मैं मूल रूप से कवियत्री थी। डोगरी भाषा के गीत, लोकगीत व छंदोबद्ध कविताएं लिखती थी। दिल्ली में आकर पंजाबी, हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के कवियों व लेखकों से मुलाकात होने लगी। जिससे मेरे लेखन को खाद मिलने लगी और मेरी लेखनी और समृद्ध होती गई।

● आपके समकालीन कवियों और लेखकों में किन लोगों से ज्यादा मेलजोल होता था?

मैं फैज अहमद फैज की प्रशंसक थी। ब्राउनिंग की मुक्त छंद की कविता का फैज ने जो अनुवाद किया था, 'मुझे दे दो रसीले होंठ, मासूमाना पेशानी, हसीं आंखें कि मैं इक बार फिर रंगीनियों में गर्क हो जाऊं, मिरी हस्ती को तेरी इक नजर आगोश में ले ले'। अपने आप में किनी अद्भुत कृति थी। वे लंदन रहते थे। याद है कि किस तरह से मैं, इस्मत आपा (इस्मत चुगताई) और फैज एक साथ बैठते थे। इस्मत आपा से इतना गहरा स्नेह था कि वे 10-15 दिन आकर घर रह जाती थीं। समकालीन लेखकों में पंजाबी लेखक पापा जी, पाश आदि से मुलाकात होती थी।

● आज की दिल्ली और उस दौर की दिल्ली में कितना अंतर पाती हैं?

आज की दिल्ली बड़बोली हो गई है। उस समय शांत थी। आज लोग ज्यादा हो गए हैं। व्यवस्था बिगड़ने लगी है। प्रदूषण से लेकर सड़कों तक का हाल उस दौर में ऐसा नहीं था।

● उस दौरान लेखकों की बैठकियों में आप हिस्सा लेती थीं?

मैं उन बैठकियों में जाना पसंद नहीं करती थी जो बाहर होती थीं। उस समय किसी के घर में बैठकी होती तो मैं जरूर जाती थी। इन बैठकियों में आकर्षण होती थीं अमृता प्रीतम। मुझे याद है, जब मैं जम्मू में थी तो मुझे जम्मू की अमृता प्रीतम कहते थे। मैं अमृता जी को बहुत ज्यादा पसंद करती ती लेकिन फिर भी मैं कहती थी कि मैं जम्मू की पद्मा हूं।

● कविताओं के अलावा लेखन कैसे शुरू हुआ? इसमें आपने डोगरी भाषा की परिधि से निकलकर हिंदी में लेखन किया।

डोगरी में कविता लिखती और हिंदी में आलेख। लेखन कुछ इस तरह शुरू हुआ कि मैं डॉ. धर्मवीर भारती से मिलने गई। बाद में उन्हें राखी भी बांधती थी। उस दौरान डोगरी भाषा की पहली कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी। उन्होंने धर्मयुग में कुछ लिखने को कहा। मैं जैसे ही उड़कर घर पहुंची और लिखने बैठ गई। भारती जी ने उस लेख की सराहना की और फिर मैं आगे बढ़ती चली गई।

● लेखन सफर की कोई ऐसी याद जो आज भी जेहन में बसी हुई हो?

रामधारी सिंह दिनकर को जब पहली बार मैंने जम्मू में देखा था तो उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने उसी समय ठान लिया कि मैं अपनी पहली किताब की भूमिका उन्हीं से लिखवाऊंगी। उनकी एक छात्रा से मेरी दोस्ती थी। मैंने उनसे जिक्र किया और उन्होंने उन्हें मिलने के लिए तैयार कर लिया। मुझे उन्होंने पांच मिनट का समय दिया क्योंकि उन्हें संसद भी जाना था। मैं बैठी। मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या डोगरी लोकगीत आते हैं? गा सकती हो? मैंने गीत सुनाए। वे संसद भूल गए और मैं चार घंटे वहां बैठी रही। 'मेरी कविता, मेरे गीत' की जो भूमिका उन्होंने लिखी वह आज भी मेरे लिए धरोहर है। उन्होंने कुछ यूं लिखा था -'पद्मा की कविताएं देखकर लगा रहा है कि मैं अपनी कलम फेंक दूं, वही अच्छा है।' उन्होंने मेरी नज्म का अनुवाद बड़ी खूबसूरती से किया था।

● जिन साहित्यकारों और लेखकों से मेलजोल रखती थीं उनसे घरेलू संबंध हो जाते थे, ऐसे में कोई खास याद?

नामवर जी से अच्छे संबंध थे। उनकी बेटी मेरी दोस्त है। मुझे याद है कि जब उनकी नातिन पैदा हुई तो अस्पताल में नामवर जी बाहर बैठे थे। मैं ही उनके साथ थी। उनकी नातिन को जब नामवर जी की गोद में दिया तो वे घबरा गए, उस समय लगा कि वे बस ज्ञाता बनते हैं, उन्हें बच्चे संभालने नहीं आते।

● आजकल कविताओं का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लेखक आ गए हैं, आज के काव्य लेखन पर क्या कहेंगी?

आजकल मुक्त छंद हावी है। ऐसा नहीं है कि मुक्त छंद अच्छा नहीं लगता लेकिन वह स्तरीय तो हो, उसका कोई अर्थ तो हो, भाषाई गंभीरता तो हो। लेखक ब्राउनिंग ने मुक्त छंद की कविता लिखी थीं और फैज ने उसका जो अनुवाद किया था, वह भी मुक्त छंद था लेकिन उसमें रस था, भाषा का कसाव था, खूबसूरती थी। कवियों और लेखकों की सफलता उनके पाठकों से तय होती है। अगर पाठक पढ़ेगा ही नहीं, आपकी रचनाएं उसको प्रभावित ही नहीं करेंगी तो आप कैसे चल सकते हैं। ऐसे में पढ़ना, लिखना और अपने विचारों को कविता के रस में डुबोना ही बेहतर लेखन का सूत्र बन सकता है।

● आपको क्या लगता है क्षेत्रीय भाषाओं में लेखन कम हो रहा है?

दक्षिण भारतीय अपनी भाषा बचाकर रख रहे हैं। उत्तर के कुछ लोग तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन जितने प्रयास होने चाहिए उतने नहीं हो रहे हैं। अपनी भाषाओं व बोलियों को बचाने की जरूरत है। बच्चों को अपनी भाषा जरूर सिखानी चाहिए नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भाषाएं इतिहास की भाषाएं बनकर रह जाएंगी।

● फिल्मों के लिए भी गीत लिखे, बाद में इसे जारी क्यों नहीं रखा?

मैं मुंबई में भी रही हूं। वहां मेरे घर से सात मिनट के फासले पर जयदेव जी का घर था, वे म्यूजिक डायरेक्टर थे। मेरे पति से भी उनकी दोस्ती थी। मेरे पिता जी का नाम भी जयदेव था तो उनके अच्छी रिश्ते हो गए थे। उन्होंने मुझसे गीत लिखने को कहा तो मैने 'छोटा सा घर बार मेरे अंगना में...' लिखा। इसे लता दीदी ने गाया था। हमारे घर के सामने कल्याण जी रहते थे। उन्होंने मेरे पति से कहा कि पद्मा गीत लिखे और लता जी को गाने के लिए तैयार करें, उनके डेट्स ले लें। मैंने दीदी से बात की तो दीदी ने कहा कि तेरे लिखे गीत मैं जरूर गाऊंगी लेकिन मैं रास्ते भर सोचती रही कि इतनी गहरी दोस्ती का मैं ऐसा फायदा नहीं उठाऊंगी। इसके अलावा दिनकर जी ने मुझे कहा कि साहित्य छोड़कर तुम यह जूता काटने का काम क्यों कर रही हो। यह दोनों बातें मुझे इस कदर चुभीं कि मैंने फिल्मों में गीत न लिखने का निर्णय कर लिया।

● लता मंगेशकर जी के साथ एक तरह का बंधन साझा किया है, आज आपसे कैसे संबंध हैं?

दीदी (लता मंगेशकर) और आशा दीदी दोनों ही मेरी परम मित्र हैं। दीदी की मैं इकलौती दोस्त हूं और सुबह शाम दोनों समय हमारी बात होती है। बस मैं इतना चाहती हूं कि मेरी दीदी जल्द ठीक हो जाएं। हालांकि वे नब्बे वर्ष की हैं ऐसे में डर बहुत लगता है लेकिन दीदी अमर हैं। उन्होंने पूरे देश को गाना सिखा दिया। अपने गीतों से लोगों के दिलों में बसी हैं। आशा दीदी पर तो मैंने लेख भी लिखा है। 'तुम, तोम तराना...' मैं साक्षात्कार लेती थी। मैंने बर्मन दा से उनके बारे में बात की थी और उनके नजरिए से आशा दीदी पर लेख दिया था।

ज्ञान-विज्ञान के साथ मिलेगी प्रेरणा

काम की दुकान

नए-नए डिजाइन के कपड़ों की खरीदारी के लिए आप कनॉट प्लेस स्थित जनपथ मार्केट तो अक्सर जाते होंगे, पर क्या कभी वहां हैरी पॉटर की जादुई दुनिया, ज्योतिष, हस्त रेखा विज्ञान, इंडियन आर्ट जैसी किताबों की खरीदारी की है। नहीं न, तो एक बार फेमस बुक स्टोर का रुख कर के देख लीजिए। यहां पहुंचते ही आंखों में किताबों की खूबसूरत दुनिया बस जाती है। एक ही स्थान पर आपको घर, राज्य, देश व विदेश की जानकारी से संबंधित सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी। तभी तो विदेशी पर्यटक भी यहां किताबों की तलाश में खींचे चले आते हैं। 96 वर्षों के सफर में इस दुकान ने किताबों का खजाना जमा कर लिया है जो यहां आने वाले पाठकों को खूब आकर्षित करता है।

ज्ञान के साथ प्रेरणा भी : एस्ट्रोलॉजी (ज्योतिष विज्ञान), पलमिस्ट्री (हस्त रेखा विज्ञान), न्यूम्रोलॉजी (अंकशास्त्र), मैनेजमेंट (प्रबंधन), योग, इनसाइक्लोपीडिया, इंग्लिश क्लासिक व प्रसिद्ध हिंदी क्लासिक, इंडियन आर्ट, इंटीरियर, गार्डनिंग, स्वास्थ्य, म्यूजिक व इंस्ट्रूमेंट पर आधारित किताबें, फैशन डिजाइनिंग, कुकिंग, घुड़सवारी, पेट केयर, पशु व पक्षियों की किताबें, धार्मिक किताबें, हिंदी व अंग्रेजी साहित्य की किताबें सब कुछ उपलब्ध है। अगर राज्यों की रेसिपी जाननी है तो राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, आदि राज्यों के खान-पान, संस्कृति, भूगोल की विस्तृत जानकारियों के लिए भी यहां हजारों किताबों का भंडार है। उर्दू किताबों का हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद जिसमें ढ़ेर सारी उर्दू व सूफी कविताओं की किताबें हैं। आभूषण में रुचि रखने वालों के लिए यहां कई एंटीक गहनों से लेकर नवीनतम गहनों की दुर्लभ किताबें भी उपलब्ध हैं। दुकान मालिक संजीव अरोड़ा कहते हैं कि उनके पास आत्मविश्वास में वृद्धि, बॉडी लैंग्वेज व कई प्रेरक किताबें हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद व्यक्ति तनाव से बाहर आ सकता है।

बच्चे भी कर सकते हैं ज्ञानवर्द्धन : छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक, माय मिनी लाइब्रेरी ऑफ लिटिल टेल्स, इंडियन फैरी, स्पोर्ट्स, मैजिक ट्रिक, डिजनी की पिक्चर डिक्शनरी, अंडरईज ट्रेजर नेशनल जियोग्राफीक सोसायटी आदि किताबों की खूब मांग होती है। इसके अलावा निबंध, कहानी, उपन्यास, कविता आदि से संबंधित हजारों किताबें हैं, जिसे पढ़कर बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है।

दुर्लभ व नवीनतम का मिश्रण : नासा द्वारा निकाली गई द यूनिवर्स स्पेस व फोर्स ऑफ नेचर और बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड आदि दुर्लभ पिक्चर्स बुक के साथ दुर्लभ जापानी कॉमिक नारुतो व डेयरडेविल द मैन विदाउट फियर आदि भी यहां मिल जाएंगे। अगर कश्मीर के बारे जानने को इच्छुक हों तो उनके लिए नवीनतम किताब कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी, कश्मीर रेज एंड रीजन, स्पाय क्रोनिकल्स रॉ आइएसआइ एंड द इल्यूजन ऑफ पीस आदि भी है। इसके अलावा इस वर्ष नोवल पुरस्कार प्राप्त किताब पूअर इकोनोमिक्स, बुकर अवॉर्ड से पुरस्कृत गर्ल वीमेन अदर व नेशनल अवॉर्ड से पुरस्कृत सुधा मूर्ति की किताबें भी यहां उपलब्ध हैं। सुधा मूर्ति ने अपने असल जिंदगी से प्रेरित होकर यह किताब लिखी है जो कि बच्चों व बड़ों दोनों के लिए अलग-अलग उपलब्ध है।.

हैरी पॉटर का विशेष संग्रह : अगर जादुई दुनिया को जानने में दिलचस्पी है तो जेके रोलिंग के अंग्रेजी उपन्यास हैरी पॉटर का यहां विशेष संग्रह है। हैरी पॉटर के पहले एडिशन से लेकर अब तक के सभी एडिशन मिल जाएंगे। इसकी हिंदी व अंग्रेजी की सभी किताबें यहां उपलब्ध है। इतना ही नहीं हैरी पॉटर की बीसवीं सालगिरह का रेयर एडिशन हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबन किताब पीले, काले, लाल, हरे समेत विभिन्न रंगों में उपलब्ध है, जो बहुत ही आकर्षक लगती हैं।

-रितु राणा

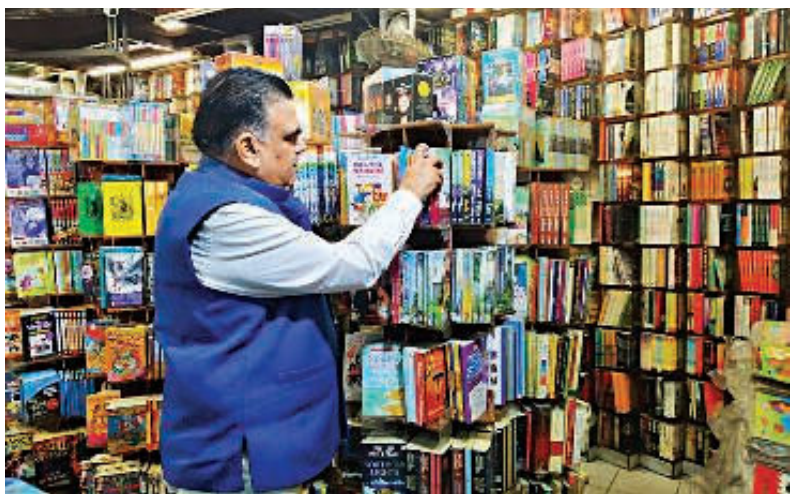
फेमस बुक स्टोर पर मिलेगा हर उम्र वर्ग के लिए किताबों का अद्भुत कलेक्शन। जागरण

पाकिस्तान से हुई शुरुआत

संजीव अरोड़ा के दादा गिरिजा राम ने 1923 में पाकिस्तान के क्वेटा शहर में फेमस बुक स्टोर खोला था। वह किसान परिवार से थे। लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। इसके बाद संजीवन के दादा और पिता अर्जुन देव ने कनॉट प्लेस में फुटपाथ पर किताबें बेचीं। 1950 में जब सरकार ने जनपथ बसाया तब उन्होंने भी यहां दुकान लगाई। पहले यह दुकान जनपथ मार्केट में थी। 1970 में जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई तब उसमें चार दुकानें शरणार्थी कोटा में रखी गई और उन्होंने यहां अपनी दुकान खोल ली।

यारी-दोस्ती और दिल्ली की दिलदारी

दिल्ली मेरी यादें

एक तरफ मेरा बचपन साइकिल में पैडल लगा रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली शहर में भी विकास के पैडल लग रहे थे। मेरी उम्र यही कोई दस वर्ष रही होगी जब पिता जी को नौकरी मिली और हम दिल्ली आ गए। 1955 की बात है, यहां सबसे पहले हम रमेश नगर में किराए के घर में रहे। रमेश नगर विभाजन के बाद यहां आए लोगों के लिए बसाया गया था, यहीं पर लोगों को जमीन और घर मिले थे।

कह सकते हैं शहर और हमारे परिवार दोनों का ही संघर्ष का दौर चल रहा था। लेकिन जब ऐसे संघर्ष भरे दौर के बीच भी घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है तो वो हर दुख पर भारी पड़ती है। साइकिल के उस युग में हम तीन दोस्त बनें आनंद भूषण, वेद हांडा और मैं। स्कूल में एक और दोस्त इन दोनों से अलग था रमेश मलहोत्रा उन्होंने ही मुझे सबसे पहले कुशवाह कांत की एक किताब पढ़ने को दी और मुझे पढ़ने का चस्का लग गया। यही कोई आठवीं क्लास की बात होगी। मतलब किताब पढ़ने का ऐसा चस्का लगा था कि मैं दिन में दो-तीन किताब खत्म कर जाता था। एक तरफ पढ़ने का सिलसिला चल रहा था। मैं हरिवंश राय बच्चन, नीरज, नेपाली, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत को पढ़ रहा था तो दूसरी तरफ हमारी तिकड़ी खूब खुराफाती थी, स्कूल में हम तीनों का पूरा भौकाल रहता था। ये दोस्ती बनी भी कुछ ऐसी थी। हम तीनों में हांडा सबसे ज्यादा पैसे वाला था। मैं चूंकि पढ़ने में ठीक था तो हांडा मुझसे होमवर्क कराता था और बदले में मुझे मिठाई, छोले-भटूरे खिलाता था। तीनों उसी के पैसे से फिल्में देखने जाया करते थे। फिल्मिस्तान में बहुत फिल्में देखीं। उसी के सामने एक रसगुल्ले वाला था उसके यहां खूब रसगुल्ले भी खाए। उस दौर में हमने मौज मस्ती में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई जगह ईंट भट्टे होते थे हम वहां चले जाते और छिप-छिपकर सिगरेट पिया करते थे। अपने शिक्षकों का मजाक बनाया करते। फिल्में देखते-देखते हीरो बनने का ऐसा शौक चढ़ा कि एक दिन हम तीनों घर से भाग गए। ट्रेन पकड़कर मुंबई जाना था, लेकिन कुछ पता नहीं था इसलिए अमृतसर पहुंच गए। एकाध दिन वहां रहे जब हांडा के पैसे खत्म हो गए तो लौट आए। वैसे हमारी तलाश में लगे परिवार वालों ने हमें ट्रेस भी कर लिया था। मैं सोच रहा था अब घर क्या मुंह लेकर जाएं, लेकिन परिवार में किसी ने कुछ नहीं कहा, मां का रो रोकर बुरा हाल था। तब समझ आया परिवार क्या होता है और यहीं से मेरी जिंदगी में काफी कुछ बदल गया।

इसके बाद ये दोनों दोस्त भी अलग हो गए थे क्योंकि हमारा परिवार कर्मपुरा शिफ्ट हो गया। यहीं से मेरा साहित्यिक विकास होने लगा था। स्कूल में ही ज्ञान वाटिका पत्रिका निकालने लगा, कविता, कहानियां भी पत्रिकाओं में छपने लगीं थीं। एक दोस्त रमेश मलहोत्रा अभी भी साथ था। एक दिन हम दोनों कनॉट प्लेस घूमने गए, वहां सेंट्रल पार्क तब भी था, लेकिन अब जैसा नहीं था। हम दोनों बस से उतर कर इनर सर्कल में घूमने लगे। घूमघाम कर घर लौटना था, लेकिन हम बाहर निकल कर बस स्टैंड तक नहीं पहुंच पाए। तीन-चार बार इनर सर्कल का चक्कर लगाते रहे लेकिन घमूकर वहीं सर्कल के अंदर ही खुदको पाते थे। बड़ी मुश्किल से किसी से पूछने के बाद हम बाहर निकल पाए। 1962-63 की बात है इसी दौर में दिल्ली का विकास भी हो रहा था। राजौरी गार्डन, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, एम्स ये सब बन रहा था। पहले पश्चिमी दिल्ली बसी थी उसके बाद दक्षिणी दिल्ली के इलाके बसे थे। मैंने अभी शुरुआत ही की थी लेखन के लिए मेरे पंख खुले ही थे कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दबाव बना और मुझे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। दो साल 1963-65 तक मेरी पढ़ाई रुक गई। उन दिनों चिटफंड कंपनी होती थीं तो लाजपत नगर मार्केट के पास उसी में नौकरी की। साथ में अपने स्तर पर तैयारी कर सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देता रहा। कुछ दिन बाद ही रेलवे में नौकरी मिल गई। फिर पढ़ाई शुरू की साथ में नौकरी भी करते रहे। रेलवे मंत्रालय में ही एक दोस्त बना सुरेश धींगड़ा। हम दोनों ने दिल्ली कॉलेज से बीए किया। बाद में नार्थ कैंपस से एमए किया। हम शाम वाली शिफ्ट में थे। तब दिल्ली विवि परिसर में कई गोष्ठी भी हुआ करती थी। इन दिनों मैं जैनेंद्र कुमार जी के संपर्क में आ गया था। उन्होंने 'मनीषा' नाम से मंच बनाया था दरियागंज में गोष्ठी करते थे, वहीं कहानियों की भी 'सननिधि' नाम से गोष्ठी होती थी। जिसमें सभी छोटे-बड़े साहित्यकार आया करते थे। इसके अलावा 'प्रगति', 'प्रज्ञा' और 'अथवा' नाम से भी कई गोष्ठी शुरू हुईं, जो कई साल तक चलीं। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में प्राध्यापक हो गया। 1986 में मैंने 'गावाक्ष' नाम से साहित्यिक मंच बनाया था। राजौरी गार्डन स्थित घर के छत पर गोष्ठी करता था। तकरीबन 14 साल तक मंच चला। इसमें हरिवंश राय बच्चन, गिरिजा कुमार माथुर, रामनाथ अवस्थी, केदारनाथ आया करते थे। अब तो ऐसे मंच खत्म से ही हो गए।

बहरहाल अब आपको अपनी शादी का रोचक किस्सा बताता हूं। मेरा विवाह शशि सहगल से हुआ। हमारी शादी 5 दिसंबर, 1971 को होनी थी। इससे तीन दिन पहले ही भारत-पाकिस्तान की जंग छिड़ गई। और घरों में कैद रहने के निर्देश दे दिए गए। रात के वक्त ब्लैक आउट रहता था। अब शादी कैसे हो? हमने तो सभी जगह कार्ड बांट दिए थे रात का फंक्शन था। तब चुनिंदा घरों में ही फोन होते थे। एक-दूसरे के जरिए सभी तक संदेश पहुंचवाया गया कि अब शादी दिन में होगी। जैसे-तैसे शादी संपन्न हुई। घर वालों ने हनीमून पर नहीं जाने दिया। मैंने दिल्ली में दो बार युद्ध वाला माहौल देखा एक बार 1962 में और दूसरा 1971 में। जब सुरंगे बना दी जाती थीं कि जरा भी कुछ हालात बिगड़ते दिखें तो इन सुरंगों में सपरिवार सब चले जाएं। वाकई दिल्ली के अद्भुत संस्मरण रहें हैं। पहले दिल्ली में बसों की भी बहुत दिक्कत थी घंटों बसों का इंतजार करना पड़ता था। जब कमलापति त्रिपाठी परिवहन मंत्री हुए तो उन्होंने रिंग रोड बनवाई और उसी दौर में मुद्रिका बस चलनी शुरू हुई थी उससे लोगों को कुछ राहत हुई।

-मनु त्यागी से बातचीत पर आधारित

प्रताप सहगल नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, आलोचना...में विभिन्न रचनाएं कर चुके हैं। भरपूर लेखन के लिए मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य कला परिषद द्वारा सम्मान, सौहार्द सम्मान, राजभाषा और हिंदी अकादमी साहित्यकार जैसे कई सम्मान भी मिले।

मिल्टन को ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड

नई दिल्ली (वि) : हाउसवेयर प्रोडक्ट ब्रांड मिल्टन को वर्ल्ड ब्रांडिंग अवार्ड्स 2019 के अवसर पर लंदन में आयोजित समारोह में 'ब्रांड ऑफ द ईयर' अवार्ड दिया गया है। इस अवसर पर दुनिया के बड़े ब्रांड मसलन नेटफ्लिक्स, कैडबरी (यूके), थाई एयरवेज और एक्वा गल्फ जैसे ब्रांडों को अवार्ड मिला है। यह अवार्ड ग्राहकों की वोटिंग के आधार पर दिया जाता है। मिल्टन देश का अकेला ऐसा ब्रांड है जिसे यह अवार्ड मिला है। हैमिल्टन हाउसवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक व संस्थापक अजय वघानी ने कहा कि ग्राहकों ने मिल्टन पर ग्राहकों का भरोसा हमारे लिए खुशी की बात है।

अमेरिका को हुआवे पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में हम विकल्प तैयार कर लेंगे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियों को उठाना पड़ेगा।
— रेन झेंगफेई, सीईओ, हुआवे

सेंसेक्स	41,020.61	▲ 199.31
निफ्टी	12,100.70	▲ 63
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 38,503	▼ ₹35
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 45,345	▲ ₹147
$ डॉलर	₹ 71.35	▼ ₹0.15
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 64.51	

न अभी मंदी है, न आगे इसका कोई खतरा है : सीतारमण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में मंदी पर विपक्ष के आरोपों को किया खारिज
- संप्रग सरकार के मुकाबले राजग सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेहतर किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में आर्थिक मंदी के विपक्ष के आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर राज्यसभा में हुई चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन न कोई मंदी है और न आगे इसका कोई खतरा है। हालांकि वित्त मंत्री के जवाब से कांग्रेस, तृणमूल और वाम सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया।

अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को ठीक बताते हुए सीतारमण ने कहा कि गत दो वर्षों से जीडीपी में जो गिरावट दिख रही है, वह बैंकों के एनपीए तथा कॉरपोरेट सेक्टर पर कर्ज के बोझ के कारण है। इसीलिए सरकार ने बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान की है। अब जीडीपी के मुकाबले कर का अनुपात 5.5 फीसद से बढ़कर 5.58 फीसद हो गया है। पहली छमाही में राजस्व प्राप्तियां बढ़कर 18 फीसद हो गई हैं, जबकि राजस्व खर्च 13.97 फीसद और पूंजीगत व्यय 15.31 फीसद है। हम चुनौतियों के प्रति पूरी तरह सचेत हैं।

राज्यसभा में आर्थिक मोर्चे पर पक्ष रखतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। टीवी ग्रैब, एएनआइ

अर्थव्यवस्था को सुधारने में प्रधानमंत्री स्वयं व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने अब तक 32 कदम उठाए हैं जिनके परिणाम आने लगे हैं। 2019-20 के लिए 6.63 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह के लक्ष्य के मुकाबले पहले सात महीनों में 3.26 लाख करोड़ का संग्रह हो चुका है। कर प्रशासन में सुधार किया गया है और कॉरपोरेट फ्राड रोकने के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया है। नोटबंदी से नकदी प्रवाह में कमी के आरोपों पर वित्तमंत्री ने कहा सरकारी बैंकों के जरिये 2.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण बांटे गए हैं। क्या यह नकदी के बिना संभव था।

ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थिति पर सीतारमण ने कहा कि इस सेक्टर की समस्या अप्रैल, 2020 से बीएस-6 लागू होने की अनिवार्यता के कारण पैदा हुई है। वित्त मंत्री ने हर सेक्टर का ध्यान रखने का भरोसा जताया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें फसल का सही मूल्य दिया जाएगा। किसानों को कर्ज समेत अन्य सभी मदद मिलेगी। बन चुके मकानों के बिल्डरों को मदद दी जा रही है। खरीदारों को रियायतें भी दी जा रही हैं।

पहले से बेहतर स्थिति : वित्त मंत्री ने दावा किया कि संप्रग सरकार के आखिरी पांच वर्षों के मुकाबले राजग सरकार के शुरुआती पांच वर्ष बेहतर रहे हैं। 2009-14 के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4 फीसद थी। जबकि 2014-19 के दौरान यह दर 7.5 फीसद रही है। यही नहीं, संप्रग-2 में सामान्य महंगाई दर 9.4 फीसद और खाद्य महंगाई दर 11.2 फीसद थी। राजग-1 में सामान्य महंगाई दर घटकर 6.4 फीसद और खाद्य महंगाई दर 3.5 फीसद पर आ गई। तब एफडीआइ 189.5 अरब डॉलर था, जो भाजपा राज में बढ़कर 283.9 अरब डॉलर हो गया। हमने विदेशी मुद्रा कोष को 304.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 412.6 अरब डॉलर पर पहुंचा दिया है।

पूरी दुनिया में मंदी : इससे पहले भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष मोदी विरोध की भावना से अर्थव्यवस्था के बारे में बातें कर रहा है। हकीकत यह है कि अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान समेत पूरा विश्व मंदी की चपेट में है। भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है। फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। सरकार ने सारी योजनाएं गरीबों को ध्यान में रखकर ही चलाई हैं। सुरेश प्रभु ने भी वैश्विक मंदी के असर की बात कही।

आर्थिक मंदी के मसले पर विपक्ष ने की सरकार की घेराबंदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में विपक्षी दलों ने अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर सरकार की जमकर घेराबंदी की। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आर्थिक मंदी से लोगों की कठिनाइयों और लगातार घटती नौकरियों से गहराते संकट को लेकर भी सवाल उठाया।

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सभी मानकों पर अर्थव्यवस्था गहरे संकट में दिखाई दे रही है। आर्थिक मंदी का आलम यह है कि आम लोगों के लिए रोजाना की जरूरी चीजें खरीदना कठिन हो गया है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। औद्योगिक उत्पादन से लेकर ढांचागत क्षेत्र के विकास की गति लगभग ठप है। निर्यात निरंतर घट रहा है और भारत का व्यापार घाटा चिंताजनक असंतुलन की स्थिति में है। विदेशी ही नहीं अपने देश के कारोबारियों का विश्वास सरकार की नीतियों और अर्थव्यवस्था में इस तरह टूट गया है कि लोग निवेश नहीं कर रहे। इससे नई नौकरियां नहीं पैदा हो रहीं, बल्कि मौजूदा लाखों लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। अकेले टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25 लाख नौकरियां छिन चुकी हैं।

सच स्वीकार करे सरकार : आनंद शर्मा का कहना था कि सबसे चिंता की बात यह है कि सरकार आर्थिक मंदी की इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है। सच्चाई यह है कि नोटबंदी और जीएसटी की खामियों के दोहरे प्रहार ने छोटे व मध्यम कारोबार को लगभग तबाह कर दिया है। कॉरपोरेट टैक्स में डेढ़ लाख करोड़ रुपये की छूट पर उन्होंने कहा कि उद्योग इस राशि का निवेश में उपयोग नहीं करेंगे बल्कि अपना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेंगे, जिसका फायदा आमलोगों को नहीं मिलने वाला।

अन्य दलों ने भी जताई चिंता

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मंदी के चलते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए सरकार को इधर-उधर की बातें छोड़ आर्थिक हालत सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आर्थिक कुप्रबंधन के लिए सीधे पीएम मोदी जिम्मेदार बताया।

कवायद ▶ 31 मार्च तक पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए खरीदार तलाश रही सरकार

नहीं बिकी तो बंद हो जाएगी एयर इंडिया

विमानन कंपनी के लिए बेहतर डील की हो रही कोशिश

नई दिल्ली, आइएएनएस : सरकार ने कहा है कि अगर एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हुआ तो इसका परिचालन बंद करना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा को बताया कि सरकार इस सार्वजनिक विमानन कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। 31 मार्च, 2020 तक इसके विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी अभी इसके मूल्यांकन में जुटे हुए हैं। इसके बाद बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।

एयर इंडिया काफी समय से घाटे में चल रही है। इसके चलते सरकार पहले भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्रयास कर चुकी है। सरकार ने पिछले साल मई में इसमें 76 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी। उस दौरान एक भी निजी खरीदार ने इस सौदे में रुचि नहीं दिखाई थी। हालांकि अब एविएशन सेक्टर के हालात जुदा हैं। जानकारों का मानना है कि इस बार एयर इंडिया को खरीदार मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा कंपनी को आकर्षक बनाने के लिए इसके कर्ज को कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बोली आमंत्रित करने से पहले एयर इंडिया प्रमुख अश्विनी लोहानी संभावित निवेशकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले पुरी ने कहा था कि एयर इंडिया के मसले पर बातचीत करने के लिए मंत्रियों के समूह ने पिछले सप्ताह बैठक की थी। इस बैठक में कुछ जरूरी फैसले लिए गए थे। इस सरकारी विमानन कंपनी के पास भारत सहित दुनियाभर में लाभप्रद लैंडिंग स्लॉट और अन्य संपत्तियां हैं। फिलहाल कंपनी कर्ज के बोझ तले दबी हुई और परिचालन का खर्च चुकाने में असमर्थ है। यहां तक कि कई बार कंपनी अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में विफल रही है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश के एविएशन सेक्टर में हर वर्ष 100 पायलटों की जरूरत है। यह मांग अभी पूरी नहीं हो पा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी को अपग्रेड करेगी।

कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखेगी सरकार : नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि निजीकरण होने तक एयर इंडिया के किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। इसके साथ ही समझौते में भी कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने उन रिपोर्ट को भी खारिज किया, जिनमें कुछ पायलटों के नौकरी छोड़ने की बात कही जा रही है। पुरी ने बताया कि वित्तीय संकट के दौरान कर्मचारियों का 25 परसेंट वेतन रोक लिया गया था। विनिवेश से पहले ही उनका पूरा वेतन चुका दिया जाएगा। इस बीच पुरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज के कर्मचारियों की नौकरी संबंधी चिंताएं उड्डयन मंत्रालय के कार्यक्षेत्र से संबंधित नहीं हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि पूर्व कर्मचारियों को नौकरी तलाशने में मदद के लिए एक पोर्टल खोला गया है।

राज्यसभा में सवालों के जवाब देते केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। टीवी ग्रैब, प्रेट्र

अंतरराष्ट्रीय उड़ान में यात्री बढ़े, कार्गो सेक्टर में गिरावट

कुआलालंपुर, एएनआइ : इस वर्ष अक्टूबर के दौरान अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों की संख्या में ठीक-ठाक इजाफा हुआ। लेकिन कार्गो (माल) परिवहन में सुस्ती देखी गई। बुधवार को एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइन (एएपीए) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के दौरान 3.07 करोड़ यात्रियों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 3.1 परसेंट अधिक है। हालांकि समीक्षाधीन अवधि में विमान द्वारा कार्गो परिवहन में 5.9 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई।

नए भारत के लिए बनाई जाएं नीतियां

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। सुरक्षित भविष्य के लिए अलग-अलग नीतियां बनाने और प्रभावी तरीके से उन्हें लागू करने की जरूरत है। नए भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, कृषि व ऑटो इंडस्ट्री को मजबूत बनाना होगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बातें बुधवार को आइएमटी मानेसर के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आइकेट) में आयोजित तीन दिवसीय न्यू जेन मोबिलिटी समिट के उद्घाटन के मौके पर कहीं। बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे गडकरी ने नई पहल को सरकार के सहयोग का भरोसा दिलाया।

गडकरी ने देश की तरक्की के लिए बेहतर सड़कों को जरूरी बताया। उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं है कि अमेरिका अमीर देश है इसलिए उसकी सड़कें बढ़िया हैं। वहां की सड़कें बढ़िया हैं, इसलिए अमेरिका अमीर देश है।' उन्होंने बताया कि पिछली योजना में देश में 22 बड़े हाईवे बनाने का कार्य किया गया। केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण के निपटने के लिए मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग पर जोर दिया। आइकेट के अधिकारियों को भी केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि वह इस ओर ध्यान दें।

गडकरी ने जलमार्ग द्वारा माल ढुलाई को उद्यमियों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि जलमार्ग विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। न्यू जेन मोबिलिटी समिट के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा भविष्य में बाजार में उतारी जाने वाली गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही विभिन्न ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनियों ने अपने उपकरणों की भी प्रदर्शनी लगाई है।

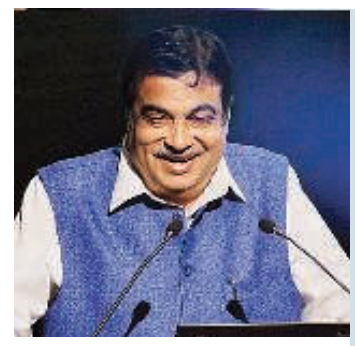

गुरुग्राम के आइकेट में बुधवार को शुरू हुए तीन दिवसीय न्यू जेन मोबिलिटी समिट को संबोधित करते केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। जागरण

- सुरक्षित भविष्य के लिए नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी
- केंद्रीय मंत्री ने विकास में अच्छी सड़कों के योगदान को अहम बताया

ऑटोमोबाइल क्षेत्र की होगी बड़ी भूमिका

न्यू जेन समिट के पहले दिन दुनियाभर के विशेषज्ञों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के भविष्य पर मंथन किया। इस दौरान इस पर बल दिया गया कि देश को आर्थिक शक्ति बनाने में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी। इस क्षेत्र में अनुसंधान व तकनीकी विकास को लेकर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2030 तक देश को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में ऑटोमोबाइल क्षेत्र भी विशेष भूमिका होगी। समिट के पहले दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। आइकेट के निदेशक दिनेश त्यागी ने कहा कि समिट के माध्यम से दुनियाभर में 125 वर्ष से चल रहे आइसी इंजन का विकल्प खोजने का अवसर मिलेगा। सेक्टर की चुनौतियों के समाधान के लिए तकनीक का विकास जरूरी है।

लागत में कमी पर सेल का नया अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्तीय दृष्टि से खुद को मजबूत करने की दिशा में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) ने देशभर में स्थित अपने सभी संयंत्रों व इकाइयों में लागत नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 'डू मोर विद लैस' के नाम से चलाया जा रहा है।

सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने नए सिरे से लागत नियंत्रण पर जोर देते हुए बड़ी संख्या में इसमें कर्मचारियों की भागीदारी पर जोर दिया है। सेल के बयान के मुताबिक कंपनी के सभी संयंत्र और इकाइयां लागत कम करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही हैं। इसके लिए सभी केंद्रों में विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यशालाओं का फोकस उत्पादन वृद्धि और तकनीकी-आर्थिक मानकों, कच्चे माल के बेहतर उपयोग और अन्य साधनों से आय बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर है।

ट्राई नहीं करेगा टेलीकॉम फर्मों के शुल्क निर्धारण में हस्तक्षेप

- कंपनियां पहले ही कर चुकी हैं शुल्क में वृद्धि की घोषणा

नई दिल्ली, प्रेट्र : दूरसंचार नियामक ट्राई फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों द्वारा किए जाने वाले शुल्क निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। टेलीकॉम कंपनियां पहले ही शुल्क में इजाफा करने की घोषणा कर चुकी हैं। इसलिए ट्राई न्यूनतम मूल्य निर्धारण से इस प्रक्रिया में रुकावट नहीं डालना चाहता। सूत्रों के मुताबिक ट्राई का कहना है कि जब टेलीकॉम कंपनियां मूल्य बढ़ाने का फैसला कर चुकी हैं, ऐसे में न्यूनतम मूल्य निर्धारण का कोई औचित्य नहीं बनता। गौरतलब है कि एयरटेल और वोडाफोन ने दिसंबर से शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद रिलायंस जियो ने भी शुल्क में इजाफा करने की बात कही थी।

ट्राई ने 2020 के लिए नियमन एजेंडे का खाका तैयार करने के लिए बुधवार को बैठक बुलाई थी। इस दौरान नियामक ने टेलीकॉम सेक्टर के कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। इनमें एजीआर, इन्फ्रास्ट्रक्चर में साझेदारी और न्यूनतम शुल्क जैसे मुद्दे शामिल हैं। न्यूनतम शुल्क निर्धारण के मसले पर टेलीकॉम सेक्टर बंटा हुआ है। इंडस्ट्री का एक धड़ा चाहता है कि न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाए। इसका मानना है कि सेक्टर में जरूरत से ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है। इसके चलते नियामकीय हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। हालांकि ट्राई ने फिलहाल इस पर विचार करने से मना कर दिया है। एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेक्टर पर देनदारी बहुत ज्यादा हो गई है।

इस बीच ट्राई ने टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से टैरिफ कैलकुलेटर जैसी व्यवस्था लाने की बात कही है। इसकी मदद से ग्राहकों को टेलीकॉम सेवाएं चुनने में आसानी होगी। फिलहाल नियामक ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ट्राई के इस कैलकुलेटर के माध्यम से अलग-अलग कंपनियों द्वारा दिए जा रहे प्लान की पूरी जानकारी, डाटा की स्पीड और पुराने प्लान से नए प्लान की तुलना संभव हो सकेगी।

अब सिर्फ जूट की बोरियों में ही होगी एफसीआइ में अनाज की पैकिंग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जूट किसानों और मिलों को राहत के उद्देश्य से सरकार ने अनाज की शत प्रतिशत पैकिंग जूट में ही करने का फैसला किया है। जूट पैकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रावधान अनिवार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) से ही जुड़े एक अन्य फैसले में सरकार ने निगम की अधिकृत पूंजी को बढ़ाने का फैसला लिया है।

कैबिनेट के फैसले में एफसीआइ की मौजूदा अधिकृत पूंजी को 3500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से एफसीआइ की अधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे एफसीआइ को केंद्रीय बजट से धन आवंटन हो जाएगा। इससे एफसीआइ को खुले बाजार से कम उधारी उठानी पड़ेगी और बैंकों से लिए जाने वाले भारी कर्ज पर लगने वाले ब्याज से राहत मिलेगी। इससे खाद्य सब्सिडी में कटौती करने में मदद मिलेगी।

प्रतीकात्मक फोटो

- जूट बोरी के प्रोत्साहन से किसानों और उद्योग को मिलेगी बड़ी राहत
- एफसीआइ की पूंजी को बढ़ाकर किया गया 10 हजार करोड़ रुपये

प्लास्टिक बोरी के इस्तेमाल की नहीं मिलेगी छूट

सरकार ने सभी तरह के अनाज की पैकिंग में जूट बोरी का प्रयोग को अनिवार्य बना दिया है। इसके पहले एफसीआइ को जूट बोरी की अनुपलब्धता के नाम पर प्लास्टिक बोरियों के उपयोग की छूट दी गई थी, जो अब नहीं रहेगी। इस फैसले से जूट किसानों और जूट उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत सरकार की खाद्य नीति को लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम अधिनियम-1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य एमएसपी सुनिश्चित करना, खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखना और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्नों का वितरण करना है।

वित्त आयोग का कार्यकाल एक साल बढ़ाया गया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का फार्मूला तय करने का काम कर रहे 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल सरकार ने एक साल और बढ़ा दिया है। वित्त आयोग का कार्यकाल अब 30 अक्टूबर, 2020 तक होगा। आयोग का कार्यकाल इस महीने 30 तारीख को समाप्त हो रहा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त आयोग को पहले वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए अंतिम रिपोर्ट देने की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। आयोग की अवधि अक्टूबर, 2019 में समाप्त हो गई थी लेकिन सरकार ने इसे 30 नवंबर, 2019 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने कहा है कि कार्यकाल बढ़ने से आयोग को राज्यों के वित्तीय अनुमानों का सही तरीके से अध्ययन करने का और वक्त मिलेगा। इससे आयोग को अगले पांच वर्ष के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी।

शेयर बाजार

चौतरफा उम्मीदों से मजबूत हुई निवेशकों की धारणा और बाजार में रहा उत्साह, यस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल

सेंसेक्स हुआ 41 हजारी, निफ्टी भी नए शिखर पर

मुंबई, प्रेट्र : बुधवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 199.31 अंक यानी 0.49 परसेंट उछाल के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर 41,020.61 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 63 अंक का सुधार देखा गया। निफ्टी 12,100.70 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में यस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 7.65 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। इसके अलावा एसबीआइ, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, मारुति सुजुकी, सन फार्मा और एचयूएल के शेयर भी 2.43 परसेंट की बढ़त के साथ बंद हुए। दूसरी ओर एलएंडटी, आइसीआइसीआइ बैंक, आइटीसी, टाटा स्टील, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक के शेयरों में 2.05 परसेंट तक की गिरावट आई।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक यूएस-चीन में प्राथमिक व्यापार समझौते को लेकर दोनों पक्षों से आई उत्साहवर्धक खबरों का बाजारों पर सकारात्मक असर पड़ा। इसके अलावा आरबीआइ द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से भी बाजारों को बल मिला है। इससे खासकर बैंकों के शेयरों में तेजी देखी गई है। बीएसई में मिडकैप और स्माल कैप में 0.82 परसेंट तक का उछाल दर्ज किया गया। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग, टोक्यो और सियोल ने वृद्धि दर्ज की, जबकि शंघाई लाल निशान पर बंद हुआ।

प्रतीकात्मक फोटो

इन शेयरों में रही गहमागहमी

यस बैंक : बुधवार को यस बैंक के शेयरों में तेज उछाल दर्ज किया गया। बीएसई में बैंक के शेयर 7.65 परसेंट की तेजी के साथ 68.25 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में 8.31 परसेंट चढ़कर बंद हुए। यहां यह 68.40 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। इससे पहले बैंक ने शेयर बाजारों को बताया था कि 29 तारीख को इसके बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में बैंक के लिए फंडिंग जुटाने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

एआरएसएस इन्फ्रा : अरुणाचल प्रदेश में रोड प्रोजेक्ट मिलने के चलते इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी एआरएसएस के शेयरों में करीब पांच परसेंट तक का उछाल दर्ज किया गया। दिन के कारोबार में बीएसई में कंपनी के शेयर 4.93 परसेंट तेजी के साथ 24.50 रुपये पर बंद हुए। वहीं एनएसई में भी इसके शेयरों में 4.90 परसेंट तक की तेजी देखी गई।

रिलायंस कैपिटल : बुधवार को इसके शेयर 3.5 परसेंट तक लुढ़क गए। बीएसई में कंपनी के शेयर 3.54 परसेंट की गिरावट के साथ 15 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में इनमें 2.57 परसेंट की गिरावट आई। इससे पहले कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया था कि वह बांड और उन पर दिए जाने वाले ब्याज को अदा करने में विफल रही है।

एचडीएफसी : असेट मैनेजमेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर एक परसेंट से अधिक उछाल के साथ बंद हुए। बीएसई में इसके शेयरों में 1.35 परसेंट की तेजी देखी गई। इस दौरान कंपनी के शेयर 3,642.15 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में इसके शेयर 1.51 परसेंट उछाल के साथ 3,633 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बिके। इससे पहले एचडीएफसी ने शेयर बाजारों को बताया था कि उसे एस्सेल ग्रुप से 167 करोड़ रुपये वापस मिले हैं।

स्क्रैप की किल्लत से फर्नेस उद्योग ने उत्पादन घटाया

राजीव शर्मा, लुधियाना

- ग्लोबल मार्केट में तेजी के चलते महंगा पड़ रहा है आयातित स्क्रैप

ग्लोबल मार्केट में स्क्रैप की कीमतों में तेजी का दौर है, जबकि घरेलू बाजार में कीमतें कम हैं, ऐसे में इंडक्शन फर्नेस उद्यमी स्क्रैप के आयात से हाथ खींच रहे हैं। इसका असर यह है कि घरेलू बाजार में इंडस्ट्री की मांग के मुकाबले स्क्रैप की आपूर्ति कम हो गई है। कच्चे माल कमी के कारण उत्पादन आधा हो गया है।

उद्यमियों का मानना है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू बाजार के मुकाबले स्क्रैप की कीमतें कम नहीं होतीं, तब तक इंडक्शन फर्नेस उद्योग पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। इंडस्ट्री अपनी जरूरत का करीब 30 फीसद आयात से पूरा करती है। करीब 80 लाख टन स्क्रैप की आपूर्ति ग्लोबल मार्केट से की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाई मेल्टिंग स्क्रैप नंबर वन की कीमत करीब 280 डॉलर प्रति टन है। इस भाव पर स्क्रैप खरीदकर लुधियाना में उद्यमियों को फैक्ट्री में इसकी कीमत 25 रुपये किलो पड़ती है, जबकि घरेलू स्क्रैप 23.50 रुपये किलो में उपलब्ध है। नतीजतन तीन-चार माह से उद्यमी आयात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पहले से ऑर्डर किया माल ही पहुंच रहा है।

ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जैन ने कहा कि प्रदेश में करीब 150 फर्नेस मिलें हैं। कच्चे माल की किल्लत के कारण मिलें पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही हैं। ज्यादातर मिलें सिर्फ रात में ही चल रही हैं, क्योंकि उद्योगों को रात में इकाइयां चलाने पर बिजली के फिक्स चार्जेज आधे लगते हैं। नार्दर्न इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन के प्रधान केके गर्ग ने कहा कि देश में आर्थिक सुस्ती के चलते उत्पादन कम है। खासकर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एवं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सुस्ती के चलते इंडस्ट्री से स्क्रैप भी कम निकल रही है।

3 टन कोकीन मिली है स्पेन के समुद्र तट से एक पनडुब्बी से। स्पेन के अधिकारियों ने बताया कि देश के उत्तर-पश्चिमी तट पर इसे बरामद किया गया। कहा गया कि यह पहली बार है जब पनडुब्बी से यूरोप में कोकीन की तस्करी की गई हो।

ढाका कैफे आतंकी हमले में सात को मौत की सजा

मिला इंसाफ ▸ हमले में एक भारतीय छात्रा समेत 20 लोगों की हुई थी मौत

आतंकियों को धन और हथियार मुहैया कराने के पाए गए दोषी, आतंकी संगठन से जुड़ाव साबित नहीं होने पर एक आरोपित बरी

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश की विशेष अदालत ने राजधानी ढाका के एक कैफे पर 2016 में हुए आतंकी हमले के मामले में बुधवार को सात लोगों को मौत की सजा सुनाई। बांग्लादेश के इस सबसे बड़े आतंकी हमले में भारतीय छात्रा समेत 20 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे।

आतंक रोधी विशेष ट्रिब्यूनल के जज मुजीबुर रहमान ने खचाखच भरे कोर्टरूम में सजा का एलान किया। उन्होंने कहा, 'दोषियों को मौत तक फांसी पर लटकाया जाए।' कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किए गए आरोपितों को कैफे पर हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को धन और हथियार मुहैया कराने का दोषी पाया गया। जज ने आठवें आरोपित को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष आतंकी हमले को अंजाम देने वाले प्रतिबंधित संगठन नव-जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (नव-जेएमबी) से उसका संबंध साबित नहीं कर सका था। जज ने अपने फैसले में बांग्लादेशी-कनाडाई तमीम चौधरी को हमले का मास्टरमाइंड करार दिया। चौधरी को सुरक्षा बलों ने आतंक रोधी कार्रवाई के दौरान मार गिराया था। ढाका के होली आर्टिजन कैफे पर हुए आतंकी हमले की दो साल की जांच के बाद आतंक रोधी शाखा ने पिछले वर्ष 23 जुलाई को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

इस आतंकी हमले ने 16 करोड़ की आबादी वाले इस देश को हिलाकर रख दिया था। खासतौर पर दूतावासों वाले इलाके में हुए इस धमाके ने बांग्लादेश की छवि को दुनियाभर में कमजोर करने का काम किया था।

ढाका में बुधवार को ढाका कैफे आतंकी हमले में विशेष अदालत द्वारा दोषी को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल ले जाते पुलिसकर्मी। एपी

पांच आतंकियों ने किया था हमला

हथियारों और गोला-बारूद से लैस पांच आतंकियों ने एक जुलाई, 2016 को ढाका के गुलशन मार्केट स्थित होली आर्टिजन कैफे पर धावा बोला था। उन्होंने कैफे में आए लोगों को 12 घंटे तक बंधक बनाए रखा था। सेना के कमांडो ने बाद में इन आंतकियों को ढेर कर दिया था। आतंकियों के हमले में मारे गए लोगों में नौ इतालवी, सात जापानी, एक भारतीय और तीन बांग्लादेशी थे। इस हमले की जिम्मेदारी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के धड़े नव-जेएमबी ने ली थी। इस धड़े ने खुद को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से प्रेरित बताया था।

छुट्टी मनाने गई थी भारतीय छात्रा

आतंकी हमले में जान गंवाने वालीं 19 साल की तारिषी जैन ढाका में छुट्टी मनाने गई थीं। वह अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं। न्यूज एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, तारिषी ने हमले के दौरान अपने परिवार को किए आखिरी फोन कॉल में कहा था, 'मैं दोस्तों के साथ टॉयलेट में छुपी हूं। मुझे लगता है कि हमें एक-एक कर मार दिया जाएगा।' उन्होंने अपने पिता और चाचा को फोन किया था। उस समय तारिषी के पिता बांग्लादेश में ही थे, जबकि उनके चाचा राकेश मोहन जैन उत्तर प्रदेश में थे।

अमेरिका को पछाड़ सर्वाधिक राजनयिक मिशन वाला देश बना चीन

चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा राजनयिक मिशनों का संगठन खड़ा कर दिया है। पचास साल पहले जहां चीन का सिर्फ एक दूतावास था, वहीं आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी राजनयिक ताकत के रूप में उभरा है। सिडनी स्थित लॉवी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन के राजनयिक मिशनों की संख्या 276 पहुंच गई है। वहीं अमेरिका के मिशनों की संख्या 273 है। इस सूची में भारत की रैंक 12वीं है और दुनिया में उसके 186 मिशन हैं। चीन का यह राजनयिक उभार उसकी अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जो वह समय-समय पर दर्शाता रहा है।

इसलिए पिछड़े अंकल सैम

चीन अपनी राजनयिक ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसके प्रतिकूल अमेरिका इस मामले की लगातार अनदेखी कर रहा है। अमेरिका ने पिछले साल सेंट पीटर्सबर्ग का अपना वाणिज्य दूतावास उस वक्त खो दिया था जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे बंद करने का आदेश दिया था। चीन दूसरे देशों में अपनी पैठ बढ़ाता गया और संगठन को मजबूत करता रहा लेकिन अमेरिकी राजनयिकों ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही सत्ता में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के बजट में उल्लेखनीय कटौती कर दी। अमेरिका ने अपने मिशन का विस्तार आखिरी बार 2016 में किया था जब उसकी संख्या 271 से 273 तक पहुंची थी।

> चीन ने राजनयिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जो देश की राजनीतिक महत्वकांक्षाओं और प्राथमिकताओं का बैरोमीटर हो सकता है। यह सूचकांक भू राजनयिक पहुंच की ताकत और कमियों को बताता है। राजनयिक ढांचा, राजनयिक प्रभाव का भले ही बहुत ही छोटा सा हिस्सा है लेकिन इस बदलाव का प्रतीकात्मक महत्व है।
>
> **बॉनी ब्ले,** डिप्लोमेसी सूचकांक तैयार करने वाली टीम की सदस्य

ड्रैगन की विदेशी फुफकार

2016 में चीन अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरे पायदान पर था, लेकिन एक साल बाद ही वह फ्रांस को पछाड़कर दूसरे और इस साल पहले नंबर पर पहुंच गया। दुनिया के कई देशों में उसने आक्रामक रूप से अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की। ताइवान के राजनयिक मित्र माने जाने वाले बुरकिना फासो, डोमिनिक गणराज्य, अल सल्वाडोर, जांबिया, साओ टोम और प्रिंसिपे में अपने राजनयिक मिशन शुरू किए।

दुनिया में ये है पहले दस देश

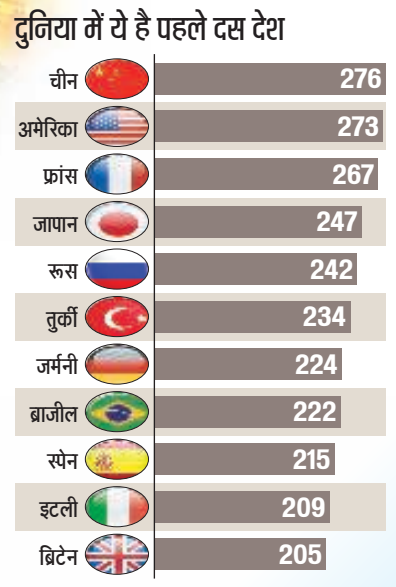

एशिया में ये हैं टॉप टेन

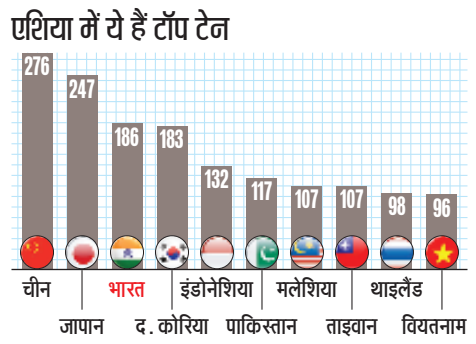

कहां खड़े हैं हम

रिपोर्ट में चीन जहां पहले पायदान पर है, वहीं भारत का 12वां स्थान है। दोनों देशों के राजनयिक मिशनों में जमीन आसमान का अंतर है। चीन के पास कुल 276 राजनयिक मिशनों में 169 दूतावास, 96 वाणिज्यिक दूतावास, आठ स्थायी मिशन और तीन अन्य मिशन हैं। वहीं भारत 123 दूतावास/उच्चायोग, 54 वाणिज्यिक दूतावास, पांच स्थायी मिशन और चार अन्य प्रतिनिधित्व हैं। दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों में भारत की उपस्थिति है लेकिन चीन के मुकाबले में उसके राजनयिक मिशनों का उतना विस्तार नहीं है।

व्यापार बढ़ाने की ओर है ध्यान

इस रिपोर्ट को देखने के बाद साफ पता चलता है कि चीन की कोशिशें दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार बढ़ाने की ओर है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों की संख्या 88 है तो चीन के पास 96 वाणिज्य दूतावास हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड वार में उलझा चीन व्यापार के लिए नए ठिकाने तलाशने में जुटा है।

पाकिस्तान ने पूर्व सेना जनरल को सौंपी सीपीईसी की कमान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान की सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) से जुड़ी अरबों डॉलर की परियोजनाओं की निगरानी के लिए बनाए गए सीपीईसी प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। बाजवा की अध्यक्षता में यह प्राधिकरण चीन की आर्थिक मदद से पाकिस्तान में निर्माणाधीन सड़क, रेल, बिजली और अन्य क्षेत्र की परियोजनाओं को समय से पूरा कराने पर ध्यान देगा। बाजवा पाकिस्तानी सेना की दक्षिणी कमान का नेतृत्व कर चुके हैं। 2012 से 2016 तक वह सेना के मीडिया विंग के महानिदेशक भी रहे थे। सीपीईसी प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में बाजवा की नियुक्ति चार वर्षों के लिए की गई है।

पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर (करीब 4,200 अरब रुपये) की लागत वाली सीपीईसी परियोजनाओं के लिए चीन वित्तीय मदद दे रहा है। सीपीईसी के जरिये वह अरब सागर स्थित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को सड़क मार्ग से गुलाम कश्मीर होते हुए अपनी सीमा से जोड़ने में जुटा है। सीपीईसी पर 2015 में काम शुरू किया गया था।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख का सेवा विस्तार अधर में, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रोकी

- अपने काम पर नए सिरे से विचार करे इमरान सरकार
- बाजवा को विस्तार देने के विरोध में आज कामकाज नहीं करेंगे वकील

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने सेना प्रमुख को 'शटलकॉक' बना देने के लिए अटार्नी जनरल को फटकार लगाई। साथ ही, इमरान खान सरकार से कहा कि वह जो कुछ कर रही है, उस पर नए सिरे से विचार करे। पाक सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच पाकिस्तानी वकीलों ने गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। वकीलों ने बाजवा को दिए गए सेवा विस्तार और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आदेश रोकने को असंवैधानिक कहा है।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिये जनरल बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार दिया था। इसके पीछे उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा के माहौल का हवाला दिया था। बाजवा का मूल कार्यकाल गुरुवार मध्य रात्रि को समाप्त होने वाला है और यदि सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले उनके पक्ष में फैसला दिया तो वह इस पद पर बने रह सकते हैं।

पाक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, 'अब भी समय है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि वह क्या कर रही है। वह शीर्ष पद पर बैठे एक अधिकारी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती।' पीठ ने सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल अनवर मंसूर खान से कहा, 'आपने सेना प्रमुख को एक शटलकॉक में बदल दिया है।'

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया नया पत्र सेना प्रमुख की पुनर्नियुक्ति के लिए एक अनुरोध है। लेकिन राष्ट्रपति ने उनके कार्यकाल में विस्तार की अधिसूचना जारी की। खोसा ने कहा, 'सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह सेना प्रमुख को सेवा विस्तार देना चाहती है या उन्हें फिर से नियुक्त करना चाहती है।' प्रधानमंत्री खान ने इस गफलत का कारण कानून मंत्रालय द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटि बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, 'आपने ऐसी चूक कैसे की? आपको देखना चाहिए कि इस दस्तावेज को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है।' सुनवाई करने वाली पीठ में मुख्य न्यायाधीश खोसा, जस्टिस मियां अजहर आलम खान मियांखेल और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह शामिल हैं। बाजवा की पैरवी फारूग नसीम कर रहे हैं जिन्होंने इसके लिए मंगलवार को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्य न्यायाधीश खोसा ने एक अप्रत्याशित कदम के तहत मंगलवार को कानूनी खामियों का हवाला देते हुए सरकार के आदेश को निलंबित कर दिया था। बाजवा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका रियाज राही नाम के एक व्यक्ति ने दायर की है। शीर्ष कोर्ट के मंगलवार के आदेश के बाद कैबिनेट ने सेना नियम एवं नियमन की धारा 255 में संशोधन किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, 'सेना प्रमुख के कार्यकाल का विषय बहुत अहम है।

दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन बनेंगे श्रीलंकाई प्रांत के गवर्नर

- राष्ट्रपति गोतबाया पूर्व गेंदबाज समेत तीन गवर्नरों की करेंगे नियुक्ति

कोलंबो, आइएएनएस : अपनी फिरकी से दुनिया के धुरंधर बल्लेबाजों को पस्त करने वाले श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन अब सियायत के मैदान में कदम रखने जा रहे हैं। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे उन्हें उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनाने जा रहे हैं। डेली मिरर अखबार में राष्ट्रपति सचिवालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गोतबाया ने मुरलीधरन को निजी तौर पर बुलाकर उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनाने का प्रस्ताव दिया। गोतबाया तीन प्रांतों के नए गवर्नर नियुक्त करने जा रहे हैं। इनमें 47 वर्षीय मुरलीधरन को उत्तरी, अनुराधा यहमपथ को पूर्वी और तिस्सा वितर्णा को उत्तर-मध्य प्रांत का गवर्नर बनाया जाएगा।

गजब के मुरली : टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड मुरलीधरन के ही नाम है। मुरलीधरन ने अपने क्रिकेट करियर में कुल 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट झटके। जबकि 350 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 534 विकेट लिए थे। उन्होंने 2010 में टेस्ट और 2011 में वनडे क्रिकेट से सन्यास ले लिया था।

35 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ : राष्ट्रपति गोतबाया ने बुधवार को 35 नए राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को शपथ दिलाई। उन्होंने गत 22 नवंबर को 16 सदस्यीय कैबिनेट को शपथ दिलाई थी। 70 वर्षीय गोतबाया ने राष्ट्रपति चुनाव में यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के उम्मीदवार सजित प्रेमदासा को हराया था। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया और कैबिनेट में एक अन्य भाई चमल राजपक्षे को भी शामिल किया था।

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की फाइल फोटो। एएफपी

एड्स से रोजाना 300 से ज्यादा बच्चों की हो जाती है मौत : यूनिसेफ

संयुक्त राष्ट्र, आइएएनएस : एचआइवी संक्रमण से होने वाली बीमारी एड्स से विश्वभर में हर दिन 320 बच्चों की मौत हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के अनुसार, 0-14 साल उम्र के एचआइवी पीड़ित बच्चों की इतनी संख्या में मौत के पीछे की मुख्य वजह समुचित इलाज का नहीं मिलना है।

भारत समेत विश्वभर के बच्चों पर एड्स की मार से संबंधित आंकड़े जारी करते हुए मंगलवार को यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने कहा, एचआइवी पीड़ित बच्चों में से केवल 54 फीसद को ही एंटीरेट्रोवाइरल इलाज प्राप्त हो रहा है। एड्स के खिलाफ जारी लड़ाई में विश्व ने काफी प्रगति की है, लेकिन यह अब भी पर्याप्त नहीं है। एड्स पर जारी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 0-9 साल तक के बच्चों में सिर्फ 2018 में इस खतरनाक बीमारी के डेढ़ लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस तरह इस आयुवर्ग के एचआइवी पीड़ित बच्चों की संख्या 11 लाख तक पहुंच गई है।

बर्फीले तूफान से अमेरिका में करीब पांच सौ उड़ानें रद...

अमेरिका के मिनेसोटा और कोलोराडो प्रांत में बर्फीले तूफान ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। करीब 10 से 12 इंच तक की बर्फबारी से सड़क और हवाई यातायात पर गंभीर असर पड़ा है। अब तक करीब पांच सौ उड़ानें रद कर दी गई हैं। कोलोराडो स्थित डेनेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बर्फ की चादर ओढ़े रनवे पर खड़े विमान। यातायात समस्या के चलते बुधवार को स्कूल और विश्वविद्यालय भी बंद रहे। तूफान से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मौसम विभाग ने अभी और बर्फीले तूफान की आशंका जताई है। रायटर

मुंबई हमले के दोषियों का दंडित न होना संवेदनाओं का अपमान

- हाफिज सईद की ओर इशारा कर अमेरिकी विदेश मंत्री की पाकिस्तान को लताड़

वाशिंगटन, प्रेट्र : मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले के साजिशकर्ता अभी तक दंडित नहीं हुए हैं, यह 166 बेकसूर लोगों की शहादत और उनके परिजनों की संवेदनाओं का अपमान है। यह बात हमले की बरसी पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कही है।

भारत में हुए जघन्यतम आतंकी हमलों में शामिल मुंबई हमले में समुद्र के रास्ते आए दस पाकिस्तानी आतंकियों ने दो पंचतारा होटलों और यहूदी हॉस्टल में 166 लोग मारे थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। मरने वालों में छह अमेरिकी भी शामिल थे। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में पोंपियो ने कहा, लश्कर ए तैयबा के इस हमले से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। 11 वीं बरसी पर हम छह अमेरिकी नागरिकों सहित मारे गए सभी बेकसूर लोगों को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बेकसूरों को मारने वालों का अभी तक दंडित न होना शहादत का अपमान है। पोंपियो का इशारा पाकिस्तान में बैठे जमात-उद-दावा के प्रतिबंधित आतंकी सरगना हाफिज सईद की ओर था। सईद संयुक्त राष्ट्र का घोषित अंतरराष्ट्रीय आतंकी है। उसी इसी साल 17 जुलाई को आतंकी संगठनों को धन मुहैया कराने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग और वित्त विभाग ने सईद को विशेष वैश्विक आतंकी घोषित कर उस पर दस लाख डॉलर (सात करोड़ भारतीय रुपये) का इनाम घोषित कर रखा है। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने ट्वीट कर पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई। कहा, अमेरिका दिवंगत लोगों से जुड़ी यादों का सम्मान करता है और घटना के दोषी लोगों को दंडित होते हुए देखना चाहता है।

वाशिंगटन में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पाकिस्तानी दूतावास के समक्ष प्रदर्शन कर पाक सेना व आइएसआइ की आतंकियों को पोषित करने की नीति के खिलाफ आवाज उठाई। एएनआइ

पाकिस्तानी दूतावास के समक्ष प्रदर्शन : मुंबई हमले की बरसी पर बड़ी संख्या में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक और मूलवासी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तानी दूतावास के समक्ष प्रदर्शन कर दोषी आतंकियों को दंडित करने की मांग की। प्रदर्शनकारी हाथों में पाकिस्तान को धिक्कारने वाले और आतंकियों को शरण न देने की नसीहत देने वाले कार्ड, पोस्टर लेकर आए थे।

महाभियोग की सुनवाई में भाग लेने के लिए ट्रंप आमंत्रित

- राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि पेश होकर आपत्ति जता सकते हैं
- एक सप्ताह तक चलने वाली प्रक्रिया में राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप तय किए जाएंगे

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी संसद (प्रतिनिधि सभा) ने चार दिसंबर को होने वाली महाभियोग प्रक्रिया की सुनवाई में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया है। एक सप्ताह चलने वाले प्रक्रिया के इस नए दौर में राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप तय किए जाएंगे।

इस सुनवाई में राष्ट्रपति के मौजूद रहने की बाध्यता नहीं है लेकिन वह या उनकी वकीलों की टीम आरोपों पर चर्चा के दौरान उपस्थित रह सकती है। इससे सुनवाई भेदभावपूर्ण होने के आरोप से बच जाएगी। राष्ट्रपति या उनके वकीलों को अपने पक्ष में तर्क रखने का मौका मिल जाएगा। अभी तक की प्रक्रिया को राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस ने खारिज किया है। चूंकि गवाहों से सवाल पूछने की अनुमति व्हाइट हाउस को नहीं है, इसलिए महाभियोग प्रक्रिया में आरोपित पक्ष के लिए यह दौर महत्वपूर्ण होता है।

ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निजी राजनीतिक हित साधने के लिए अमेरिका की विदेश नीति के इस्तेमाल के आरोप के चलते शुरू हुई है। इस आरोप में 25 जुलाई को ट्रंप ने अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू कराने पर बात की थी। बिडेन पर 2015 में अमेरिकी सैन्य सहायता में हुई गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप है। बिडेन 2020 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि बिडेन को फंसाने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन में उनके खिलाफ जांच शुरू कराने की कोशिश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति से ट्रंप की बातचीत कई अधिकारियों ने सुनी। उन्हीं से से एक ने व्हिसल ब्लोअर बनकर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं तक यह बात पहुंचाई और उनमें से कई अब ट्रंप के खिलाफ सार्वजनिक गवाही दे रहे हैं।

पॉलीटेक्निक विवि में आज प्रवेश करेगी पुलिस

हांगकांग, रायटर : सघन तलाशी के लिए हांगकांग पुलिस गुरुवार को पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकती है। वहां से वे छिपे हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार कर बाहर लाएंगे। साथ ही बारीकी से विश्लेषण करेंगे कि छात्रों की तैयारियां किस प्रकार की थीं। पुलिस करीब दो सप्ताह से विश्वविद्यालय की घेराबंदी किए हुए है।

बुधवार को दूसरे दिन विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने अंदरूनी हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जिला पुलिस प्रमुख हो युन-सिंग ने कहा है कि जैसे ही विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी अपना काम पूरा कर लेंगे, वैसे ही पुलिसकर्मी विश्वविद्यालय के भीतर जाकर अपना काम शुरू कर देंगे। सिंग ने बताया कि पुलिस गुरुवार को विश्वविद्यालय में प्रवेश करेगी। परिसर में चलने वाले स्कूल में पढ़ाई का समय पूरा होने के बाद पुलिस वहां जाएगी। सिंग ने बताया- वहां हम खतरनाक सामान हटाएंगे और सुबूत एकत्रित करेंगे, जो कोर्ट में हमारे काम आएंगे। अगर वहां पर कोई आंदोलनकारी घायल और बीमार अवस्था में पाया जाता है तो उसे चिकित्सकीय सहायता भी दी जाएगी।

लाल ईंटों से बने पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय में 30 हजार से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन में यह आंदोलनकारियों का मुख्य गढ़ बन गया था। लेकिन दो सप्ताह पूर्व हुई पुलिस कार्रवाई में छह महीने पुराने आंदोलन का यह गढ़ ढह गया। यहां से एक हजार से ज्यादा आंदोलनकारी गिरफ्तार हुए, कई हजार जैसे-तैसे भागकर बच पाए। पुलिस ने विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर सील कर रखा है और वहां बाहर से किसी को जाने की इजाजत नहीं है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निशाने पर हांगकांग के अमीर शिंग

हांगकांग, रायटर : हांगकांग के सबसे धनी व्यक्ति 91 वर्षीय ली का शिंग विवाद में फंस गए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन पर लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन के समर्थन का आरोप लगाया है। कहा है कि शिंग ने अपराधियों को संरक्षण दिया। जबकि हांगकांग के ही एक ट्रेड यूनियन नेता ने शिंग को कॉकरोचों का राजा तक कहा। 30 अरब डॉलर (दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) की संपत्ति वाले शिंग की हांगकांग में हमेशा से अलग पहचान रही है। कई तरह के कारोबार करने वाले शिंग ने एक तिहाई संपत्ति शिक्षा, शोध कार्य और लोगों की सुविधाओं के लिए दान की करने की घोषणा कर रखी है। इसी के तहत वह कई क्षेत्रों में सेवा कार्य करते रहते हैं। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में मुश्किल में फंसे कई आंदोलनकारी छात्रों की उन्होंने मदद की, इसलिए वह चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के निशाने पर आ गए। हांगकांग के 1997 में चीन के कब्जे में आने के बाद ज्यादातर कारोबारियों ने चीन की नीतियों का अनुसरण करना शुरू कर दिया और उसका लाभ भी लेने लगे। लेकिन शिंग ने हमेशा खुद को अलग रखा। वह लोकतंत्र और प्रगतिवादी व्यवस्था के पक्षधर है।

नाटो का खर्च सहयोगियों पर डालने की तैयारी में अमेरिका

- लंदन में 3-4 दिसंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में ट्रंप बनाएंगे दबाव

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका अंतरसरकारी सैन्य गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के खर्च को सदस्य देशों पर डालने की तैयारी में जुट गया है। वह अगले माह होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में इस संगठन के खर्च को साझा करने को लेकर दबाव बनाएगा। साथ ही नाटो के भावी विकास का भी जिक्र करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि नाटो की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर तीन से चार दिसंबर तक लंदन में होने वाले शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोंपियो शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में नाटो के सभी सदस्य देशों के नेता भी हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन ऐसे समय होने जा रहा है, जब इस गुट की एकता सवालों के घेरे में है। ट्रंप प्रशासन इस बात की कई बार शिकायत कर चुका है कि नाटो के सहयोगी देश अमेरिकी सेना की सेवा मुफ्त में पा रहे हैं। ईरान के परमाणु मसले और उत्तरी सीरिया में तुर्की के सैन्य अभियान को लेकर भी नाटो सदस्यों में मतभेद हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हालिया इंटरव्यू में नाटो को ब्रेन डेड करार दिया था। इसकी ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने तीखी आलोचना की थी।

नाटो के ये हैं सदस्य

29 सदस्यीय नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, नार्वे, नीदरलैंड्स, फ्रांस, लक्जमबर्ग, इटली, आइसलैंड, डेनमार्क, कनाडा और बेल्जियम इसके संस्थापक सदस्यों में हैं। जबकि ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोंटीनिग्रो, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया बाद में इसमें शामिल हुए।

विश्व मुक्केबाजी सीरीज का अनुभव बिग बाउट लीग में मदद करेगा। मैं लीग में शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा।
— गौरव बिधूड़ी, मुक्केबाज, भारत

सचिन बोले, ट्विटर पर नहीं बेटा अर्जुन और बेटी सारा

नई दिल्ली : दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर साफ किया है कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर उनके बेटे अर्जुन और बेटी सारा नहीं हैं। युवा क्रिकेटर अर्जुन और सारा के नाम से ट्विटर पर काफी अकाउंट बने हैं, लेकिन सचिन ने कहा है कि सभी फर्जी हैं। इतना ही नहीं, सचिन ने एक ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की।

गेंद के स्वभाव को आसानी से समझ जाता है अच्छा गेंदबाज : इशांत

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज पिछले दो साल से विदेशों में ही नहीं भारतीय सरजमीं पर भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी भारतीय पिचों पर अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव के भरोसे टीम इंडिया टेस्ट मैच जीतती थी, लेकिन अब वही काम इशांत शर्मा, उमेश यादव और मुहम्मद शमी कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह के नहीं खेलने के बावजूद भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और उनकी बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका व बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ किया। कोलकाता में गुलाबी गेंद से हुए पहले डे-नाइट टेस्ट में इशांत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 12 साल में पहली बार घर मे पारी में पांच विकेट लिए। उन्होंने इस मैच में नौ और सीरीज में 12 विकेट लिए। **अभिषेक त्रिपाठी** ने गुलाबी टेस्ट के मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज **इशांत शर्मा** से विशेष बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश :

साक्षात्कार

कोलकाता में डे-नाइट टेस्ट मैच के दौरान पारी में पांच विकेट लेने के बाद गेंद दिखाते इशांत शर्मा साथी खिलाड़ियों के साथ • फाइल फोटो, बीसीसीआइ

- **बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अपने प्रदर्शन को कैसे देखते हैं?**

-एक खिलाड़ी के रूप में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने का लक्ष्य रहता है। बांग्लादेश के खिलाफ यह टेस्ट यादगार रहा। भारत में पारी में पांच विकेट झटकना और मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज बनना विशेष है। मेरे लिए यह सीरीज हमेशा यादगार रहेगी।

- **लाल गेंद और गुलाबी गेंद में क्या अंतर देखा? एक गेंदबाज के तौर पर आपके लिए गुलाबी गेंद से गेंदबाजी कैसी रही?**

-लाल गेंद सुबह के समय स्विंग ज्यादा होती है। गुलाबी गेंद फ्लड लाइट में ज्यादा स्विंग होती है। दोनों गेंदों का स्वभाव अलग है, लेकिन एक अच्छा गेंदबाज जल्द ही इसको समझ जाता है। मैंने इससे अभ्यास किया और उसका फायदा मुझे मिला। कुल मिलाकर गुलाबी गेंद से मेरा अनुभव अच्छा ही नहीं, बल्कि यादगार भी रहा।

- **12 साल बाद अपने देश में पारी में पांच विकेट लेना कितना महत्वपूर्ण है और इसके पीछे की वजह क्या है?**

-हर गेंदबाज हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। मैंने पहले भी भारत मे अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पारी में पांच विकेट पिछले मैच में मिले, जो खास है। अच्छी बात यह है कि मेरे प्रदर्शन से टीम जीती। टीम का जीतना महत्वपूर्ण है। पिछले दो साल से सारे टेस्ट बाहर थे, जहां मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा और विकेट भी मिले। दो साल बाद देश में टेस्ट खेलने का मौका मिला और मैंने यहां भी अच्छा किया।

- **पिछले डेढ़-दो साल में आपकी गेंदबाजी में बहुत परिवर्तन दिखा है? क्या कोई खास बदलाव किया है?**

-विकेट का कॉलम भरने (ज्यादा विकेट मिलने) के कारण लोग मेरे प्रदर्शन पर ध्यान दे रहे है। मैं हमेशा की तरह पूरी ईमानदारी से अभ्यास करता हूं। अभ्यास हमेशा से ही मेरी प्राथमिकता रहा है। मेरे प्रदर्शन की यही वजह है।

- **अभी आपने इस सीरीज में नई गेंद (लेग कटर) फेंकी? उसके बारे में बताएं?**

-मैंने इंग्लैंड में भी टेस्ट सीरीज में लेग कटर डाली थी। उसका अनुभव अच्छा रहा। उस गेंद का प्रयोग यहां भी किया।

गुलाबी गेंद से मैच खेलना काफी अच्छा अनुभव रहा, न्यूजीलैंड दौरा अहम रहेगा

- **ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के पिछले दौरे में आपकी गेंदबाजी शानदार रही। अगले साल न्यूजीलैंड दौरा है। विदेशी दौरों पर अपने प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं? न्यूजीलैंड दौरा कितना कठिन रहेगा?**

-विदेश की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद करती हैं। वहां हमें स्विंग ज्यादा मिलती है और यह मेरे लिए अच्छा है। अगले साल हमें न्यूजीलैंड में दो टेस्ट खेलने हैं। हम वहां भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत वो हमारे लिए अहम दौरा होगा।

जागरण विशेष

- **हाल के दिनों में भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की बहुत बात हो रही है। आपकी नजर में उमेश, आपका और शमी का संयोजन कैसा है? गेंदबाजी करते समय आपस मे कैसे बात करते हैं?**

-हम हमेशा टीम स्प्रिट में रहते हैं। टीम के सारे साथी एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। टीम का माहौल बहुत अच्छा है।

- **आजकल आपके वाराणसी के गंगा भ्रमण के चर्चे खूब हैं। वाराणसी के प्यार और वहां के लगाव के बारे में बताएं?**

-शादी के बाद से बनारस आना-जाना लगा रहता है। मेरी ससुराल वहां है। खिलाड़ियों वाले परिवार में शादी हुई है। उनके साथ शांति से समय बीत जाता है। गंगा में नाव में सैर करना वहां का लौंगलता खाना पसंद है।

लंबे आराम पर धौनी बोले, जनवरी तक मत पूछो

इस साल विश्व कप के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं एमएस

मुंबई, प्रेट्र : महेंद्र सिंह धौनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे या फिर वह मैदान पर वापसी करेंगे। अगर वापसी करेंगे तो आखिर कब? यह सवाल इन दिनों भारतीय क्रिकेट में खूब चर्चा में है। धौनी की वापसी पर कभी टीम के कोच रवि शास्त्री अभी और इंतजार करने की बात कहते हैं तो कभी मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद कहते हैं कि वह धौनी से आगे का सोच रहे हैं। लेकिन, बुधवार को जब धौनी से उनके इस लंबे आराम पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा, 'इस पर उनसे जनवरी तक कुछ मत पूछो।' धौनी ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2019 विश्व कप के सेमिफाइनल में खेला था। इसके बाद से वह करीब चार महीने से ब्रेक पर हैं।

विश्व चैंपियन टीम के स्वागत को कभी नहीं भूल सकता: धौनी ने कहा कि 2007 में विश्व टी-20 और 2011 में विश्व कप जीतने वाली उनकी टीम का शानदार स्वागत जैसे क्षण उनके दिल के बेहद करीब हैं। धौनी की अगुआई में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में पहला टी-20 विश्व कप जीता था, जबकि इसके बाद उनके नेतृत्व में अपनी सरजमीं पर 2011 में वनडे विश्व कप अपने नाम किया था। धौनी ने कहा, 'मैं यहां दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। हम 2007 में (टी-20) विश्व कप के बाद भारत आए और हमने खुली बस में यात्रा की और हम मरीन ड्राइव (मुंबई) में खड़े रहे। हर तरफ जाम लगा था और लोग हमारे स्वागत के लिए अपनी कारों में आए थे। इसलिए मुझे हर किसी के चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लगा था, क्योंकि दर्शकों में कई ऐसे लोग रहे होंगे, जिनकी उड़ान छूट गई होगी, हो सकता है कि वे किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हो। वह शानदार स्वागत था।'

उन्होंने कहा, 'दूसरा पल 2011 विश्व कप फाइनल था। मैच में जब 15-20 रन चाहिए थे तब वानखेड़े स्टेडियम में दर्शक 'वंदे मातरम' का उद्घोष कर रहे थे। ये दो वाकये हैं। मुझे लगता है कि उन्हें दोहराना बहुत मुश्किल होगा। ये दो घटनाएं मेरे दिल के काफी करीब हैं।'

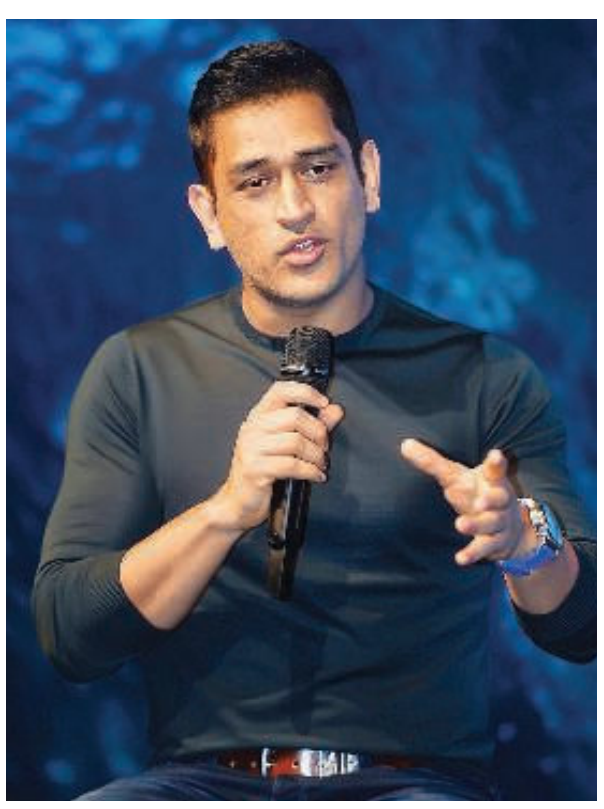

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महेंद्र सिंह धौनी • प्रेट्र

शादी से पहले सभी पुरुष होते हैं शेर : धौनी

चेन्नई, आइएएनएस: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी खुद को आदर्श पतियों से भी बेहतर मानते हैं। उनका कहना है कि वह अपनी पत्नी की कही हर बात का जवाब हां में देते हैं, क्योंकि इससे वह खुश रहती हैं। धौनी ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सभी पुरुष शादी से पहले तक शेर होते हैं। शादी का सही मतलब तभी पता चलता है, जब आप 50 साल की उम्र पार कर लेते हैं। जब आप 55 के हो जाते है, तो वही प्यार करने की सही उम्र होती है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धौनी और साक्षी की शादी 2010 में हुई थी। कार्यक्रम के दौरान हंसी मजाक के बीच इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने शादीशुदा जिंदगी को लेकर कहा कि मैं आदर्श पतियों से भी बेहतर हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को वह सब कुछ करने देता हूं, जो वह करना चाहती हैं। मेरी पत्नी भी केवल तभी खुश रहेगी, जब मैं उसकी कही हर बात का जवाब हां में दूंगा।

धौनी से तुलना नहीं करें पंत

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय टीम के मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता एमएसके प्रसाद का मानना है कि रिषभ पंत खुद को एमएस धौनी का उत्तराधिकारी मानकर अपने ऊपर गैरजरूरी दबाव बढ़ा रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि खराब फॉर्म से जूझ रहे इस खिलाड़ी को वापसी के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा का सहारा लेना चाहिए।

अभी कुछ समय पहले तक पंत तीनों प्रारूपों में विकेटकीपिंग के लिए पहली पसंद थे, लेकिन पिछले काफी समय से वह फॉर्म हासिल करने में विफल रहे हैं। अनुभवी रिद्धिमान साहा की चोट से वापसी के बाद पंत टेस्ट टीम की अंतिम एकादश में जगह नहीं बना सके। सीमित ओवरों के प्रारूप में भी उनका बल्ला नहीं चल रहा और उन्होंने विकेट के पीछे भी लचर प्रदर्शन किया। प्रसाद ने कहा, 'मैं रोहित शर्मा और सुनील गावस्कर की बातों से सहमत हूं जो पंत को अकेला छोड़ने की बात कह रहे हैं। पंत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें लय में लौटने के लिए कुछ अच्छी पारियों की जरूरत है। टीम प्रबंधन से मेरी चर्चा हुई है और उन्होंने कहा कि वे पंत से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक दबाव की बात है तो पंत को निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि खेल के इस स्तर पर दबाव रहता है और जो इस दबाव को झेल लेता है वही वास्तविक चैंपियन बनता है। उनके सामने विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण है।'

राष्ट्रीय चयनकर्ता प्रसाद ने कहा, धौनी का उत्तराधिकारी मानकर खुद पर दबाव बढ़ा रहे हैं रिषभ

प्रसाद 2016 में भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता बने थे। उन्होंने कहा कि पंत को कभी भी धौनी का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'पंत को यह भी अहसास होना चाहिए कि उनकी अपनी पहचान है और उन्हें कभी भी धौनी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग कुछ ऐसा ही चल रहा है। एमएसडी ने काफी समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलकर अपनी अच्छी छवि बनाई। उनका आत्मविश्वास घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उनके शानदार प्रदर्शन से उपजा है। जब कोई किसी महान व्यक्ति से अपनी तुलना करने लगता है तो वह खुद पर गैरजरूरी दबाव डालता है। निजी तौर पर मुझे लगता है कि पंत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं।'

धवन बाहर, संजू को मौका

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: सलामी बल्लेबाज शिखर धवन घुटने की चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हो गए, जिनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच के दौरान धवन के बायें घुटने में चोट लगी थी।

बीसीसीआइ ने कहा कि बोर्ड की मेडिकल टीम ने मंगलवार को उनकी चोट की समीक्षा की। उन्हें कुछ और समय आराम देने की सलाह दी गई है, ताकि वह पूरी तरह से चोट से उबर जाएं। अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने उसकी जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। केरल के सैमसन को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम में रखा गया था, लेकिन एक भी मैच खेले बिना बाहर कर दिया गया था। इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी और पूर्व खिलाड़ियों ने इस पर सवाल उठाए थे। 33 वर्षीय धवन वनडे सीरीज से पहले फिट हो सकते हैं। हालिया खराब फॉर्म के कारण वह काफी दबाव में भी हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 15 दिसंबर से शुरू होगी। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों में धवन सिर्फ 91 रन ही बना सके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वह कुछ खास नहीं कर सके। धवन को रन लेने के दौरान चोट लग गई थी, लेकिन वह खेलते रहे और पवेलियन लौटते समय उन्हें घुटने में कट लगने का पता चला था।

पहले टी-20 की मेजबानी करेगा हैदराबाद: बीसीसीआइ ने बुधवार को भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले और तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के स्थलों में अदला-बदली करने की घोषणा की और अब पहला मैच छह दिसंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आठ दिसंबर को तिरुअनंतपुरम में होगा। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में पहला टी-20 मैच होना था, जबकि तीसरा मैच हैदराबाद में खेला जाना था। बीसीसीआइ के सचिव जय शाह ने कहा कि दोनों देशों के बीच पहला टी-20 मैच, जो कि पहले छह दिसंबर को मुंबई में होना था, अब हैदराबाद में होगा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम अब दोनों टीमों के बीच टी-20 सीरीज के पहले मैच की मेजबानी करेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 11 दिसंबर को तीसरा टी-20 मैच खेला जाएगा।

बदलाव

- **चोट के कारण शिखर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज से हटे**
- **बीसीसीआइ की मेडिकल टीम ने धवन को आराम करने की सलाह दी**

संजू सैमसन • फाइल फोटो, प्रेट्र

भारतीय टी-20 टीम: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्रा सिंह चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, मुहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, संजू सैमसन।

साहा की अंगुली का हुआ सफल ऑपरेशन

नई दिल्ली, जेएनएन: भारत के टेस्ट विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के दायें हाथ की अंगुली में बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट के दौरान फ्रैक्चर हो गया था जिसका ऑपरेशन कराया गया। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी में होने वाली दो मैचों की सीरीज में उनके फिट होने की उम्मीद है। 35 वर्षीय साहा का मंगलवार को मुंबई में ऑपरेशन हुआ। बीसीसीआइ ने कहा कि मेडिकल टीम ने हाथ और कलाई के विशेषज्ञ से सलाह ली। उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा गया। मुंबई में मंगलवार को उनका सफल ऑपरेशन हुआ। अब वह जल्दी ही बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन कराएंगे। टीम प्रबंधन के करीबी सूत्र ने बताया कि साहा न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज तक फिट हो जाएंगे। वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में टेस्ट से पहले भारत को हैमिल्टन में तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलना है।

बाहर होने पर सकारात्मक बने रहना मुश्किल : उमेश यादव

नई दिल्ली, प्रेट्र: उमेश यादव को पता है कि भारतीय तेज आक्रमण में चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा में मौका मिलना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि टीम से बाहर होने पर नकारात्मक विचारों और बोरियत से पार पाना मुश्किल होता है।

उमेश को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के कारण उन्हें टीम में जगह मिल गई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट में 11 और बांग्लादेश के खिलाफ 12 विकेट लेकर मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि टीम से बाहर होने पर सकारात्मक बने रहना बहुत मुश्किल है। उमेश ने कहा, 'जब आप बाहर होते तो वह समय काफी बोरियत भरा होता है तथा कुछ ऐसे विचार आपके दिमाग में घर करने लगते हैं जिनसे आप दूर रहना चाहते हो। मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं? क्या हो रहा है? खुद को सकारात्मक बनाए रखना, कड़ी मेहनत करना और खुद को तैयार रखना मुश्किल होता है। मैं जानता था कि अगर मैं फिट रहा तो मुझे मौका मिलेगा क्योंकि हमें कई मैच खेलने हैं। आपको इंतजार करना होगा क्योंकि तेज गेंदबाजी आक्रमण वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।'

तेज गेंदबाजी आक्रमण में बुमराह, इशांत शर्मा और मुहम्मद शमी भी शामिल हैं और यादव ने कहा कि वह इसमें फिट बैठते हैं तथा कार्यभार संबंधी प्रबंधन से सुनिश्चित है कि हर किसी को पर्याप्त मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा, 'हम सभी चार अब उस स्तर पर हैं जहां आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो कि एक समय में कौन तीन खेलेंगे। ऐसा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण है। मैं इसे बहुत अच्छी बात मानता हूं कि हम खिलाड़ियों को रोटेट कर रहे हैं क्योंकि इससे हम लंबे समय तक खेल में बने रहेंगे और अधिक मैच विजेता प्रदर्शन करेंगे। जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा वह टीम का हिस्सा होगा। सबसे महत्वपूर्ण मौकों का पूरा फायदा उठाना है। जब मैं बुमराह, इशांत और शमी को देखता हूं तो उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। सीखना कभी बुरा नहीं होता।'

नजरिया

- **कहा, कड़ी प्रतिस्पर्धा के रहते मौका मिलना आसान नहीं**
- **जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा वह टीम इंडिया का हिस्सा होगा**

उमेश यादव • फाइल फोटो, प्रेट्र

भुवनेश्वर और राउरकेला करेंगे हॉकी विश्व कप की मेजबानी

भुवनेश्वर, प्रेट्र : ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को यहां कहा कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के मुकाबले भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किए जाएंगे। आठ नवंबर को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना, जिससे देश लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। एफआइएच के अनुसार, पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में 13 से 29 जनवरी 2023 के दौरान खेला जाएगा।

पटनायक ने कलिंगा स्टेडियम में एक संक्षिप्त समारोह में लोगों से कहा, 'हमने 2018 विश्व कप की मेजबानी की और मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि 2023 हॉकी विश्व कप फिर से भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। क्या आप खुश हैं। मैं खुश हूं।'

इस समारोह में एफआइएच और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुहम्मद मुश्ताक अहमद, ओडिशा के खेल मंत्री तुषारकांति बेहरा के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम 2018 में इस टूर्नामेंट के पिछले सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन करने के बाद लगातार दूसरी बार इसकी मेजबानी करेगा। बेल्जियम में 2018 में कलिंगा स्टेडियम में विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था।

पिछले कुछ समय में भुवनेश्वर ने 2017 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2017 एफआइएच हॉकी विश्व लीग फाइनल, 2019 में एफआइएच पुरुष सीरीज फाइनल्स और हाल ही में एफआइएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर जैसे कुछ अहम टूर्नामेंटों का आयोजन किया है। राज्य की राजधानी 2020 के फीफा महिला अंडर-17 विश्व कप के कुछ मैचों की मेजबानी भी करेगी।

अवसर

- **13 से 29 जनवरी 2023 के दौरान होना है आयोजन**
- **ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरी बार मेजबानी पर जताई खुशी**

टेस्ट मैच टेस्ट सीरीज के पहले दिन वेस्टइंडीज के फिरकी गेंदबाज रहकीम ने झटके सात विकेट

कॉर्नवाल का कहर, अफगानिस्तान 187 रन पर ढेर

जासं, लखनऊ

बांग्लादेश को उसी घर में करारी शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान की टीम यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से शुरू हुए एकमात्र टेस्ट मुकाबले में खराब बल्लेबाजी की वजह से बैकफुट पर है। रहकीम कॉर्नवाल (7/75) की घातक गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने टेस्ट मैच के पहले मेजबान टीम को 68.3 ओवर में सिर्फ 187 रनों पर आउट कर दिया। वहीं, पहले दिन का खेल खत्म होने तक कैरेबियाई टीम ने दो विकेट पर 68 रन बना लिए हैं। जॉन कैंपबेल 30 और शामराह ब्रुक्स 19 रन पर नाबाद हैं।

इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कैरेबियाई कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मेजबानों ने सधी शुरुआत की। खासकर, जावेद अहमदी (39) ने पहले और दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी कर अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि, दूसरी ओर बढ़िया आगाज के बावजूद इब्राहिम जादरान (17) एक गलत शॉट खेलकर कॉर्नवाल की गुगली पर होल्डर के हाथों कैच आउट हो गए। वहीं जावेद के साथ 56 रनों की अहम साझेदारी करने के बाद इहसानुल्लाह (24) भी कॉर्नवाल के दूसरे शिकार बने।

बायें पैर में चोट से जूझ रहे कॉर्नवाल ने अपनी कहर बरपाती गेंदों के सामने अफगानी बल्लेबाजों को टिकने का मौका तक नहीं दिया। उनकी सटीक लाइन-लेंथ की बदौलत ही मेजबान टीम महज 14 रनों के अंतराल पर अपने चार महत्वपूर्ण विकेट गंवाकर बैकफुट पर आ गई। कप्तान राशिद खान तो महज एक रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा अफसर जाजई और आमिर हमजा ने 32 और 34 रनों का अहम योगदान देकर किसी तरह अफगानिस्तान को डेढ़ का आंकड़ा पार कराया। वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान जेसन होल्डर ने दो विकेट झटके। जबकि जोमेल वारिकन को एक विकेट मिला। अफगानिस्तान ने इस टेस्ट मैच से पहले टी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-1 हराया था, जबकि वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था।

मैच के दौरान वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज रहकीम कॉर्नवाल। एएफपी

...तो क्या लियोन मेसी जीत चुके हैं बैलन डि ओर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

फ्रांस फुटबॉल मैग्जीन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित बैलन डि ओर पुरस्कार जीतने की दौड़ में बार्सिलोना के दिग्गज स्ट्राइकर लियोन मेसी, लिवरपूल के विर्गिल वान डिज्क और जुवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल हैं, लेकिन स्पेनिश मीडिया के मुताबिक मेसी का यह पुरस्कार जीतना तय हो गया है और उन्हें इसके बारे में बता भी दिया गया है।

स्पेनिश मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक दो दिसंबर को पेरिस में होने वाले बैलन डि ओर पुरस्कार की घोषणा से पहले ही मेसी को विजेता घोषित कर दिया गया है। वान डिज्क ने मेसी को पछाड़कर यूएफा के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया था। हालांकि अर्जेंटीना के दिग्गज स्ट्राइकर मेसी ने वान डिज्क को पीछे छोड़कर फीफा के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान हासिल किया था। ऐसे में अब सभी को बैलन डि ओर समारोह का इंतजार है जहां पांच बार के विजेता मेसी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। मेसी ने पिछले सत्र में बार्सिलोना को ला लीगा चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान उन्होंने 36 गोल दागे थे। हालांकि चैंपियंस लीग में उनकी टीम वान डिज्क की टीम लिवरपूल से सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई थी। उधर रोनाल्डो इटालियन क्लब से जुड़ने के बाद भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जुवेंटस को पिछले सत्र में सीरी-ए में खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

फेलिक्स ने जीता गोल्डन ब्वॉय पुरस्कार : एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलने वाले पुर्तगाल के युवा फुटबॉलर जोआओ फेलिक्स ने बुधवार को गोल्डन ब्वॉय पुरस्कार हासिल किया। यह पुरस्कार इटली के अखबार टुटोस्पोर्ट्स द्वारा यूरोप के सर्वश्रेष्ठ अंडर-21 खिलाड़ी को दिया जाता है। फेलिक्स ने डोर्टमंड के जैडन सांचो और बायर लेवरकुसेन के जर्मन मिडफील्डर केइ हैवेर्ट को पछाड़कर यह पुरस्कार हासिल किया।

- **स्पेनिश मीडिया में लियोन का नाम तय होने की चर्चा, वान डिज्क और रोनाल्डो भी हैं होड़ में**

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए मैं लगभग पहले टेस्ट के अंतिम एकादश को ही खेलने का मौका दूंगा।
– जस्टिन लैंगर, कोच, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम

पांच टेस्ट खेलने वाले बेली बने ऑस्ट्रेलिया टीम के चयनकर्ता

सिडनी, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टी-20 कप्तान जॉर्ज बेली को ग्रेग चैपल की जगह तीन सदस्यीय राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति में चुना गया। समिति में ट्रेवर होंस और कोच जस्टिन लैंगर भी हैं। बेली ने कहा कि मैं खुश किस्मत हूं कि इतने साल बतौर खिलाड़ी योगदान दे सका। अब मेरे पास चयनकर्ता के रूप में योगदान देने का मौका है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए पांच टेस्ट, 90 वनडे और 30 टी-20 मैच खेले हैं।

15 मिनट में चार गोल करके लेवांदोवोस्की ने रचा इतिहास

फुटबॉल ▸ बायर्न ने रेड स्टार बेलग्रेड को 6-0 से दी करारी शिकस्त, यूएफा चैंपियंस लीग में सबसे कम समय में चार गोल करने वाले खिलाड़ी बने रॉबर्ट

बेलग्रेड, एएफपी : जर्मन फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख के दिग्गज खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांदोवोस्की ने मंगलवार को यूएफा चैंपियंस लीग में 15 मिनटों के अंदर चार गोल करके इतिहास रच दिया, जिसकी बदौलत उनकी टीम ने ग्रुप-बी में रेड स्टार बेलग्रेड को 6-0 से करारी शिकस्त दी। लेवांदोवोस्की चैंपियंस लीग के इतिहास में सबसे कम समय के अंदर चार गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वह यूरोपियन चैंपियनशिप के मौजूदा सत्र के पांच मुकाबलों में कुल 10 गोल के साथ शीर्ष गोल स्कोरर हैं। रेड स्टार के खिलाफ मुकाबले में लेवांदोवोस्की के गोल की संख्या और अधिक हो सकती थी। पहले हाफ में उनके द्वारा किए गए गोल को वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वार) की मदद से अयोग्य करार दिया गया।

रेड स्टार बेलग्रेड के खिलाफ मुकाबले में लेवांदोवोस्की (53वें, 60वें, 64वें और 68वें मिनट) के चार गोल के अलावा ल्योन गोरेत्जका (15वें मिनट) और कोरेंटीन टोलिसो (89वें मिनट) ने भी बायर्न के लिए स्कोर किए और बायर्न को इस लीग में लगातार पांचवीं जीत दिलाई। चैंपियंस लीग के अंतिम-16 में जगह बना चुकी बायर्न म्यूनिख की टीम ग्रुप-बी में 15 अंकों के साथ शीर्ष पर है। अगर अपने अगले मुकाबले में बायर्न ने टॉटनहम को हरा दिया तो वह ग्रुप चरण में अपने सभी चारों मुकाबले जीतने वाला पहला जर्मन क्लब बन जाएगा।

सबसे अहम बात यह है कि हमने आक्रमण के साथ-साथ डिफेंस में भी बहुत अच्छा खेल दिखाया। चार गोल करने के बाद भी मैं वैसे ही खुश हूं जैसे मेरे गोल नहीं करने के बावजूद टीम के जीतने के बाद होता हूं।
– रॉबर्ट लेवांदोवोस्की, खिलाड़ी, बायर्न म्यूनिख

नॉकआउट में पहुंचा सिटी

मैनचेस्टर : ग्रुप-सी में मैनचेस्टर सिटी ने शाख्तर डोनेट्स्क से 1-1 से ड्रॉ खेलने के बावजूद लगातार सातवीं बार चैंपियंस लीग के नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की की। एतिहाद स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पेप गॉर्डियोला की टीम अपनी ख्याति के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। आइकर गुंडोगन ने सिटी को दूसरे हाफ में बढ़त दिलाई, लेकिन मानोर सोलोमोन के गोल की बदौलत शाख्तर ने बराबरी हासिल की। उधर, इसी ग्रुप में अटलांटा की टीम ने डायनमो जाग्रेब को 2-0 से हरा दिया।

चार गोल करने का इशारा दिखाते रॉबर्ट लेवांदोवोस्की। एएफपी

11 मिनट के अंदर रॉबर्ट लेवांदोवोस्की ने रेड स्टार बेलग्रेड के खिलाफ अपनी हैट्रिक पूरी की

27 गोल सभी प्रतियोगिताओं के कुल 20 मुकाबलों में लेवांदोवोस्की ने मौजूदा सत्र में किए हैं

07 गोल हेंसी फेलिक के अंतरिम मैनेजर बनने के बाद चार मुकाबलों में लेवांदोवोस्की ने किए हैं

डायबाला की फ्री किक से जीता जुवेंटस

तुरिन : पाउलो डायबाला ने कोण बनाती फ्री किक पर शानदार गोल करके चैंपियंस लीग के ग्रुप-डी में जुवेंटस को एटलेटिको मैड्रिड पर 1-0 की जीत दिलाई। पहले ही नॉकआउट में जगह बना चुका इटालियन चैंपियन जुवेंटस इस जीत के साथ ग्रुप-डी में शीर्ष पर पहुंच गया।

डायबाला ने पहले हाफ के इंजुरी टाइम के दूसरे मिनट में फ्री किक के जरिये शानदार गोल किया, जिसे एटलेटिको के गोलकीपर जॉन ओब्लाक के पास रोकने का कोई मौका नहीं था। फिट होकर लौटे जुवेंटस के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरे मैच में खेले, लेकिन कुछ मौकों पर उन्हें लंगड़ाते देखा गया। ग्रुप-डी में जुवेंटस 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। एटलेटिको की टीम तीसरे स्थान पर काबिज बायर लेवरकुसेन से एक अंक आगे है। उधर, इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में लेवरकुसेन ने लोकोमोटिव को 2-0 से हराया।

अंतिम-16 में पहुंचा टॉटनहम

लंदन : चैंपियंस लीग के ग्रुप-बी में टॉटनहम ने दो गोल से पिछड़ने के बाद यूनानी क्लब ओलंपियाकोस को 4-2 से हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई। टॉटनहम के मैनेजर के तौर पर जोस मौरिन्हो का यह पहला घरेलू मुकाबला था और उन्होंने यूरोपियन टूर्नामेंट में अपनी ख्याति के मुताबिक नजीता दिया। ओलंपियाकोस के यूसेफ अल अरेबी और रुबेन सेमेदो के गोल की बदौलत टॉटनहम दो गोल से पिछड़ रहा था, लेकिन डेले अली ने पहले हाफ के इंजुरी टाइम में टॉटनहम का खाता खोला। इसके हैरी केन ने 17 मिनट के अंदर दो गोल करके टॉटनहम को 3-2 की बढ़त दिलाई और फिर सर्जी ऑरियर के गोल ने इस इंग्लिश क्लब की जीत सुनिश्चित कर दी। पिछले बार की उप विजेता रही टॉटनहम की टीम लगातार तीसरी बार नॉकआउट में पहुंची है। ऑरियर की मदद से दोनों गोल करने के साथ ही केन चैंपियंस लीग में सबसे कम 24 मुकाबलों में 20 गोल करने वाले खिलाड़ी बने।

पीएसजी ने रीयल से खेला ड्रॉ

मैड्रिड : ग्रुप-ए में कायलियन एमबापे के नाटकीय गोल की बदौलत फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने स्पेनिश क्लब रीयल मैड्रिड को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। दो मिनट में दो गोल करके पीएसजी ने मुकाबले को ड्रॉ कराया और ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस मुकाबले में करीम बेंजमा (17वें व 79वें मिनट) ने दो गोल करके रीयल को जीत की ओर अग्रसर कर दिया था, लेकिन पहले एमबापे (81वें मिनट) और पाब्लो सराबिया (83वें मिनट) ने गोल करके पीएसजी को हार से बचा लिया। पीएसजी की ओर से 100वां मुकाबला खेलने उतरे एमबापे ने अपने खेल से प्रभावित किया। इस ड्रॉ मुकाबले से ग्रुप-ए में पीएसजी का शीर्ष पर रहना तय है, जबकि रीयल दूसरे स्थान पर रहेगी। गेरेथ बेल दूसरे हाफ में स्थानापन्न के तौर पर उतरे, जिन्हें घरेलू प्रशंसकों से मिला-जुला स्वागत मिला। रीयल के ईडन हैजार्ड इस दौरान चोटिल हो गए, जिससे उनका आगामी एल क्लासिको में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। पीएसजी ने इस मुकाबले में नेमार को शुरुआत में बेंच पर बैठाया, लेकिन दूसरे हाफ में उन्हें मैदान में उतारा गया। ग्रुप-ए में ही गालातसारी और क्लब ब्रुग के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ।

फीफा की टीम ने युवाभारती क्रीड़ांगन पर जताया संतोष

खेल संवाददाता, कोलकाता : भारत में अगले साल होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता पहुंची फीफा की टीम ने विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन पर संतोष जताया है। ओलिवर वोग्ट की अगुआई में टीम ने बुधवार को स्टेडियम के आधिकारिक निरीक्षण का काम सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस दौरान स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) के प्रतिनिधि भी शामिल थे। फीफा की ओर से कहा गया कि विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन इससे पहले पुरुषों के अंडर-17 फीफा विश्व कप के मैचों का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका है। स्टेडियम की आधारभूत संरचना अच्छी हालत में है। जिस तरह से 2017 में पुरुषों के अंडर-17 मैचों का आयोजन हुआ था, उसी तरह से इन मैचों का भी आयोजन किया जाएगा। नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। फीफा स्टेडियम में सर्वोत्तम सुविधाएं और माहौल प्रदान करना चाहता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन अगले साल दो से 21 नवंबर तक होगा।

विराट कोहली ने अनुष्का को लेकर कहा, जीवन के सफर में साथ-साथ

नई दिल्ली, जेएनएन : भारतीय कप्तान विराट कोहली बांग्लादेश से सीरीज खत्म होने के बाद कुछ आराम करने के मूड में हैं। इस दौरान वह अपने प्रशसंक को नहीं भूले हैं। बुधवार को उन्होंने प्रशंसकों के लिए अपनी और पत्नी अनुष्का की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की। ज्यादातर मौकों पर अपनी तस्वीरों पर कैप्शन नहीं लिखने वाले विराट ने इस बार इस तस्वीर पर कैप्शन भी दिया।

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कोहली तीन टी-20 मैचों की सीरीज के दौरान आराम पर थे। इस दौरान वह अपनी पत्नी संग भूटान की यात्रा पर गए थे। विराट ने अपने इस टूर की ही एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में विराट और अनुष्का किसी पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। विराट ने इस तस्वीर पर कैप्शन दिया, 'जीवन के सफर में एक साथ चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ नहीं बस प्यार है।' विराट ने यह तस्वीर अनुष्का को टैग करते हुए इस पर एक दिल वाला इमोजी भी बनाया है।

जब दादा-दादी संग सुबह की सैर पर निकले मयंक

नई दिल्ली : भारतीय टेस्ट टीम के ओपनर मयंक अग्रवाल ने बुधवार को अपने दादा-दादी के साथ दो तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में मयंक अपने दादा-दादी के साथ सुबह की सैर कर रहे हैं। इन प्यारी तस्वीरों ने प्रशंसकों का दिल छू लिया और प्रशंसक इस शानदार काम के लिए उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। अपने दादा-दादी के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए मयंक ने लिखा, '20 साल पहले, जब हम अपने घर पर आए, तो मेरे दादाजी मुझे इस सैर पर लेकर आए थे। आज भी, अपने हर टूर के बाद, जब भी मैं लौटता हूं तो यह सिलसिला जारी है।'

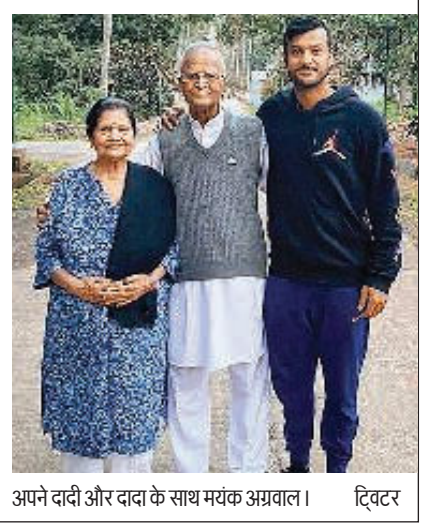

अपने दादी और दादा के साथ मयंक अग्रवाल। ट्विटर

अभिषेक और ज्योति की जोड़ी ने जीता सोना

बैंकाक, प्रेट्र : अभिषेक वर्मा और च्योति सुरेख वेन्नाम की मिश्रित डबल्स भारतीय जोड़ी ने 21वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में बुधवार को यहां कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे भारत ने कुल सात पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। वर्मा और च्योति की जोड़ी ने चीनी ताइपे की यी ह्सुआन चेन और चीह लुह चेन की जोड़ी को 158-151 से हरा का भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता। टूर्नामेंट में भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत व दो कांस्य पदक हासिल किए।

इससे पहले वर्मा टीम स्पर्धा में सटीक निशाना लगाने से चूक गए, जिससे भारतीय टीम को कोरिया के खिलाफ एक अंक से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कोरिया ने यह मुकाबला 233-232 के अंतर से जीता।

पुरुष टीम स्पर्धा में शीर्ष वरीय वर्मा, रजत चौहान और मोहन भारद्वाज की भारतीय तिकड़ी ने पहले दौर में 58 अंक बनाए। कोरिया के जेइवॉन यांग, यांगही चोइ और ईयून-क्यू चोई ने भी इतने ही अंक बनाए। दूसरे दौर में कोरियाई टीम ने भारतीय टीम से एक अंक की बढ़त हासिल की।

गत चैंपियन समीर वर्मा बाहर श्रीकांत व प्रणीत अगले दौर में

जागरण संवाददाता, लखनऊ

▸ सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के गत चैंपियन समीर को जयराम ने हराया, ओलंपिक स्वर्ण विजेता मारिन अगले दौर में

सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में बुधवार को पुरुष सिंगल्स में समीर वर्मा पर अनुभवी अजय जयराम भारी पड़े। लगभग एक घंटे तक चले मुख्य दौर के रोमांचक मुकाबले में अजय जयराम ने समीर को 15-21, 21-18, 21-13 के अंतर से शिकस्त देकर बाहर कर दिया। हालांकि, अन्य भारतीय खिलाड़ियों में तीसरी वरीय किदांबी श्रीकांत और साई प्रणीत ने शानदार जीत के साथ अगले दौर में अपनी-अपनी जगह सुनिश्चित की। इसके अलावा ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन ने भी दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं, पुरुष सिंगल्स के पहले मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के शी यू का अभियान भी हार के साथ समाप्त हो गया।

बाबू बनारसी दास यूपी बैडमिंटन अकादमी में चल रही इस चैंपियनशिप में बुधवार को मुख्य दौर का सबसे बड़ा मुकाबला समीर वर्मा और अजय जयराम के बीच खेला गया। हाल के वर्षों में समीर ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके बाद उन्हें यहां तीसरी बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। जयराम के खिलाफ पहला गेम 21-15 से गंवाने के बाद समीर ने दूसरे गेम में 21-18 से जीत दर्ज करते हुए जोरदार वापसी की थी। पर, तीसरे और निर्णायक गेम में अजय समीर पर भारी पड़े और अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए 21-13 के अंतर से जीत दर्ज करते हुए वर्मा को चैंपियनशिप से बाहर का रास्ता दिखाया। साइना नेहवाल इस चैंपियनशिप में नहीं खेल रही हैं। ऐसे में यहां प्रशंसकों की उनके पति और पुरुष सिंगल्स के स्टार खिलाड़ी पी कश्यप पर निगाहें थीं, लेकिन कश्यप को पहले दौर में फ्रांस के लुकास कॉर्वी के खिलाफ वॉकओवर मिला। वहीं, लक्ष्य सेन का पहले दौर में फ्रांस के थॉमस रॉसेल से मुकाबला होना था।

विविध

बिना बताए छोड़ गई पत्नी, तलाक मंजूर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पत्नी ने पति को बिना किसी उचित कारण के अकेला छोड़ दिया था। पति ने साथ रहने की लगातार कोशिशें कीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने तलाक की अर्जी दायर की। तीस हजारी पारिवारिक न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति को तलाक की अनुमति दे दी, क्योंकि पत्नी अलग रहने के लिए कोई उचित कारण नहीं दे सकी थी और उनके बीच 2014 के बाद से कोई संबंध नहीं था। उनकी शादी के 21 साल हो गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम तलाक की अनुमति देता है, अगर पति या पत्नी में से किसी एक को याचिका दायर करने से पहले दो साल की लगातार अवधि के लिए छोड़ दिया गया हो।

पारिवारिक न्यायालय ने यह भी कहा कि अगस्त 2016 में महिला अपने पति को सूचित किए बिना एक शोध कार्य के संबंध में देश छोड़कर दुबई चली गई। अदालत ने पाया कि पति की तलाक की अर्जी पर पत्नी ने लिखित बयान में यह उल्लेख नहीं किया कि वर्तमान में वह दुबई में रह रही है या नहीं। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि याचिकाकर्ता की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद की मांग करते हुए दावा किया था कि उसकी पत्नी ने न केवल उसे निर्वासित किया, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता के अधीन कर दिया। सभी तथ्यों को जांचने के बाद पारिवारिक न्यायालय ने तलाक मंजूर कर दिया।

फिल्मकारों की पसंदीदा शूटिंग स्थान बनाने की कोशिश करेंगे : सावंत

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अपने आयोजन की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। पिछले पंद्रह साल से इसका आयोजन स्थायी रूप से गोवा में हो रहा है। फेस्टिवल का सह-आयोजक इंटरटेंनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा है। गोवा के मुख्यमंत्री **प्रोमद सावंत** इसके चेयरमैन हैं। दैनिक जागरण के **अनंत विजय** से उन्होंने इस मौके पर विशेष बातचीत की।

● यह फेस्टिवल का 50वां साल है, आपने क्या खास किया है?

इस वर्ष के आयोजन को खास बनाने के लिए हमने कई इंतजाम किए हैं। डेलीगेट्स को बेहतर सुविधा मिले, अच्छी फिल्मों का चुनाव किया गया। फिल्म मेकिंग की तकनीक के बारे में विस्तार से बात हो, इसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोगों को आमंत्रित किया। आपको बताना चाहूंगा कि इस बार फिल्म फेस्टिवल में देश के आठ राज्य हिस्सा ले रहे हैं। इसने अंतरराष्ट्रीय आडियंस को विविधता की खूबसूरती का अहसास कराया है।

● गोवा में फिल्म फेस्टिवल का यह 15वां साल है। इससे गोवा के फिल्मकारों को क्या लाभ मिला?

इस वर्ष हमने गोवा के स्थानीय फिल्मकारों के लिए ऑन द स्पॉट फिल्म बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। कोंकणी फिल्मों के लिए इस बार हमने अलग से एक सेक्शन बनाया है। पहले कोंकणी फिल्म इंडियन पैनोरमा का हिस्सा होती थी। अलग होने से कोंकणी फिल्मों की ओर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म मेकरों और फिल्म प्रेमियों का ध्यान गया है। यह इसके विकास के लिए बेहतर साबित होगा।

● गोवा में फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से यहां की स्थानीय प्रतिभाओं को क्या फायदा हुआ?

हमने गोवा आर्ट कॉलेज के छात्रों को अलग से जगह दी ताकि वे फिल्म फेस्टिवल के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति को फिल्म फेस्टिवल से जोड़ने और यहां फिल्म संस्कृति के विकास के लिए हमने नार्थ और साउथ गोवा के अलावा अन्य तालुका में भी फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था की है। मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

● गोवा फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतर स्थान है। फिर भी कम फिल्मकार यहां आते हैं।

हम जल्द ही गोवा में फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था करने जा रहे हैं और यह काम इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के माध्यम से किया जाएगा। इसकी घोषणा जल्द की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि इसके लागू होने से गोवा फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्मकारों की पसंदीदा जगह बन जाएगी।

● क्या आप गोवा की पृष्ठभूमि पर बनने वाली फिल्मों या गोवा के कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने वाले फिल्मकारों को आर्थिक मदद भी देंगे?

इस तरह का प्रस्ताव भी मेरे संज्ञान में आया है। हम इस पर भी जल्द ही निर्णय लेंगे। अंत में मैं दैनिक जागरण के माध्यम से पूरे देश के फिल्म प्रेमियों को निमंत्रित करना चाहूंगा कि वे फिल्म फेस्टिवल के दौरान गोवा जरूर आएं।

नशेड़ी युवक ने मां, पत्नी व बच्चों समेत पांच को मार डाला

जासं, कोडरमा : झारखंड मे कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिजन टोला में मंगलवार देर रात नशे में धुत सनकी युवक ने गर्भवती पत्नी, मां व बच्चों समेत परिवार के पांच लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या का कारण युवक का नशे को लेकर पत्नी व मां से विवाद बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार मसमोहना के रविदास टोला निवासी गांगो दास हमेशा गांजे के नशे में धुत रहता है। घर का भरण-पोषण उसकी मां शांति देवी को मिलने वाली विधवा पेंशन और पत्नी की दैनिक मजदूरी से चलता था। मंगलवार रात उसने चाकू व रॉड से पहले गर्भवती पत्नी शीला देवी (26), पुत्री राधिका (4) व पुत्र पीयूष (2) की हत्या की। इसके बाद बगल के कमरे में सोई मां शांति देवी (62) व उसके बड़े भाई यमुना दास की दो बेटियां निकिता (4) व चांदनी द्वारा शोर मचाने पर उन तीनों पर भी चाकू व रॉड से हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, तब सनकी युवक ने एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी श्यामलाल यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व एंबुलेंस को बुलाकर घायल शांति देवी, निकिता व चांदनी को सदर अस्पताल भिजवाया, जहां शांति देवी व निकिता ने दम तोड़ दिया। वहीं चांदनी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है।

श्राइन बोर्ड के सुपुर्द होंगे उत्तराखंड के चार धाम

राज्य ब्यूरो, देहरादून

कैबिनेट के फैसले

- पवित्र चार धामों समेत उत्तराखंड के प्रसिद्ध 51 मंदिरों का होगा कायाकल्प
- पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास का 25 फीसद ज्यादा देना होगा किराया

उत्तराखंड में चार पवित्र धामों बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत अन्य प्रसिद्ध मंदिरों का कायाकल्प, प्रबंधन और यात्रा संचालन श्रीवैष्णो देवी माता मंदिर, सांई बाबा, जगन्नाथ और सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस दिशा में अहम कदम उठाते हुए उत्तराखंड चार धाम श्राइन प्रबंधन बोर्ड विधेयक-2019 को मंजूरी दी। प्रस्तावित नए अधिनियम के तहत चार धाम विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, बशर्ते वह हिंदू हों। उधर, सरकारी आवास का उपयोग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब आवास के मानक किराये से 25 फीसद ज्यादा बतौर किराया भुगतान करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाओं के मामले में हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए सरकार ने पहले जारी अध्यादेश में संशोधन कर करते हुए नए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है।

उत्तराखंड राज्य बनने के 19 साल बाद पहली बार चारों पवित्र धामों, उनके नजदीकी मंदिरों समेत करीब 50 प्रसिद्ध मंदिरों के विकास, प्रबंधन और देश-दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा संचालन को व्यवस्थित करने को सरकार ने उक्त कदम उठाया है। लंबे अरसे से नया श्राइन बोर्ड बनाने पर विचार तो किया जा रहा था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त विधेयक को मंजूरी दी गई। विधानसभा सत्र के चलते मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुल 36 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें एक को स्थगित किया गया, जबकि उत्तराखंड चार धाम श्राइन प्रबंधन बोर्ड विधेयक समेत 35 बिंदुओं को मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के गैर हिंदू होने की स्थिति मे हिंदू धर्म को मानने वाले मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ मंत्री को बोर्ड अध्यक्ष का जिम्मा दिया जा सकेगा। संस्कृति और धार्मिक मामलों का प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होगा।

मंत्रिमंडल ने भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में बड़ा फैसला लिया है। अध्यादेश के जरिये 31 मार्च 2019 तक माफ किए गए सरकारी आवास किराये पर सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर से सरकारी आवास किराये की वसूली के मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लिहाजा सरकार ने किराया माफी का प्रावधान खत्म करने के साथ ही उसे नए दर से वसूल करने का फार्मूला तय किया है। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक बाजार दर और मानक किराये के बजाए अब समुचित रूप से मानक किराये से 25 फीसद अधिक किया गया है। इस प्रावधान से पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी कुछ राहत मिली है।

एसटीएफ के हत्थे चढ़ा दो लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर तोतला, कई मामले हैं दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और रंगदारी के 30 से अधिक मामलों में शामिल कुख्यात गैंगस्टर पवन उर्फ तोतला मंगलवार रात स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के हत्थे चढ़ गया। उसे एक बाइक एवं दो देसी पिस्टल के साथ रोहतक जिले के सांपला इलाके के गांव इस्माइल के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। उस पर हरियाणा पुलिस ने दो लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

यह मोस्ट वांटेड कुख्यात गैंगस्टर राजू बासौदी गैंग का भी शॉर्प शूटर रह चुका है। इसके संबंध पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर संपत से लेकर राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर बिश्नोई गैंग से भी हैं। इसके ऊपर साथियों के साथ मिलकर 11 हत्याएं, दो हत्या के प्रयास एवं 20 लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप हैं।

पिछले दो साल से एसटीएफ सोनीपत जिले के गांव नाहरा निवासी 38 वर्षीय गैंगस्टर तोतला के पीछे लगी हुई थी। मंगलवार शाम एसटीएफ के गुरुग्राम स्थित मुख्यालय को सूचना मिली कि तोतला सांपला इलाके में पहुंचने वाला है। इसके बाद एसटीएफ की रोहतक टीम को ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। वैसे रोहतक टीम भी काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। तोतला जैसे ही बाइक से गांव इस्माइल में बस स्टैंड के नजदीक पहुंचा, एसटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया। टीम ने इतनी फुर्ती से कार्रवाई की कि गैंगस्टर को हथियार निकालने तक का मौका नहीं मिला। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले सोनीपत में हुई एक व्यक्ति की हत्या के बाद से हरियाणा पुलिस एवं एसटीएफ के ऊपर उसे पकड़ने का दबाव अधिक बन गया था। इसे देखते हुए एसटीएफ ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। इसी साल तोतला अब तक 10 से अधिक वारदात को अंजाम दे चुका है।

बुधवार को भोंडसी स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसटीएफ के डीआइजी सतीश बालन ने कहा कि तोतला न केवल हरियाणा, बल्कि पंजाब, दिल्ली एवं राजस्थान पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था। वैसे इसने अपने साथियों के साथ अधिकतर वारदात सोनीपत, रोहतक एवं झज्जर इलाके में ही अंजाम दी थीं।

एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

ईकोटेक तीन कोतवाली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से अलग-अलग बैंकों के 24 डेबिट कार्ड, तमंचा, चाकू व कार बरामद की है। बदमाश चार अलग-अलग राज्यों में सक्रिय थे। बदमाशों ने गौतमबुद्धनगर के अलावा दिल्ली, फरीदाबाद व इंदौर में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपितों पर विभिन्न थानों में 18 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को आशंका है कि गिरोह में कई अन्य बदमाश शामिल हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि डेबिट कार्ड बदलकर खाते से रुपये निकालने की कई घटनाएं होने पर पुलिस इस पर गंभीरता से काम कर रही थी। सीओ तृतीय राजीव सिंह के नेतृत्व में ईकोटेक तीन कोतवाली प्रभारी अनीता चौहान की टीम ने एटीएम बूथ के आसपास विशेष रूप से नजर रखनी शुरू की। इसी के तहत कुलेसरा के समीप से तीन आरोपितों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपितों की पहचान इमरत उर्फ इमा, सैफ अली उर्फ सैफल व मुकीम निवासी गांव घाघोट जिला पलवल हरियाणा के रूप में हुई है। आरोपितों के कब्जे से 24 डेबिट कार्ड, दो तमंचा, कारतूस, चाकू व एसेंट कार बरामद की गई है। आरोपित अलग-अलग एटीएम बूथ की निगरानी करते थे।

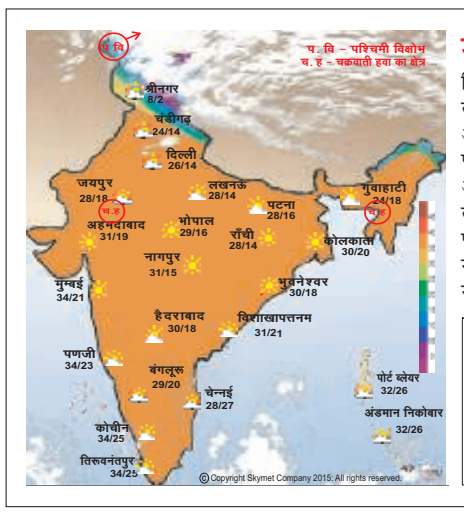

मौसम विशेष

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान में बदलीयुक्त आसमान के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा व ओलावृष्टि होगी। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी जारी रहेगी। सुबह ठिठुरन रहेगी। बादलों के साथ दिन ठण्डा व शीतल रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	35/22/व	अहमदाबाद	30/14/आंबा
कोलकाता	31/20/सा	बड़ौदा	31/18/आंबा
चेन्नई	31/25/व	नागपुर	31/15/व
हैदराबाद	30/19/आंबा	इन्दौर	27/20/सा
बंगलूरू	28/20/सा	रांची	29/19/सा
त्रिवेन्द्रम	33/25/व	पटना	31/19/आंबा
गुवाहाटी	24/16/सा	जमशेदपुर	30/17/व
गंगटोक	08/-3/व	पुणे	31/21/सा

स्टीम की प्रिंटिंग प्रेस पर छपने वाला पहला अखबार द टाइम्स

लंदन से प्रकाशित होने वाले द टाइम्स अखबार को 1814 में आज ही स्टीम संचालित प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था। इस मशीन का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक कुनिंग ने किया था। 1785 से प्रकाशित हो रहे इस अखबार का शुरुआती नाम द डेली यूनिवर्सल रजिस्टर था।

THE TIMES

अमेरिका ने बनाई पहली आइसीबीएम

1958 में अमेरिका ने पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल (आइसीबीएम) एसएम-65 एटलस को लांच किया। वायुसेना के लिए तैयार मिसाइल की मारक क्षमता पांच हजार किमी से अधिक थी। शुरुआती मिसाइल को बड़े लक्ष्य भेदने के लिए बनाया गया था।

जयपुर कृत्रिम पैर के जनक थे डॉक्टर प्रमोद करण सेठी

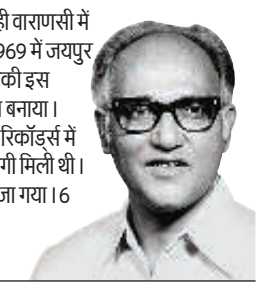

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ सेठी का जन्म 1927 में आज ही वाराणसी में हुआ था। उन्होंने श्री रामचंद्र शर्मा के साथ मिलकर 1969 में जयपुर पैर नामक सस्ते कृत्रिम पैर का निर्माण किया था। उनकी इस खोज ने अपना पांव गंवाने वाले लाखों लोगों को चलने के काबिल बनाया। पूरी दुनिया इसके व्यापक इस्तेमाल से डॉ सेठी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। अभिनेत्री सुधा चंद्रन को भी जयपुर पैर से नई जिंदगी मिली थी। 1981 में उन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड और पद्मश्री से नवाजा गया। 6 जनवरी 2008 को दुनिया को अलविदा कह गए।

इधर-उधर की

केलानुमा कार ने किया चमत्कार

न्यूयार्क, एजेंसी : जहां चाह वहां राह। अमेरिका के स्टीव ब्रेथवेट ने सोचा और कर लिया। जनाब को शौक था कुछ अलग करने का, जिसे देखकर लोग हंसे और दंग भी रह जाएं। सोच को साकार करने के लिए हूबहू केले जैसी कार तैयार की। नाम दिया बनाना कार। ब्रेथवेट 1986 में अपने पैतृक निवास इंग्लैंड से अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। लेकिन आर्थिक तंगी बाधा बनने लगी। इसमें मदद की दोस्तों ने। पुरानी कार खरीदकर 2011 में उसे केले की शक्ल देनी शुरू की। सबसे लंबी बनाना कार के रूप में उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कराया। कार से 2018 में उन्होंने पूरे अमेरिका की सैर की। अब उनकी योजना विश्व भ्रमण की है। हालांकि कई बार कार के आकार-प्रकार के चलते इन्हें पुलिस ने रोका लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक न पाने पर इन्हें सम्मानपूर्वक जाने दिया गया।

कार्टोसैट-3 व 13 सेटेलाइट का प्रक्षेपण

लंबी छलांग ▶ प्रक्षेपण के 17 मिनट 46 सेकेंड बाद कार्टोसैट-3 कक्षा में हुआ स्थापित

26 मिनट 56 सेकेंड बाद 13 अमेरिकी नैनोसेटेलाइट भी कक्षा में स्थापित किए गए

श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी-सी47 रॉकेट की लांचिंग देखते इसरो के वैज्ञानिक। प्रेट्र

श्रीहरिकोटा, प्रेट्र : अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने सफलता की एक और लंबी छलांग लगाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कार्टोसैट-3 और 13 नैनो अमेरिकी सेटेलाइट को बुधवार सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर मिनट पर सफलतापूर्वक लांच किया। इसरो प्रमुख के. सिवन ने इसे 'अद्भुत सफलता' करार दिया। प्रधानमंत्री ने इस सफलता के लिए इसरो और उसकी टीम को बधाई दी है।

कार्टोसैट-3 और 13 अमेरिकी नैनोसेटेलाइट को 44.4 मीटर लंबे पीएसएलवी-सी47 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लांच पैड से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के 17 मिनट 46 सेकेंड बाद कार्टोसैट-3 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जबकि, 26 मिनट 56 सेकेंड बाद 13 अमेरिकी नैनोसेटेलाइट कक्षा में स्थापित किए गए। मून मिशन चंद्रयान-2 के बाद इसरो की यह दूसरी सफलता है। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। उसका ऑर्बिटर तो काम सही काम कर रहा है, लेकिन सात सिंतबर को उसका लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा था। लैंडिंग के चलते विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था।

तीसरी पीढ़ी का उन्नत सेटेलाइट है कार्टोसैट-3 : कार्टोसैट-3 तीसरी पीढ़ी का उन्नत सेटेलाइट है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एक फीट से भी कम ऊंचाई तक की स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है। अपनी इस खूबी के चलते यह सैन्य कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसकी मदद सेना सीमा पर दुश्मन देशों की नापाक हरकतों पर नजदीकी नजर रख सकेगी।

टीटीसीएन ने नियंत्रण में लिया : इसरो के बेंगलुरु स्थित टेलेमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (टीटीसीएन) ने सेटेलाइट को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सिवन ने कहा कि इसरो ने अब तक जितने भी सेटेलाइट बनाए हैं, उनमें से कार्टोसैट-3 सर्वाधिक रेजलूशन वाला नागरिक और जटिल व उन्नत किस्म का सेटेलाइट है। स्पष्ट तस्वीरें लेने की इसकी क्षमता के चलते इससे पृथ्वी की नजदीकी निगरानी की जा सकेगी। सिवन ने कहा कि सभी सेटेलाइट को 509 किलोमीटर दूर सही कक्षा में स्थापित कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने इसरो को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता के लिए इसरो और उसकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उन्नत कार्टोसैट-3 से हमारी स्पष्ट तस्वीरें लेने की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं पीएसएलवी-सी47 के जरिए स्वदेशी कार्टोसैट-3 और दर्जन भर से ज्यादा अन्य छोटे सेटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर पूरी इसरो टीम को दिल से बधाई देता हूं।' उन्होंने ट्वीट किया, 'इसरो ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है।'

अगले साल तक अभी 13 प्रक्षेपण : इसरो प्रमुख ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी के पास मार्च 2020 तक फुरसत नहीं है। हमें मार्च तक 13 मिशन लांच करने हैं-इनमें छह रॉकेट और सात सेटेलाइट मिशन हैं, हमने मार्च से पहले इन्हें लांच करने का लक्ष्य रखा है।'

पांच साल तक काम करेगा कार्टोसैट-3 : कार्टोसैट-3 पांच साल तक काम करेगा। लगभग 1,625 किलोग्राम के कार्टोसैट-3 से शहरी क्षेत्रों में नियोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास और संसाधनों की मैपिंग, तटवर्ती क्षेत्रों में भू उपयोग इत्यादि कामों में मदद मिलेगी।

फिल्म रिव्यू

आतंक के साए में साहस की कहानी

होटल मुंबई

प्रमुख कलाकार : अनुपम खेर, देव पटेल आदि
निर्देशक : एंथोनी मारस
अवधि : 2 घंटे 8 मिनट

गया रह साल पहले 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले को लोग भूले नहीं हैं। समुद्र के जरिए पाकिस्तान से आए दस आतंकियों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, ताज और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थीं। इस घटना पर हिंदी में कई फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन 'होटल मुंबई' ताज होटल पर किए गए हमले के दौरान बने खौफ के माहौल, स्टाफ की बहादुरी और मेहमानों की सुरक्षित निकासी पर केंद्रित है। ताज के स्टाफ ने 'अतिथि देवो भवः' का पालन करते हुए अपने मेहमानों की रक्षा की थी। फिल्म में बाकी हमलों का संक्षिप्त जिक्र है। फोकस ताज के अंदरूनी माहौल और आतंकियों से जूझते निहत्थे लोगों के संघर्ष पर है। वर्ष 2009 में आई डॉक्यूमेंट्री 'सरवाइविंग मुंबई' से प्रेरित यह फिल्म उस काले दिन की याद फिर दिला देगी।

ऑस्ट्रेलियाई फिल्ममेकर एंथोनी मारस की यह डेब्यू फिल्म है। उन्होंने माहौल को वास्तविक बनाए रखने का यथासंभव प्रयास किया है और असल लोगों की पहचान उजागर न करने के लिए इन किरदारों को काल्पनिक बताया है। शेफ ओबराय (अनुपम खेर) अनुशासनप्रिय और नियमों को लेकर सख्त हैं। वह गलत जूते पहनकर आने के कारण वेटर अर्जुन (देव पटेल) को वापस जाने को कहते हैं। गर्भवती पत्नी और एक छोटा बच्चा घर पर होने की दुहाई देते हुए अर्जुन उनसे शिफ्ट में काम करने देने का आग्रह करता है। आपदा से बेखबर सभी रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते हैं। एक विदेशी दंपती अपने नवजात बच्चे के साथ वहां आता है। वे होटल के रेस्त्रां में खा-पी रहे होते हैं और उनका बच्चा आया के साथ कमरे में होता है। उसी दौरान चार आतंकी होटल में घुस आते हैं और ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू कर देते हैं। कोई कुछ समझ पाता, तब तक काफी लोगों को वे मौत के घाट उतार देते हैं।

फिल्म होटल की कार्यप्रणाली की झलक देते हुए असल मुद्दे पर आ जाती है। इसमें आतंकियों के अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ होने, पाकिस्तानी आका से फोन पर निर्देश लेने, आका का उन्हें हमले के बदले जन्नत का ख्वाब दिखाने का चित्रण है। आतंक के उस माहौल में कदमों की आहट या लोगों की आवाजाही को लेकर दोनों पक्षों की बेचैनी, सतर्कता, खौफ और सिसकी को उभार पाने में निर्देशक कामयाब रहे हैं। इसमें पुलिस की मदद, टीवी चैनल्स की भूमिका, एनएसजी कमांडो के देरी से आने जैसे पहलुओं को भी उठाया गया है। होटल के गलियारे से भागने का प्रयास करते लोगों को देखकर आपकी सांसें थम जाती हैं। अनुपम खेर का किरदार उस समय ताज के शेफ हेमंत ओबराय से प्रेरित है। सिख वेटर के तौर पर देव पटेल की परफॉर्मेंस दिल को छू जाती है। मुंबई को दहला देने वाली इस घटना के कुछ असली फुटेज का इस्तेमाल उन जख्मों को ताजा करता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल के अनुरूप है। कुल मिलाकर, यह फिल्म होटल के उन कर्मचारियों के साहस और सूझबूझ को सलाम करती है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने अतिथियों की रक्षा की।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

शोध अनुसंधान

शराब की तलब कम करने में केटामाइन मददगार

शराब की तलब कम करने का एक नया तरीका मिला है। एक नए अध्ययन का दावा है कि केटामाइन दवा की एक खुराक से उन लोगों में शराब पीने की तलब में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है, जो बहुत ज्यादा पीते हैं।

नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में छपे अध्ययन के अनुसार, केटामाइन की एक खुराक से बहुत ज्यादा शराब पीने वालों में इसकी तलब में कमी पाई गई। यह निष्कर्ष 90 लोगों पर करीब नौ माह तक किए गए एक प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ता रवि दास ने कहा, 'हमने बहुत ज्यादा पीने वालों पर एक आसान प्रयोगात्मक उपचार का दीर्घकालीन प्रभाव पाया।' इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजीव कांबोज ने कहा, 'केटामाइन सुरक्षित और आम दवा है, जिसके प्रभाव को डिप्रेशन समेत कई मनोरोगों पर परखा जा रहा है। इस दवा में शराब की समस्या को दूर करने की संभावना भी तलाशी जा रही है।' -प्रेट्र

लंबी निष्क्रियता के बाद करें रजिस्टेंस एक्सरसाइज

लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने या अन्य वजह से आई निष्क्रियता से उबरने के लिए रजिस्टेंस एक्सरसाइज जैसे कि लेग प्रेस आदि फायदेमंद हो सकती है। इससे मांसपेशियों को ठीक करने में मदद मिलेगी। पिछले अध्ययनों में कहा गया था कि अगर घुटने के नीचे कृत्रिम पैर लगा है तो उस जांघ की मांसपेशियों का उपयोग कम होता है। इसलिए वे कमजोर हो जाती हैं। 'एक्सपेरीमेंटल फिजियोलॉजी' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में इसी प्रकार की जांघ की मांसपेशियों की जांच की गई। ब्रिटेन की रीहैम्पटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि अस्पताल में निष्क्रिय पड़े रहने या इस तरह के लोगों की जांघ की मांसपेशियां झटके के साथ बल नहीं लगा पाती हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि रजिस्टेंस एक्सरसाइज से यह क्षमता हासिल की जा सकती है। - प्रेट्र

जलवायु परिवर्तन की वजह से 'निमो' मछली के अस्तित्व पर मंडराया खतरा

- समुद्री एनीमोन और शैवाल पर पूरी तरह निर्भर है यह मछली
- जलवायु परिवर्तन से दिन प्रति दिन इनमें आ रही गिरावट

10 साल तक किया गया मछली का आनुवंशिक अध्ययन। प्रतीकात्मक

मेलबर्न, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने बताया है कि 'निमो' मछली का दीर्घकालिक अस्तित्व समुद्री एनीमोन पर निर्भर करता है। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन से इन दोनों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो रहा है। निमो एक क्लाउनफिश मछली है। इस पर आधारित प्रशिद्ध हॉलीवुड फिल्म 'निमो' आने के बाद क्लाउनफिश को इस नाम से भी जाना जाने लगा है।

ऑस्ट्रेलिया में जेम्सकुक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं सहित एक शोध टीम ने पापुआ न्यू गिनी की रीफ में क्लाउनफिश की आबादी का 10 साल तक आनुवंशिक अध्ययन किया। पाया गया कि क्लाउनफिश परस्पर दो समुद्री एनीमोन प्रजातियों - हेटेरिस मैगिसिपा और स्टिचोडैक्टाइल के साथ रहती है। शोधकर्ताओं ने एक प्रशिद्ध जैवविविधता वाली जगह किम्बे बे के एक द्वीप पर क्लाउनफिश की आबादी की पांच पीढ़ी का फैमिली ट्री तैयार किया। वैज्ञानिकों ने बढ़ते जलवायु परिवर्तन में क्लाउन फिश की जनसंख्या का आकलन किया। साथ ही प्रत्येक क्लाउनफिश की बदलते परिवर्तन को स्वीकार करने की आनुवंशिक क्षमता की भी जांच की। 'इकोलॉजी लेटर्स' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि क्लाउनफिश की प्रजनन दर पूरी तरह से एनीमोन पर निर्भर करती है। इस अध्ययन के सहलेखक ज्योफ जोन्स ने बताया कि क्लाउनफिश की आबादी इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि वह कितनी गुणवत्ता वाले एनीमोन के संपर्क में है। अगर एनीमोन स्वस्थ रहते हैं तो क्लाउनफिश की आबादी भी बढ़िया रहती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि एनीमोन भी शैवाल पर निर्भर होते हैं। यदि शैवाल काफी समय तक एनीमोन से दूर हो जाएं तो एनीमोन की मौत होने लगती है, जिससे क्लाउनफिश की आबादी पर भी असर पड़ता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि क्लाउनफिश पूरी तरह से अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर है। जो जलवायु परिवर्तन की वजह से साल दर साल खराब हो रहा है। अब क्लाउनफिश की आबादी इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य उनके आवास की गुणवत्ता बनाए रखें।

निष्क्रिय अकाउंट्स हटाएगा ट्विटर

सैनफ्रांसिस्को, आइएएनएस : माइक्रोब्लागिंग साइट ट्विटर ने कहा है कि वह निष्क्रिय पड़े अकाउंट्स को हटाएगी। इस दौरान ऐसे अकाउंट्स बंद किए जाएंगे जो पिछले 6 महीने से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इसके लिए कंपनी ने यूजर्स को चेतावनी मेल भेजना शुरू कर दिया है। 11 दिसंबर तक साइन इन नहीं करने वाले यूजर के अकाउंट बंद कर दूसरे यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

ट्विटर के एक प्रवक्ता ने बताया है कि कंपनी निष्क्रिय अकाउंट्स को बंद करने का काम कर रही है। कंपनी यूजर्स को बेहतर सर्विस देना चाहती है। इसी प्रतिबद्धता के तहत इन अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है। इससे यूजर्स को सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। इस कदम के जरिये लोगों को एक्टिव रहने का प्रोत्साहन भी मिलेगा।

वर्ष 2020 तक कंपनी नए फीचर्स पेश करने की तैयारी कर रही है। इसमें रिट्वीट और मेंसन टैब पर पहले से ज्यादा कंट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। अगर इन पर कंट्रोल हो जाता है तो इन फीचर्स के रोलआउट के बाद ऐंटी-हैरसमेंट टूल और दमदार हो जाएगा।

भारत की प्राचीन कलाकृतियां लौटाएगा ऑस्ट्रेलिया

मेलबर्न, रायटर : भारत की तीन प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया वापस करने को राजी हो गया है। अगले साल जनवरी में भारत की अपनी यात्रा के समय ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन इन कलाकृतियों को भारत को सौंपेंगे। इसमें छठी से आठवीं सदी के बीच की नागदेवता वासुकी की मूर्ति और तमिलनाडु से गायब 15वीं सदी की दो द्वारपालों की मूर्तियां शामिल हैं। भारत की इन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया 1970 के यूनेस्को समझौते के तहत लौटा रहा है। इन कलाकृतियों को नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने न्यूयॉर्क के एक व्यवसायी से खरीदा था, जिसे लेकर अब भी जांच चल रही है।

ट्रंप ने टर्की पक्षी को दिया जीवनदान

वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में थैंक्सगिविंग के उपलक्ष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की पक्षी को जीवनदान दिया। दरअसल थैंक्सगिविंग उत्सव पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा टर्की पक्षी को जीवनदान देने की परंपरा है। थैंक्सगिविंड डे अमेरिका में प्रतिवर्ष नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 28 नवंबर को है। इस उत्सव की शुरुआत सालाना कृषि उत्सव के रूप में हुई। थैंक्सगिविंग कनाडा, ग्रेनाडा, सेंट लुसिया, लाइबेरिया और नीदरलैंड में भी मनाया जाता है। हालांकि, कनाडा में अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। रायटर

कैलिफोर्निया में जन्मी मादा सफेद गैंडा

कैलिफोर्निया के सैन डिएगो जू सफारी पार्क में एक दक्षिणी सफेद मादा गैंडे का जन्म हुआ है। पार्क प्रशासन का कहना है कि मादा गैंडे की मां का नाम अमानी (11वर्षीय) है। बताया गया कि पार्क में पैदा होने वाली यह 100वीं सफेद गैंडा है। इस गैंडा का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के जरिये हुआ है। इससे पहले जुलाई में भी एक नर गैंडे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के जरिये ही हुआ था। वर्तमान में दो मादा सफेद गैंडा ही दुनिया में बचे हैं। एपी

स्क्रीन शॉट

गाना सुनकर रो पड़े कार्तिक आर्यन

कई बार कुछ ऐसे पल सामने आ जाते हैं, जो आंखों में आंसू ले आते हैं। कार्तिक आर्यन अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। हाल ही में 'इंडियन आइडल 11' के सेट पर कार्तिक भावुक हो गए। दरअसल, अपनी आगामी फिल्म 'पति, पत्नी और वो' के प्रमोशन के लिए भूमि पेडणेकर और अनन्या पांडे के साथ कार्तिक 'इंडियन आइडल 11' के सेट पर पहुंचे थे। शो का एपिसोड 'मदर्स स्पेशल' था। सभी प्रतिभागियों ने अपने गाने को अपनी मां के लिए समर्पित किया था। जब शो के प्रतिभागी शाहजान मुजीब ने 'सदमा' फिल्म से 'सुरमई अंखियों में...' गाना गाया, तो कार्तिक इतने भावुक हो गए कि वह सेट पर रो पड़े। कार्तिक को अपनी मम्मी का संघर्ष याद आ गया, जो उन्होंने कार्तिक के लिए किया था। शो के मेकर्स ने कार्तिक की मम्मी का एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसमें उनकी मम्मी ने कार्तिक के ग्वालियर से बॉलीवुड पहुंचने के सफर को बयां किया है। कार्तिक इस वीडियो का देखकर इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मम्मी ने ब्रेस्ट कैंसर से जंग जीती है और कैसे उनके संघर्ष के दिनों में वह वालियर से मुंबई आया करती थीं।

'एक्सरे' में साइको लवर का रोल कर रहे हैं राहुल शर्मा

बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के राहुल शर्मा अपनी पहली ही फिल्म 'एक्सरे द इनर इमेज' में साइको लवर जैसा ग्रे शेड किरदार निभा रहे हैं। बिहार से बॉलीवुड तक की यात्रा पर राहुल कहते हैं, 'मैं जब 12-13 साल का था, नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। तभी से अभिनय, थियेटर व संगीत में रुचि है। पहले मैंने म्यूजिक वीडियो में काम किया। डॉक्टरी की पढ़ाई का इरादा छोड़कर मैं मुंबई आ गया और एक्टिंग सीखी। फिर डायरेक्टर राजीव रुइया के सहायक के रूप में काम किया।' अपनी पहली ही फिल्म में साइको लवर का ग्रे कैरेक्टर करना उन्होंने क्यों स्वीकार किया? इस पर राहुल कहते हैं, 'मेरा किरदार ग्रे है, निगेटिव है या पॉजिटिव, जो भी है, यह चुनौतीपूर्ण है।' बाबा मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और राजीव रुइया निर्देशित यह फिल्म 29 नवंबर को रिलीज होगी। टी-सीरीज ने संगीत जारी किया है।

शादी की सालगिरह से पहले प्रियंका ने दिया निक को उपहार

पिछले वर्ष एक दिसबंर को प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी शादी की पहली सालगिरह करीब है और इसका जश्न अभी से शुरू हो गया है। तोहफा देने का सिलसिला प्रियंका ने शुरू किया है। अपनी आगामी फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' की शूटिंग से वक्त निकालकर प्रियंका निक को सरप्राइज देने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचीं। प्रियंका ने निक को एक डॉग गिफ्ट किया है। निक ने प्रियंका का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'इस सुबह प्रियंका एक सरप्राइज लेकर पहुंचीं। हमारे नए पप जीनो से मिलिए। सुबह जब से उठा हूं, मेरे चेहरे पर मुस्कान है। फिर मुझे एहसास हुआ कि हुआ क्या है।' निक की इस पोस्ट पर प्रियंका ने कमेंट करते हुए लिखा, 'करीब आ चुके सालगिरह की शुभकामनाएं बाबू, तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिख रही है।'

शाह रुख खान से शादी के सवाल पर काजोल ने दिया मजेदार जवाब

सोशल मीडिया पर अक्सर सितारे अपने प्रशंसकों से बातचीत कर लेते हैं। काजोल ने इस बार एक दिलचस्प तरीका निकाला। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा कि उनके फैन्स उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। ज्यादातर सवाल दोस्त शाह रुख खान और पति अजय देवगन को लेकर पूछे गए। 'बाजीगर', 'कुछ कुछ होता है', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' जैसी हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके शाह रुख और काजोल अच्छे दोस्त हैं। एक प्रशंसक ने पूछा कि अगर आप अजय से नहीं मिलतीं, तो क्या शाह रुख से शादी करतीं? काजोल ने जवाब दिया, 'क्या एक शख्स को प्रपोज नहीं करना चाहिए।' काजोल ने बताया कि शाह रुख और वह जीवनभर के लिए दोस्त हैं। अजय देवगन के साथ काजोल काफी समय बाद फिल्म 'तानाजी : द अनसंग वॉरियर' में नजर आएंगी।

परिणीति ने फिर शुरू की बायोपिक की शूटिंग

परिणीति चोपड़ा ने साइना नेहवाल पर बन रही बायोपिक के लिए फिर से शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में वह बैडमिंटन खिलाड़ी साइना का किरदार निभा रही हैं। कुछ समय पहले शूटिंग के दौरान चोट लगने की वजह से परिणीति ने एक ब्रेक ले लिया था। अब वह पूरी तरह फिट हैं और शूटिंग पर लौट आई हैं। परिणीति ने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत भी की है, अब वह फिर बैडमिंटन कोर्ट में वापसी कर चुकी हैं। इस बात की जानकारी खुद परिणीति चोपड़ा ने ही दी है। उन्होंने कहा, 'मैं अब 100 फीसद ठीक हूं और बैडमिंटन कोर्ट में जाकर खेलने का इंतजार नहीं कर पा रही हूं। मैं अपनी पूरी साइना टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिसने इस दौरान मुझे पूरा सहयोग किया।' परिणीति ने जल्दी सेहतमंद करने के लिए मेडिकल टीम का भी धन्यवाद किया। कुछ दिन पहले गरदन और पीठ में चोट लगने से डॉक्टरों ने लगभग दस दिन तक बैडमिंटन खेलने के लिए मना किया था। साइना बायोपिक का निर्देशन अमोल गुप्त कर रहे हैं। साइना नेहवाल की बायोपिक में पहले श्रद्धा कपूर लीड रोल निभाने वाली थीं। श्रद्धा ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, मगर डेंगू होने की वजह से शूटिंग रुक गई। इसके बाद श्रद्धा फिल्म करने के लिए नहीं लौटी थीं।

अध्ययन

सोशल मीडिया के साथ ही कंप्यूटर और टेलीविजन पर ज्यादा समय बिताना भी किशोरों में अवसाद और चिंता का कारण

किशोरों में अवसाद बढ़ा रहा सोशल मीडिया

- सोशल मीडिया का उपयोग और टीवी देखना केवल अवसाद को ही बढ़ाता है
- बताया कि कंप्यूटर का संबंध अवसाद से नहीं बल्कि चिंता से है
- कनाडा के मॉन्ट्रियल विवि के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन

12 से 16 वर्ष के चार हजार किशोरों पर चार सालों तक किया अध्ययन। प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : किसी भी चीज की अधिकता जीवन में नुकसान ही पहुंचाती है। आधुनिक दुनिया में सोशल मीडिया, कंप्यूटर और टेलीविजन ने लोगों की दुनिया आसान कर दी है। वहीं, दूसरी ओर इनके अधिक इस्तेमाल से बीमारियां भी पनप रही हैं। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि चार साल की अवधि के दौरान सोशल मीडिया, टेलीविजन और कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से अवसाद और चिंता के लक्षणों के अधिक गंभीर होने का खतरा हो सकता है।

कनाडाई जर्नल ऑफ साइकेट्री में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि सोशल मीडिया, कंप्यूटर और टेलीविजन देखने पर औसत आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति के संपर्क में रहने के कारण चिंता और अवसाद के लक्षण नजर आने लगते हैं। कनाडा की मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार जब किशोर सोशल मीडिया का उपयोग कम कर देते हैं तो अवसाद के लक्षणों में भी कमी आ जाती है।

हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक अहम बात यह पाई कि सोशल मीडिया का उपयोग और टीवी देखना केवल अवसाद को ही बढ़ाता है। जहां तक कंप्यूटर के इस्तेमाल का सवाल है तो शोधकर्ताओं ने बताया कि कंप्यूटर का संबंध अवसाद से नहीं बल्कि चिंता से है। यह अध्ययन बताता है कि किस तरह से युवाओं और उनके परिवारों को डिजिटल स्क्रीन पर समय बिताना चाहिए ताकि अवसाद और चिंता दोनों से बचा जा सके। स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना भविष्य में अवसाद और चिंता से पीड़ित होने का सूचक है। मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पेट्रीसिया कॉनरेड ने बताया कि इस दिशा में और अधिक शोध करने की जरूरत है। ताकि और गहराई से सोशल मीडिया के प्रभावों का पता लगाया जा सके।

इस तरह किया गया अध्ययन : अध्ययन में कनाडा के 12 से 16 वर्ष की उम्र के चार हजार किशोर शामिल किए गए। प्रत्येक वर्ष इन किशोरों से यह बताने के को कहा गया कि उन्होंने कितना समय डिजिटल स्क्रीन में बिताया। इसके साथ ही सोशल मीडिया, कंप्यूटर, टेलीविजन और वीडियो गेम में अलग-अलग बिताए गए समय के बारे में भी जानकारी ली गई।